राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ९] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का २६ वां दिवस [संख्या २४

शनिवार

दिनांक २६ मार्च, १९६६

विधान सभा को बैठक म. पू. ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(विद्युत, अकाल सहायता, राजस्व, उद्योग, कृषि, यातायात पंचायत, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण एवं चिकित्सा विभाग)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सुमित्रा।

उद्योग हेतु दी जाने वाली बिजली की दरें

१०१. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में उद्योग के लिए दी जाने वाली बिजली की न्यूनतम दर क्या है? तथा कृषि के लिए क्या है?

(२) देश की खाद्य स्थिति को सुधारने के लिए तथा किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या राज्य सरकार कृषि के लिए भी रियायती दरों पर बिजली देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) राजस्थान में उद्योगों को कम वोल्टेज पर दी जाने वाली विद्युत की न्यूनतम दर १२.०५ पैसे प्रति यूनिट है। उद्योगों को उच्च वोल्टेज पर बिजली टू पार्ट टेरिफ के अन्तर्गत दी जाती है, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है। उनकी प्रति यूनिट दर मैक्सिमम डिमांडलोड फेक्टर व पॉवर फेक्टर पर निर्भर करती है। अतः कोई निश्चित दर प्रति यूनिट नहीं बतलाई जा सकती। कृषि की दर १२ पैसे प्रति यूनिट है।

(२) इस समय जो १२ पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है वह रियायती दर ही है। इससे अधिक रियायत का कोई प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है। समय पर भुगतान न करने पर १ पैसा प्रति यूनिट जो रिबेट दी जाती है वह नहीं दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट पूछा है कि राजस्थान में उद्योग के लिए दी जाने वाली बिजली की न्यूनतम दर क्या है? आप उनको कम से कम दर पर दे रहे हैं वह आप बतादें। यह आपका क्या डिमान्ड लोड फेक्टर और पॉवर लोड फेक्टर है, मेरे समझ में नहीं आता। उद्योग को आप मिनिमम दर पर दे रहे हैं वह बतादें।

Page No.2

श्री हरिश्चन्द्र : अभी तीन पैसे यूनिट है।

श्रीमती सुमित्रा : सुनाई नहीं दिया।

श्री हरिश्चन्द्र: डी. सी. एम. को न्यूनतम दर पर दी जा रही है और उसकी रेट तीन नये पैसे है।

श्रीमती सुमित्रा : यह एक समाजवादी समाज का नमूना है आपका। कृषि को बिजली देते हैं आप १२ पैसे यूनिट और इन्डस्ट्री को देते हैं ३ पैसे यूनिट।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

अकाल सहायता हेतु कार्यवाही

४०२. श्री दिग्विजयसिंह (रनियाना) : व **श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने अकाल सहायता के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि अधिकतर ग्रामों में चारे व पानी की बड़ी खराब स्थिति है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में जिला अधिकारी व राज्य सरकार क्या कदम उठा रहे हैं ?

(३) क्या राज्य सरकार फोडर के डिपो खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हो रहा है ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में निम्नोक्त कदम उठायें है :

(१) पी. डब्ल्यू. डी. एवं रेवेन्यू एजेन्सी द्वारा राहत कार्य:—अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य खोले गये हैं।

(२) अपाहिजों को मुफ्त इमदाद के लिए धनराशि स्वीकृत की है।

(३) जल व्यवस्था व चारे की व्यवस्था की गई है। तकावी के लिए काफी धनराशि स्वीकृत की है। बाहर चरने के लिए जाने वाले मवेशियों को मुफ्त चारा दिये जाने की एवं उनकी सुविधा की व्यवस्था की गई है।

(४) लेन्ड रेवेन्यू की वसूली ३०-९-६९ तक स्थगित कर दी गई।

(२) जिन-जिन गावों में चारे व पानी की अभाव स्थिति है वहां चारा याने घास १२ रु० प्रति क्वि० और खार फलगटी १४ रु० क्वि० दिया जाना निश्चित हुआ है। घास स्थानीय बीडों से एवं अन्य प्रदेशों से याने मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब से भी, घास मंगवाने की कार्यवाही की जा रही है। एवं आवश्यकतानुसार घास वितरण हेतु डिपो खोले जावेंगे। पानी के लिए सहकारिता से कुएं चलाने की व्यवस्था की गई है, इसके अतिरिक्त ट्रकों और रेल द्वारा पानी पहुंचाया जावेगा।

(३) जहां जहां आवश्यकता होगी, राज्य सरकार द्वारा फोडर डिपो खोले जायेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : फोडर के लिए आपने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सुनाई नहीं दिया।

श्री दिग्विजयसिंह : फोडर के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, तीन लाख की धनराशि एक दी गई और ३ लाख २० हजार ५७० की और दी है।

Page No.3

श्री दिग्विजयसिंह : आपने मुझे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें एक पैसा भी नहीं बताया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : टोटल लगा रखा है उसमें भी ३ लाख २० हजार ५७० है। हो सकता हैं कि आपके पास आंकडे पहुंचे नहीं होंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने जिलेवाइज आंकडे दिये है। कितनी कितनी धनराशि किस किस जिले को दी जावेगी यह आपने बताया है। अगर टोंक जिले में एक पैसा भी नहीं दिया गया है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो फोडर डिपो कहां से खोलेंगे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह जो राशि बताई गई है वह इस अरेंजमेंट के लिए हैं जो उनको करना पड़ेगा। वरना गवर्नमेंट ने फोडर एलॉट किया है इससे उनको खरीदने की जरूरत नहीं पडेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आप टोंक में फोडर देंगे कहां से? मैं निवेदन करूंगा कि आपने जब एक कोडी का भी प्रावधान उसके लिए नहीं किया है, और मंत्री महोदया कह रही हैं कि ७ लाख ७५ हजार रुपया मंजूर किया है। जब आपने अमुक जिले के लिए एक पैसा भी नहीं रखा है तो क्या आप इस धनराशि को रिएप्रोप्रियेट करावेंगे? आपने सब जगह रखा है। इसलिए आपका खुद का स्टेटमेंट सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी इसलिए नहीं है कि हमने फोडर के लिए फारेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया है। इस चारे को बीड करके जहां जहां हमने उनको लेजाने का कहा है वे वहां पर पहुंचा देंगे और जिलेवार जितनी चारे की व्यवस्था की जानी है उसके लिए हमने कलेक्टर को कन्वे कर दिया है और जो धन-राशि फोडर के लिए तकाबी के रूप में देंगे, उससे वे ले सकेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : जहां जहां अकाल क्षेत्र है वहां फोरेस्ट डिपार्टमेंट को आदेश दे दिया है कि जो कुछ उनके पास है उपलब्ध करें। जब वहां पर अकाल की स्थिति है वहां पर वे रोजगार से खुद खावेंगे या अपने मवेशियों को खिलायेंगे, इसलिए उनके मवेशियों को चारा दिलावें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया है कि सरकार सब्सिडी रेट पर चारा देगी। इसके लिए तकावी देगी। सब्सिडी रेट पर तकावी इसके लिए दी जाती है कि जिनके पास ज्यादा मवेशी होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

श्री दिग्विजयसिंह : एक प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, । आपने फरमाया रेट्स के सम्बन्ध में रिलीफ के अन्दर जो रेट्स दी जा रही हैं वे रेट्स क्या हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया इस प्रश्न के उत्तर के दौरान में कि घास की रेट १२ रुपया प्रति क्विन्टल है।

श्री दिग्विजयसिंह : घास की रेट नहीं मजदूरों को क्या रेट्स घास की देते हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके लिये तीन व्यक्तियों का एक समूह मान कर दस इन्टू दस, दस इन्टू दस का एक गड्ढा

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

खोदने के लिये पुरुषों को १ रुपया २ आना औरतों को १४ आना और लड़कों को १२ आना तय किया है कि ये तीनों मिलकर इतने मेजरमेंट का खोदें।

श्री दिग्विजयसिंह : एक रुपया २ आना, १४ आना और १२ आना की रेट्स दी हैं क्या इस मंहगाई के जमाने को देखते हुए ये पर्याप्त हैं, ऐसा आप मानती हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पर्याप्त हैं इसके लिये बहुत जांच-पड़ताल की जरूरत है, आज के दिन में कितना बैठता है पर फेमीन कोड के अन्तर्गत जो सुविधा मिलनी चाहिये उसको देखते हुए निर्धारित दर में धान, मवेशी के लिये चारा और तकावी आदि की व्यवस्था की है उसको देखते हुए महसूस किया जाता है कि कम नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : इस मंहगाई के जमाने में १ रुपया २ आना, १४ आना और १२ आना रखते हैं यह पर्याप्त नहीं है, फेमीन कोड कोई रिजिड तो है नहीं, उसको चैंज करने का क्या सरकार विचार रखती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : फिलहाल कोई विचार नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने जो एक गड्ढे के लिए दर रखी हैं तो पी०डब्लू०डी० की जो शिड्यूल्ड रेट्स हैं, जितना रुपया पी० डब्लू०डी० से इस इतने ही कार्य के लिये मिलता है उसके हिसाब में यह कितना कार्य होता है, क्या इसका अन्दाजा आपने लगाया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पी०डब्लू० डी० से २।। रुपया मिलता है, हम जो देते हैं, वह उस हिसाब से २।।। रुपया होता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): पी० डब्ल्यू०डी० में पुरुषों और औरतों को बराबर देते हैं फिर अकाल सहायता में यह फरक क्यों रखा गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पी० डब्ल्यू०डी० में बराबर देते हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने इन्टरनेशनल लॉ पर हस्ताक्षर किये हैं कि पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन दिया जायगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : डिगर का काम मुश्किल होता है इसलिये उसको ज्यादा देते हैं, स्त्री अगर वही काम करेगी तो उसको भी वही देंगे जो पुरुषों को देते हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप महिला मंत्री हैं तो महिलाओं के लिये किसी प्रकार की सहूलियत करेंगी क्या ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ फोडर क्या होगा, इसका कोई अन्दाजा बता सकती हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं आपका प्रश्न समझी नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपने कहा है कि उनको सब्सिडाइज्ड रेट से फोडर दिया जायगा, तो क्या बता सकती हैं कि वह सब्सिडाइज्ड रेट्स क्या होंगी ?

Page No.5

श्रीमती कमला बेनीवाल : चारा १२ रुपया पर क्विन्टल और फलगटी वगैरह १४ रुपया क्विन्टल।

प्रश्न संख्या ५०३

श्री उपाध्यक्ष : महाराज कुमार श्री ब्रजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री विजयपाल कटारा।

डूंगरपुर जिले में अकाल ग्रस्त गांवों की घोषणा

५८४. श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में सन् १९६३-६४ में जो गांव अकालग्रस्त थे लेकिन पटवारियों द्वारा झूठी गिरदावरी कर दिये जाने के कारण अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किये गये थे उन्हें अकालग्रस्त माने जाने की सिफारिश जिला रिलीफ कमेटी ने की थी ? यदि हां, तो उस सिफारिश पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

उपमंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता

(३) प्रश्न ही नहीं उठता

(४) प्रश्न ही नहीं उठता

श्री विजयपाल कटारा : यह जो सर्वे कराया गया था अकालग्रस्त क्षेत्र का वह किस आधार पर कराया गया था, कुओं में पानी नहीं होने से अकाल पड़ा इस आधार पर करवाया गया, या बारिश नहीं हुई और उसके कारण अकाल पड़ा इस आधार पर करवाया गया, कौनसा मीडियम आपने माना ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी तो एक जमी हुई पद्धति है कि जिस खेत के अन्दर ८ आना से ज्यादा खराब होता है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है फसल के हिसाब से।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या सरकार को पता है कि रिलीफ कमेटी डूंगरपुर के द्वारा इस सम्बन्ध में सिफारिश हुई थी, सिफारिश हुई थी तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप पिछले समय का कह रहे हैं या वर्तमान के बारे में ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रश्न को देखिये, १९६३-६४ से सम्बन्धित है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : डूंगरपुर जिला राहत कमेटी की तरफसे तो ऐसी कोई सिफारिश नहीं आई, हां जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आया था। उस पर जांच की गई तो जांच के बाद पाया गया कि तहसीलदार साहब ने जो आंकड़े पेश किये थे उससे अधिक गांव होते थे उसके लिये जांच के बाद ८२ गांव और जोड़े गये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ८२ गांव और जोड़े पर बीसियों गांवों में ऐसी स्थिति थी की वहां खेतों में मक्का के सूखे हुए डंठल थे। गलत गिरदावरी इन्दराजात

Page No.6

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करके जो व्यवस्था सरकार के द्वारा हुई आप खुद कह रही हैं कि कांग्रेस कमेटी ने उसे असन्तोषजनक मानकर सिफारिश की। उसके परिणाम स्वरूप कोई न कोई उदारता तो बरतनी चाहिये। यह तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था की है, क्या सरकार दुबारा विचार नहीं करेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसा कि मैंने निवेदन किया जो असंतोष की बात जाहिर की गई जो राज्य सरकार की निगाह में आई कमिश्नर ने जांच की, मैं स्वयं भी बहुत से गांवों में गई, उनके घरों में जाकर हालात देखे। वास्तव में जो गांव रह गये थे उनको डिक्लेयर करना चाहिये था, वह किया। दुबारा मैं डूंगरपुर गई तो जिला रिलीफ कमेटी के लोगों से और अधिकारियों से बात की तो उन्होंने संतोष प्रकट किया कि जो ऐतराज हमने प्रकट किये, वह पूरे हो गये हैं, अब हमें कोई गिला नहीं है।

श्री विजयपाल कटारा : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि अकाल ग्रस्त गांवों में लगान माफ करने के क्या आधार हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं आपका प्रश्न समझी नहीं। तीन साल से लगातार जहां अकाल हो उनके बारे में कहते हैं या जो अकाल ग्रस्त घोषित किये जाकर उनमें लगान सस्पेन्ड किया जाता है उनके बारे में कहते हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सस्पेन्शन या रेमिशन करते हैं, उसका क्या आधार है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सस्पेन्शन के बारे में तो यह है कि जैसे ही कहीं अकाल घोषित किया जाता है वहां साल भर के लिये लैंड रेवेन्यू स्थगित कर दिया जाता है। जहां लगातार तीन साल तक अकाल पड़ता है वहां लगान माफ कर दिया जाता है।

श्री दिग्विजयसिंह : फेमीन कोड में यह है कि जहां १० आना अकाल पड़ता है वहां लगान माफ किया जाना चाहिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसा नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपके लॉ में साफ है कि दस आने से ऊपर नुकसान है तो वहां लगान माफ किया जाना चाहिये। यह नहीं करते हैं तो फिर काश्तकारों को क्या राहत है ? सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

फर्म्स को दिये गये कोटे की उपयोगिता सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट

५०५. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जनवरी सन् १६६१ में श्री वासुदेव यादव, एस.आई.सी. आई०डी०सी०बी० ने निम्नलिखित फर्म्स को दिये कोटे की उपयोगिता के सम्बन्ध में जांच करने के पश्चात् एक रिपोर्ट पेश की और इन फर्म्स के विरुद्ध एसेन्शियल कमोडिटीज

Page No.7

(श्री भैरोंसिंह)

एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सिफारिश की है:-

फर्म्स के नाम:-

१. मेसर्स मुरलीधर झुन्झुनू वाला।
२. जयपुर साईकिल एण्ड प्लेट इण्डस्ट्रीज़
३. ऐक्सिल इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर
४. जयपुर वायर नैटिंग इन्डस्ट्रीज़।
५. जयपुर ओटोमोबाइल इन्डस्ट्रीज़।
६. राजस्थान साईकिल एण्ड पार्ट्स इन्डस्ट्रीज़।
७. भारत वायर प्रोड्यूसर्स, जयपुर।
८. ओटो इन्जीनियरिंग, जयपुर।
९. किशन एण्ड सन्स, जयपुर।
१०. शारदा इन्डस्ट्रीज़ जयपुर।
११. मेसर्स महेश्वरी एम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट (पी०) लिमीटेड, जयपुर
१२. मैसर्स राजस्थान साईकल इंडस्ट्रीज़, जयपुर।

(२) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई।

(३) इन फर्म्स को सन् ६१ से लेकर अब तक किस किस चीज का किस किस वर्ष में कितना कितना कोटा अलाट किया गया और किस किस कार्य के लिए।

(४) क्या यह सही है कि इन फर्म्स के कोटे के दुरुपयोग की शिकायतें विभाग को निरन्तर मिलती रही हैं? यदि हां, तो किस किस प्रकार की शिकायत आई और उन पर क्या कार्यवाही की गई।

(५) क्या यह सही है कि फर्म्स मुरलीधर झुंझुनूवाला के प्रतिनिधि श्री के०एम० जैन को लघु उद्योग निगम का सदस्य बना रखा है। यदि हां, तो किस आधार पर।

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट उद्योग विभाग में प्राप्त नहीं हुई।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जिन फर्म्स के बारे में शिकायत विभाग में प्राप्त हुई या जिनका कार्य सन्तोष जनक नहीं था उनके खिलाफ जो कार्यवाही की गई वह निम्न प्रकार है:-

(१) मेसर्स एस० किशन एण्ड सन्स: इस फर्म्स की सिस्टर कन्सर्न अरुन केमिकल्स के विरुद्ध जस्ते के दुरुपयोग की शिकायत आई जिसका सही उपयोग वह साबित नहीं कर सके अतः उनकी निम्नलिखित फर्म्स (सिस्टर कन्सर्न्स) को १-४-६३ को काली सूची में दर्ज करने के ऑर्डर दिये गये (ब्लैक लिस्ट) और भविष्य में कोटा देना बन्द कर दिया गया।

१. एम० किशन एण्ड सन्स, जयपुर।
२. आर० एस० डालमिया।
३. गोतम इण्डस्ट्रीज़, भरतपुर।
४. अरुन केमिकल्स, जयपुर।
५. रामा रोलिंग मिल्स एण्ड जनरल इंजीनियरिंग।
६. किशन मेटल फेरस एण्ड नॉन फेरस शैलर, जयपुर।

बाद में इसके प्रोपाइटर एस० के० बजोरिया द्वारा प्रतिवेदन करने पर रामा रोलिंग मिल्स एण्ड जनरल इंजीनियरिंग

(श्री हरिश्चन्द्र)

वर्क्स जयपुर पर से अगस्त, १९६३ में उपरोक्त प्रतिबंध हटा दिये गये और उनको कोयला व बिलेट (Billets) का कोटा देना शुरू कर दिया गया।

२. राजस्थान साईकिल एण्ड पार्ट्स इंडस्ट्रीज जयपुर– इनके विरुद्ध साईकिल पार्ट्स व टायर ट्यूब के दुरुपयोग की शिकायत थी। यह मामला डी०आई०जी० पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच के लिए भेजा गया लेकिन उसकी रिपोर्ट आई कि इनके विरुद्ध ब्लैक-मार्केटिंग का कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके बाद इस विभाग व लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा उनके हिसाब की जांच की गई जिसमें यह पाया गया कि इन्होंने हिसाब सन्तोषजनक नहीं रक्खा है। इस कारण इनको कोटा देना अप्रेल-सितम्बर, १९६३ से बन्द कर दिया गया।

३. मुरलीधर झुन्झुनूवाला (मेटल उद्योग (प्रा०) लि०, जयपुर) को जो कोटा दिया गया है उसके उपयोग के बाबत हिसाब प्रस्तुत करने को लिखा गया है लेकिन इनके प्रतिनिधि श्री के० एन० जैन ने कुछ हिसाबात कलकत्ता चले जाने की बिना पर इसके प्रस्तुत करने की मोहलत चाही है जिस पर क्षेत्रीय उप-संचालक जयपुर को शीघ्र जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लिखा गया है।

४. जयपुर वायर नेटिंग इंडस्ट्रीज, जयपुर। इनका कार्य सन्तोषजनक नहीं होने से इनको ६०-६१ के बाद कोई कोटा नहीं दिया गया है।

५. जयपुर ओटोमोबाइल इंडस्ट्रीज :— इनको १९६१ से १९६५ तक कोई कोटा नहीं दिया गया।

६. ओटो इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर। इनको १९६१ से १९६५ तक कोई कोटा नहीं दिया गया।

७. भारत वायर प्रोडक्टस जयपुर:– इनका काम सन्तोषजनक नहीं होने से १९६०-६१ के बाद कोई कोटा नहीं दिया गया।

८. महेश्वरी इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट जयपुर – ये कन्ट्रोल स्टॉकिस्ट्स है इनको कोई कोटा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया।

बाकी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है और ये उद्योग अभी भी चालू हैं और अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

(५) जी हां। इनको शेयरहोल्डर्स ने जनरल मीटिंग में चुना है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने कुछ समय पूर्व यह निर्णय लिया था कि जो लोग कोटा का दुरुपयोग करते हैं उनको एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट में चालान किया जाय और इस सम्बन्ध में सक्यूलर जिला उद्योग अधिकारी को भेजा गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : कानून बना है तो उसके अन्तर्गत कार्यवाही करनी ही पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह : मैं जो बात पूछ रहा हूं उसका सीधा जवाब दीजिये। क्या यह सही है कि जिला उद्योग अधिकारी को सरकार ने सक्यूलर द्वारा इस बात की

(श्री भैरोंसिंह)

तबीह की है कि लोग कोटा के माल का दुरुपयोग करते हैं उनको एसेन्शियल कमोडिटीज् एक्ट के अन्तर्गत चालान किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा सर्क्यूलर निकाला होगा। इस समय सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जब कानून बना है तो उसके अंतर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होता है।

श्री भैरोंसिंह : जब यह कानून बना हुआ है और आंपने सूची के अन्दर इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कुछ लोगों ने कोटा का सही उपयोग नहीं किया तो उन लोगों का आपने एसेन्शियल कमोडिटीज् एक्ट के तहत चालान क्यों नहीं करवाया।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो पुलिस के हाथ में है। इस विभाग के हाथ में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने पुलिस विभाग को लिखा है इसका चालान करने के लिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक मेरी सूचना है, पुलिस ने स्वयं ही कार्यवाही की है।

श्री भैरोंसिंह : उद्योग विभाग को जब इस बात की जानकारी मिल गई कि उन्होंने कोटा का दुरुपयोग किया, आपने उनको ब्लेक लिस्ट किया इसी आधार पर भविष्य में उनको कोटा न मिले ऐसे आदेश दिये हैं, इसके बावजूद पुलिस को सूचना दी है या नहीं कि एसेन्शियल कमोडिटीज् के तहत चालान किया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : पुलिस ने स्वयं ही इसकी जांच की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या पुलिस ने अपने आप किया है या उद्योग विभाग की शिकायत पर किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कई शिकायतें आई, तरह तरह की आई थीं। उद्योग विभाग के पास भी आई और पुलिस के पास भी आई फिर उद्योग विभाग ने भी अपनी कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने भी ...

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी कैसे मिली कि पुलिस ने अपने आप कार्यवाही की है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं सरकार की ओर से बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, जी नहीं। क्या सरकार के नोटिस में अभी तक नहीं आया कि पुलिस के सी०आई०डी० सब इन्सपेक्टर वासुदेव ने इन सब मामलों की जांच करके रिपोर्ट पेश की है जिसमें लिखा है कि इन लोगों ने ब्लेक मार्केट किया है, इनको एसेन्शियल कोमोडिटीज् एक्ट के तहत चालान किया जाय, और उसकी सूचना उद्योग विभाग को मिली है।

श्री हरिश्चन्द्र : उद्योग विभाग को सूचना नहीं मिली है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को इसकी सूचना है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पुलिस विभाग के पास हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास इसकी जानकारी है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास कैसे होगी ? पुलिस ने जांच की और उसका रिकार्ड होगा ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह प्रश्न राज्य विधान सभा में एक वर्ष पूर्व उठाया गया था और वासुदेव, एस. आई. की रिपोर्ट सदन में पढ़कर सुनाई गई, उसके बाद में उद्योग विभाग ने जांच नहीं की कि इनके खिलाफ एसेन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत एक्शन लिया जाय ? पुलिस में जांच हो रही है, यह आपके नोटिस में आया है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है वह १९६१ से···

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस ने जो फाइल्स बनाये थे, वह उद्योग विभाग ने मंगवा लिए, यह लिखकर कि पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और फाइल्स उद्योग विभाग को भेज दिये जांय ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सवाल ही नहीं उठता है। जब जांच उन्होंने शुरू की तो रिकार्ड भी वे ही ले जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जो रिकार्ड ले गए वह किसके पास है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पुलिस विभाग के पास होंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भूतपूर्व उद्योग मन्त्री ने आदेश देकर डाईरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ को लिखा कि वे सारी फाइल्स पुलिस विभाग से उद्योग विभाग में मंगालें और उस समय से सारी फाइल्स दब गई हैं, फाइल्स खो गई हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास फाइल्स खोने की जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप बताएं कि फाइल्स कहां हैं ? पुलिस विभाग से आपने मंगवाई ?

श्री हरिश्चन्द्र : हमने नहीं मंगवाई।

श्री भैरोंसिंह : कहां गई ? आप पहले कह चुके हैं कि पुलिस विभाग में नहीं हैं, एक साल पहले जिस समय पहली बार प्रश्न उठा था उस समय कह चुके हैं कि उद्योग विभाग पुलिस की रिपोर्ट पर जानकारी कर रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने एक साल पहले की बात कही है। मैंने क्या आश्वासन दिया था वह मुझे याद नहीं है, लेकिन उद्योग विभाग ने जरूर कोशिश की थी कि पुलिस विभाग से फाइल्स आईं, लेकिन वे फाइल्स पुलिस विभाग के पास में ही हैं, हमारे पास नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब आपको जानकारी मिल गई है कि पुलिस विभाग ने जांच की है और ब्लैक मार्केट का पता लगा है तो इन लोगों का एसेन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत चालान किया या नहीं, इस संबंध में आपके विभाग ने पुलिस विभाग पर किस प्रकार का प्रेशर डाला है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो आपके पास कौनसी जानकारी है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह १८ लाख रुपए का माल खा गए, कन्ट्रोल का

(श्री भैरोंसिंह)

कोटा दिया १९६१ में, उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद सब-इन्सपेक्टर ने लिख दिया है कि ब्लैक मार्केट हुआ है, एसेन्शियल कमोडिटीज् एक्ट में चालान किया जाय, १९६१ के मामलों को दबाकर मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, तो बाकी किस बात की जानकारी है ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं ।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या यह सही है कि सब इन्सपेक्टर की उपरोक्त रिपोर्ट करने के बाद उसको सस्पेन्ड कर दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : तो किस बात की सूचना है ? उसको इसलिए सस्पेन्ड कर दिया कि वह सेठ लोगों के खिलाफ...

श्री हरिश्चन्द्र : उसके अगेन्स्ट कोई कार्यवाही हुई है, यह सूचना है। सस्पेन्ड हुआ, यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : की गई थी ना कार्यवाही ?

श्रीमती सुमित्रा : (झुन्झुनूं) इस रिपोर्ट के बाद उसको सस्पेन्ड किया गया या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे नहीं मालूम है। लेकिन उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही जरूर की गई थी। किस वजह से की गई, यह मुझे नहीं मालूम है ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Jwala-Prasad.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इस मसले को मैंने कई बार उठाया है। उद्योग मन्त्रीजी से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इस सिलसिले में जब यह शिकायत आई और कोटा १८ लाख का दिया गया, १८ लाख का कच्चे माल का कोटा सरकार की तरफ से उनको दिया गया और दिये जाने के बाद उसका बम्बई, कांडला, कलकत्ता, मद्रास के अन्दर ब्लैक मार्केट किया और उसकी सूचना सरकार के सामने शिकायत के रूप में आई तो आपके डिपार्टमेन्ट ने यह मामला पुलिस को दिया और पुलिस वालों ने हिन्दुस्तान में घूमघूम कर हजारों रुपया खर्च करके कागजात इकट्ठे किये, ये कागज हमने जानकारी दी आपके सामने पेश किये और हमारे लॉ मिनिस्टर वे बैठे हुए हैं जिन्होंने आश्वासन दिया था कि मुझे एक केस बतला दो, उनको लाखों रुपयों के और केसेज बताये उन्होंने छाती ठोककर कहा था कि मैं जांच कराऊंगा, वे भी आज मौन हैं। यहां पर इस प्रकार आश्वासन दिये जाते हैं और उन आश्वासनों को इस तरह 'ना', 'हां' करके टाल देते है। माथुर साहब तो एक्सपर्ट बन चुके हैं, हां करो और फिर ना करो। माथुर साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि जो आश्वासन पहले केस के ऊपर इस विधान सभा में आपने दिये थे उनका क्या हुआ ? और भैरोंसिंहजी को दिये उनका क्या हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनको गवाह बना रहा हूं। मामला आपका है।

Page No.12

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला इस बात का है कि गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। यहां के कॉरपोरेशन में मेम्बर बनाते हैं तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं और सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको हक मिले हुए हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कोटा मिलता है इन्डस्ट्रिलाइजेशन आदि के लिये और आपके स्टेटिक्स के सारे फीगर्स झूठे होते हैं कि इतनों को एम्प्लायमेन्ट मिला है, हमारा ला स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग है इसी कारण से हैं और इस तरह से झूठे फीगर्स देकर उसको ऊंचा उठाया जाता है। हमारी टैक्स देने की पॉवर नहीं है, लेकिन इस प्रकार झूठे फीगर्स देकर हम पर और टैक्स लगाया जाता है। ये मेटर्स हैं। हमने पेश किये हैं। आपने पढ़ने की दिक्कत की हो, माथुर साहब और हरिश्चन्द्रजी साहब। उसमें यह लिखा है कि ७ सेक्शन हैं, मुझे इजाजत दी जाय। सारे पेपर्स इकट्ठे कर लिये मद्रास और कांडला बम्बई, कलकत्ता जाकर और जिन्होंने ब्लेक मार्केट किया है उसने लिखा है कि मेरे पास सब सुबूत हैं।

(विपक्ष द्वारा हियर-हियर)

एसेन्शियल कमोडिटीज् एक्ट में उसका चालान करें।

श्री उपाध्यक्ष : यह भाषण का समय नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'क्या' लगा देता हूं बीच बीच में।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि यह उसमें लिखा हुआ है और लिखने के बाद यह होता है कि कागजों की मालूम पड़ती है, यह व्यक्तिगत बात नहीं है, सन् १९६१ की बात हैं और आपके ही इलाके के श्री धारीवाल जी का मामला है।

श्री भैरोंसिह : धारीवालजी ने ही नहीं इन्हीं ब्लैक लिस्टेड की कोटा आपके (श्री हरिश्चन्द्रजी के) जमाने में भी दिया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह आप कहना। मैं ६१ की बात कह रहा हूं। डाइरेक्टर लिखता है कि पुलिस से फाइल्स मंगाने का कोई हक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि धारीवालजी ने लिख कर पुलिस से सारी फाईलें मंगायी, पुलिस से स्नेच किया, आपके डिपार्टमेंन्ट ने स्नेच किया और उस आदमी को दूसरे चार्जेज पर सस्पेन्ड किया।

(विराम)

और सस्पेन्ड करने के बाद खास-खास इलाकों में अर्जुन और भीम का नाम लेकर एस.एच.ओ. बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके बाद १८ लाख का जिन्होंने ब्लैक मार्केट किया उन ब्लैक मार्केटियर्स का कोई भी चालान इस एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत किया ? उन केपिटलिस्ट्स का, बिजनैसमैन का चालान किया ? That is a dead piece of legislation as far as Rajasthan Government is concerned and these people ... गरीबों की गाढ़ी कमाई पर ये मोटे से मोटे हो रहे हैं, उसका क्या कारण है ? आप इन्क्वायरी करेंगे क्या ? आप दोनों साहब जवाब दीजिये।

Page No.13

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन पूछने के बजाय माननीय सदस्य ने तो भाषण ही झाड़ दिया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पूरे सवाल किए हैं । आप एक एक का जवाब दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : जो कुछ भी करना है वह सब करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र : उनके कोटे के दुरुपयोग की रिपोर्ट आयी, उस पर इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने पुलिस को कहा कि आप एन्वेस्टीगेशन के द्वारा चालान करिये । उसके बाद सारी फाइलें और सारी चीजें पुलिस में गई और ६१ से कार्यवाही चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह : इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने पुलिस को यह नहीं लिखा कि दुबारा कार्यवाही नहीं कर सकते और फाइलें यहां भेज दीजिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई नहीं लिखा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : स्थिति यह नहीं है कि कोई जांच न की हो । आपके पास शिकायत आने पर आपने पुलिस को दी । उसने महीनों मेहनत की । आपसे इजाजत चाही, आपके ऑफिसर्स की इजाजत लेनी पड़ती है.इस वजह से कागज गये थे, कागज गये ओरिजनल । आप इन्क्वायरी करो, जो कागज गये, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं था, आपके मिनिस्टर ने मंगा लिए और डेड पड़े हुए हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र : जो आप कह रहे हैं वैसी स्थिति नहीं हैं इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट के पास न तो फाइल्स आयीं । इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने पुलिस को लिखा कि चालान कराये और पुलिस ने कार्यवाह की ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या आप ये समझायेंगे इस मामले पर कि १८ लाख का ये जनता का माल खा गये; आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरी तरह से जांच कराके इस हाउस को सेटिस्फाई करेंगे कि यह कैपिटलिस्ट की गवर्नमेन्ट नहीं है, सोशलिस्टों की गवर्नमेन्ट है और कैपिटलिस्ट्स को दिन दहाड़े कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकते और देते है ..

(हियर हियर)

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): माननीय उपाध्यक्षजी, इतना निवेदन कर सकता हूं कि किसी ब्लैक मार्केटियर को, जहां तक गवर्नमेन्ट की नीति का सम्बन्ध है, प्रोटेक्शन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता । इस मामले में ६१ से पुलिस जांच कर रही है । ये मिसलें पुलिस के पास हैं । इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने पुलिस को लिखा था । ये मिसलें देखने के लिए भेजी जायं । उस पर यह उत्तर दिया कि जाँच कर रहे हैं और कम्प्लीट नहीं हुई हैं । असेम्बली में दौराने बहस में आश्वासन दिया तो विभाग के सेक्रेटरी ने फिर लिखा कि फाइलें जांच के लिए भेजी जायं कि आज यह चर्चा हुई हैं । इन्क्वायरी कम्प्लीट नहीं कर पाये और मुझे यह सूचना मिली है कि इन्स्पेक्टर ने जो माल को जब्त किया तो कानून के अनुसार नहीं किया, उस पर कार्यवाही चल रही है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह अलग प्रश्न है । किसी और इन्क्वायरी में वह मौत्तिल होगा । आप चाहे फांसी चढ़ावें ।

Page No.14

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आप कम्पलीट इन्क्वायरी कर लीजिये। आप से आश्वासन चाहते हैं कि एसेन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट में उसका चालान करेंगे या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इतना ही आश्वासन दे सकता हूं और कह सकता हूं कि पुलिस के पास मामला पेन्डिग है । पूरी इन्क्वायरी होने पर जो कानूनी कदम लेना चाहिए वह लेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सन् ६१ का मामला है। आज ६६ हो गया और मिनिस्टर उद्योग विभाग इस बात के लिए सेटिस्फाई होगये, १८ लाख का जो माल है, उसमें एसेन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। जब वे सेटिस्फाई हो गये तो उनको चालान करते। अगर उसमें दुरुपयोग नहीं मानते हैं, उपयोग हुआ है तो आप हमको समझाइये। या उसकी पूरी जांच कराई जाय। आपने उनको कोरपोरेशन का डाइरेक्टर बना दिया। उन लोगों के पीछे गवर्नमेन्ट बदनाम हो रही है, अगर आप उनका चालान करेंगे तो उसमें कांग्रेस सरकार की प्रतिष्ठा ऊंची होगी।

श्री भैरोंसिंह : यह गवर्नमेन्ट तो ब्लैक मार्केटियर्स पर ही चल रही है।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक कार्यवाही करने का सवाल है मैं समझता हूं सरकार हमेशा इस बात के लिए जागरूक रहती है। जहां भी ऐसा काम हो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कोई भी चीज हाइड नहीं करना चाहता, जिस किसी ने भी गलती की है उसको जरूर सजा मिलेगी।

यह जो रिपोर्ट पुलिस ने बनाई थी पुलिस ने जो इन्वेस्टीगेशन किया था वह फाइनल होकर के कोई चालान नहीं हुआ है। अभी वह इन्वेस्टीगेशन की स्टेज पर है। यह इन्वेस्टीगेशन १९६१ से चल रहा है इस वक्त इसमें क्या हो रहा है, यह मैं नहीं कह सकता। इस वास्ते माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप सेटिस्फाइड हो जायं, मेम्बरान सेटिस्फाई हो जायं। हम किसी को शील्ड नहीं करना चाहते।

श्री भैरोंसिंह : आप एक बात बता दीजिये पेपर्स, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय को दिये, इसकी एक कॉपी मुरलीधरजी व्यास, ज्वालाप्रसादजी के पास, थी ज्वालाप्रसादजी ने मुझे नहीं मालूम किनको दी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने वे कागजात यहां पेश किए हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने मंत्री महोदय को पेपर्स दिये उन सब को आपने देखा है; एक-डेढ़ साल पहले वे पेपर्स रखे गये थे उसके बाद आज माननीय मंत्री महोदय कहें मुझे कोई जानकारी नहीं क्या हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो जानकारी मेरे पास है वह मैं सदन को दे रहा हूं। इन्वेस्टीगेशन हो रहा है। मैं कोई चीज हाइड नहीं करूंगा। जो सूचना आपने मांगी है वह मैंने मेम्बरान के सामने रख दी है, अभी तक इन्वेस्टीगेशन फाइनल नहीं हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की ? आपसे पुलिस ने इजाजत मांगी इनको पकड़ने की, आपने उनको इजाजत क्यों नहीं दी ?

श्री हरिश्चन्द्र : It is still in an investigation stage.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या इस प्रकार के मामले में पांच-पांच साल लग जाते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब तक फाइनल इन्वेस्टीगेशन नहीं होता तब तक चालान करने का सवाल कहां पैदा होता है ? मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : आप ईमानदारी से यह कह दीजिये कि पुलिस ने कम्पलीट इन्क्वायरी करके आपके सामने केस नहीं रखा पुलिस ने जो ब्लैक मार्केट का चार्ज लगाकर भेजा उस पर गवर्नमेन्ट को एक्शन लेना चाहिये था। १९६१ में सब से पहले यह रिपोर्ट पेश हुई उसमें भूतपूर्व उद्योग मंत्री ने डाइरेक्टर से यह लिखवाया कि फाइल्स पुलिस से वापिस मंगवा ली जाय। उन्होंने कहा यह फाइल्स नहीं भेजी जाती प्रोसीक्यूशन की इजाजत दी जाए। उनको प्रोसीक्यूशन की इजाजत नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो कोटा उनको दिया गया उसका मैंने टोटल लगाया वह १४ लाख का बनता है। जो ब्लैक लिस्टेड फर्म्स थीं, जिन पर चार्जेज लगे हुए हैं उनको फिर १४ लाख का कंट्रोल्ड कमोडिटी का काम दे दिया गया, इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता। मुझे दुख इस बात का है कि आप केपिटलिस्ट्स और ब्लैक मार्केटियर्स को बचाने का परिश्रम कर रहे हैं। अगर आप यह साबित करना चाहते हैं कि आप ब्लैक मार्केटियर्स को बचाना नहीं चाहते तो आप सदन के सदस्यों की समिति बना दें जो जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन को दे। मेरा यह भी आग्रह नहीं है कि उसमें अपोजीशन के भी मेम्बर रखे जायं। आप अगर चाहें तो अपोजिशन के मेम्बर न लेकर केवल कांग्रेस के ही दो सदस्यों को नियुक्त कर दें जो अपनी रिपोर्ट पेश कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन आवर का बहुत ज्यादा समय इसी एक क्वेश्चन में ले लिया गया है, अभी काफी क्वेश्चन हैं। यदि आपको इस बारे में बहस ही करनी हैं तो आप इसके लिये हाफ एन आवर का डिस्कशन उठा सकते हैं। रूल्स में और भी विधियां हैं उसके अन्तर्गत आप कार्यवाही कर सकते हैं। आप क्वेश्चन आवर में इस प्रकार वाद-विवाद करने लग जायं, यह रूल्स के अन्तर्गत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जितना उपदेश दिया है उतने समय में तो हम तीन सवाल कर लेते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : राजस्थान के भले के लिये सुनना होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): माननीय उद्योग मंत्री ने कहा इस बारे में जांच की जा रही है कोई शील्ड करने का इरादा नहीं है, इरादा नहीं तो फिर जो यह १८ लाख का गोलमाल हो रहा है जिसने किया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कर रहे है? Are you sleeping over the papers. You must do some thing. कुछ न कुछ तो करना चाहिए। एक तरफ आप कुछ नहीं करते हैं तो हम लोगों को यह आशंका होती है कि आप उनको जान-बूझकर शील्ड करते हैं। जहां ब्लैक मार्केट हों, घोटाले हों ऐसे मामलों में भी आप चार-चार वर्ष तक कुछ नहीं करते तो आप इस पद पर बैठने के योग्य नहीं हैं, आप इस तरह से ब्लैक मार्केटियर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार प्रश्नों का कोई अन्त नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूं आप इसके बारे में आधा घंटा का वाद-विवाद उठा सकते है।

श्री भैरोंसिंह : हाफ एन आवर का मौका नहीं आने वाला है। यह सरकार इस तरह से ब्लैक मार्केटियर्स को बचाकर इलेक्शन के समय फिर उनसे चन्दा इकट्ठा करेगी और चन्दे के नाम पर उनको स्नेच करने वाले हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : परमिट कोटा लाइसेंस की गवर्नमेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : कोटा लाइसेन्स ब्लैक-मार्केटियर्स और चोरी की सरकार है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): ब्लैक मार्केटियर्स के चन्दे पर चलने वाली सरकार है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके बारे में कैटेगोरिकली सदन को आश्वासन मिलना चाहिए। इन्डिया गवर्नमेंन्ट से जो कोटा मिलता है इसका मिसयूज होता है, उसकी एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत चालान किया जाना चाहिए। इस संबंधी जितने कागजात हैं वे आप डिप्टी स्पीकर साहब के सामने रख दें और उसके साथ साथ आप यह भी आश्वासन दे दें इस मामले में पूरी जानकारी करके जल्दी से जल्दी इस बारे में कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सारे कागजात हाउस की टेबल पर रख दिये जायं और लीडर ऑफ दी अॉपोजीशन विधि मंत्री, उद्योग मंत्री, सब मिल कर देख कर तय कर लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनसंघ दल के लीडर महोदय ने जो कहा मैं उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं इसमें अपोजीशन के लीडर की जरूरत नहीं कि वह देखे, आप अपनी निष्ठा का परिचय दीजिये। कितने दिन तक आप कागजों पर बैठे रहेंगे, आखिरकार कुछ निर्णय तो होना चाहिये। आपने इस मामले में चार वर्ष बिगाड़ दिये, फिर भी आप मौनवृत्ति धारण कर विराजमान हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपको भी मौका मिलना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : कारण इसका यही हैं कि पहले इनके और उनके बीच में आपस में लड़ाई थी, अब समझौता होगया है, अब ये उनको बचाने की चिन्ता में हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : जो श्री भैरोंसिहजी ने प्रश्न पूछा, उसमें १२ फर्म्स के नाम लिखे हैं। उसमे से ८ को १९६१ के बाद कोटा दिया गया।

Page No.17

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट क्यों तोड़ा ?

श्री हरिश्चन्द्र : कुल चार फर्मों को बाद में मिला। अब यह प्रश्न हो सकता है कि इनको कोटा क्यों मिला ? इसके लिये मुझे यह निवेदन करना है कि फाइनल तय नहीं किया कि इनको ब्लैक लिस्ट किया तब दिया गया। क्वान्टिटी रिड्यूस की गई।

श्री भैरोंसिंह : क्वान्टिटी रिड्यूस करने का क्या मतलब ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्वान्टिटी रिड्यूस क्यों की गई ? Why the Government reduced the quota.

श्री भैरोंसिंह : कोटा जो रिड्यूस किया वह पैनल्टी के रूप में किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोटा रिड्यूस किया।

श्री भैरोंसिंह : किस कारण से किया? एज ए पैनल्टी किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोटा रिड्यूस हुआ...

(व्यवधान)

पहले मुझे सुन तो लो। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि कोटा रिड्यूस हुआ अब जो १२ फर्म्स हैं उनको कइयों को कोटा मिलता नहीं है। जिन लोगों को मिलता है अगर माननीय सदस्यों की यह इन्फोर्मेशन है कि यह ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसके लिए सरकार की ओर से यह आश्वासन देता हूं कि हम किसी भी ब्लैक मार्केटियर को प्रोत्साहन या प्रोटेक्शन नहीं देना चाहते हैं। अब इस सिलसिले में यह मैं नहीं कह सकता कि जो एवीडेन्स है वह सफीशियेन्ट है। लेकिन इसकी जांच हम करवा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं विराज जायें, फाइल देखकर आप जो हुक्म देंगे मैं करने के लिये तैयार हूं। किसी और माननीय सदस्य को बुला लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यह आक्षेप लगाना कि सरकार हर चीज के लिए हाइड करना चाहती है वह मैं स्पष्ट तौर से कहदूं कि सरकार हाइड नहीं करना चाहती है। यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार किसी को हाइड नहीं करना चाहती है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने आज तक हाइड किया है। यदि हम नहीं बोलते तो इन ब्लैक मार्केटियर्स के ब्लैक मनी को सरकार खा गई, सब मंटल को खा गई। यह तो अपोजीशन की करामात है कि १८ लाख रुपये का मामला सदन के सामने लाकर रखा। आपने उसको बचाया है। यदि हिम्मत हो तो सारे कागजात विधान सभा की मेज पर रखो।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूं कि जो मेरा आश्वासन है...

श्री भैरोंसिंह : कोई आश्वासन नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कह दिया है, आप जांच कर लीजिए।

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस के मेम्बरों की एक कमेटी बना लें और फिर इसकी जांच करा लें।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, जिसको चाहे उसको बुलालें इससे ज्यादा और क्या आश्वासन चाहते हैं सरकार की

(श्री हरिश्चन्द्र)

तरफ से । अध्यक्ष महोदय बैठ जावें, कोई और बैठ जायें और इसकी जांच करलें । मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के एलोगेशन सरकार के ऊपर न लगायें ।

श्री भैरोंसिंह : This is a proved allegation. इससे ज्यादा और क्या सुबूत चाहते हैं ? ५ वर्ष तक १ हजार रुपया महावार की आपको सरकार ने तनख्वाह दी, आपने ६० हजार रुपये खराब कर दिये और एक भी केस को आप नहीं कर पाये ।

श्री हरिश्चन्द्र: This is not a proved allegation. It is not proved at all. The matter is still under investigation.

श्री भैरोंसिंह : गरीबों का तो आप चालान करदें और करोड़पति और लखपति ऐसा कर दें तो पांच पांच वर्ष तक उनका इन्वेस्टीगेशन नहीं हो ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सो रहे हैं, सो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

तकावी आदि का वितरण, जिला बूंदी

५०६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बूंदी जिले के कृषि विभाग द्वारा सन् १६५२ से लगाकर अब तक कुल कितनी रकम तकावी, बीज व खाद के रूप में वितरित की गई है ?

(२) क्या विभाग ने इस बात की जांच करने की कोशिश की है कि इनमें से कितनी पंचायतों के मारफत दिया जाने वाला बीज किसानों को नहीं दिया जाकर उसका गबन किया गया ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह): (१) बूंदी जिले में कृषि विभाग द्वारा सन् १६५६-५७ से ५६-६० तक खाद की तकावी १,३१,४४१ रु० और ४,७३,४५७ रु० बीज की तकावी वितरण की गई । सन् १६५२-५३ से ५५-५६ तक का रेकार्ड अग्नि दुर्घटना में जल जाने से उपलब्ध नहीं है, वह बनाया जा रहा है ।

(२) इस प्रकार के गबन की कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह जो कागज जल गए ५२ से ५६ के बीच में और १६५६-५७ से ५६-६० तक खाद की तकाबी १,३१,४४१ और बीज की तकावी ४,७३,४५७ रुपये दी गई पंचायत के मार्फत इसका वितरण किया गया तो कागज जल गये, आपने फिर इसकी वसूली की ?

श्री भीमसिंह : जैसा मैंने पहले प्रश्न में निवेदन किया कि उनके कागज तैयार हो रहे हैं, जहां जहां सोर्सेज से आये थे उन को कम्पाइल करके रेकार्ड तैयार कराया जा रहा है ताकि वसूली की मुकम्मिल कार्यवाही की जा सके ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जल नहीं गये, जला दिए गये । ५२ से ५६ तक लाखों रुपये के बीज तकाबी और खाद की तकाबी बांटी और कृषि विभाग में आग लगवादी गई, उसकी जिम्मेदारी किस ऑफिसर की थी और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

Page No.19

श्री भीमसिंह : जो कागज जले हैं उन की इन्क्वायरी चालू है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आज ६६ है और १० लाख की तकाबी के कागज जले हैं तो किस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है और उसके लिए क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री भीमसिंह : इन्क्वायरी कम्प्लीट होने पर जवाब दिया जायेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कौन ऑफिसर थे जिनकी देखरेख में ५२ से ५६ तक १० लाख की तकाबी के कागज जल गए और वे पैसे अब वसूल नहीं हो रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या कार्यवाही की ? वह कौन ऑफिसर थे ? इस प्रश्न को ३ साल से टाल रहे हैं।

श्री भीमसिंह : अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो सका है कि किस कारण यह अग्नि दुर्घटना हुई थी। फिर भी इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी पूर्ण इन्क्वायरी करा ली जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ऐसा घोटाला हुआ है कि काश्तकारों को न बीज मिला और न तकावी मिली। इन्डीविजुअल लोग उसको खा गए और सारे कागज को कृषि विभाग से मिलकर, सारी मिसलों को जला दिया और सन् ५२ से अब तक बैठे हैं। मैं बराबर ३ साल से प्रश्न दे रहा हूं और इसको टाला जा रहा है। इसमें बड़े-बड़े लोगों का हाथ है। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि जिनकी देखरेख में यह कागज जल गए उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ? आप टैक्स के पैसे को इस तरह से लोगों को खिला दें और ऐसे ऑफिसरों को खिला दें किसी प्रकार का एक्शन न लें मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि कागज जल गए इसलिए वसूलात नहीं हो सकी और सरकार को नुकसान हुआ है। कागज जले यह भी स्वीकार किया है तो क्या कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर किया, एफ० आई० आर० हुई और उसके बाद में किसी ने तफतीश की या मंत्री महोदय का वैसे ही जबाब देने का रुटीन तरीका है कि कार्यवाही चल रही है। यह जवाब भी दिया जाता है तो मंत्री महोदय से पूछ लिया जाये कि आज किस प्रकार की जांच चल रही है ?

श्री भीमसिंह : निवेदन है कि जैसा प्रश्न नम्बर १ में पूछा है बूंदी जिले के कृषि विभाग के द्वारा सन् १९५२ से लगाकर अब तक कुल कितनी रकम तकावी, बीज व खाद के रूप में वितरित की गई है ? तो उसके फिगर्स मैंने निवेदन कर दिये हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह लिस्ट तो बता दें, किसको यह रकम दी गई और कितनी दी गई ?

श्री भीमसिंह : अगर उन्होंने पोइंटेन्डली पूछा होता कि इस तरह से अग्नि काण्ड हुआ और उसकी इन्क्वायरी का क्या हुआ, किस पर उनकी जिम्मेदारी आई है, तो सारी तफसील से मैं क्वेश्चन का उत्तर तैयार करके लाता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप किस बात के मिनिस्टर हैं, आप किस बात की तनख्वाह पाते हैं।

श्री भीमसिंह : इसके लिए दुबारा टाइम दे दिया जाये ताकि सारा मैटिरियल देख लिया जाये। मैं नहीं चाहता कि सदन के सामने इन्कम्पलीट उत्तर रखूं।

श्री उपाध्यक्ष : The question is postponed.

(विराम)

श्रीजयनारायण सालोदिया।

स्टेट रोड़वेज कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट

५०७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) स्टेट रोड़वेज कॉरपोरेशन के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट बन गई है या नहीं ? यदि बन गई है तो कब।

(२) यदि नहीं, तो कर्मचारियों की पदोन्नति किस आधार पर की जा रही है।

उप मंत्री, यातायात (श्रीभीमसिंह) :-
(१) निगम में दो प्रकार के कर्मचारी हैं, एक वे जिनकी नियुक्ति निगम द्वारा की गई है और दूसरे वे जो सरकार की ओर से निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं। जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं उनमें से कनिष्ठ लेखकों की वरिष्ठता सूची दिनांक १२-४-६५ ई० को तैयार करली गई थी। निगम में भरती किये गए कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची साथ की साथ तयार होती रहती है।

(२) जिन कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अभी तैयार नहीं हैं उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए अस्थाई तौर पर पदोन्नत किया जाता रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि विभाग में ए० टी० आई० को कितनों को प्रोमोशन मिला और वह सोनियोरिटी लिस्ट के आधार पर मिला क्या ?

श्री भीमसिंह : आपने स्पेसिफिकली नहीं पूछा था कि कितने ए०टी०आई० को दिया, इसलिए यह फिगर्स मौजूद नहीं हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने यह चार्ज लगाया है कि आपके पास में सीनियोरिटी लिस्ट नहीं है और उसके आधार पर प्रोमोशन नहीं होता ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): ऐसा है कि विभाग में दो तरफ के कर्मचारी हैं एक तो कॉरपोरेशन बनने के बाद रिक्रूट किए गए उनकी रिक्रूटमेंट की डेट से सीनियोरिटी लिस्ट तैयार हैं। दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और उसमें ट्रांसफर होकर आए वह काम कर रहे हैं। अब उनको ऑप्शन किया गया है वह चाहे तो अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट में ऑप्ट कर ले और चाहे तो निगम की कर लें। उनको नोटिस दिया गया है वे जो गवर्नमेंट में ऑप्ट करेंगे उधर चले जायेगे और जो निगम की ऑप्ट करेंगे उनकी और जो निगम में पहले से हैं उनकी कन्सोलीडेटेड लिस्ट बनेगी। नये आदमियों को प्रोमोशन डेट ऑफ अपॉइन्टमेंट से है। उसके बारे में अगर कोई बात आपकी नजर में है कि सीनियोरिटी को बदल कर मातहत वाले को प्रोमोशन दे दिया है तो नोटिस में लाइए, हम जांच करेंगे।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या निगम की ओर से इन सर्विसेज के प्रोमोशन देने के नियम बने हुए हैं और क्या उन नियमों के अनुसार इनकी सर्विसेज और इनकी एफिशियेंसी को देखकर प्रोमोशन दिया जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : नियम बने हुए हैं प्रोमोशन देने के सीनियारिटी-कम-मेरिट और मेरिट-कम-सीनियोरिटी और प्योरली मेरिट। ये सब मामले हैं और इनके अनुसार ही सब काम किया जा रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वह सरकार से आने वाले कनिष्ठ लेखकों की ही है। क्या सरकार के पास से आने वाले कनिष्ट लेखकों की सीनियोरिटी लिस्ट ही बनाई गई है।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार से आने वालों की लिस्ट भी नेग्लीजिबल फॉर्म में है। जब तक वे ऑप्ट करके फाइनल डिसिजन नहीं ले लेते कि उन्हें सरकार में जाना है या निगम की सेवा में रहना है, तब तक फाइनल कैसे हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। अब कुछ स्थगन-प्रस्ताव हैं।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry please.

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगापुर से खेड़ा तक विद्युत सप्लाई में प्रगति

५०३. **महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगापुर से खेड़ा चम्बल पॉवर सप्लाई के कार्य की क्या प्रगति है ?

(२) क्या यह सही है कि यह प्रगति धीमी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

१. गंगापुर से खेड़ा को चम्बल पॉवर सप्लाई दिनांक ४ मार्च सन् १९६६ से प्रारंभ कर दी है।

२. प्रश्न नहीं उठता।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर)

ब्यावर—सालपुरा कच्ची सड़क

१०३. **श्री माधोलाल** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ब्यावर से सालपुरा कच्ची सड़क को कब तक पक्का बनाये जाने की योजना है ? यह सड़क कितने मील कच्ची है ?

(२) क्या यह सड़क तीसरी पंच वर्षीय योजना में पक्की बनाने हेतु ली गई थी ? यदि हां, तो फिर इस पर काम चालू क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक इस रोड़ को पक्का बना दिया जावेगा ;

उत्तर

१. ब्यावर से सालपुरा कच्ची सड़क की जानकारी इस विभाग को नहीं है। ब्यावर

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

से सालपुरा रोड के भाग में गऊ घाट से सालपुरा तक का भाग योजना में स्वीकृत था जो पूर्ण कर दिया गया है। बाकी भाग योजना में स्वीकृत नहीं है।

२. गऊ घाट से सालपुरा तक का भाग योजना में स्वीकृत था जो पूरा कर दिया गया है। बाकी भाग के लिये अर्थाभाव के कारण कुछ नहीं कहा जा सकता।

मारोठ डिस्पेंसरी तहसील, नावां में डॉक्टर की कमी

१०४. हनुमान सिंह चौधरी (नावां): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मारोठ डिस्पेन्सरी व प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कुकनवाली (तहसील नावां) में डाक्टर कब से नहीं है, व क्यों ?

उत्तर

मारोठ डिस्पेन्सरी में दिनांक ८-८-६३ व प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कुकनवाली (जिला नागौर) में दिनांक १३-६-६५ से डाक्टरों के स्थान रिक्त हैं। वर्तमान काल में राज्य में डाक्टरों का अभाव है, जल्दी ही डाक्टर भेजने की कोशिश की जायेगी।

लसाड़िया की तहसील पंचायत के चैयरमेन के विरुद्ध कार्यवाही

१०५. श्री उदयलाल वदिया (लसाड़िया): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत बनने के पहले उदयपुर जिले की लसाड़िया तहसील में कोई तहसील पंचायत थी और क्या उसके श्री रामप्रताप चेयरमैन के बजाय श्री जड़ावचन्द चेयरमेन नियुक्त हुए थे ?

(२) क्या यह सही है कि श्री रामप्रताप चेयरमेन ने जड़ावचन्द चेयरमेन को जिलाधीश के कईबार आदेश हो जाने पर भी रेकार्ड एवं कोष व तहसील पंचायत की रकम का चार्ज अब तक नहीं दिया और रकम अपने काम में ले ली ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त रकम के नहीं होने से आज तक तहसील पंचायत के कर्मचारियों का वेतन चढ़ा हुआ नहीं चुकाया जा रहा है ?

(४) उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में विभाग में अब तक क्या कार्यवाही की गई और क्या निर्णय हुआ ? और नहीं की तो क्यों ? क्या यह सही है कि चार्ज नहीं देने से सैकड़ों फरीक मुकदमा अपने दावों के निर्णय के इन्तजार में भटक रहें हैं और न्याय से वंचित हो रहे हैं ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी नहीं। चार्ज दिनांक १२-१२-६३ को दिया जा चुका है।

तहसील पंचायत कोष के ७८.४२ पैसे बाकी है। उसकी वसूली की एवं श्री रामप्रताप के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।

३. जी नहीं। केवल उक्त रकम के कारण ही वेतन चुकाने में रूकावट नहीं हो रही है।

४. चार्ज दिया जा चुका है, अतएव यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनाज के निर्यात का पर्मिट

१०६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१ अप्रेल, १९६४ से अब तक राज्य सरकार द्वारा किस किस व्यक्ति, संस्था एवं प्रदेश को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियम, उप-नियम, आदेश अधिनियम एवं अध्यादेश के अन्तर्गत किस किस प्रकार के कितने कितने अनाज के निर्यात (प्रदेश के बाहर) का परमिट दिया गया ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मोडर्न कन्स्ट्रकशन कम्पनी के क्लेम्स का चुकारा

१०७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राणा प्रतापसागर के निर्माण के सम्बन्ध में मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की ओर से कितनी रकम के अब तक कुल कितने क्लेम्स सरकार को प्रस्तुत हुए हैं ?

(२) उपरोक्त क्लेम्स में से कितनों का चुकारा कब कब हो चुका ?

(३) क्लेम्स के चुकारे का आदेश किस अधिकारी द्वारा हुआ ?

उत्तर—

१–मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की ओर से अब तक २६ क्लेम्स प्राप्त हुए हैं जिनकी दावाकृत राशि ७४ लाख रुपये के लगभग है ।

२–ऊपर वर्णित २६ क्लेम्स में से अब तक किसी भी क्लेम्स का चुकारा नहीं हुआ है । क्लेम्स के पेटे में १० लाख रु० की अग्रिम धन-राशि का भुगतान किया था ।

(३)समस्त क्लेम्स आर्बीट्रेटर के समक्ष विचाराधीन हैं अतः अभी चुकारे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

उदयपुर जिले में वर्षा का अभाव

१०८. श्री विजयसिंह झाला(नाथद्वारा): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

इस वर्ष उदयपुर जिला के किन किन गांवों में वर्षा का अभाव रहा तथा उन गांवों में राजस्व विभाग द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

गांवों की सूची संलग्न है । राजस्व विभाग द्वारा जो कदम उठाये हैं, इसका सम्बन्ध राजस्व विभाग से है । अकाल सहायता विभाग द्वारा लगान वसूल स्थगित करने के आदेश ३०-९-६६ तक प्रचलित कर दिये गये हैं । अकाल सहायता कार्यो वास्ते सूची में बतलाये हुए अनुसार कार्य स्वीकृत करके प्रत्येक कार्य के लिये उसके सामने लिखी धन-राशि भी स्वीकृत कर दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छोटी सादड़ी (जिला चितोड) में पुलिस की मनमानी सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

(१२. २ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव श्रीअब्दुल जब्बार, सदस्य विधान सभा ने छोटी सादड़ी जिला चित्तौडगढ़ में श्री बलवन्तसिंह नामक व्यक्ति की....................

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): on a point of order, sir........

श्री उपाध्य : There can be no point of order when I am reading a Sthagan Prastav.

पुलिस द्वारा मारपीट आदि से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज विचार किया जाय । अतः इसको प्रस्तुत करने की अनुमति में नहीं देता हूं । माननीय गृह मंत्रीजी इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करने हेतु-शीघ्र ही एक वक्तव्य देने की कृपा करें ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत संगीन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से मंत्री महोदय को बता दिया जाय कि वे जल्द से जल्द इस सदन को सूचना दें। उपाध्यक्ष महोदय, इस इलाके में ५७ किलो सोने से शास्त्रीजी को तोलने की बात थी और आज वह ५७ किलो सोना कलेक्टर चितौड़गढ़ के पास जमा है और इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज है । पुलिस मामले की तफतीश कर रही है तो इसमें कोई एतराज नहीं है कि पुलिस तफतीश करे लेकिन जिस तरह से पाखाना, टट्टी वगैरह से डण्डों को भरकर मुंह में घुसाया जा रहा है और उसको टोर्चर किया जा रहा है, लोगों को थानों के अन्दर लाकर पीटा जा रहा है.....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) :आदेश मुझको जानकारी देने का हुआ है और आप जानकारी दे रहे हैं। जानकारी मुझे देने को कहा गया है और आप जानकारी दे रहे हैं तो फिर मुझे देने की जरूरत नहीं है ।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरी जानकारी के आधार पर मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूं और आपको निवेदन कर कर रहा हूं कि पुलिस के इन कर्मचारियों की हरकतों की वजह से जनता परेशान है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि मैंने शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य देने के लिए आदेश दिया है और मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी भी शीघ्रातिशीघ्र इस पर वक्तव्य देगें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): लेकिन कब तक ? शीघ्रातिशीघ्र का मतलब कब तक, आज शाम को, कल या कब तक ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शीघ्रातिशीघ्र से एक सप्ताह के अन्तर्गत तक ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : 'शीघ्रातिशीघ्र' से मतलब एक सप्ताह के अन्तर्गत है, उपाध्यक्ष महोदय, तो...

श्री उपाध्यक्ष : एक सप्ताह से जल्दी लाने की कोशिश करें।

ग्राम गोठड़ा पीपलदा तथा मंडावर (त. खण्डार) में हुई डकैती सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा स्थगन प्रस्ताव खण्डार के गांव में हुई डकैती के अन्दर जो हत्याकाण्ड हुआ, उस विषय में था जिस पर आज वक्तव्य देना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, थाना खण्डार के गांव में हाल ही में हुई डकैतियों के बारे मेरा वक्तव्य।

दिनांक १७-२-६६ को गांव गोठड़ा व पीपलदा, जो थाना खण्डार, जिला सवाई माधोपुर के अधीन है, उसमें डकैती हुई।

इस तारीख को रात को ८-८॥ बजे गांव गोठडा में हथियारबन्द डकैत छैल बिहारी महाजन के घर पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अन्दर दाखिल हुए। यहां से एक घड़ी व बारह बोर के दस कारतूस ले गये, इसके पश्चात डकैतान ने महाजनान कपूरचन्द, दूलीचन्द, रामकल्याण व प्रहलाद के मकान में लूट-खसोट की और कुल ९५०) रु० की मूल्य की सम्पति लूटी।

छैलबिहारी महाजन अपने घर से रस्सा बांध कर ऊपर निकल गया उसने थाना खण्डार पर पहुंचकर ९.५५ पर इत्तिला दी जिस पर एस० एच० ओ० गुलाबसिंह मुकदमा दर्जकर उपलब्ध पुलिस दल को लेकर घटनास्थल पर ११.१५ पर रात को पहुंचा। परन्तु वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि डकैत पीपलदा की तरफ रवाना हुए हैं। अतः पुलिस दल भी उसी ओर रवाना हुआ।

पीपलदा में पहुंचकर डाकुओं ने गोकुल प्रहलाद को साफे से बांध दिया और एक टुकड़ी लादूराम महाजन के कर पहुंची वहां मोतीलाल महाजन को भी बांध दिया। डाकुओं की दुसरी टुकडी ने मीणों के मोहल्लों में जाकर लूट-खसोट की तथा एक मीणी का नेकलस छीनने की कोशिश की उसके चिल्लाने पर गांव वाले इकट्ठे हो गए और डकैतों का सामना किया। गांव वालों ने भंवरजी डकैती को लाठियों से पीटा जिसको देखकर दूसरे डकैती ने मेगजीन फायर किया जिससे चार आदमी घायल हुए और उनमें से एक विशाना मीणा वहां पर ही मर गया डाकू लोग प्रहलाद, गोकुल व मोतीलाल को गांव से बाहर ले गये और उनको गोली से मार दिया। इस गांव से डकैत लगभग १५००) रु० का माल लूट कर ले गये।

सूचना मिलते ही डी० एस० पी० व आर० आई०, सवाई माधोपुर पुलिस दल लेकर डाकुओं के पीछे रवाना हुए किन्तु डकैतान कटना के बाद चम्बल पार कर मध्यप्रदेश के थाना मानपुरा में दाखिल हो गये।

मध्यप्रदेश पुलिस को उसी समय वायरलेस से सूचना दी जिन्होंने भी डकैत दल का पीछा शुरु किया किन्तु करनाल के हल्के से आगे कोई सुराग नहीं मिला।

हमारा पुलिस दल भी ताकुब करता हुआ थाना मानपुरा गया तथा मध्यप्रदेश के पुलिस के सहयोग से डकैतों का सुराग लगाने का प्रयत्न किया। जिससे दो डकैत लक्ष्मण धोबी तथा मन्ना भाई गिरफ्तार किये गये। इसके पहिले हमारी पुलिस ने रतना डकैत, निवासी गोठाड़ा थाना खंडार

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

को दिनांक २-३-६६ को गिरफ्तार कर लिया था उसकी पूछताछ से लक्ष्मण तथा मन्ना सहित ८ डकैतों के नाम ज्ञात कर लिए। रतना के अलावा सभी शेष आठ डकैत मध्यप्रदेश के हैं।

जिला सवाई माधोपुर तथा मिलती हुई मध्यप्रदेश की सरहद पर विशेष पुलिस दल लगा दिया गया है तथा दोनों प्रदेशों की पुलिस डकैतों का पता लगाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। अधीक्षक, आरक्षी, सवाई माधोपुर स्वयं अपने दल के साथ डकैतान का पता चलाने में प्रयत्नशील हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्रीजी ने जो सदन को सूचना दी है उसमें तो कुछ अंश चबा गए और कुछ गलत बोल गए। वहां जब डाका पड़ा और डाकू मकान तोड़कर अन्दर गए, यह भी उन्होंने बता दिया। उसमें रहने वाले छैल बिहारी वहाँ की खिड़की से रस्सा बांधकर, अपनी मां को साथ लेकर भाग निकले। वहां वे अपनी मां को छोड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचे और थाने पर रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट लिखाने के बाद जब उन्होंने एस०आई० से घटनास्थल पर चलने के लिए कहा तो आनाकानी की। फिर उसने थानेदार को बुलाया और थानेदार ने टेलीफोन पर एस० पी०, सवाई-माधोपुर से कांटेक्ट किया तो पहले तो वे वहां पर मौजूद ही नहीं थे फिर जब वहां से एस० आई० ने फरदर कांटेक्ट किया एस०पी० से तो उन्होंने आर०आई० को कहा आर० आई० मय अपनी फोर्स के खण्डार पहुंचे और वहां पहुंचकर फौरन डाकूओं के पीछे रवाना हो गए। वहां से वे गोठड़ा पहुंचने पर मालूम पड़ा कि डाकू रामेश्वर की तरफ गए है तो उन्होंने उनका उधर पीछा किया। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब डाकू गोठड़ी पहुंचे तो वहां उन्होंने डाकुओं की टार्चेज को देखा। एक वहां कार्यकर्त्ता थे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ये सब तो माननीय उपगृहमंत्रीजी ने बता दिया है अब आगे आप क्या कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ये भी यही बता रहे हैं जो इन्होंने बताया है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं आपको डी० वाई० एस० पी०, सवाई माधोपुर की नेग्लीजेंसी के बारे में बता रहा हूं। डिप्टी मिनिस्टर साहब ने जो वक्तव्य दिया है उस में उन्होंने डी० वाई० एस० पी० की नेग्लीजेंसी को छुपाया है। जब सवाई माधोपुर के डी० वाई० एस० पी० गोठडा में पहुंचे और वहां पर उन्होंने डाकुओं की टार्च की रोशनी देखी तो भी तुरन्त उन डाकुओं का पीछा न करके, वहां पर तफतीश करने लग गये कि कैसे दरवाजा टूटा, यहां तुम किस तरह से कूदे आदि इस तरह की बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद जब उस व्यक्ति ने जिसका नाम मैं आपसे अर्ज करूंगा उसने जब मजाक में कहा कि डिप्टी साहब आप थक गये हों तो आप के लिये बिछौने बिछा दें। आखिर मन में तो वह समझे ही होंगे। उन्होंने पूछा कि आर० आई० किधर गये और जिस तरफ वे गये थे वहां से वे जीप में फोर्स के साथ रवाना हो गये। इसी बीच में ग्राम पीपलदा में डाकुओं ने डकैती डाली और चार आदमियों को घायल कर दिया और एक

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

आदमी का कत्ल किया, और गांव के बाहर चले गये, और बाहर जाने पर शायद यह मालूम हुआ कि जिन दो आदमियों को जिन का नाम गोकुल और प्रहलाद था और जिनके लिये माननीय डिप्टी मिनिस्टर ने बताया उन्होंने डाकुओं में से एक को पहचान लिया था और कहा था कि रतना क्या जुल्म करता है, तो वे डाकू वापिस उस गांव में आये और उन दोनों आदमियों को जो आपस में बन्धे हुए थे एक ही रस्सी से, एक का मुंह इधर और एक का उधर, उन दोनों के गोली मारी एक ही गोली से वे मारे गये। अगर डी० वाई० एस० पी० पीपलदा में जल्दी चले जाते और गोठड़ा में इतना टाइम न लेते तो उन दो आदमियों की हत्या नहीं होती। उन दो आदमियों की हत्या के लिये डी० वाई० एस० पी० पूरी तरह से जिम्मेदार है और जो हमारे उप मन्त्रीजी ने डी० वाई० एस० पी० को बचाने की कोशिश की है कि उसका कहीं जिक्र नहीं किया अपने स्टेटमेंट में। इस पर मैं आश्चर्य प्रकट करता हूं। इसमें उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को ऐसे गलत आदमी को वह करते हैं। इस लिये डी० वाई० एस० पी० इसके लिए जिम्मेदार हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो पूछा है उस का प्रतिकरण सुनलें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अभी तक वहां पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लोग भाग कर इधर उधर जा रहे हैं।

आपने बतलाया कि पुलिस ने परस्यु नकरके डाकुओं को गिरफ्तार किया है वह गलत है एक डाकू इलाज के लिये शफाखाने में गया तो इलाज के दौरान में डाक्टर को शक हुआ तो डाक्टर ने श्योपुर पुलिस को फोन किया तब तक उसको अस्पताल में सर्वेलिन में रखा पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट आये तब तक। इसलिए उससे मालूम पड़ा। आप उसके बारे में बहादुरी का श्रेय लेना चाहते हैं जब कि कायरों का काम किया है।

(१०.१२ म० प०)

डीडवाना में पुलिस द्वारा गोली काण्ड विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव श्री कृष्णकुमार गोयल और श्री हरिप्रसाद शर्मा का था कि कल दिनांक २३-३-६६ को डीडवाना में श्री खेताराम केशियर, सरकारी बैंक, लाडनूं, द्वारा शान्ति लड़की के साथ छेड़छाड़ करने विषय में था उसके बारे में स्टेटमेंट देने की बात थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय के आदेश के मुताबिक स्टेटमेंट देने के लिये तैयार हूं, लेकिन मेरे पास जो तथ्य आये हैं वे टेलिग्राम के माध्यम से आये हैं, फोन के माध्यम से आये हैं। जैसा इस एडजोर्नमेंट मोशन में बतलाया गया है उसके आधार पर मुझे विस्तृत विशद रूप से तथ्यों को इस सदन में रखना है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि अभी तक तथ्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां से उस आधार पर विस्तृत रूप से नहीं आ पाया है। इसलिए मैं विवश हूं कि स्टेटमेंट दूं। फिर भी अगर आदेश हो तो जो कुछ भी तथ्य मेरे पास हैं उनको सदन के सामने रखूंगा। उसके उपरान्त में उन तथ्यों का क्लेरिफिकेशन करने स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि जो कुछ भी

(श्री निरंजनाथ आचार्य)

टेलिग्राम से मसाला प्राप्त हो सका है वह अपर्याप्त है, ऐसी मेरी मान्यता है, फिर जैसा आदेश हो। अगर सदन उचित समझे तो दो रोज का टाइम और दे दें तो मैं विस्तृत रूप से कह सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि पूरे तथ्य आ जायें उसके बाद में स्टेटमेंट दें तो काफी ठीक भी हो सकेगा, नहीं तो अधूरे तथ्यों से क्या होगा ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, दुःख यह है कि २३ तारीख को घटना हुई और एडजोर्नमेंट मोशन कल दिया था और उपमंत्री को भी अभी तक सूचना नहीं मिली। हमने अपने सूत्रों से जितनी भी सूचना चाहिये थी वह सारी की सारी मंगालीं लेकिन सरकार नहीं मंगा पाई। आप निश्चित कह दें कि कब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दो तीन दिन बाद को कहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर एडजोर्नमेंट मोशन की क्या कीमत रही ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आज शाम तक देदें।

श्री उपाध्यक्ष : आप मंडे तक देदें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन कर रहा था कि जितनी सूचना चाहिये थी उससे भी अधिक मिल गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आज तारीख २६ है। कल सन्डे है और परसों मन्डे है तो परसों हम प्रयत्न करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको सन्तुष्ट करूं, आपकी तुष्टि करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डेलीबरेटली एवॉइड किया जा रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मन्डे को दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मन्डे तक नहीं। शाम तक आप दिलवाइये जवाब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि माननीय उपमंत्री मन्डे तक देदें।

श्री भैरोंसिंह : मन्डे को हम नहीं सुनेंगे। हम प्रोटेस्ट करते हैं। एडजोर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है ? पांच-पांच दिन तक जवाब न दें।

श्री उपाध्यक्ष : I expect it will be earlier than Monday but

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनको सब तथ्य देने पड़ेंगे और तथ्यों पर निर्णय करना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : जब २३ तारीख को घटना हुई है और आज २६ तारीख है तो २६ तारीख तक स्पेशल मैसेन्जर भेजते। वहां पर जो ए० डी० एम०, डी० एम., या एस० डी० एम० हैं उनको टेलीफोन किया होता, कलेक्टर को टेलीफोन किया होता कि सारी घटना को लिखकर सुबह भेज दें तो

(श्री भैरोंसिंह)

आपके पास अपने आप आ जाती। उपाध्यक्ष महोदय, आप जो रियायत कर रहे हैं तो उस रियायत से गलत परम्परा पड़ रही है और एडजोर्नमेंट मोशन का महत्व खत्म हो जाता है। सरकार को दो-तीन दिन का समय दे रहे हैं। आपने उनकी आदत पटक दी है एडजोर्नमेंट मोशन के महत्व को खत्म करने की। शाम तक जो कुछ भी उनको जवाब देना हो और जितना भी मेटेरियल उनके पास आया है, वे सदन में रखें। शाम तक की उनको इजाजत दें। वर्ना एडजोर्नमेंट मोशन का कोई महत्व नहीं है। वर्ना हम इसी समय जवाब के लिए प्रेस करेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : २३ और २४ को घटनाएं हुई और २५ को इस सम्बन्ध में एडजोर्नमेंट मोशन रखा गया और २६ तारीख तक जो कुछ भी इस सम्बन्ध में टेलीफोन से या टेलिग्राम से मेरे पास सामग्री आई है, लेकिन टेलिफोनिक और टेलिग्राफिक मेसेजेज corroboration of the Symbolic words is or was .... मैंने अर्ज किया कि २३ और २४ तारीख को प्रोसेशन्स हुए और प्रोसेशन्स के सिलसिले में कई इम्प्लीकेशन्स इस एडजोर्नमेंट मोशन में लिखे गये हैं और आज शाम को ही उनका जवाब दिलाना चाहते हैं तो वह अपर्याप्त है अगर आप चाहें तो अभी दे दूं।

श्री भैरोंसिंह : शाम तक का भी सवाल नहीं है। यह सरकार की देरी करने की बात है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आज शाम तक जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगी सूचना वह टेलीफोन से अथवा टेलिग्राम से होगी। स्पेशल मेसेन्जर्स के द्वारा आज पूछना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कल क्यों नहीं भेजा? आज भेजना चाहते हैं तो यह अक्ल आज ही आई है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आज जो हैं वह तो दे दूं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज ही जवाब दिलवाइये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उनकी तो आदत है टालबाजी करने की। वह टालबाजी कर रहे हैं you are expert at evading the issues. अभी मंत्रीजी ने कहा है कि मेरे पास में कुछ मसाला और सामग्री है तो उसके आधार के रूप में कहें। जो कुछ भी आपके पास मिर्च मसाला है उसके आधार के रूप में जवाब देदें थोड़ा बहुत।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें अपूर्ण तथ्य आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कह दें कि परसों पूरा जवाब दे देंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय सदस्य इसको दो इस्टालमेंट में रखना चाहते हैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं सदन को परम्परा के अनुकूल यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी एडजोर्नमेंट मोशन दो इन्स्टालमेंट्स में नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, वह एक ही दफा स्टेटमेंट होता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं हैं, आप अपना काम करें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह तो प्रोसीजर की बात है कि जो कुछ भी स्टेटमेंट हो वह एक ही दिन होना चाहिए और उस

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पर जितने क्वेश्चन्स हों वह भी एक ही दिन होने चाहिए। यह आसन इस व्यवस्था को उचित समझता है कि नहीं यह एडजोर्नमेंट मोशन दो रोज चले या सन्डे (Sunday) बीच में आजाय तो मन्डे (Monday) तक सवालात चलें। मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन यह हमारी परम्पराओं के अनुकूल नहीं होगा। जैसा आदेश हो मैं करने को तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन परम्पराओं के चक्कर में आने को कोई जरूरत नहो हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में तो यह निर्णय दे चुका हूं कि यदि आज तथ्य पूरे नहीं हो तो अपूर्ण तथ्य तो ये आज दे सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन पूर्ण तथ्य मन्डे तक दे सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अपूर्ण आज और पूर्ण सोमवार को रखें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा, इस सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न भी पूछेंगे तो अपूर्ण तथ्यों से उस पर प्रकाश नहीं पड़ सकेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि मन्डे तक स्थगित कर दें, और सदन की परम्परा यह रही कि जिस समय एडजोर्नमेंट मोशन डिसएलाउ हो जाता है तो उसका एक स्टेटमेंट दिया जाता है। उसके बाद स्पष्टिकरणात्मक प्रश्न भी लम्बे-चौडे भाषणों के रूप में आते हैं तो उनको भी अकोमोडेट किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं हैं। मन्डे तक इस पर विचार हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें दिक्कत यह है कि फायरिंग तो हो गया। इसके संबंध में एविडेन्स बर्नी नहीं जिन्होंने फायरिंग किया है वे कहीं दोषी न ठहराये जावें इसलिए हमारी सरकार हमारे जन संघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तरह तरह के चार्जेज लगा रही है डकैती, चोरी और तरह तरह के चारर्जेज लगारही हैं ४२ वर्कस के साथ ज्यादतियां की जा रही है, यह सारी मिसचीफ डीडवाना में चल रही हैं और मंत्री महोदय सदन को सूचना नहीं दे रहे हैं। यह मिसचीफ डेलिबरेटली मंत्री महोदय द्वारा की जा रही हैं। ··

श्री निरंजननाथ आचार्य : डीडवाना में दिनांक २३-३-६६ को हुई घटना के बारे में मैं सदन को जानकारी दे रहा हूं जो कि अपर्याप्त विवरण है···

श्री भैरोंसिंह : अपर्याप्त नहीं पर्याप्त देना होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कह रहा हूं, जैसा मेरे पास विवरण आया है वैसा बता रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका विवरण है उसकी क्वालिफाई मत करिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं यह चेयर के प्रति डिसरेस्पेक्ट है। जैसा आया है वैसा दे रहे हैं तो आप यहां किस लिये आये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मेरे पास प्राप्त हुआ है उस को इधर उधर लिन्क करके जानकारी दे रहा हूं जो अपर्याप्त हैं

श्री भैरोंसिंह : अपर्याप्त जानकारी नहीं दी जा सकती। ये प्रोटेक्शन ले रहे हैं। आज शाम तक पूरी जानकारी देने के लिये आप इनसे कहिये। टेलीफोन से पूछलें उसके बाद शाम तक जवाब दे दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, डीडवाना में जनसंघ के साथ अन्याय कर रहे हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : जितने तथ्य हैं वे अभी बता दूंगा।

ऐसा बताया गया है कि गत दिनांक २३-३-६६ की रात को सहकारी बैंक लाडनूं के एक खेताराम ने डीडवाना में एक कम्पाउन्डर की स्त्री के साथ छेड़ छाड़ की जिसकी रिपोर्ट तुरन्त थाने में दर्ज की गई. परन्तु खेताराम पुलिस के हाथ नहीं आया। जिससे रुष्ट हुवे लोगों द्वारा तारीख २४-३-६६ को हड़ताल संगठित की गई और जुलूस निकाला व सभा की। जिसके फलस्वरूप लोगों में उत्तेजना भड़क उठी और थाने में पत्थर फेंके गये। थानेदार व दो कान्सटेबिल के चोटें आई। पुलिस ने जब रोकना चाहा तो लोग हमलावर हो गये और अशान्ति की स्थिति पैदा हो गई जुलूस जब टाउन पोस्ट ऑफिस के पास से दोपहर को निकल रहा था तो भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। एक पुलिस कान्सटेबिल की राइफल छीनने की कोशिश की। छीना झपटी हुई और स्थिति बिगड़ गई जिससे फायरिंग हुआ। फायरिंग के बाबत पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है। पांच व्यक्तियों के चोटें आई।

सूचना मिलते ही जिलाधीश व एस.पी. नागौर शाम को पहुंच गये और धारा १४४. लागू कर दी। स्थिति सामान्य हो रही है। जिन पांच व्यक्तियों को चोटें आई उनमें से एक श्री सुरेश को गंभीर चोटें पहुँची थी किन्तु उसकी स्थिति चिन्ताजनक नहीं है। अन्य चार व्यक्तियों के साधारण चोटें पहुँची हैं; श्री सुरेश को सुजानगढ़ अस्पताल में उपचार हेतु तुरन्त भेज दिया गया था। खेताराम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी की कार्यवाही हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश जारी कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : यह फायरिंग एस० डी० एम० के लिखित आदेश से हुई या जबानी आदेश से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : यह मामूली बात थी टेलीफोन पर पूछा जा सकता था कि फायरिंग लिखित आदेश से कराया गया या मौखिक आदेश से। यह सूचना टेलिफोन से आ सकती थी, वायरलैस से आ सकती थी कौनसी चीज है जो नहीं आ सकती। डेलिबेरेटली ये छिपा रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी की बात कही है।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी किस बात की; लिखित रूप से आदेश दिया या नहीं; यह पूछ सकते थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी नहीं मिली इसलिए मांग रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : फिर यहां किस लिए आए हैं, जवाब किस बात का दे रहे हैं, जब कह नहीं सकते कि फायरिंग एस० डी एम० के लिखित हुक्म से हुआ या जबानी हुक्म.

(श्री भैरोंसिंह)

से हुआ ? यह सदन का अपमान है आप चाहे नाराज हों, नाराजगी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन सदन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधान सभा में प्रश्न पूछा जाता है कि फायरिंग किसके हुक्म से हुआ, लिखित हुक्म से हुआ या जबानी हुआ, क्या ये इतना नहीं बता सकते...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं नम्रता से निवेदन कर रहा हूं...

श्री भैरोंसिंह : यह मिसचीफ है। डेलिबरेट मिसचीफ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तार और टेलीफोन से प्राप्त की गई सामग्री जो कुछ मेरे पास थी उसके एक्सट्रैक्ट्स रख दिये, जानकारी किसी आधार पर ही की जा सकती है अन्यथा नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसके आधार पर इनको कल अवसर दिया गया आज जवाब देने के लिए ये बाध्य थे। जनता की भावना की अवहेलना करके इकट्ठी हुई जनता के समूह पर गोली चलादी। गोली चलाने का क्या कारण था, किसके आदेश से चलाई गई इसके तथ्यों की सूचना देने में चेयर के आदेश की अवहेलना की जा रही है। अवहेलना मंत्री करते हैं और हमसे आशा की जा रही है कि हम चुपचाप बर्दाश्त करें तो यह बर्दाश्त काबिल नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गोली चलादी गई अथवा गोली चली, इसका मैंने विश्लेषण किया है। छीना-झपटी हुई, पुलिस की राइफल छीनने की कोशिश की गई। लेकिन यह प्रश्न कि गोली चली या गोली चलानी पड़ी यह बिना जानकारी के कैसे कहदूं ? गोली चलाई या यह कहदूं गोली चल पड़ी ये दोनों प्रश्न तथ्यों के आधार पर पता लगा सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गोली चलाई गई या चल पड़ी इन तथ्यों को सदन के सामने रखूंगा। छिपाने की आवश्यकता नहीं है, समय दीजिए, विस्तृतरूप से सदन के सामने रखने में कोई गुरेज नहीं होगा। छिपाया नहीं जायगा। जो सूचना मेरे पास में नहीं है जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है उसको मैं कहां तक यहां रख सकता हूं। चेयर के प्रति उदासीनता या अपमान का कोई प्रश्न नहीं है। अधिक जानकारी इस समय नहीं दे पा रहा हूं। चेयर के प्रति मेरा पूर्ण सम्मान है...

श्री भैरोंसिंह : कोई सम्मान नहीं है, हाउस को मजाक समझ बैठे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं यह मामला जरूर कुछ हद तक पेचीदा होगा, छानबीन हो सकती है। गोली चलाई या चल पड़ी, इस बारे में जानकारी करना सरकार का परम पुनीत कर्त्तव्य है लेकिन जनसंघ के माननीय नेता ने तरह तरह की बातें रखीं, जनसंघ के कार्यकर्ताओं के जरिये मालूमात से यहां पर पहुंची होंगी। कम से कम उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह तो आवश्यक समझता हूं कि आखिरकार कोई सरकार है भड़भूंजे की दुकान नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : इससे भी बुरा है। भगवान की कृपा से सारे भड़भूंजे यहीं पर इकट्ठे हो गये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई विस्तृतरूप से यही बात कहना चाहें तो कम से कम माननीय मंत्री महोदय को तैयारी करके आना चाहिए। मैं जानता हूं कि किस तरह का उनका फर्टाईल दिमाग है, उसमें कितनी ही बातें आती होंगी। गोली चल पड़ी या चलाई गई यही मोटा तथ्य सरकार को मालूम नहीं हो तो उप-मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि he may better resign

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं ६७ में अपना पार्ट अदा करूंगा पहले नहीं।

श्री भैरोंसिंह : गोली चली या नहीं चली, यह तो बतादें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चली।

श्री भैरोंसिंह : कितनी चलीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक चलीं या संभवतः दो चलीं...

श्री उपाध्यक्ष : Now please.

श्री भैरोंसिंह : ये आपसे मजाक कर रहे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! let me say.

यद्यपि इस विषय में कि गोली चली या गोली चलाई गई, विशेष जानकारी हो जाती तो अच्छा होता। जैसा मैंने कह दिया हैं कि सोमवार...

श्री भैरोंसिंह : सोमवार नहीं, उसका उपाय मैं बताऊं अभी आप एस.डी.एम. को टेलीफोन करें वह जीप लेकर चार बजे तक आसानी से यहां आ सकता है सारा मेटिरि-यल लेकर अगर आप चाहें तो।

श्री उपाध्यक्ष : सोमवार को पूरा स्टेटमेंट दें।

श्री भैरोंसिंह : सोमवार इसका मतलब यह है कि जनता के ऊपर गोली चलती रहे और राजस्थान सरकार उसका जबाब नहीं दे। राजस्थान की विधान सभा में उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य कहें और उसकी सुनवाई नहीं और एक मजाक यहां होता रहे। ऐसे सिरियस मसले में राजस्थान सरकार हमारी उपेक्षा करती हैं तो हम जनता के पैसे का चार सौ रुपया लेकर यहां बैठे हैं वह इसलिए नहीं कि उन चार सौ को पेट में डकारने के लिए यहां पर बैठे हैं। हम जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यहां पर बैठे हैं। और हम सरकार को नहीं, उपाध्यक्ष महोदय आपको कहते हैं कि ऐसे मौके पर भी चेअर का प्रोटेक्शन हमें नहीं दिया जाय तो इससे गम्भीर और क्या बात होगी हम निवेदन कर रहे हैं कि शाम तक एस.डी.एम. को यहां आने के लिए कहें, वह अपनी जीप लेकर यहां आ जाये। वहां पर गोली चली और चलाई जा रही है, लोगों को गिरफतार किया जा रहा हैं। आप इसको राजनैतिक स्टन्ट समझ रहे हैं। वहां पर इस तरह के लोगों को जनसंघ के लोगों को हैरान किया जा रहा हैं। ऐसे मसले में भी अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता हैं चेअर से तो हम क्या उम्मीद करें। चेअर ने कह दिया कि स्टेटमेंट परसों तक हो जायगा लेकिन परसों तक तो वहां पर लोगों का कचूमर निकाल दिया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ के माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे हैं उनसे एक हद तक सहानुभूति है क्योंकि हम विरोधी पक्ष में बैठने वाले हैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हमारे ऊपर जो मुसीबत और दिक्कत इस सरकार के द्वारा आती हैं वह हम ही जानते हैं; आपका निर्णय है वह तो सर्वमान्य है। इसके ऊपर तो हमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता लेकिन कम से कम यह महत्वपूर्ण मुद्दा है उपाध्यक्ष महोदय, कि गोली चली या चल पड़ी; चली और चल पड़ी– इसके संबंध में कम से उप मंत्रीजी कृपा करके और मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूं आज शाम तक कुछ न कुछ स्टेटमेंट दें गोली चली या चल पड़ी; इतना ही सिर्फ आप कह दें तो गनीमत है फिर तो निरंजन निराकार की माफिक बैठे हैं यहां आप

श्री निरंजननाथ आचार्य: मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को जहां तक इसके तथ्यों का सम्बन्ध हैं वह पूर्णतया इस सदन के सामने रखे जायेंगे लेकिन इसका मैं प्रयत्न अभी से प्रारम्भ करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जीप से उनको बुलाने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी अभी यह टाइम हैं साढे बारह से आगे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं टेलीफोन करूं कि सद्भाग्य से मिल जायं और दुर्भाग्य से नहीं मिले तो सारी स्थिति को देखते हुए मुझको यह सम्भव नहीं लगता कि आज शाम तक स्टेटमेंट दे दूं आपने भी सारी स्थिति को समझ कर व्यवस्था दी है। मैं विश्वास दिलाता हूं मैं अभी प्रयत्न करता हूं, अभी जाकर टेलीफोन पर बैठ कर कोशिश करूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कल से मौज उड़ा रहे थे। जब यहां पर स्थगन प्रस्ताव रखा जाता है तब आप कहते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : टेलीफोन पर बात की और टेलीग्राम दिये और आये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लोग घायल हुये हैं और एक की हालत खराब है। आप कहते हैं कि सोमवार को स्टेटमेंट देंगे उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सारी जानकारी प्राप्त की जायगी।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री कृष्णकुमार गोयल : राजस्थान के अन्दर आपकी हुकूमत ...

(शोरगुल व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं बार बार यह निवेदन कर रहा हूं और अपनी इस बात को रख रहा हूं कि जो भी तथ्य होंगे उनको प्राप्त किया जायगा और सदन के सामने रखें जायेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उठाया है यह मुझे मान्य नहीं हैं और आपने जो व्यवस्था दी है उसके प्रतिकूल है आपकी व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। मेरा विश्वास है कि सदन के इस विश्वास के अनुकूल ही काम करूंगा। मैं यह भी कह...

(दोनों पक्षों की ओर से शोरगुल–व्यवधान)

दूं कि कभी अपर्याप्त सूचना नहीं दूंगा आपकी जो व्यवस्था है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रयत्नशील होऊंगा क्योंकि यह आपकी व्यवस्था को मानने का प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह राजस्थान की सरकार है कोई भड़भूंजे की दुकान नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझको ऐतराज नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : हम उपमंत्री को नहीं सुनाना चाहते। हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

कुछ माननीय सदस्य : यहां बैठे मौज उड़ाते रहते हैं, ऐश करते रहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सवाल यह है कि यह शब्द इनके हैं पागलों की जबान से निकले हुए शब्द हैं। इनके लिए कुछ नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इतना सिरियस मामला हैं और इसको इस तरह मजाक में टालते हैं। हम इस चीज को सहन नहीं कर सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ भी कहो मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यहां मौज उड़ाते हैं और ऐश करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि परम्परा के आधार पर शासक दल के माननीय नेता से निवेदन करूंगा कि इस स्थिति के ऊपर सदन की इस बात के लिए आश्वासन फर्मायें कि हकीकत में मामला सीरियस है और हमारी भावना की कदर करते हुए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारे राइट को प्रोटेक्ट करते हुए कम से कम शासकदल के लीडर महोदय को आगाह करें कि हकीकत में यह सीरियस मामला है और कोई बात नहीं है, वह आराम के साथ आ सकता है और सदन में व्यवस्था कायम रह सकती है। वह शाम तक आ सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने नम्रतापूर्वक कहा, उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष: That's all Finish

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा। इस सम्बन्ध में उप-मंत्री जी ने सदन को यह आश्वासन दिया है, जैसा आप चाहते हैं कि सोमवार को इसकी विस्तृत जानकारी रखी जाय.....................

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वह भी आप रखें। उप मंत्री में हमको विश्वास नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री मानसिंह महार : हमे उप-मंत्री में विश्वास नहीं। वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, हम नहीं सुनेंगे उप मंत्री को। वह स्टेटमेंट देंगे तो हम उठ कर चले जायेंगे। हम आपको पहले कहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी बात सुन लीजिये। मैं निवेदन कर दूं कि इस सम्बन्ध में किसी तथ्य को तोड़-मरोड़ कर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रखने का या छिपा कर रखने का सवाल नहीं है। वहां जो घटना हुई उसको हम दुर्भाग्यपूर्ण और गम्भीर स्वयं मानते हैं। सदन को वास्तविक स्थिति बताई जायगी पूरी तरह से।

श्री भैरोंसिंह : सोमवार को क्यों ? यह मुख्य मंत्रीजी बता दें ? आप तीन दिन तक क्या कर रहे थे, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी ? आज यह क्यों कह रहे हैं कि आज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। डिप्टी मिनिस्टर ने जो कह दिया है आप उसकी ताईद कर रहे हैं। आप यह बताइये कि आखिर किस काम में लगे हुए थे। तीन दिन पहले डीडवाना में फाइरिंग हो रहा हो और राजस्थान के मुख्य मंत्री और उप-मंत्री उसका जवाब नहीं दे पायें तो फिर कर क्या पायेंगे ? कौनसा ऐसा काम था जिसमें आप मशगुल थे और अब तक फायरिंग की रिपोर्ट नहीं मंगा सके आप यह बता दें ? और ....

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला...

श्री भैरोंसिंह : उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक महिला का, जो कि हिन्दुस्तान की लाज है, अपमान होता है और उस पर स्थगन-प्रस्ताव लाया जाय ....

श्री भैरोंसिंह: -एक महिला का शील-भंग हो और यह सरकार सोती रहे और वक्तव्य नहीं दे सके, यह शर्म की बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : और आपके उपमंत्री का यह तरीका रहा है, इस प्रकार का रवैया उनका बन गया है कि हम बात को मजाक में टालते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइंट ऑफ ऑर्डर... ..

श्री कृष्णकुमार गोयल : ऐसे उप-मंत्री को अपने व्यवहार के लिए इस सदन से क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस बात को तो वह कहते कम से कम कि सारी जानकारी करने का मैं प्रयत्न करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक बार नहीं, दूसरी बार तीसरी बार,...

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री भैरोंसिह : आप कौनसे रूल के अन्तर्गत यह कह रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने बराबर यह रूलिंग दी है और उसके बाद भी वही चीज होती जा रही है।

श्री भगणलाल (हिन्डौन-सु.) : अब यह नाटक रहने दो, यह नाटक आप वर्षों से करते चले आ रहे हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह नाटक नहीं है।

Page No.37

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको यह आदेश दें कि इस सम्बन्ध में शाम तक स्टेटमेंट दें।

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है और……

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकार को बचाये या नहीं लेकिन जिस महिला का शीलभंग किया गया है और शीलभंग करने वाला जो मुलजिम था, जिसे पुलिस ने बचाया, उस मुलजिम को पकड़वाने के लिए जनता गई तो उस पर फायरिंग किया गया और उसको तीन व्यक्ति दबाये हुए हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री, उपमंत्री और आई. जी. पी., उस मसले को दबाये हुए बैठे हैं। यह बात कह नहीं सकते कि आखिर मसला क्या है, गोली क्यों चली, गोली किसके लगी- इन बातों की जानकारी नहीं है। और कितनी गोली चलीं इसकी जानकारी नहीं। किसने गोली चलवाई इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर आपको जानकारी किस बात की है, इस बात की जानकारी होगी कि आपके घर में कितने बीमार हैं और कितनों के डाक्टर ने कितने इन्जेक्शन लगाये हैं। इस बात के लिए आपको जनता के पैसे से तनख्वाह नहीं मिलती कि किसी महिला का शीलभंग हो और शीलभंग करने वाले मुलजिम को आप बचाये और जनता उसको पकड़वाने के लिए आये तो आप उस पर गोली चलायें। इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और उप मंत्री यह कहते हैं कि हम परसों जवाब देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस विषय में आपने बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दिया है कि कितनी दिक्कतें हैं इनको देखते हुए।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने फर्माया वह वाजिब हम मान लेंगे लेकिन स्पष्टीकरण किस बात का किया है। इस बात को उन्होंने कितनी गम्भीरता से लिया है। यह इनके जवाब से मालूम पड़ता है। आप बोल रहे थे और वे मुस्करा रहे थे। अरे, एक नारी का अपमान हो और तुम उसे इस प्रकार साधारण रूप से लो।

कुछ माननीय सदस्य : डूब मरो, डूब मरो !

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई डूब मरने वाली बात नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। डूब मरो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे साथ तुम भी डूबो, मैं भी डूबूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म से डूब मरो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप भी डूब जाओगे।

श्री अमृतलाल : आपको डूब कर मरना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई बात नहीं है डूबने की।

श्री भैरोंसिंह : इस बात से आप इसकी गम्भीरता का अन्दाज लगाइये कि मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य की बहिन या परिवार की सदस्या का अपमान हो जाये तो इस प्रकार….

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी बहिन या स्त्री के साथ ऐसा होगा तब ही ऐसा ही व्यवहार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : तब क्या आपको दुःख नहीं होगा। मैं कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार महिला का शील भंग नहीं किया जा सकता। और आप इस तरह मजाक में लेते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी बहिन या स्त्री के साथ ऐसा होगा तब सख्ती और आदर से लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप राजस्थान में एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हो जाय और उसके बाद भी राजस्थान के मुख्य मंत्री और उप मंत्री सोते रहते हैं और उसके बाद में पूरी बात पता नहीं करते। इसको बर्दाश्त नहीं किया जायगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी बहिन और हमारी बहिन एक है।

श्री भैरोंसिंह : यदि बहिन एक होती तो ऐसा नहीं होता और इस तरह सोते नहीं रहते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी घटना आपकी बहिन के साथ होती तब भी हम ऐसे ही आतंकित होते ......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस मामले के विषय में अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : हम जानना चाहते हैं कि फायरिंग किसके ऑर्डर से हुआ। जब तक आप यह नहीं बतायेंगे तब तक हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे।

श्री मानसिंह महार : पूरे मामले के तथ्यों से हमें अवगत करायें। इस सरकार के मंत्री इसलिये नहीं हैं कि मुफ्त की तनख्वाह लें और ऐश करें। इसीलिये तनख्वाह नहीं मिलती कि यहां बैठ कर रास रचाया करो और ऐसे गम्भीर मामले में भी शाम तक सूचना इकट्ठी करके जवाब देने के लिए इंकार करो। उपाध्यक्ष महोदय, हम न्याय चाहते हैं। यह नहीं हो सकता कि राजस्थान की महिला के साथ इस तरह अन्याय हो और शील भंग हो और गोली चले और इस राज्य के मुख्य मंत्री और उप मंत्री कहें कि सोमवार को जवाब देंगे। क्यों सोमवार को जवाब देंगे ? आप वायरलेस से जानकारी नहीं कर सकते ? यह हमें मुख्य मंत्री बतायें, हम उप मंत्री को नहीं सुनेंगे। आपको सुनेंगे और हम उप मंत्री को सुनने को तैयार नहीं हैं ; आपका जवाब सुनेंगे। उनको नहीं सुनेंगे, कभी नहीं बोलने देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास आपकी कई बातें है आप मुझे कैसे सुन सकते हो .....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : हम उप मंत्री को नहीं बोलने देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो भी जवाब देंगे वह पूरी जिम्मेदारी से तथ्य रखेंगे, कोई ऐसा गलत जवाब नहीं देंगे।

कुछ माननीय सदस्य : हम नहीं सुनेंगे। हम नहीं सुनेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और मैं नहीं सुन रहा हूं।

कुछ माननीय सदस्य : उपमंत्री को नहीं सुनेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं भी आपको नहीं सुनता हूं। मैं जनता की तकलीफ को सुन सकता हूं।

श्री मानसिंह महार : हम इस काले मुंह वाले व्यक्ति को नहीं सुनेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं राज्य की जनता की तकलीफ को सुन सकता हूं। आपको नहीं सुन सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक स्त्री का शील भंग हो और राजस्थान के अंदर ऐसा अत्याचार हो और फिर भी जवाब दें कि अगर तुम्हारी मां-बहिनों के साथ होगा ऐसा होगा तब भी ऐसा ही व्यवहार किया जायगा। ऐसेXXXX को हम नहीं सुनेंगे। ऐसेXXXX को अब डूब मरना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : ऐसेXXXX को हम नहीं सुनेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तुम सौ बार XXX हो।

कुछ माननीय सदस्य : तुम XXX हो

श्री श्रवणलाल : शर्म नहीं आती है। तुमने क्या समझ रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह कोई बोलने का तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सरकार का स्तर बहुत गिरता जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please XXX word is expunged.

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सारे सदन को निवेदन करना चाहूंगा, इस मसले को आप राजनतिक रूप से न देखें. . . .

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कौन देखता है !

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कोई राजनैतिक मसला नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप बना रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न केवल इतना है कि एक नारी के साथ में न केवल छेड़छाड़ की गई ...

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य....

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसका शील भंग भी किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आसन की व्यवस्था के बाद इस विषय पर डिस्कशन किया जायगा तो That will not recorded.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप भले ही इसको रेकार्ड में न लें मगर हम तो बोलते ही रहेंगे।

XXX अध्यक्ष— पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No.40

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम सही तथ्यों को सदन में नहीं कहेंगे तो फिर कहां कहेंगे। सरकार मन माने तरीके से काम करती रहे। पुलिस की मानी चलती रहें और जनता पर गोलियें चलाती रहे और जनता को किसी प्रकार से विश्वास में नहीं लिया जावे और जब हम यहां पर कुछ कहें तो आप यह कहें कि कि यह रेकार्ड में नहीं लो जावे। हमें यह तमन्ना नहीं है कि हमारी ये बातें अखबारों में आवे। हमें अखबारों में आने की जरूरत नहीं है। हम सदन में सही बातें कहना चाहते हैं और यह जानना चाहेंगे कि गोली किसके हुक्म से चली, कैसे चली ? जब तक आप यह नहीं बतावेंगे तब तक हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको आप साधारण रूप से न लें। इस प्रकार की घटना घटी है उसको दबाईये मत।

(घन्टी)

जो रिपोर्ट की गई है उसको छिपाया गया है। और जब जनता ने उसके लिये मांग की तो उन पर फायरिंग किया गया और इस प्रकार की घटना को आपने गंभीर नहीं माना है। मैं आपसे कहूंगा कि आपमें इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए यह कहने की कि मेरी गलती हुई, आज भी आप आदमी भेज कर एस.डी.ओ. को बुलाते और उसकी गलती है या और किसी की गलती है इसकी जानकारी करके सूचित करते।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि इस विषय में पर्याप्त रूप से आपसे कहा है.... ...

श्री भैरोंसिंह : हमें सन्तोष नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : वहां से सूचना आवे सम्बन्धित अधिकारी नहीं मिले और यहां पर पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो सके। इस विषय में यह भी हो जावे कि आज शाम तक सूचना आ जाऐ तो जवाब दे दें। इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया कि सोमवार को इस प्रश्न पर जवाब दिया जावे। इस मामले के महत्व को देखते हुए जो कुछ कहा गया, जो बातें हैं उनको आपके सामने रख दी। कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं की गई है। लेकिन जितने तथ्य आये उनके बारे में जानकारी दी है। और आगे के लिये अपनी मजबूरी बता रहे हैं वह है ही। आपने जो कुछ कहना था कहा हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो गलती उप गृह मंत्री ने की है और सदन का अपमान किया है उसके लिये उनको सदन से बाहर निकाला जावे। क्योंकि उन्होंने जो गलती की है उसने सदन का अपमान किया है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (बैठे बैठे) बहुत बढ़िया समर्थन किया है आपने।

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपगृह मंत्री को सदन के बाहर निकाला जावे क्योंकि इन्होंने सदन का अपमान किया है।

Page No.41

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक इसका कुछ सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो यह सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी जब तक आप ५० आदमियों को बाहर नहीं निकालेंगे यह नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ? There is no notice of such a resolution.

श्री मानसिंह महार : यह नहीं हो सकता कि राजस्थान में इस तरह से महिलाओं का शील भंग किया जावे और आज इस बात को तीन दिन हो गये, आज तीन दिन के बाद भी चीफ मिनिस्टर या उप गृह मंत्री यह कहें कि हमारे पास सूचना नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका पुलिस विभाग फिर किस लिये हैं। आपके पास वायरलेस किस लिए है। आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं। वायरलेस से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आप दो तीन घन्टों में पूरी की पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मुझे तीन घन्टों के लिए आपकी हकूमत दें तो मैं सारी सूचना प्राप्त कर सकता हूं। आप मुझे आपकी जगह तीन घन्टों के लिए बनाइये। पाकिस्तानी को निकालिये जिसके पी० ए०...........

(शोरगुल व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें कोई तथ्य नहीं हैं।...........

(शोरगुल व्यवधान)

(घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ? Order please !

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वे सारे विपक्षी दल की भावना की कदर करें और सारे विपक्षी दल के आदर में कम से कम उप-मंत्रीजी को यह तो चाहिए कि वे अपनी हठधर्मी को थोड़ा त्याग करके उस पर पुनः विचार करें और कम से कम इतना ही आश्वासन दें कि आज पांच बजे वे कोई न कोई स्टेटमेंट देंदेंगे तो कोई ऐतराज नहीं है। आखिरकार जनतन्त्र में विरोधी पक्ष की भावना की कुछ न कुछ तो कद्र करनी चाहिए। मेरे को यह समझ में नहीं आता कि आपकी नीति क्या हैं और आप धीरता पूर्वक कोई इस पर विचार करके कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं चीफ मिनिस्टर से कहूंगा कि आपको खड़े होकर दो शब्द तो कम से कम आश्वासन के रूप में कहने चाहिएं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि......

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: इसमें प्रेस्टिज का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: अगर पूरी जानकारी होती तो नहीं देने का भी प्रश्न नहीं है। इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज शाम तक जवाब पूरा आ गया तो हम शाम को स्टेटमेंट दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आखिर इस तरह से चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर शाम तक जवाब आ गया तो स्टेटमेंट दे देंगे......

श्री मानसिंह महार: उपाध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूं। लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि २३ तारीख को वकुआ हुआ है आज २६ तारीख है। तीन दिन में आपको अभी तक उसका पता नहीं चला।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में तो आप कह चुके हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि कटेगोरिकली यह फरमा दें कि ५ बजे स्टेटमेंट देदेंगे तो हम मान सकते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : यह मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि अगर ·····

श्री मानसिंह महार : अगर, मगर, चुनाचे नहीं चलेगा·······

श्री उपाध्यक्ष : वस्तुस्थिति को तो देख कर ही होता है ·····

श्री मानसिंह महार: यह ऐसा प्रश्न है कि हम इस सदन में किसी प्रकार की गड़ बड़ नहीं करना चाहते, सदन को सही ढंग से चलाना चाहते हैं, पर हमारी बात की इतनी अवहेलना करते हैं, मैं तो एक मध्यस्थता के रूप में कहता हूं, इधर वालों ने प्रश्न उठाया उधर वालों ने उसका जवाब दिया, हम तो थर्ड पार्टी हैं तो इसमें हमारी आकवर्ड पोजीशन हो जाती है तो मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, उपमंत्री तो जवाब देगें तो हम बहिर्गमन कर जायेंगे ····

We have no confidence in that Pakistani.

(शोरगुल)

श्री नरन्जननाथ आचार्य : अभी और बाकी है भोंपू में, १२ बजे होता है।

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार : मैं इन काले मुंह के बन्दरों की परवाह नहीं करता, मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि हमें आश्वासन दे दीजिये कि जितनी सूचना आपको मिले शाम तक हमें सूचना दे दें। यह मत कहिये कि अगर आ गई तो दे देंगे। ५ बजे भले ही यह कह दीजिये कि हमें सूचना नहीं मिली तो हम मान जायेंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि विरोधी पक्ष के नेता ने भी यही कहा है, तीन दिन हो गये, एक महिला का शीलभंग किया गया। ·······

श्री उपाध्यक्ष: आप रिपीट कर रहे हैं···

श्री मानसिंह महार : रिपीट नहीं करूं तो·······

श्री उपाध्यक्ष : वह सारी बातें जहन नशीन हो चुकी हैं।

श्री मानसिंह महार : वह यह कह दें कि ५ बजे स्टेटमेंट दे दूंगा नहीं तो गंभीर स्थिति पैदा हो जायगी, सदन का वातावरण खराब हो जायगी, खासतौर से हम इधर बैठने वालों के लिए बड़ी गम्भीर समस्या हो जायेगी। वातावरण को ठीक रखने के लिए मुख्य मंत्री कह दें कि आज शाम को स्टेटमेंट दे दूंगा। हमारे दिमाग में मुख्य मंत्री के प्रति बड़ी रेस्पेक्ट है, इसको प्रेस्टिज का इश्यू नहीं बनायें ठंडे दिमाग से सोचिये, आप गुस्से मत होइये, आपकी प्रेस्टिज का सवाल है इसलिए आप यह बात कहिये।

[श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) बोलने के लिए खड़े हुए]

श्री भैरोंसिंह : यह आप फिर रखना, पहले यह मामला तय हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि सायंकाल तक जितनी सूचना आसके अगर वह आ सके तो उसके विषय में अगर हो सकेगा तो जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिंह : हो सकेगा क्या, एक मामूली सा संशोधन, जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि ५ बजे तक जो भी सूचना आ जाय वह सदन में रख दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यह कहा है ५ बजे तक अगर सूचना आ जाती है, अगर अधूरी आती है तो उससे कोई फायदा नहीं इसलिए पूर्ण सूचना सोमवार को सुबह मिले इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : तीन दिन में सूचना नहीं मंगाई, इसके लिए सदन में खेद प्रकट कर दीजिये खेद प्रकट नहीं करते तो शाम को ५ बजे तक जितनी सूचना आपके पास आ जाय उतनी सूचना सदन को दे दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, यह फायरिंग २४ तारीख को हुआ, कल एड्जोर्नमेंट मोशन रखा, उस पर जो कुछ जानकारी उपलब्ध हो पाई, अधूरी मालूम होती है इसलिए निवेदन किया गया कि आज इस पर बहस नहीं करके एड्जोर्नमेंट मोशन सोमवार को ले लिया जाय तो ठीक है। जो जानकारी उपलब्ध हो पाई यहां रखी गई, उससे पूर्ण संतोष माननीय सदस्यों को नहीं हुआ शाम तक अगर अधूरी जानकारी आती है और उसको यहां रखा जाता है तो फिर यही बहस होगी इसलिए कहा गया कि पूरी जानकारी हासिल कर के सोमवार को यहां रख दी जायगी।

कु० श्री महेन्द्रसिंह (गांवड़ी) : हमें बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ता है कि जो फायरिंग हुआ वह किस के आर्डर से हुआ यह नहीं बता सकते तो यह सदन का अपमान किया जा रहा है, इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार डेफिनेटली बताये कि फायरिंग किसके आर्डर से हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह निश्चित हो गया है कि सरकार ने इसे एक फाल्स प्रेस्टिज का इश्यू बना रखा है। एक महिला का बड़ा नाजुक प्रश्न है, उसकी इज्जत का सवाल है, यह मोटी बात है, गोली चली, क्यों चलाई इसके बारे में भी सरकार जानकारी नहीं दे सकती तो मैं समझता हूं विरोधी पक्ष की बात मानने को सरकार तैयार नहीं और आपका जो कुछ निर्णय हुआ है ठीक है लेकिन यह सारी व्यवस्था बड़ी असंतोषजनक है। इसलिए विरोध प्रकटकरते हुए मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं।

(स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, २३ तारीख की घटना को लेकर कल मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा, उसको आपने टेबल किया, अगर आपने उसको टेबल नहीं किया होता और उप गृह मन्त्री को आज विवरण देने के लिए नहीं कहा होता तो और बात थी पर कल आपका स्पष्ट आदेश था कि विवरण विस्तृत रूप से सदन को देंगे। इस आदेश के बावजूद भी सरकार की तरफ से प्रयास नहीं करके······

श्री निरन्जननाथ आचार्य : गलत कह रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसके बाद भी लापरवाही उन्होंने की और उसके बाद सदन के समक्ष इस प्रकार की बात कहें तो इससे बढ़ कर सरकार के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। हम इसके खिलाफ सदन से वाक आउट करते हैं।

(जन संघ के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(१२.५५ म० प०)

कार्य सलाहकार समिति के २५वें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का २५वां प्रतिवेदन को पुरः स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २५ वें प्रतिवेदन को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया

(मांग संख्या २७ एवं ४२ सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत)

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २७-मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय ५२ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,००,६३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ...

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पोइन्ट आफ आर्डर, सर, जब तक इस पर डिस्कशन नहीं हो जाय तब तक मंजूर करने का प्रस्ताव नहीं रख सकते।

श्री हरिश्चन्द्र : अभी तो मैं पढ़ रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमन्त्री गृह) : इन्होंने वाक आउट किया, वापिस कैसे आगये ?

श्री विजयसिंह झाला : मैं वापिस आ गया, आप कौन हैं कहने वाले ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५३,१०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

वोट के लिये प्रेस कर रहा हूं, वोट करा दीजिये।

Page No.45

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इस पर डिस्कशन नहीं हो जाता तब तक वोटिंग नहीं हो सकता यह इनकी चाल है इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७ स्वीकार की जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई।

(विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

अनेक माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता, 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : Too late.

विराम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२ स्वीकार की जाय...

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह रवैया सहन नहीं करेंगे...

(शोर गुल)

(१ म: प०)

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों हां कहें

(हां की ध्वनि)

जो विपक्ष में हों नां कहे...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह आपका रवैया गलत है...

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : I will put it again.

श्री मानसिंह महार : आज कार्यवाही नहीं चल सकेगी, हम आपका इस प्रकार का रवैया पसंद नहीं करते...

(शोरगुल)

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात)

श्री विजयसिंह झाला : यह आपने विश्वासघात किया है।

(व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियो का जुलूस आए उससे पहले आप भाग जायें, मगर हम आकर आपको घर भी पकड़ लेंगे। सरकारी कर्मचारी अपनी वाजिब मांगों के लिए आज यहां आयेंगे और आप मांग पास करके दुम दबा कर भागे जा रहे हैं। हम सुखाड़ियाजी, आपको घर पर आकर पकड़ेंगे। आप मत समझना कि आप ऐसे छूट जायेंगे। मैं जुलूस को लीड करूंगा। आपके घर पर आयेंगे, मन्त्रियों के घर पर पिकेटिंग होगा और आपकी अच्छी तरह से सेवा की जायगी। दुम दबा कर एक मिनट में 'हां-हां' करवा दिया। आपने स्टेटमेंट भी दिया।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप बाहर क्यों चले गए ?

श्री मानसिंह महार : आपकी नालायकियों का विरोध करने के लिए।

आप लोगों ने बयान क्यों नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२ ...

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े हो गए)

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२....

(शोरगुल-अश्रव्य)

'हां पक्ष' जीता।

(शोरगुल)

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक २८-३-६६, ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० १.५ बजे स्थगित हुई)

(सदन की कार्यवाही पुनः १ बज कर ४३ मिनट पर प्रारम्भ हुई)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

(विराम)

मांग संख्या ४२

(मांग संख्या २७ व ४२ पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए)

मांग संख्या २७

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :-

१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा दिये जाने वाले ठेकों में पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

२. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बारां क्षेत्र की सड़क द्वारा अलग से झालावाड़ डिवीजन में मिलने पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या २७

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल):-

३. मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपये कम कर दिये जाय (खाटू तरणाऊ सड़क जो स्टेट हाईवेज का हिस्सा है उसे पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

४. मांग संख्या ४२,मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००)रु० कम कर दिया जाय (नागौर कन्या सेकेन्डरी स्कूल का भवन निर्माण नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (शिकराय-सु०):--

५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)

Page No.47

(श्री लक्ष्मणप्रसाद)

रुपये कम कर दिया जाय (सिकराय में विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

६. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रथम पंच वर्षीय योजना से लगाकर तीसरी पंच वर्षीय योजना तक १ मील भी सड़क का कार्य सिकराय में नहीं हो पाया है, इस पर चर्चा के लिये)।

७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम चांदोरा पंचायत में लीक रोड जोड़ी जाने पर चर्चा के लिये)।

८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिकन्दरा से वाया गडराया होती हुई सड़क लाफा में मिलाने पर चर्चा के लिये)।

९. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिकराय से वाया बन्ध माधोसागर घाटी होती हुई एक सड़क उकड़ी की घाटी तक के निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):-

१०. मांग संख्या २७, शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सड़कों एवं भवन के निर्माण कार्यों के बारे में विभाग की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री चोसरसिंह चावेल (बेंगू):—

११. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में मंजूरशुदा सड़क कार्यों को समय अनुसार पूरा नहीं किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

१२. मांग संख्या २७ मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपये कम कर दिया जाय (सिंगोली से भैंसरोडगढ़ तक पुलियें तथा सड़क जल्द नहीं बनाने हेतु, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

१३. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (महुनाल से रावड़दा खान तक सड़क बनाने के संबंध पर चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेगूं से चेची तक सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये)।

१५. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेगूं से नंदवाई, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ में सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

Page No.48

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

१६. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेगूं से पालनपुर तक सड़क बनाने हेतु धन राशि का प्रावधान कराने पर चर्चा के लिए) ।

१७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया (पारसोली पुलिस स्टेशन का जल्द निर्माण कराने हेतु, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २७

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :—

१८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर के राज-भवन जो सरकार के पास है उनकी देख रेख नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४२

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) :—

१६- मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बदनोर ब्यावर व आसीन्द, भीलवाड़ा सड़क को डामर करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २७

श्री श्रवणलाल (हिण्डोन-सु०) :—

२०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों को P.W.D. विभाग की सड़कों में नहीं जोड़ा है इससे उन सड़कों की हालत खराब हो चुकी है । इस पर चर्चा के लिए) ।

२१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग, यातायात के साधन जुटाने में व सड़कें ठीक बनाने में असमर्थ रही है । इस पर चर्चा के लिए) ।

श्री गोविन्द सिंह (पिड़ावा) :—

२२. मांग संख्या २७,मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की असावधानी से निर्माण कार्यों पर अधिक खर्चे पर चर्चा के लिए) ।

२३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत-पिड़ावा सड़क की मरम्मत व पुलियों की मरम्मत न होने पर चर्चा के लिए) ।

२४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पिड़ावा से सुनेल तक सड़क को अधूरे कार्य से हो रही जनता की असुविधाओं पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ४२

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम):—

२५. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

Page No.49

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी)

में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देवगढ़-कुआथल रोड़ को निर्माण कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २७

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) :

२६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री दयाचन्द सोन (बारां सु०):

२७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों की मरम्मत वगैरा में विभाग द्वारा धन के दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिए)।

२८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नये भवनों की इमारतों में चूना सिमेंट की मात्रा की कमी के कारण इमारतों में होने वाली गड़बड़ियों की ओर अभियन्ताओं द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

२९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अमानी से कराये गये कामों में फिजूल खर्चा व जाली मस्ट्रोल बनाने पर चर्चा के लिए)।

३०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सड़कों के किनारों के वृक्षों को चोरी से कटवा देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४२

श्री देवीलाल (सराड़ा-सु०) :

३१. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा से सेमारी सड़क और परसाद से सलूम्बर सड़कें नहीं बनाने पर चर्चा के लिए)।

३२. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में पलोदड़ा से डीगरी सड़क को सराड़ा तहसील तक डामर सड़क बनाई जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २७

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०) :

३३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर आसपुर सड़क के निर्माण में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

३४. मांग संख्या ४२,-मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा डूंगरपुर से साबुना सड़क पर डामर कार्य में शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २७

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

३५- मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ सब डिवीजन की सार्वजनिक सड़कों के कार्य की शिथिलता पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री जयलाल (डग) :

३६, मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्य में विभाग द्वारा बरती गई शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़) :

३७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बूंदी से चितौड़गढ़ सड़क की मरम्मत नहीं करने पर चर्चा के लिये।)

३८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (संगरामपुरा सड़क बनाये जाने में विभाग द्वारा विलंब किये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा-सु.):—

३९. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा खैरवाड़ा, गिरवा पहाड़ी में सब जगह सड़कें टुटी हुई हे, दुरुस्ती पर चर्चा के लिये)।

४०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा खेरवाड़ा, गिरवा जिला उदयपुर में सड़कों की दुरस्ती न कराने पर चर्चा के लिये)।

डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर) :

४१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की अव्यवस्था से धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

४२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की अलवर जिले में सरकारी भवन निर्माण के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रभुलाल "सेन्टर" (खानपुर):

४३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण में विशेष रुचि न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

४४. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खानपुर, कंनवार वाया दहीखेड़ा रोड बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक):

४५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

१००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिले में योजनाओं स्वीकृत कार्यों को अभी तक पूरा न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

४६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुशलता एवं स्वच्छता लाने के बारे में चर्चा के लिये)।

४७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक खण्ड के सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की वाजिब मांगों की स्वीकार करने में ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा देख रेख किए जाने वाली सड़कों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

४६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक सवाई माधोपुर रोड़ को न सुधारने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

५०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक के चौथ का बरवाड़ा तक सड़क निर्माण के बारे में चर्चा के लिये)।

५१. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु०कम कर दिया जाय (टोंक इंडस्ट्रीयल एस्टेट के लिए बनने वाला भवन बिजली विभाग को दे देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये)।

५२. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया (टोंक में सार्वजनिक भवन संस्था विशेष को दे देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा):

५३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरलाल "काला बादल"

(अकलेरा-सु.)—

५४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सड़कों की अव्यवस्था से निर्माण के कार्यों पर होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

५५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण निर्माण कार्य पूरे होने में देरी पर चर्चा के लिये)।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

५६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ठेके पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यो में विभाग द्वारा नियन्त्रण नहीं रखने से समय पर पूरे नहीं होते इस पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोलाल खानपुरिया (पटन) :

५७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भवनों के निर्माण पर विशेष रुचि न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)--

५८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के चारों ओर विभिन्न स्टेट राष्ट्रीय पथों से जोड़ने हेतु Ring Road बनाने पर चर्चा के लिये)।

५६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरदार शहर से विजयनगर वाया लूणकरणसर सड़क को योजना में शामिल करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

६०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर गंगानगर रोड फंड में से लूनकरणसर में डाक बंगला बनाने पर चर्चा के लिये)।

६१. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर गंगानगर रोड से रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न रेल्वे स्टेशनों तक एप्रोच रोड बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

वैद्य श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

६२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग की अव्यवस्था के कारण धनराशि का सदुपयोग न होने के बारे में चर्चा के लिए)।

६३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भवनों व सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिए)।

६४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५२– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की व्यवस्था ठीक न रखने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) :

६५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले के सार्वजनिक सड़कों को मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

६६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक

(श्री मोतीलाल चौधरी)

निर्माण विभाग के अन्तर्गत आने वाले उद्यानों एवं सरकारी बंगलों में खाली स्थानों पर सब्जी और अन्न उत्पादन करने के कार्य-क्रम पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४२

६७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ :—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जैसलमेर, नागौर के जिला हैड क्वार्टर को राज्य की राजधानी जयपुर से सीधा संबंध स्थापित करने के लिए सड़क निर्माण करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २७

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई):

६८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचार साधन योजनाओं का समय पर क्रियान्वित न करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४२

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवारा):

६९. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिरोही से आबूरोड जाने वाली सड़क पर बनास स्टेशन और किवरली गांव के पास बनास नदी पर पुल बनाने के बाद पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

७०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिवगंज तहसील में सड़कों की कमी को पूरा कराने के लिए विभाग का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिए)।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़):

७१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०:- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा बिजोलियां चित्तौड़ बूंदी रोड़ की हालत में सुधार न किए जाने पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या ४२

७२. मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माण्डलगढ़ तहसील जिला भीलवाड़ा में तहसील भवन तथा एस० डी० एम० कोर्ट न बनने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २७

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा):

७३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन व सड़क का काम शुरू करने में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

७४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्य करने में विभाग द्वारा जनता के साथ पक्ष पात करने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री मानसिंह महार (आमेर) :

७५. मांग संख्या २७,मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में गंगापोल बाहर वर्षा के कारण बनी हुई खाई पर सड़क निर्माण न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

७६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में मंजूर शुदा सड़क कार्यो को शुरू न किया जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) :

७७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (आदर्श नगर, राजापार्क, गुरूनानकपुरा आदि बस्तियों की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

७८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत में से १००)रु० कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में बाढ़ की रोकथाम की दृष्टि से अधिक धनराशि रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

७९. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३–सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत में से १००)रु० कम कर दिया जाय (S. M. S. Hospital एवं Zenana Hospital में Additional Cottage ward) बनाने हेतु अधिक धन राशि रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्रीमती गोरी पूनिया (डेगाना) :

८०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सड़कें बनाने में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली) :–

८१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण पर विभाग द्वारा उचित ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :—

८२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सार्वजनिक निर्माण कार्यो की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

८३. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यो पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले और डूंगरपुर जिले के बीच माही नदी पर पुल के सम्बन्ध पर चर्चा के लिए)।

Page No.55

मांग संख्या २७

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा):

८४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

८५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन और सड़कें सही ढंग से न बनाने पर चर्चा के लिए)।

श्री चंद्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) :

८६. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जोधपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण कार्यों की पूर्ति में विभाग विफल रहा इस पर चर्चा के लिए)।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर):

८७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४२

८८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विद्यालय भवनों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २७

श्री जीवराज सिंह (गुढा) :

८६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले के विभागीय अधिकारियों का ठेकेदारों से मिलकर भ्रष्टाचार करने पर चर्चा के लिए)।

श्री जेटमल बरबड़ (परबतसर) :

६०. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले में सड़कों की मरम्मत करने में विभाग द्वारा लापरवाही करने पर चर्चा के लिए)।

श्री रावतराम (सादूलपुर) :

६१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५० सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर) :

६२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निर्माण विभाग में प्रशासनिक कुशलता से धन के अपव्यय पर चर्चा के लिए)।

श्री मानधातासिंह (महुआ) :

६३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं के कारण धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

Page No.56

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत):

९४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत तहसील में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष १९६३–६४ में बनी रोजाला से रूपावास की सड़क को चाडवास ग्राम की सरहद में तोड़ देने व सड़क के बीच कच्चा कुआ खोद देने पर भी विभाग द्वारा ध्यान न देने पर चर्चा के लिए)।

९५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत तहसील में मैसाणा से सोजत रोड की सड़क पर ठेकेदार द्वारा Asstt. Engineer द्वारा बताई हुई लाइन पर कार्य न कर काश्तकारों की खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर देने व विभाग द्वारा उस पर कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए)।

९६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत व जैतारण उप खण्डों में विभाग द्वारा किये गये अकाल सहायता कार्यों पर खुदे हुए मुड को न डलाने व उनकी मरम्मत की ओर विभाग का ध्यान न होने से उत्पन्न मुद्दों व समस्या पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४२

९७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जैतारण से चंडावत की सड़क वाया आगेवा बावड़िया, रामपुरा को चौथी योजना में डामर की करवाने पर चर्चा के लिए)।

९८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत से बिलाड़ा की सड़क को पक्की करने एवं योजना में सम्मिलित की जाने पर चर्चा के लिए)।

९९. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत से पीपाड़ वाया चामदीपाक, मेव रामसनी, साधवां मालकोलनी, बाला की सड़क को चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में पूर्ण करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २७

श्री मोहरसिंह (चूरू):

१००. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (साहवा से मादरा सड़क निर्माण में बहुत देरी की गई हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

१०१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तारानगर से साहवा सड़क निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ है, इस पर चर्चा के लिए)।

१०२. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरगढ़ से भूंपा सड़क निर्माण कार्य में विभाग की लापरवाही के कारण अत्यधिक विलम्ब हुआ है इस पर चर्चा के लिए)।

(श्री मोहरसिंह)

१०३. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०— सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण सीकर से धोरमसर सड़क निर्माण कार्य में अत्यधिक विलम्ब हुआ है इस पर चर्चा के लिए)।

१०४. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में सड़क निर्माण कार्य चालू नहीं करने पर विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

१०५.मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की शिथिलता से बीकानेर से डूंगरगढ़ तक सड़क निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ है इस पर चर्चा के लिए)।

१०६. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की शिथिलता से फतेहपुर से रामगढ़ तक सड़क बनाने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और इससे इस इलाके के लोगों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिए)।

१०७. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की अव्यवस्था से मंडावा से बिसाऊ सड़क निर्माण में अत्यधिक विलम्ब किया गया है इस पर चर्चा के लिए)।

१०८. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झूंझनू से बिसाऊ सड़क की मरम्मत होकर गढे पड़ गये हैं और आवागमन में कठिनाई हुई है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ४२

१०९. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू में सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की सुविधा प्रदान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

११०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू से तारानगर सड़क के लिए धन राशि उपलब्ध न करने पर चर्चा के लिये)।

१११. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजगढ़ सैंबहल सड़क न बनाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए)।

११२. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू जिले में अधिशासी अभियन्ताओं के लिए कार्यालय भवन एवं निवास की कमी पर चर्चा के लिये)।

११३. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला चूरू में डाक बंगला बनाने पर चर्चा के लिए)।

(श्री मोहरसिंह)

११४. मांग संख्या ४२-मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चूरू के रेस्ट हाउस में न वृद्धि होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री हरिकिशन (राजगढ) :

११५. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा Heavy rain fall area में सड़क की मरम्मत के लिए अधिक धन राशि न देने की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

११६. मांग संख्या ४२. मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा बजट में सड़कों के निर्माण के लिये कम धन राशि रखने पर चर्चा के लिये)।

११७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा आदिवासी बहुजन संख्या वाले क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये)।

११८. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माचाड़ी से चिमरावली तहसील राजगढ जिला अलवर में Fair Weather Road है में तीन पंच वर्षीय योजना गुजरने पर भी अभी तक पक्की सड़क सरकार द्वारा नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

११९. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा राजगढ जिला अलवर में विश्राम गृह (Dak Bunglow) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१२०. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माचाडी से मुण्डावर तक जिला अलवर में सड़क पर तार कोल पथ विभाग द्वारा नहीं डलाने के कारण सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २७

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू):--

१२१. मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५०- सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जयपुर में सड़कों की मरम्मत व डामर न कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ४२

श्री मोहनराज (बाली) :

१२२. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (केनपुरा, देसूरी सड़क एवं सादड़ी पिंडवाड़ा सड़क हेतु आवश्यक धनराशि न देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री मोहनराज)

१२३. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देवली से नाढोल, [जिला पाली] तक की सड़क के लिए प्रावधान न रखने पर चर्चा के लिए)।

श्री मुकिलाल मोदी (कोटपुतली):

१२४. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान संचार साधनों की आवश्यकता को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद):

१२५. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट में सड़कें व पुलियों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल,जयपुर):

१२६. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३– सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी इमारतों की कमी के कारण दफ्तरों के लिये इमारतें किराये पर ली जाती हैं और फिजूल खर्चा होता है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया):

१२७. मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ धरियावद. धरियावद सलूंबर वगैरा सड़कें नहीं बनाई, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, पी०डब्लू०डी० की मांग पर .....

श्री गिरधारीलाल व्यास: इनसे पहले तो मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष: (श्री व्यास की ओर मुखापेक्ष) आप स्थान ग्रहण करें।

श्री कृष्णकुमार गोयल: आज हम इस डिमाण्ड पर विचार कर रहे हैं।

इस विभाग का केवल सम्बन्ध इतना ही हो कि सड़कें बना देना, कुंए बना देना और जितने तखमीने विधान सभा पास कर के दे उसका काम कर देना। अगर इतना ही होता तो भी शायद मैं इस पर अपने विचार नहीं रखता, लेकिन राजस्थान के अंदर आज जितना भी सड़कों का विस्तार होता है, जितनी सड़कें बढ़ाई जाती हैं उनमे गांवों का गांवों से सम्बन्ध बनता है, एक सड़क से दूसरी सड़क का सम्बन्ध जुड़ता है और गांव का तहसील हेड क्वार्टर से संबंध जुड़ता है और तहसील हैड क्वार्टरों का डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से। इस प्रकार सारे राजस्थान के जितने गांव हैं, जितनी मण्डियां है उन्हें एक मण्डी से दूसरी मण्डी के साथ संबंध बैठ जाता है। तो ऐसा प्रदेश जो आर्थिक दृष्टि से साधन सम्पन्न नहीं है और किसी भी देश की और प्रदेश की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आर्थिक परिस्थिति पर विचार करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो हमारे प्रदेश के अन्दर आर्थिक साधन हैं उन साधनों को अधिक से अधिक प्राप्त करके हम उसका कितना उपयोग कर सके हैं। और उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर ही राजस्थान सरकार ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और उस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर बीस साला योजना को अपने सामने रख कर, बीस साल के कार्य क्षेत्र को सामने रखकर इस सारी योजना का, तीसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और उसके अन्दर सरकार ने यह निश्चय किया कि हम इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपनी सड़कों के माध्यम से उस ध्येय को प्राप्त करना चाहते हैं जबकि सरकार······

श्री उपाध्यक्ष : मैं पहले माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार से नित्य प्रति होता है सारे कटमोशन्स को मूव हुआ माना जाता है, यह मान लिया जाता है कि सदस्यों ने कटमोशन मूव कर लिए हैं उसके साथ साथ ही सिम्बोलिक रूप में जिस प्रकार निर्णय प्रति होता है पार्टी के लोग उन कटमोशन्स पर बोलते हैं। लेकिन यह मैं और माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि जैसा कि पहले की डिमाण्ड पर हुआ है उस पर मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कटमोशन का नाम बोलूं, कटमोशन का प्रस्ताव करने वाले का नाम बोलूं यह जरूरी नहीं है, अकार्डिंग टू रूल्स और वह चांस माननीय सदस्यों को ही लेना पड़ेगा उस वक्त में। मुझे केवल यह देखना है कि कौन सदस्य किस समय बोले और किस पार्टी की वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई माननीय सदस्य को उठता हुआ नहीं देखूंगा तो यह जरूरी नहीं है कि मैं उनका नाम बोलूं और उनको बोलने के लिए उठाऊं। उस वक्त भी डिमाण्ड पास करते समय और जब डिमाण्ड को वोट पर रखा तो उस समय इस प्रकार की गलतफहमी रही है, वह रहनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से नित्य प्रति का एक नियम बना हुआ है सिम्बोलिक रूप में प्रत्येक पार्टी से मेम्बर बोलेंगे और जैसा आपको मालूम है कि कई बार जिनके कटमोशन्स नहीं थे उनको भी बोलने की इजाजत दी गई है, उसी प्रकार चैयर की आई कैच करके वे जिस प्रकार से बोलते रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। इसके अलावा, समय का अन्दाजा भी रखना होगा कि जिससे अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपने कटमोशन्स पर बोल सकें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका मतलब है कि कोई भी खड़ा होकर बोल सकेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी आदमी नहीं। दस आदमी खड़े होकर बोलने लग जाएं, ऐसा नहीं मैं जिसको कहूंगा वही बोलेगा और जितना समय मैं दूंगा उतने समय तक ही बोलेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के आर्थिक विकास को सामने रखकर ही राजस्थान सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाते समय किसी ध्येय की पूर्ति की ओर···

श्री उपाध्यक्ष : The clarification is made in view of certain objections raised in connection with first demand. इसलिये मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें सारा स्कोप है, इसमें सारी डिमाण्ड पर बोले जाने का स्कोप है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर सरकार ने यह लक्ष्य रखा कि इस योजना के पूर्ण होने तक राजस्थान के अन्दर कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा कि जिसके चार मील के एरिया के अन्दर से पक्की सड़क नहीं निकलती हो। कोई गांव राजस्थान के अन्दर ऐसा नहीं बचेगा कि जिसकी सड़क से दूरी तीन मील से अधिक हो, इस लक्ष्य को सामने रख कर आपने योजना बनाई थी, लेकिन आज निर्माण मंत्रीजी में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी यह राजस्थान सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल हुई है? क्या आप सदन के सामने हिम्मत के साथ यह कहने को तैयार हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो हमने लक्ष्य निर्धारित किये थे और जिन सड़कों का निर्माण हम करना चाहते थे, हम उन सड़कों को बना चुके हैं और आज कोई भी गांव सड़क से चार मील या तीन मील से दूर नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि हमने जो अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसके अन्दर जो लक्ष्य रखा था वह हमने १३ करोड़ का रखा था, और १३ करोड़ के मुकाबले में यह खर्च हुआ है मुश्किल से ६-५६ करोड़ ये ६-५६ करोड़ खर्च कर पाये हैं। इस प्रकार से चार करोड़ रुपया इस योजना के अन्दर जो १३ करोड़ रखा गया था उसके मुकाबले में ६ करोड़ रुपया खर्च कर पाये हैं और चार करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाये हैं। चार करोड़ के अन्दर राजस्थान में कितनी सड़कें और भवनों का निर्माण होता इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार ने जो इकोनोमिक मेजर्स लिये हैं उन इकोनोमिक मेजर्स में राजस्थान सरकार ने सड़कों के महत्व को मालूम पड़ता है, नहीं आंका है। सड़कों का महत्व आर्थिक दृष्टि से क्या होना चाहिए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया हुआ इसको भुलवाकर इकोनोमी का नारा लगाकर उस चार करोड़ रुपये की बचत की।

और मैं, उपाध्यक्ष-महोदय, इस विभाग का खास तौर से इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह ३,४८,४६१ वर्गमील है। जिस प्रदेश का फैलाव ३,४८,८६१ वर्गमील हो और जहां की दो करोड़ की आबादी हो और जिस प्रदेश के अन्दर शहर लगभग १४५ हो और गांवों की आबादी ३४,५३२ हों ऐसे बड़े प्रदेश के अन्दर केवल आप यह कहना चाहेंगे कि हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था वह पूर्ण कर लिया है तो मैं सोचता हूं कि यह सरासर गलत है। आज सरकार की यह मान्यता है, सरकार ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि आज राजस्थान के अन्दर १८३६७ मील सड़कों की लम्बाई है और उसके मुकाबले में राजस्थान का क्षेत्र है ३,४८,८६१ वर्गमील, और उसके अन्दर जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि १४५ शहर और ३४,५३२ गांव हैं, तो आप अनुमान लगाइये कि १८,३६७ मील की सड़कें जो आज तक बनी हैं क्या उस आधार पर

निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान के गांवों तक हमने सड़कें पहुंचा दी है ? आज किसी भी जगह राजस्थान में रहने वाला ग्रामवासी आसानी से मंडी तक पहुंच सकता है, आसानी से शहर तक पहुंच सकता है। १२ महीने कोई रुकावट नहीं है अपने गांव तक पहुंचने में। लेकिन आज उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर १६,७७४ मील लम्बी सड़कें बनाई गई थी। हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह पूरा कर चुके थे, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर आपने केवल उनको १८,३६७ मील लम्बा किया है। इस हिसाब से हम इन पांच सालों में १६२३ मील लम्बी सड़कों का निर्माण कर पाये। १६२३ मील लम्बी सड़कों के ऊपर आपने ९ करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया है। आप इसको कहां तक जस्टीफाई कर सकते है ? आप सदन को कहां तक विश्वास में ले पायेंगे कि १६२३ मील लम्बी सड़कों के निर्माण के अंदर ९ करोड़ रुपये खर्च किये वह ठीक हैं ?

(१.५३ म. प.)

सदन की स्थगित बैठक पुनः मिलने विषयक औचित्य प्रश्न

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : औन ए पॉइंट ऑफ आर्डर, सर, मैं अभी इधर से जा रहा था तो सदन की कार्यवाही होती देखी। मुझे और मेरे साथियों को तो यह सूचना मालूम हुई थी कि २८ तारीख के ११ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। उसकी बिना सूचना के दुवारा कब कार्य चालू हो गया बहुत से माननीय सदस्यों का यहां पहुंचना संम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपके नेता से पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल: यह अवैधानिक तो नहीं होगा कि कई माननीय सदस्यों के...

श्री उपाध्यक्ष: सोमवार तक स्थगित नहीं की। हुल्लड़ में किसी ने कोई चीज नहीं सुनी थी। उस समय जिस प्रकार की सदन में गर्मी थी उसको देखते हुए कुछ समय तक स्थगित की गई थी न कि सोमवार तक।

श्री कृष्णकुमार गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: The house was adjourned due to disturbances.

मांग संख्या २७ व ४२ सार्वजनिक निर्माण कार्य इत्यादि (पूर्वक्रम से)

श्री कृष्णकुमार गोयल: कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम राजस्थान के अन्दर केवल १६२३ मील लम्बी सड़कें बना पाये हैं और इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि अगर १६२३ मील लम्बी सड़कें ही बना पाये हैं तो और एचीवमेंट क्या है ? क्या जो पक्की सड़कें थी उनको डामर की बना पाये हैं जहां पर डामर की थीं उनको सीमेंट की बना पाये हैं या जो कच्ची सड़कें थीं उनका विस्तार अधिक कर पाये हैं। और उस पर विचार करना

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ६२-६३-में राजस्थान में ४२ मील सीमेंट की सड़कें थीं जो आपकी सरकार में और शासन में ६३-६४ में केवल ४१ मील रह गईं यानी एक मील सड़क आपकी बदइन्तजामी के कारण आज राजस्थान के अन्दर बेकार हो चुकी हैं। इस प्रकार जो आपकी पेन्टेड सड़कें थीं, जो डामर की सड़कें थीं वे ६२-६३ में ६१७२ मील थीं वे जाकर ६३-६४ में १०,०१३ मील हुईं। इसमें आप कह सकते हैं कि इसके अन्दर आपने ८४१ मील का एचीवमेंट किया है। इस प्रकार जो मेटल्ड रोड्स थीं ६२-६३ में वे ६१५४ मील थीं वह जाकर ६३-६४ के अन्दर ६०३३ मील रह गईं यानी १२१-मील लम्बी सड़क आपकी इसके अन्दर कम हुई है। जो ग्रेवल्ड रोड्स थी। ६२-६३ में वह ५१३९ मील थीं वे ६३-६४ में ५४३४ मील हो गई है। इस प्रकार ३९५ मील और सड़कें बनी हैं लेकिन जहां तक फेयर वेदर रोड्स का सवाल है जो केवल अच्छे मौसम में चलने लायक है और बरसात के अन्दर बन्द हो जाती हैं और जिनका सम्बन्ध गावों से जो ग्रामवासी राजस्थान में जनता के ७० पर्सेन्ट से अधिक है, जिस ग्रामवासी के ऊपर राजस्थान का भाग्य निर्भर करता हैं, जिस ग्रामवासी की बेहबूदी के ऊपर राजस्थान ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की बेहबूदी निर्भर करती है। उनके लिए ७७१२ मील लम्बी सड़कें थी ६२-६३ में वे सड़कें ७१२९ मील रह गई। इस प्रकार से ५८३ मील सड़क कम हुई है। इसलिए मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो आंकड़ें हैं उनके अनुसार ६२-६३ के बाद ६३-६४ में केवल ५२१ मील का एचीवमेंट किया है। उसके अन्दर ५८३ मील सड़कें कच्ची खत्म हो गई और १२१ मील सड़कें जो डामर की पक्की थी वह खत्म हो गई। इस प्रकार ५२१ मील का एचीवमेंट है यह एचीवमेंट कैसे किया? क्या यह कहना चाहेंगे कि कच्ची सड़कों को पक्की बना दिया? क्या आप यह कहना चाहेंगे कि जो पक्की सड़के थी उनको डामर की बना दिया। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि आपके टारगेट पूरे हो गए हैं और केवल ५४३ मील की सड़कों में कमी आई हैं तो उपाध्यक्ष महोदय ६४-६५ के अन्दर और भी स्थिति गम्भीर है। जो ६३-६४ में ७१२९ मील फेयर वेदर रोड्स थीं वह केवल ४१८६ मील रह गई।

तो मैं इसके आधार पर विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसका कम से कम यह स्पष्टीकरण करें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो सड़कें कायम थी उसके अन्दर हो सकता है कि पक्की सड़कें बन गई हों, हो सकता है कि कुछ विकास किया हो लेकिन जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है वे ग्रामवासी जो कच्ची सड़कों में शहरों में आते हैं, पक्की सड़कों तक आते हैं उसकी संख्या ६२-६३ में ७७१२ मील थी वह ६४-६५ में ४१८६ मील कैसे रह गई। आपने जो एचीवमेंट किया है पक्की सड़कों का तो उनकी कच्ची सडकों के साथ में एडजस्टमेंट कैसे कर पायेंगे। तो मेरा यह निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष, कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर जो विभाग ने सड़क का निर्माण अपने हाथ में लिया है उसमें सरकार ने शहरों की तरफ ध्यान दिया है, शहरों की बेहबूदी पर ध्यान दिया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हैं जो पर्यटक आते हैं, विदेशी आते हैं उनको लुभाने की तरफ ध्यान दिया हैं। आपने डामर की सड़कें बनाई हैं लेकिन ग्रामवासियों को तरफ जो राजस्थान सरकार की रीढ है, बेकबोन है—·····················

(२ म. प.)

·········आज उसके साथ आपने विश्वासघात किया है। आपने उस क्षेत्र में ३००० मील सड़कें कम की हैं। आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि अपने उन सड़कों का निर्माण न करके ग्राम वासियों की अपेक्षा नहीं की है। आपने ग्रामवासियों की उपेक्षा की है, उनकी परवाह नहीं की है और उनकी कीमत के ऊपर शहरों की और अधिक ध्यान दिया है।

इसके साथ साथ जहां पर आपने सड़कों का निर्माण किया है वहां पर भी आपने पक्षपात किया हैं, वह कैसे यह मैं अर्ज करना चाहता हूं कोटा का क्षेत्रफल कुल मिलाकर १२००० किलोमिटर हैं बूंदी का क्षेत्रफल ६००० वर्ग किलोमीटर है, झालावाड़ का क्षेत्र फल ६००० वर्ग किलोमीटर हैं, उदयपुर का १८००० वर्ग किलोमीटर है, अलवर और अजमेर का क्षेत्रफल आठ आठ हजार वर्ग किलीमीटर हैं इसके मुकाबले आपने वहां पर सड़कों का निर्माण किया हैं उसकी ओर ध्यान दें तो कोटा डिविजन के साथ आपने कितना अन्याय किया हैं इसका पता चलेगा। कोटा बूंदी और झालावाड़ जो हर प्रकार से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर उद्योग बढते जा रहे हैं, खेती की दृष्टि से राजस्थान सरकार की निगाह उसकी ओर पड़ी है उस क्षेत्र में आपने सड़कों का विभाजन किस प्रकार किया है; आपने राजस्थान का सारा पैसा समेट कर उदयपुर में डाल दिया है·······

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): झूठी बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: जैसे उदयपुर का क्षेत्रफल केवल ८००० वर्ग किलोमीटर है लेकिन वहां पर आपने ३२१८ मील सड़कों का निर्माण किया हैं और कोटा का क्षेत्रफल १२ हजार वर्ग किलोमीटर हैं वहां पर आपने १५३५ वर्ग मील सड़के बनाई हैं। बूंदी जिसका क्षेत्रफल ६००० किलोमीटर है उसमें ६५५ मील सड़क बनाई हैं और झालावाड़ जिसका क्षेत्रफल ६००० किलोमीटर हैं वहां पर ११०१ मील सड़क दी है। और उसके बाद भी आपने पक्षपात केवल इतना ही किया हो यह बात नहीं हैं। आपकी जहां तक डामर की सड़कें हैं कोटा को ३६७ मील सड़कें मिली उसके मुकाबले में उदयपुर को ७७१ मील मिलीं। बूंदी को केवल १८३ मील सड़कें मिली, झालावाड़ को २६८ मील मिलीं। और अलवर का क्षेत्रफल ८००० किलोमीटर हैं उसको आपने ६६० मील सड़कें दी हैं और इसी प्रकार पक्की सड़कों को देखें तो कोटा में ४२२ मील पक्की सड़क दी है बूंदी को १८० मील दी है और झालावाड़ में ४६८ मील दी हैं। इसमें भी आपने पक्षपात किया हैं कोटा का क्षेत्रफल १२००० किलीमीटर है वहां पर तो केवल ४२२ मील पक्की सड़कें दी हैं और झालावाड़ का क्षेत्रफल केवल ६००० किलोमीटर हैं वहां पर ४६८ मील दी है। और इसक अलावा उदयपुर को ३४६ मील दी है

श्री गिरधारीलाल व्यास: उदयपुर को कहां दिया हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लूट तो लिया हमको ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने मार लिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: जहां तक ग्रेवल रोड़ का सवाल है कोटा में ७२७ मील बूंदी में ३८६ मील और झालावाड़ में ३३४ मील ग्रेवल रोड्स दी है और इसके अलावा अलबर और अजमेर वहां पर तो बड़े लोग रहते हैं उनके लिए कच्ची सडक का क्या काम हो सकता हैं आपने इस पर ध्यान नहीं दिया हैं । आकड़ों को देखते हुए जो पैसो का विभाजन या बंटवारा किया हैं वह जिलों के क्षेत्रफल को ध्यान में रख कर करना चाहिये था, जिलों के विकास की ओर ध्यान देकर करना चाहिये था और किसानो को उत्पादन की ओर ध्यान देकर करना चाहिये था । आपने इन बातों की ओर ध्यान दिया होता तो जो पक्षपात और अन्याय कोटा और बूंदी जिले के साथ किया है वह नही होता ···

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): आप कोटा की बात कहते हैं जालोर में कुछ हैं ही नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: माननीय सदस्य का कहना ठीक हैं जहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र है, क्षेत्रफल जहां का लम्बा चौड़ा है, जहां पर गांव दूर दूर हैं जिनका पक्की सड़कों से संबंध नहीं जुड़ा हुवा हैं वहां पर भी आपने सड़कों का निर्माण नहीं किया हैं ।

आपने तीन पंच वर्षीय योजनाएं बनाई उनमें जिस ध्येय की पूर्ति करनी थी वह नहीं कर पाये और इसके अलावा जो कुछ किया उसके आधार पर भी आपने जिलों में जो पेसा बांटा उसमें भी पक्षपात किया है और जो जिले पीछे रह गये हैं उनमें ग्रामीणो का विकास नहीं कर पाये हैं और दूसरी ओर जहां किसानों और गांव में रहने वाले व्यक्तियों को आभास होना चाहिये था कि उनकी तरक्की हो रही है वह उनको नही मिली । जो लोग शहरों में रहते हैं उनको भी आभास नही मिला । आज उनको इस बात का अनुभव नही हो रहा है कि वे राजाओं के राज्य में नही रहते हैं जो लोग अपने खेतों में अनाज पैदा करते हैं वे उसको मंडियों तक नही पहुंचा पाते और मजबूर होकर उनको पेसों वालों को कम कीमत पर बेचना पड़ता हैं । आपने किसानों का विकास नही किया फिर भी आज आप कहते है कि किसानों का राज्य है । मैं कहता हूं कि किसानों की उपेक्षा की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जितना पसा खर्च किया है उसका पूरा उपयोग विभाग कर पाया है मेरी ऐसी मान्यता नहीं है । मैं अलग अलग केसेज़ में नहीं जाना चाहता अलग अलग निर्माण के कामों में नहीं जाना चाहता लेकिन जिन सडकों का निर्माण हुआ है उनमें ठेकेदार से लेकर इंजीनियर्स तक ने क्या क्या नहीं किया है । जिनको ठेकेदारों के साथ पक्षपात करना था उन्होंने हर तरह से उनके साथ पक्षपात किया है । एस्टिमेट्स बनाने में पक्षपात किया, डामर के लिए एस्टिमेट गलत बना दिये । जहां पर पर मिट्टी मिला कर डामर करने की शर्त थी वहां पर ठेकेदारों ने मिट्टी में डामर मिला कर खाली पतला सा कोटिंग कर दिया । रेकार्ड में डामर बता कर पेमेंट कर दिया लेकिन जो सड़कें बनाई उनमें केवल डामर का पेन्टिंग ही किया है । मै एक दृष्टान्त आपको दूंगा । बारां मांगरोल रोड़ पर जो काम हुआ उसके बारे में कई प्रार्थना पत्र

(श्री कुमार गोयल)

भेजे, आपसे निवेदन किया लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की उसको पूरा संरक्षण दिया गया। नतीजा यह हुआ कि हजारों रुपयों का सरकार को नुक्सान हो गया। बारां मांगरोल रोड का ठेका दो ठेकेदारों को दिया गया एक बाप था दूसरा बेटा देवराज बाप और केवलराम बेटा। उन दोनों ने आधी आधी सड़क ले ली। ठेकेदारों से कहा गया था कि कारपेंट कोट करें लेकिन उसने केवल पेन्टिंग किया डामर का। उस ठेकेदार को ४॥ रुपये प्रति सौ वर्ग फुट के हिसाब से पैसे दे दिये। सड़क पर से पेड़ कटवा कर उसने जला दिये उसका भी पैसा नहीं लिया। इतना ही नहीं अधिकारियों ने ठेकेदार से मिलकर जो सरकारी खर्च से सामान तैयार करवाया था गिट्टी तैयार करवाई थी वह भी ठेकेदार को मुफ्त में देदी और रेकार्ड में यह बता दिया कि ठेकेदार ने पैसा लगाये लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि अधिकारियों और ठेकेदार ने मिलकर सरकार के पैसों का गबन किया उसकी ओर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार के पेड़ काटे जाते है, पी.डब्लू.डी. की सड़क पर से उसको जलाया जाता है उसके भी कोई पैसे नहीं लिये जाते। रोलर का फ्री उपयोग दिया जाता है। ये सारी की सारी बातें एक जगह ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान में चल रही है। पी. डब्लू. डी के अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लूट रहे हैं। आप उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने में मजबूर हैं, नहीं कर पाते आप कह सकते हैं कि सड़कों के लिए ६ करोड़ रुपये खर्च किए। ६ करोड़ रुपये खर्च जरूर हुए होंगे लेकिन ५ करोड़ से अधिक की सड़कें नहीं बनीं यह मेरी मान्यता है इसको सिद्ध करने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। सदन में कई बार बातें आई हैं पी. डब्लू. डी. के ओवरसियर जैसे मामूली आदमी का पंचायत समितियों में ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो वे तुरन्त वहां से भागते हैं उसका कारण यह है कि पंचायत समितियों में पैसा कम है, उनको वहां पर कमीशन नहीं मिलता है इसलिए वे पंचायत समितियों से भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप जागरूक होकर यह करें कि पैसे का पूरा उपयोग होना चाहिये ताकि गांव गांव में सड़कें पहुंच सकें। पैसे का लीकेज होता है उसको रोकना चाहिये, डकैती पड़ती हैं उसको रोकना चाहिये लेकिन रोक नहीं पाते। आप रोकें भी कैसे? इस सदन में कई बार ध्यान आकर्षित किया है कि आपके इंजीनियर्स का प्रमोशन होता है उसमें भेदभाव किया जाता है, पक्षपात होता है। जिनका हक है उनका हक मार कर दूसरों को प्रमोशन दिया जाता है। उसके खिलाफ रिट दायर हुई है हाई कोर्ट में रिट के अन्दर आपकी ओर से जवाब पेश नहीं किया गया और जवाब पेश न किये जाने से जो हाई कोर्ट में फैसला दिया उस हाई कोर्ट के फैसले के अन्दर आपके विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स किये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस लाईट में, जिस रोशनी में हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिये हैं– उस पर आपने क्या एक्शन लिया है, आपने उस पर क्या कार्यवाही की? लेकिन आप कार्यवाही करना नहीं चाहते है। आप सारे मामले को दबा रहे हैं। जो राजस्थान की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट है, उसने आपके विभाग के बड़े बड़े

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अधिकारियों की नीयत पर शक करने वाले रिमार्क्स दिये हैं उस पर आपको एक्शन लेना चाहिये था। लेकिन आप इस पर एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, आप एक्शन ले नहीं रहे हैं. मैं जानना चाहता हूं कि जिस रोशनी के अन्दर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आपके विभाग के बड़े बड़े अधिकारियो पर रिमार्क्स दिये हैं ! उस पर आपने क्या कार्यवाही की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग का जागरुक होना आवश्यक है और इस विभाग को जागरूक होकर करप्शन को दबाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी संकल्प लिया जाय कि किसानों तक सड़कों को पहुंचाया जाय ताकि उनकी फसल का इनको फायदा मिल सके। जब तक आप इस दृष्टिकोण को नहीं अपनायेंगे, तब तक आपकी योजनाएं कागजों पर रखी रह जायंगी।

श्री गंगासिंह (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रजातंत्र में जब कि चारों तरफ सभी विभागों में उत्थान हो रहा है, राज्य सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उत्थान के लिये कम्युनिकेशन वगैरह के साधन ज्यादा से ज्यादा जुटाये जायं। उसका कारण यह है कि इसका असर राजस्थान की परिस्थिति से इसका सम्बन्ध होने के कारण ज्यादा पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक विभाग द्वारा जो सड़कों का निर्माण हुआ है, मैं सही रूप से यह कह सकता हूं कि सड़कों का निर्माण एक प्लान्ड वे के अंदर नहीं हुआ है। जहां पर सड़कों का निर्माण जहां तक हुआ है वह या तो पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स के कारण या अन्य फोर्सेज के कारण हुआ है जिससे मैं मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर जिस तरह से आवागमन के साधनों के जो सड़कें वगैरह का निर्माण होना चाहिये था उस तरह से नहीं हुवा है। अगर राजस्थान की सारी सडकों के निर्माण की ओर ध्यान देवें, मौजूदा हालत में कहां सड़क कैसी कैसी बनी हैं- इसकी ओर ध्यान दें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान के एक अमुक भाग के अन्दर सड़कों की भरमार हो जाती है तो दूसरी ओर कुछ भाग पर निगाह भी नहीं गई है सरकार की। मैं इस समय सदन का ध्यान उस इलाके की ओर आकर्षित करूंगा जो रेतीला स्थान है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोइंट आफ व्यू से सड़कों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए था लेकिन राजस्थान बनने के बाद आज दिन तक भी उस क्षेत्र की अवहेलना की गई है। वह क्षेत्र है – नागौर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जालोर डिस्ट्रिक्ट। मेरा निवेदन है इन क्षेत्रों से सम्बंधित है। आप सारे राजस्थान का माइलेज निकालें तो आपको मालुम होगा कि इस क्षेत्र की अवहेलना जिस हद तक हुई है उस हद तक किसी भी क्षेत्र की अभी तक अवहेलना नहीं हुई है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस समय जबकि आपके गांव बहुत दूर दूर माइलेज पर हैं और आवागमन के कोई साधन नहीं हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर यहां पर कम से कम तीन जो बड़े बड़े गांव हैं – तहसील हैड क्वार्टर या पंचायत हैड क्वार्टर, या पंचायत समिति हैड क्वार्टर– इन तीन बड़े बड़े गांवों को इन सड़कों के द्वारा मिलाना बहुत जरूरी हो जाता है।

(श्री गंगासिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं कि इस क्षेत्र के अन्दर अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय मैं सरकार का ध्यान ....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कोरम है या नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : कोरम होना चाहिए, साहब !

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या जरूरत है इनकी कुर्सियां सुन लेंगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आज कांग्रेस बेंचों पर कोई नहीं हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : घन्टी बजाये या किसी को मत आने दें।

श्री जोधसिंह चौहान ; कुर्सियां सुनती हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) आप वाले किधर चले गये हैं।

(गण-पूरक घन्टी)

(कुछ माननीय सदस्यों के आने पर गण पूर्ति हुई)

श्री गंगासिंह : अभी तक जो आपके विभाग के द्वारा सड़क बनाई गई है उसकी ओर ध्यान दे तो सड़कों के ऊपर मेटेरियल बिछाया गया है वह इतना कमजोर बिछाया गया है कि हर दूसरे या तीसरे साल बहुत ज्यादा रिपेयर आती है। मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो आपकी सड़कें बनें वह पुख्ता तरह से, इस तरह बनाई जांय कि उनकी रिपेयर बहुत जल्दी जल्दी न करानी पड़े। यहां तक आज स्थिति है कि जो मेटिरियल आपने प्रेसक्राइब किया है उस मेटिरियल का लगाने का पी० डब्ल्यू० डी० के इंजिनियर तथा ठेकेदार ध्यान नहीं रखते है, जिसके कारण यह होता है कि घटिया मेटिरियल लगाया जाता है और राज्य सरकार से पैमेन्ट अच्छे मेटिरियल का मिलता है। इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कम से कम जो जो सड़कें बनें उनकी ओर इस दृष्टि से पूर्ण ध्यान दें कि जो आपका काम हो वह ठोस काम जिसके कारण सरकार का बहुत पैसा बचाया जा सकता है।

इस समय मैं आपका ध्यान वैसी सड़कों की ओर दिलाऊंगा जो आपके डिफेन्स नीड्स से सम्बन्धित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक डिफेन्स रोड्स का सवाल है, सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी काफी तादाद में इन्हें मदद दी है परन्तु डिफेन्स की रोड्स का कनेक्टिंग लिंक स्टेट हाईवेज से जरूरी है, इसलिए मैं समझता हूं कि स्टेट हाई वेज जल्दी से जल्दी आपके पूर्ण होने चाहिए जिसके कारण आपकी इन सड़कों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सकता है। अभी तक आपकी जो स्टेट हाईवेज में सड़कें ली हैं उनमें से काफी तादाद के अन्दर वह सड़कें बन गई है लेकिन बीच में बीस तीस के टुकड़े रह गए हैं जहां सड़कें नहीं बनी हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कम से कम किसी सड़क का काम आप हाथ में लें उसको पूर्ण कर दिया जाय जिसके कारण उसका फायदा लोगों को मिल सके। यह नहीं होना चाहिए कि सात रोड्स एक

(श्री गंगासिंह)

साथ चलाई और सातो में इन्कम्प्लीट वर्क हो रहा है। इससे पैसे का भी दुरुपयोग होता है और रिपेयर्स भी ज्यादा करनी पड़ती हैं बाद में। मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो स्टेट हाईवेज हैं। जिन जिन स्टेट हाईवेज का काम बाकी है उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करा दिया जाय, उनमें आधा काम छोड़ना वाजिब नहीं होगा मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो स्टेट हाईवेज हैं जो कोटा से थावना को रोड है, यह स्टेट हाई वे का हिस्सा बन जाता है तो सुचारु रूप से हाई वे का काम हो जाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तीन चार मील का टुकड़ा है उसको बना दिया जावे।

श्री हरिश्चन्द्र : आप नाम बतावें।

श्री गंगासिंह : स्टेट हाई वे। थोड़ा सा टुकड़ा तीन चार मील का रह गया है, आप इसको जल्दी से जल्दी लें ताकि यह रोड पूरी हो जावे।

[समय समाप्ति सूचक घन्टी]

मैं आप को यह निवेदन करूंगा कि यह फेमिन से पैसे लगे हुए थे। २०-२५ हजार रुपया और लग जावे तो यह रोड कम्पलीट हो सकती है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कुछ रोड्स ऐसी हैं जो फेमिन के समय में बनी थी मगर वे इनकम्पलीट रह गई। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब लाखों रुपया सरकार का उन पर लग गया है। अधूरे तीन चार काम हैं, अगर आप उनको करा दें तो बहुत उचित होगा और अगर नहीं करा पायेंगे तो सरकार का उन पर जो रुपया फेमिन में लगा है वह व्यर्थ जायेगा। वह चऊछोरड़ा सड़क है। इसमें करीब करीब एक मील का टुकड़ा रहा है। अगर यह बना देते हैं तो यह टुकड़ा पूरा हो जाता है।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल (सिकराय सु.): सभापति महोदया, निर्माण को लेकर......

श्री रघुनाथ विश्नोई : इधर से आप की नाराजगी है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : पटेल साहब आपके यहां तो सब सड़कें बन गई हैं।

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल : मैं यह कहूंगा कि मेरे यहां १५ वर्षों में कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इस तरह से आप अपने डिपार्टमेंट से जानकारी करा लें। इधर एक मील की रोड़ नहीं बनी है। यह मैं नहीं कह सकता कि १७ सालों से वह क्यों नहीं बनी। यह कह सकता हूं कि वहां पर कोई सड़क १७ सालों में नहीं बनी। इसलिये मेरी यह मांग हो कि तहसील सिकराय में कोई निर्माण विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया गया है इसलिये सिकराय से बंदूका की घाटी के लिए मेरा निवेदन है।

इसी तरह गंगापुर रूट है इसको जोड़ देते हैं तो जनता को बहुत लाभ हो जाता है! आप इन ३ टुकड़ों को बना दें। दूसरे जिले हैं वे भी इससे कनेक्ट हो जावेंगे और टोडाभीम भी कनेक्ट होता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर विचार करेगी और मैं निश्चय भावना करके चलता हूं कि इसके बन जाने से बहुत ही सुधार होगा।

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

इसके साथ साथ मैं आपको पक्षपात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार भेद भाव की नीति फेमिन ओप-रेशन जैसे कार्यों को खोलने में बरतती है। जिस समय फेमिन के कार्य चलते है तो लोगों की भावना इस तरह की है कि जहां से ओपोजिसन के लोग जीत कर आये है वहां पर जनता के लिये कोई फेमिन राहत कार्य नहीं खोले जाते और जहां से कांग्रेस के लोग जीत कर आते हैं वहां पर खोले जाते है। इसलिए मैं यह कहुंगा कि इस तरह की भेद भाव की नीति वहां की जनता के साथ सरकार को नहीं बरतनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर जो सदस्य चुन कर आते हैं वे जनता द्वारा चुनकर आते हैं चाहे वे कांग्रेस के सदस्य हो चाहे दूसरी तरफ के हो वे जनता से ही तो आते हैं। इसलिये इस तरह की भावना मेरे इलाके में वरती जाना उचित नहीं है। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि सरकार इन तीन टुकड़ों को बना दे। या गंगापुर, टोडाभीम का रूट और सिकराय से बन्दूकोली गाडी। ये टुकड़े हैं मेरी तह-सील में जिनको आप बनवा दे ये २४ मील की सड़क होगी। इसलिये मैं इस पर ज्यादा सदन का समय नहीं लेकर यही कहूंगा कि यह २४ मील की सड़क दी जाये क्योंकि जल्दी ही चतुर्थ पंच वर्षीय योजना का कार्य शुरू होने वाला है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य के द्वारा निर्माण कार्य जालोर में पिछले कुछ वर्षों में कुछ ही नहीं हुआ हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान मेरे इस कटोती प्रस्ताव द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न भी रखा था और प्रश्न के रूप में जानकारी चाही थी। मैं कह सकता हूं कि जालोर जिला रोड डवलपमेंट में सबसे पिछड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि जालौर में उत्पा-दन के कितने रिसोर्सेज है और साधन है। मगर वहां पर रोड नहीं होने से यह जिला पिछड़ा हुआ है और वहां पर पैदावार होती है उसका वहां के किसानों को पांच पांच रुपया मदा देकर डिस्ट्रक्ट हैड क्वार्टर पर अनाज ले जाना पड़ता है। यहां पर इतने रिसोर्सेज और पोटेन्शियलिटी होते हुए भी सरकार ने इस जिले के साथ उदासीनता बरती है। इसलिये इसके लिए हमारे जिले के लोगों में बड़ा भारी असन्तोष है। अगर आप जालौर जिले के निर्माण कार्य के आंकड़े पिछले १५ वर्षों के देखें तो आपको प्रतीत होगा कि इस जिले में सबसे कम पैसा खर्च हुआ है। अगर यह पैसा कच्ची ग्रेवल रोड में खर्च किया गया हैं। जब जालौर में कबिनेट की बैठक हुई थी तब हमने सरकार से आग्रह किया कि यहां पर ग्रेवल सड़क बिलकुल उपयुक्त नहीं है। इसलिये यहां पर ग्रेवल रोड़ नहीं बनाई जावे। इसलिये केबिनेट से यह निर्णय लिया गया कि वहां पर या तो मेटल रोड या डामर रोड़ होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा, सांचोर आदि सड़क पर लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है। वहां पर लोगों को इतनी कठि-नाइये होती हैं कि वहां पर चार महीने वर्षा में मीन्स ओफ काम्यूनीकेशन बन्द हो जाते हैं और इसलिये मैं यह सरकार से निवेदन करूंगा कि रानीवाड़ा से सांचोर तक डामर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की सड़क बनाई जावे। मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद भी दूंगा कि ६ मील सड़क डामर की पिछले साल बनवाई है। काम जरूर चलता है मगर उसके बावजूद भी १० मील का टुकड़ा रहेगा और दो तीन मील तो ऐसा रास्ता है जहां नदियों का पानी इकट्ठा हो जाता हैं और चारों तरफ से तहसील कट ग्रोफ हो जाती है इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

अभी उप-मंत्री ने यह सूचना दी है कि सांचोर दांती, लाल छडी आदि के लिए कोई प्रोवीजन नहीं हैं। बोर्डर की इम्पोटेंन्स होने के नाते आपने इस पर पैसा खर्च किया है इसके लिए धन्यवाद। मगर इसके बावजूद भी अगर तीन मील का टुकड़ा अगर कोई प्रोविजन नहीं भी हो तो भी बनवा दें तो बहुत उचित होगा अन्यथा सारे मीन्स ग्रोफ कम्युनिकेशन बन्द हो जाते हैं। डिफेन्स पोइन्ट ग्रोफ व्यू को देखते हुए भी इस टुकड़े को पूरा कराया जावे ताकि रास्ता बन्द न हो और लोगों को आने जाने में असुविधा न हो।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, सारे जिले में हम देखते है कि ३४ मील डामर की सड़क हमको अब तक मिली है। पिछले इतने वर्षों में बजट मिलता हैं मगर हमको अभी तक ३४ मील की डामर रोड मिली हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा सारा जिला हैं उसमें अनाज पहुंचाना पड़ता हैं और सड़कें नहीं होने से लोगों को दिक्कत होती हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों को देखते हुए राज्य सरकार को इसके लिए निर्णय लेना चाहिए कि दूसरे रिसोर्सेज हैं उनसे इनको प्रायोरिटी देकर बनाई जावे। राजा महाराजाओं के समय में भी हम पिछड़े हुए रहे और अब भी रहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अहितकर होगा।

अब मैं पी. डब्लू. डी. विभाग से निवेदन करूंगा कि आप तीन प्रकार की सड़कें बनाते हैं। ग्रेबल रोड, मेटल रोड और डामर रोड। लेकिन कुछ रेगिस्तानी इलाका जैसे बाडमेर, जैसलमेर आदि हैं उसमें निकट भविष्य में कोई ऐसा प्रावधान सालों साल कम होता जा रहा है। और निकट भविष्य में वहां पर कोई रोड डेवलपमेंट की संभावना प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि फेअर वेदर रोड पर सरकार द्वारा एक पैसा भी वहां अब तक नहीं लगाया जाता है फेअर वेदर रोड पर रास्ता वर्षों में बन्द हो जाता हैं और प्राईवेट मोटर चलाने वालों को पांच-पांच और दस-दस हजार रुपया लगा कर उन रास्तों को ठीक कराना पड़ता हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि ऐसे फेअर वेदर रूट्स जो रेगिस्तान में हैं जो बहुत लम्बे लम्बे रूट हैं जिसके जरिये से मीन्स आफ कम्युनिकेशन चलते हैं उनको कम से कम साल में एक बार या दो बार सरकार की तरफ से रास्ते साफ कराये जाने चाहिये ताकि लोगों को असुविधा होती हैं वह दूर हो सके। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि ऐसे जिले बहुत थोड़े हैं जैसा हमारा जिला हैं। इसलिए इसमें ज्यादा रुपया सरकार को खर्च करना ही होगा इससे जनता की असुविधा भी दूर हो जावेगी। इसलिए मेरा यही निवेदन हैं

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कि इन तीन रोड के अलावा फेअर वेदर रोड जहां कनेक्शन नहीं है उनके लिए प्रावधान रख कर काम कराया जाना चाहिये। अगर सरकार इस पर ध्यान देगी और कार्य करेगी तभी इस एरियां का विकास हो सकेगा वरना यह इलाका भविष्य में भी पिछड़ा हुआ रहेगा।

[समय-समाप्ति सूचक घंटी]

अगर यह इलाका पिछड़ा हुआ रहेगा तो सरकार को भी इससे बड़ा भारी नुकशान उठाना होगा।

श्री चोसरसिंह यावेल (बेगूं): उपाध्यक्ष महोदय मेरा भी कटौती का प्रस्ताव है सरकार निर्माण कार्य में खर्चा करने में असफल रही है इस सिल सिले में मेरा यह निवेदन है कि राना प्रतापसागर और सिगोली से भैंसरोड़ गढ़ तक सड़क बन गई और पुलिया नहीं बनाया गया इसलिए लोगों को बड़ा कष्ट होता है। चौमासे में भी इसी तरह से रहता है। लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च किया है वह भी बेकार है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन पुलियाओं को जल्दी बनाना चाहिए, जिससे कि जनता को राहत मिले।

इसी तरह से बेगूं से नन्दवाई और वहां से नानखेड़ा तक जाने वाली सड़क जहां रोजाना बसें चालू है, जहां जनता से श्रमदान कराया गया पर इस आश्वासन के बावजूद कि सड़क बना दी जायगी, उन लोगों ने पन्द्रह, बीस हजार का श्रमदान किया है फिर भी बेगूं से नन्दबाई सड़क नहीं बनाई है। इसे पंचायत समिति करे, चाहे सरकार करे पांच सात मील लम्बी सड़क है, वह बननी चाहिये। पर जनता के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि १५=२० हजार रुपये का श्रमदान करा लिया और सड़क नहीं बनाई यह सरकार के लिए शर्म की बात है।

इसी तरह से चेची से बेगूं तक सड़क जाती है, बेगूं से पालनपुर तक सड़क बनाना जरूरी है क्योंकि चित्तोड़ कोटा से बूंदी जाने वाली सड़क बेगूं से वापिस काटूंदा तक जाती है और फिर काटूंदा होकर बूंदी जाती है ७ मील का चक्कर डेली सब बसों को पड़ता है। बूंदी कोटा, मानख गढ़, भैसरोडगढ़ जाने वाली बसें निकलती हैं और भी गाड़ियां जाती है, उन्हें बेगूं जाकर इस रोड़ पर जाना पड़ता हैं तो मेरा निवेदन है कि पालनपुर बेगूं से दो मील हैं, यह सड़क जल्दी से जल्दी बना दी जानी चाहिये ताकि बसों को भी दिक्कत नहीं हो और मुसाफिरों का भी समय बचे।

इसी तरह से मेंदार से खाननगढ़ तक खानें बनी हुई हैं, वहां हजारों मजदूर जाते हैं, खानों का पत्थर निकलता हैं पर पत्थर ले जाने का सड़क के अभाध में साधन नहीं है। मील और दूसरे लोग खानों पर पत्थर खोदते हैं, सड़क नहीं होने से उनके पत्थर की खपत जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं होती है। मैंदान से खानलगढ़ सड़क बना देने से ये खदानें भी कामयाब हो सकती है, हजारों मजदूरों और गरीब लोगों का इससे फायदा हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार विचार करे और इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाये।

इसी तरह पारसोली पुलिस स्टेशन के टेन्डर कई बार लिये गये पर वह अभी तक नहीं बनी है। बेगूं बड़ा कस्बा है, तहसील

(श्री चोसरसिंह बाबेल)

हैड क्वार्टर है, वहां डाक बंगला नहीं है, इस पर विचार करना चाहिये। सरकार जनता से करोड़ों रुपया टैक्स का लेती है पर डाक बंगले नहीं बनाती, सड़कें नहीं बनाती है, मोटरों बसों की तादाद बढ़ाती है।

७ करोड़ २८ लाख की राशि इसमें रखी हैं मैं निवेदन करूंगा कि इसमें खर्च करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ५ हजार से ऊपर की आबादी के कस्बों को जिला हैड क्वार्टर और तहसील कार्यालयों से मिलाने का पंचवर्षीय योजना में रखा है, उन्हें पूरा करना चाहिये। बेगूं से जिला हैड क्वार्टर मिला हुआ नहीं है, राणा प्रतापसागर सड़क जाती है, तहसील हैड क्वार्टर बेगूं में है और जिला हैड क्वार्टर चित्तौड़ है ये मिले हुए नहीं है, इसलिए आपकी स्कीम कामयाब नहीं हुई है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि जब ४ मील दूर पर योजना के अन्त में पक्की सड़क के लिए और डेढ़ मील कच्ची सड़क के लिए इन्दराज किया है तो यह बनाना चाहिये।

डाक बंगलोज आपके अन्डर में हैं हमारे साथ क्या रियायतें हैं? मैं बूंदी रेस्टहाऊस में ठहरा तो एक दिन के २० रुपये चार्ज किये कहा कि सर्किट हाऊस हो गया है वहां कमरे में १ खाट और २ कुर्सियां थी और कुछ नहीं, मैंने २० रुपये दे दिये बहस नहीं की। चितौड़ में हमारी विरोधी पार्टी के नेता डाक बंगले में ठहरे उनसे ५ रुपया चार्ज किया। यहां ऐसा ऐलान हुआ था कि गेजिटेड आफिसर के साथ रियायत है नहीं आपके साथ रियायत की जायगी।

श्री परसराम मदेरणा : (उप-मंत्री वित) आपको डाक बंगले की सहूलियत है आप सर्किट हाऊस में क्यों ठहरे बूंदी का सर्किट हाऊस है डाक बंगला नहीं है। मेरे पास जी.ए.डी. थी मुझे पता है आप सर्किट हाऊस में ठहरेंगे तो २० रुपये चार्ज करेंगे ही।

श्री चोसरसिंह : बूंदी में डाक बंगला मौजूद है जहां रेस्ट हाऊस लिखा है।

श्री परसराम मदेरणा : डाक बंगले में ठहरे?

श्री चौसरसिंह बाबेल: मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं डाक बंगले में ठहरा हूं। सर्किट हाऊस में नहीं ठहरा। अगर ऐसा होता तो सदन में नहीं कहता। २० रुपये की बात नहीं कहता। हम लोगों के साथ इस प्रकार का अगर होता है तो गरीब जनता के साथ क्या होता होगा। यह बताता हूं!

तो मैं निवेदन कर रहा था कि बजट की पूर्ति करें जैसे करोड़ों रुपया टेक्स का जनता से लेते हैं तो जनता के हित में भी आपको खर्च करना चाहिये। मेरे क्षेत्र में ७ हजार की आबादी का कस्बा होते हुए भी बिजली नहीं लगाई गई है, नल नहीं लगाया है बेगूं जैसे कस्बे को आपने इस तरह से छोड़ रखा है जिसने आजादी की लड़ाई में इस प्रकार का योगदान किया कि जिसकी मिसाल नही सिवाना में गोलियां चली थीं तो बेंगू ने आगे चलकर अनाज दिया फिर बेगूं के साथ इस प्रकार का व्यवहार उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता हैं। बेगूं की जनता में आजादी के लिए लड़ने की ताकत है। देश की रक्षा के लिये लड़ने की ताकत है। २२ में आन्दोलन करके बेगूं की जनता ने सामन्त शाही सरकार को झुका दिया था। उनकी शिकायतों के बारे में नहीं सुनते हैं तो यह वहां

(श्री चोसरसिंह वाबेल)

की जनता के साथ अन्याय है अत्याचार है, इस प्रकार का अन्याय वह सहन नहीं करेगी। मै राजा साहब आपसे उम्मीद करता हूं आपसे हमें बड़ी बड़ी उम्मीदें है हम आशा करते हैं कि बेगूं में आप बिजली लायेगे ऐसा नही करेंगे तो जनतन्त्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, जनतन्त्र का गला घोंट रहे हैं और इसका फल भोगना पड़ेगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्लू.डी. की डिमाण्ड हमारे सामने है, यह ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हजारों लाखों के घोटाले हैं इस पर अच्छी तरह से निगरानी की जाय, इसको बपौती नहीं बनाया जाय तो इस डिपार्टमेंट का सुधार हो सकता है। उदयपुर में जो हमारे वहां के एग्जीक्यूटिव सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर हैं वे वहां कई वर्षो से कायम हैं, और वे इसलिए वहां कायम है कि वे मन्त्री महोदय के प्रिय हैं, मुख्य मंत्रीजी के प्रिय हैं। कई ज्यादतियां उनकी हैं, तीन तीन हजार की जगह उन्होंने ३०–३० हजार का पेमेंट किया है,एक सड़क को बिना बनाये चार चार बार पेमेंट किये हैं। वहां सड़कें बनाई हैं, कई बार नपौती भी हो चुकी है इसमें सरकार को नुकसान दिया जाता हैं।

जो नेशनल हाई वे बना हुआ है, कांकरोली से जाता है, डूंगरपुर होता हुआ, ईडर से आकर मिलता हैं, उसमें कई माइल्स पर घोटाले हैं, मैंने कई बार क्विशचन्स पूछ पूछ कर सरकार को आगाह भी किया है। कई मीलों पर डबल-ट्रिपल पेमेंट किया है इसलिए इसकी जांच होनी चाहिये। सरकार से निवेदन है कि इन्जीनियर महोदय के खिलाफ कई बार रिपोर्ट की हैं, उनकी जांच होनी चाहिये। सरकार को आगाह किया है कि तीन हजार की जगह तीस हजार पेमेंट किया है। यही नहीं जितनी बिल्डिंग्स वहां बनी हैं वहां उनकी छतें ऊपर से नीचे गिरने वाली हैं। देख रेख ठीक नहीं की गई। विभाग ने घोटाला कर रखा है। वह व्यक्ति ७ साल से वहां रह रहा हैं क्योंकि वह खुद के ही व्यक्ति हैं। जो उनके खुद के प्रिय हैं वह उनको ही वहां रखते हैं। एक खानसामा है उनके साथ वह मोटर में घूमते हैं, वह टी०ए०डी०ए० लेते हैं। इस प्रकार इस विभाग के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इस अधिकारी का स्थानान्तरण होना चाहिए। शायद आप सोचते होंगे कि चुनाव आने वाला है, उनका गढ़ कायम करने के लिए ७ साल के बाद भी उनको रखना चाहते हैं। अगर वह सरकार का प्रिय आदमी है तो आप जाकर उनको झालावाड़ में रखें। उदयपुर से इनको हटाया जाय इससे वहां के मजदूरों को भी राहत मिल सकेगी। उदयपुर में तो बड़े बड़े काम हो गए. वहां लम्बी चौड़ी सड़कें बन गई बाकी हमारे गिरवा क्षेत्र में कहीं सड़क नहीं है। गिरवा क्षेत्र में उदयपुर से जामेश्वर, वहां से जगत वहां से जिगला और बंबोरिया, इस प्रकार की रूट आती है। मेवाड़ के समय जैसी सड़क बनी थी उससे भी खराब है। आज वहां पंचायत समिति द्वारा मिट्टी डाली जाती है। इतनी पुरानी सड़क है, मेवाड़ के समय तो पक्की सड़क थी लेकिन राजस्थान बनने के बाद तो उसकी मरम्मत भी नहीं हुई। विभाग ने गैंग

(श्री जोधसिंह चौहान)

नियुक्त कर रखें हैं, दो चार गैंग्स हैं लेकिन वे काम नहीं करते। न मालूम वे गैंग्स कहां जाकर काम करते हैं। उस सडक को पक्का बनाना चाहिए। मेवाड के समय वह सबसे बड़ी सड़क थी। कई लोग वहां मोटर चलाना नहीं चाहते हैं। परमिट भी मिला है, थोड़े दिन चलाते हैं फिर चलाना बंद कर देते हैं। आज मंभोरा से आगे मोटर नहीं जाती। क्योंकि उनकी मोटर खराब हो जाती है, टायर्स खराब हो जाते हैं।

इसी प्रकार ढांढोर की सड़क है। उसमें खराब काम हो रहा है। जालोर की सडक पर सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर नाराज है। एक बहुत बड़ा कस्बा है उसमें कई व्यापारी रहते लेकिन नाई में से होकर सडक नही निकाली और एक दो मील और निकाली गई। आज लोगों को उदयपुर में आने के लिए दो नदियां पार करनी पड़ती हैं। वहां पर उदयपुर जाने वाली सड़क है, वहां पर तिजारा गांव आता है, वहां आप पुल बनाएं। वहां पर मोटरें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पेसेंजर्स मिलेंगे। नाई के पास में कई व्यापारी रहते हैं वहां मिडिल स्कूल है वहां हाई स्कूल बनना चाहिए।

यही नहीं कई जगह सड़कों के निर्माण में घोटाला है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जालोर सडक पर कितने दिनों से काम चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस सडक को पक्का बनाया जाय। वहां एक गांव है डीडावली। लोग मीलों से पहाड़ियों से सामान ढोकर लाते हैं। मीलों चक्कर उदयपुर में आते हैं, व्यापारिक सामान भी लेकर आते हैं। अगर वहां पर ४-५ मील की सड़क का टुकड़ा बनाया जाये तो लोगों को सुविधा होगी। अगर आप उसको उदयपुर नगर से जोड़ दें। तो जनता को लाभ हो सकता है। उदयपुर हमारा टूरिस्ट केन्द्र है, भारत के नक्शे में उदयपुर का विशेष स्थान है, वहां पर चारों तरफ कई लेक्स ,हैं तालाब हैं। जितनी लेक्स हैं, जितनी भीलें हैं उनको पक्की सडकों से जोड़ना चाहिए।

उदयपुर के पास सज्जनगढ़ स्थान है वह मौजूदा महाराना ने फ्री आफ चार्ज राज्य सरकार को दे रखा है और जनता के देखने के लिए दिया है। सरकार को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वहां मरम्मत हो रही है। महाराना के समय यह सड़क पक्की थी लेकिन अब मिट्टी डाल दी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उदयपुर नगर में टूरिस्ट्स आते हैं तो उस स्थान को देखने के लिए जाते हैं। लेट महाराना के दिनों लोग पिकनिक के लिए जाया करते थे। आज टूरिस्टस लोग बिना देखे नहीं रहते। वह स्थान ऐसा है जहां से उदयपुर का सारा का सारा दृश्य देखा जा सकता है। वहां की सड़क उदयपुर से होती हुई सज्जनगढ़ जाती है। जहां पर राजमहल है वहां पर कुछ सड़कें हैं २०–२५ गज दूरी पर। टूरिस्टस आते हैं तो सरकार ने टिकट लगा रखा है और कई रुपयों की आमदनी होती है। तो उन सडकों को बनाना चाहिए। ऐसे स्थानों को जहां से सारा उदयपुर दीखता है उसको इस प्रकार निगलेक्ट किया जाय यह दुख की बात है। मैं समझता हूं ५०-६० गज का टुकड़ा सड़क का बनना चाहिए। उसमें खड्डे खोद रक्खे हैं। वहां की बिल्डिंग्स पी. डबल्यू. ड़ी. के अधिकार में हैं, टिकटों से सरकार को हजारों रुपए

Page No.76

(श्री जोधसिंह चौहान)

की आमदनी होती है। महल के अन्दर पुराने पेंटिंग्स हैं उनको नया करवाना चाहिए वह कला देखने जैसी है, इतनी पुरानी संस्कृति और पुरानी कला नष्ट नहीं होनी चाहिए।

उदयपुर टूरिस्ट नगर है उसके पास में ब्रह्मपुरी का स्थान है। अगर उसका भी सर्वे कराएं तो वह स्थान भी उपयुक्त बन सकता है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, देश के निर्माण में और देश के विकास के संबंध में सबसे मुख्य चीज मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स हैं। जिस राज्य में और जिस देश में ये साधन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हों, वह देश जल्दी से जल्दी प्रगति करता है। अगर आज से १७ वर्ष पूर्व का हम राजस्थान का नक्शा देखें कि राजस्थान में किस प्रकार सड़कों क साधन थे तो यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने १७ वर्षों में किस प्रकार सड़कों का निर्माण करके देश को प्रगति की ओर बढ़ाया है।

इसमें कोई शक नहीं हैं कि राजस्थान में सीमित साधन होते हुए भी जैसा कि यह पिछड़ा हुआ प्रान्त था इसमें खास तौर से उदयपुर डिविजन के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि १७ वर्ष पूर्व एक भी ऐसी सड़क नहीं थी जहां कोई डामर का सवाल हो, कोई भी मेटल्ड रोड़ नहीं थी।

श्री दयाचन्द सोन (बारां सु०): १७ वर्ष पहले आपका पता ही नहीं था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका पता नहीं था, श्रीमानजी।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान ने इस मामले में जिस प्रकार प्रगति की हैं और अपने सीमित साधनों को देखते हुए भी जिस प्रकार से बड़े बड़े नगर, जिले के हैडक्वार्टर, तहसील और एस. डी. ओ. के हैड क्वार्टर को मिलाने का प्रयास किया है वह तो सराहनीय चीज हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह चाहते हैं कि राजस्थान इस ओर ज्यादा से ज्यादा प्रगति करे और गांव गांव को मिला कर आवागमन के साधन ज्यादा से ज्यादा बढ़ें तो हमारा प्रान्त और भी विकसित हो सकता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिस प्रकार काम किया है उसमें और तेजी लाई लाने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि छोटे से छोटा गांव जहां जहां इस प्रकार की वस्तुयें है जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की आवश्यकता है वहां पर सड़को के साधन नहीं होंगे तो नहीं भेजी जा सकेंगी और प्रगति में बाधक होंगी इसलिये सीमित साधनों के होते हुए भी कुछ इस प्रकार का प्रयास करना चाहिये कि एक गांव से दूसरा गांव, एक पंचायत से दूसरी पंचायत और पंचायत समिति के हैडक्वार्टर को मिलाये ताकि आवागमन के साधनों में प्रगति हो सके।

नेशनल हाई वे ब्यावर से उदयपुर को जाता है। यह सड़क हाई वे ब्यावर से जस्सा खेड़ा, भीम होकर उदयपुर जाता है। जस्सा खेड़ा के पास बड़ा जिकजेक है। एक्सीडेन्ट हो जाते हैं वहां। इस रास्ते को ठीक करें तो एक नेशनल हाई वे ब्यावर से बदनोर होकर भीम चला जाय और वहां से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उदयपुर चला जाय तो कोई इस प्रकार का रास्ता नहीं मिलेगा कि जहां पर एक्सीडेन्ट का खतरा हो और माईलेज में भी एक डेढ मील का फर्क पड़ता है। यह सुझाव पहले भी निवेदन किया था किन्तु पता नहीं किन कारणों से उन पर गौर नहीं किया जा रहा है और यदि इस ओर गौर किया जावेगा तो टूरिस्ट्स लोग; जहां तक लम्बे रास्ते तय न करने का सवाल हैं, जयपुर से उदयपुर और अहमदाबाद जाते हैं उनको सुविधा हो जावेगी और जो जिक जेक से खतरा होता है उससे भी बच जावेंगे। ब्यावर से बदनोर बदनोर से भीम और आगे वही रास्ता है। बीच में जस्सा खेड़ा होकर जाती है सड़क । पहाड़ी क्षेत्र हैं। एक्सीडेन्ट हुए हैं और बड़ा खतरनाक रास्ता है अगर यह रूट जो मैंने बताया वह लिया जावेगा तो सुविधा होगी।

ब्यावर से भीलवाड़ा की सड़क मंजूर की है। उसमें कई माइलेज अधूरे पड़े हुए हैं। न पुलिया है और दूसरे वर्क भी नहीं हो पाये हैं। यह ७० मील का रूट है उसकी वजह से आप दो मंडियों को, ब्यावर और भीलवाड़ा को मिलाते हैं। तहसील हैडक्वार्टर और पांच चार गांव ऐसे हैं जो चार चार हजार जनसंख्या के हैं उनको मिला दिया जावेगा तो व्यापारिक तरक्की होगी और मंडियां और तहसील हैडक्वार्टर मिल जावेगी तो तरक्की होगी। दो नदियां बीच में पड़ती हैं। बरसात में रास्ता रुक जाता है। नेखड़ी और खारी नदियां पड़ती हैं। पुलिया के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। चाहिए तो यह कि सड़क का निर्माण हो तो साथ साथ पुलियाओं का भी निर्माण होना चाहिये। ताकि आवागमन में रुकावट नहीं आवे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी इम्पोरटेन्ट सड़क हैं, बीस पच्चीस बसें रोज जाती है और काफी ट्रकें जाती हैं और यह सड़क दो मंडियों को मिलाती हैं ब्यावर और भीलवाड़ा ऐसी सड़क जो एक दूसरी मंडी को मिलाती है उस पर पुलियाओं का निर्माण आवश्यक है। इसलिये खारी और नेखड़ी पर पुलियायें बनायें और डामर करवा देंगे तो जोधपुर जाने के लिये भी सुविधा होगी

आसींद – गुलाबपुरा की सड़क के लिये निवेदन करना चाहता हूं। इसको तीसरी प्लान में रखा गया था। पता नहीं किस कारण से उसको उससे हटाकर चौथे प्लान में रखा गया। सरकार का यह आश्वासन था कि तहसील और एस. डी. ओ. के हैडक्वार्टर को मिलाया जावेगा। इस पर निर्माण का कार्य नहीं हुआ है इसको बनाया जाय।

फेमिन में इस सड़क पर काम हो रहे हैं उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अलाटमेंट दिया है वह दातड़ा के पास होकर दिया है जब कि अंटाली और खेजड़ी पंचायत के हैडक्वार्टर है और उसी रोड़ पर पड़ते हैं, मिट्टी भी पड़ी हुई थी, फेमिन वर्क भी हुए थे, उसको छोड़ कर दूसरी तरफ अलाटमेंट दिया जा रहा है। मैं मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सड़क को अंटाली और खेजडी होकर ले जायी जाय।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: आपका कटौती प्रस्ताव एक है और पोइन्ट बहुत हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दो और हैं।

वर्क चार्ज स्टाफ के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पी. डब्ल्यू. डी. का वर्क चार्ज स्टाफ हैं उसको टी. ए. डी. ए. नहीं दिया जा रहा है जबकि रूल्स में प्रोवाइड किया हुआ है, गवर्नर द्वारा स्वीकृत है, लेकिन तमाम उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको नहीं दिया जाता। चित्तौडगढ़, उदयपुर में दिया जा रहा है लेकिन सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, उदयपुर की हठधर्मी की वजह से भीलवाड़ा के वर्क चार्ज स्टाफ को नहीं दिया जा रहा है। बीस बीस, तीस तीस, पैंतालीस माइल एरिया में एक सड़क से दूसरी सड़क उनको घुमाया जाता है लेकिन उनको टी.ए.डी.ए. नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करावें। एक गेंग के लिये आठ दस मील रखा जाता है जब कि इनको बीस पच्चीस मील दूर फेंका जाता है और इस प्रकार की गडबडियां रही हैं कि उनको टी.ए.डी.ए. भी नहीं दिया जाता है इस कारण उनमें बड़ा असंतोष है।

आसींद भीलवाड़ा सड़क सवाई भोज का तालाब पड़ता है। तालाब में पानी आता है तो पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क है वह डूब जाती है, सड़क पर पानी आ जाता है उसके लिए पुलिया के लिए कई बार निवेदन किया लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। इसी प्रकार......

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत इसी प्रकार हैं अभी.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : मि० चपलोत हैं उनके लिये तो निवेदन करना बहुत ही जरूरी है। उनके विरुद्ध पिछले साल कई शिकायतें कीं। फेमिन वर्क्स कराये, मस्टर रोल फर्जी और झूठे पेमेंट कराये। खास तौर से दौलतगढ़ से लाछोड़ा, आसींद से करेडा रोड पर हो रहा है। उनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें हुई हैं। माननीय मिनिस्टर उन के खिलाफ ध्यान देकर एक्शन लेंगे।

(३. म. प.)

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे एरिया के बारे मे निवेदन करना हैं वैसे हमारी सरकार ने यातायात के विषय में, इसको ध्यान में रखते हुए सड़कों का कुछ निर्माण किया है लेकिन वह गति मन्द है। मैं इस बारे में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब से मिला गत साल मिला था उन्होंने गोगुन्दा से झारोला तक परमिट दे रखा है वहां पर कुछ सड़कें हैं, वहां से टेक्सेशन वगैरह का पैसा आता है लेकिन इन रोड्स को पक्का बनाने का आपने सोचा तक नहीं।

गोगुन्दा से कोठड़ा तक की सड़कों के लिये मैंने मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी आपने यह भी फरमाया कि इस पर ध्यान जरूर देंगे लेकिन वहां पर ऐसा है कि गोगुन्दा से कोठडा तक काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। पुलियों का निर्माण भी बहुत कम हुआ है चार छः पुलिया जरूर बनी हैं लेकिन ये भी अधूरी हैं मेरा आपसे निवेदन है कि इनको पूरा करवाया जाय।

जून के महीने में जब मुख्य मंत्री महोदय वहां पधारे उस समय वहां के लोगों ने

(श्री ललितमोहन)

प्रार्थना पत्र दिया था इसके उपरांत भी प्लानिंग इन्जिनीयर साहब द्वारा नकशा बनाकर भेजने के बाद भी गोगुन्दा से सराड़ा के बीच जो सात मील का टुकड़ा हैं जो सड़क राणकपुर को जाती है। मानपुरा जो आदीवासी क्षेत्र है। वहां छोटे छोटे सडकों के टुकड़े ऐसे रह गये हैं जिनको मिलाना बहुत जरूरी है। सराड़ा से मानपुरा तक मिलाने का प्रयत्न करना चाहिये। प्लानिंग इन्जिनियर ने नकशा बनाकर भेज भी दिया है लेकिन चार बरस से उस बारे में कार्यवाही नहीं हुई है। गवर्नमेंट को यह सात मील का टुकड़ा है उसे ठीक करना चाहिए क्योंकि यह पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां के लोगों को आवागमन की सुविधा हो सकती है।

आज से कुछ दिनों पहले मैं पी० डब्लू-डी० मिनिस्टर साहब से मिला था झालोरा से गोगुन्दा गोगुन्दा से मानपुरा, गोगुन्दा से नादेश्वर ऐसे टुकड़े हैं जो कच्चे बने हुए हैं उनको मरम्मत कराने के लिये मैंने निवेदन किया। लेकिन कुछ नही हो रहा है मैंने कहा ये सड़कें पी० डब्लू० डी० में ले लो उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया। हमारा तो बस इतना ही है कि हमें कोई तकलीफ हो तो डाक्टर के पास चले जाते है यदि डाक्टर ही यह कह दें कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिए। इतना वे कह सकते थे हम इसको छः महीने बाद या साल भर बाद लेंगे यह कहते तो हमें कुछ सन्तोष हो जाता। लेकिन जिस तरह का जवाब दिया उसको मैं अच्छा जवाब नहीं कह सकता।

हमारा उधर का सारा इलाका पहाड़ी इलाका है शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से वह बहुत पिछड़ा हुआ है इसका मुख्य कारण यातायात की कमी भी है। यातायात के साधनों में सुधार नहीं हुआ तो यह पिछड़ा हुआ इलाका पिछड़ा हुआ ही रह जायगा।

मुख्य-मंत्री सुखाड़िया साहब के होने की वजह से उदयपुर में सड़कों का जाल बिछ गया है। उदयपुर के इन्टीरियर में आप जाकर देखेंगे तो पचास साठ मील का इलाका है। वहाँ पर बच्चों की पढाई का इन्तजाम नहीं वहां छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं, उनके लिये सामान को इधर उधर लाने की व्यवस्था नहीं। सड़कों के नहीं होने की वजह से डाक्टर लोग वहां जाते नहीं मास्टर नहीं पहुंचते। उत्पादन हम बढ़ाना चाहें तो कम्प्रेसर आदि हम लेजा नहीं सकते। यातायात के साधनों के अभाव की वजह से वहां कुछ भी उन्नति नहीं हो पाती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय उधर अवश्य ध्यान करेंगे।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग के बारे यहां चर्चा हो रही है उस सम्बन्ध में मेरे भी कई कटमोशन्स हैं। मैं भी मेरे इलाके में जो कुछ कार्य हुआ है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट की ओर खींचना चाहूंगा। सवाई माधोपुर एक ऐसा स्थान है सिनरी के लिहाज से वह बहुत ही शोभनीय है। रणथम्भोर का किला वहां पर प्रसिद्ध किला है। इस किले को जो सड़क जाती है वह दरवाजे तक ही जाकर रह जाती है। वह मन्दिर दुर्ग किला वहां से करीब पांच

(श्री श्रवणलाल)

छः मील के करीब रह जाता है। यातायात की असुविधा की वजह से सड़क के नहीं होने के कारण बहुत से यात्री उस सीनरी को देख नहीं पाते। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सड़क वहां तक लेजायी जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह पांच छः मील का टुकड़ा है उसको पूरा कराया जाय जिसके कारण वहां पर अधिक से अधिक यात्रीगण आ सकें उस दुर्ग को देख सकें यह हमारा बहुत प्राचीन काल का दुर्ग है।

इसके साथ ही आज हमारे यहां की सड़कों की हालत को देखा जाय बहुत ही विचारणीय है। उपाध्यक्ष महोदय पहले भी मैं इस बारे में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से भी मिला था। कोटड़ी से जो सड़क जाती है उसकी हालत कितना खराब है जिस सड़क से सरकार को दो लाख की इनकम होती है वह रोड माइन्स विभाग द्वारा जहां से पत्थर निकाला जाता हैं उस जगह तक जाती है। इससे हर साल लाखों रुपयों का फायदा होता है। यह सड़क अगर अच्छे ढंग से बन जाती है तो मैं समझता हूं यह सरकार के लिये भी बहुत फायदेमन्द है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा इस सड़क से जहां से लाखों रुपयों को सालाना इनकम होती हैं जल्दी से जल्दी इसको डामर रोड बनाया जाय। इसके बारे में पहले वाले मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था इस सड़क को पहले लिया जायगा। लेकिन दस बारह बरस हो चुके मिट्टी डाल दी गई हिन्डौन से धुआ मानपुर, अभी तक जिन काश्तकारों की जमीन उसमें आयी है उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया, लेकिन मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। दस बारह वर्ष से मिट्टी डालकर बनवा दी गई लेकिन आज तक पता नहीं कब तक उस सड़क पर मिट्टी डला कर तैयार करवाया जायगा। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस सड़क की ओर आकर्षित किया, मैं फिर उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सड़क बहुत पुरानी हो चुकी है, जल्दी से जल्दी इसको पक्का किया जाय, ताकि किसान को सुविधा मिल सके, बरसात के दिनों में जो आवागमन रुक जाता है, किसान अपना अनाज नहीं ला सकता, इसलिये सब सुविधाओं को देखते हुए इस सड़क को बनाया जाय।

इसके साथ ही माध्यमिक शाला की एक बिल्डिंग है वह बिल्डिंग स्टेट के जमाने की थी। वहां स्कूल चल रहा है, स्टेट के जमाने में वह तहसील थी। बिल्डिंग लाखों रुपयों की लागत की है, उसकी बहुत दुर्दशा हो रही है कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। खिड़कियां टूट गई, दरवाजे टूट गये, लेकिन मरम्मत उसकी हो नहीं रही इसके बारे में मैंने प्रश्न भी पूछा था जिसका उत्तर दिया गया कि जल्दी से जल्दी रिपेयर करवा दी जायगी।

मैं फिर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो लाखों रुपये की बिल्डिंग आज वहां क्रेक हो गई हैं और होने के कारण वह बर्बाद होने जा रही है इसलिए उस बिल्डिंग को आप रोकें और उसकी मरम्मत की जाय।

इसके साथ साथ हिंडौन से खेड़ली जाने वाली रोड जिस पर काफी चर्चा पहले भी हुई हैं कि बड़ा गांव खेड़ला से खेड़ली के लिए जो बस जाती है उसकी सड़क आज

(श्री श्रवणलाल)

तक नहीं बन पाई है। माननीय मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि यह जो तीन मील की सड़क है वह भी शीघ्र ही बना दी जायेगी क्योंकि बाकी सड़क बन चुकी है। यह तीन मील का एक छोटा सा टुकड़ा ही बाकी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तीन मील के टुकड़े से जो बस चलती है उसमें कितनी मुसीबत होती है। वहां पर रेता इतना है कि जो भी अपनी बैल गाड़ी वहां पर ले जाता है उसको कितनी परेशानी और दिक्कत उठानी पड़ती है वह एक अति अशोभनीय है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी सड़क जहां पर किसानों का रोजाना का आना जाना रहता है, मण्डी और शहर का आवागमन रहता है, उसको तुरन्त बना दिया जाय।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर का है कि डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बनाने की हैं और डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर के जमाने में वे बनी हुई हैं। आज उन सड़कों की हालत देखी जाय तो पता लगेगा कि उनकी हालत कितनी खराब हो गई है। उन सड़कों का किस तरह से निर्माण कराया गया था और उन पर कितना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पैसा खर्च हुआ था। तो वे सड़कें आज इतनी गम्भीर हो चुकी हैं, इतनी नष्ट हो चुकी हैं कि उनके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जितनी भी सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने में बनी हुई हैं और जो उनकी सड़कें हैं उन सब सड़कों को पी. डब्ल्यू. डी. में मिलाना चाहिए, जिसके कारण कि जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो कि इा समय बर्बाद होने जा रही हैं, वह सड़कें इस विभाग के अन्तर्गत आकर उनकी देखरेख और अच्छी तरह से सार सम्भाल हो सके :

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो हमारी सड़क खरेटा हिण्डौन से······

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

होती हुई मासलपुर के लिए जाती है और जहां से पत्थर निकलता है। उन खानों को मिलाती है। दस साल से इस मासलपुर सड़क की मांग की जाती रही है वहां पर गाड़ियां भी पहुंच गई, लेकिन क्या कारण है यह मेरी समझ में नहीं आता कि जिसकी वजह से यह सड़क नहीं बनाई जाती है। जहां से एक नजदीक रास्ता पड़ता है मासलपुरा का वहां से पत्थर की खानों का बहुत बड़ा अहम् इन्कम का जरिया है इस लिए क्यों नहीं उसी सड़क को बनाया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उस सड़क को जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बनाया जाय तो मैं समझता हूं कि जो पत्थर की खानों से आमदनी होती है वह भी काफी बढ़ सकती है। इसलिए ऐसी सड़क को तो सबसे पहले लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर सबसे बैस्ट मेला जिसमें लाखों लोग आते हैं वह केला देवी का लगता है। इस केलादेवी को जो रोड जाती है वहां पर आए दिन यह घटनाएं होती हैं और मेले के समय पर तो वहां पर एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेण्ट होते हैं। इसका कारण यह है

(श्री श्रवणलाल)

कि वहां जो सड़क बनी हुई थी वह स्टेट के जमाने की बनी हुई थी और वह स्टेट की इतनी छोटी सड़क थी कि उसे तो कभी कभी शिकार खेलने के लिए, या केला देवी के दर्शनों के जाया करते थे तब इस्तैमाल करते थे। आज वहां जो मेला भरता है और जिसमें लाखों लोग देश विदेश के आते हैं और उस मेले के समय इतना रश हो जाता है, तांगा, मोटर, साइकिल वगैरह का और उस सड़क की इतनी उपलब्धि नहीं होने, इतनी चौड़ी नहीं होने के कारण वहां पर हर साल काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंटों के कारण वहां पर ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कि जिसके कारण बहुत से आदमियों को

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

परेशानी होती है और उन एक्सीडेंटों में बहुत से आदमी खत्म हो जाते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उस सड़क को अपने विचारार्थ लेकर उसको चौड़ा कराया जाय।

(समय-समाप्ति सूचक लगातार घण्टी)

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमुवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने मूलचन्दजी के लिए कहा है, यदि आप उनकी सहमति से बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तहसील के अन्दर जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वह ऐसी हालत में हो रहा है कि जिन सड़कों का निर्माण हुआ है उनसे आगे सड़क बन नहीं पाई है। दौसा-लालसोट रोड से हिंगोठिया से लामाना सड़क जाती है, यह चार मील का टुकड़ा चार साल में बन पाया है और बाकी का आठ मील का टुकड़ा आज तक नहीं बन पा रहा है। उसकी तरफ मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा दौसा-लालसोट सड़क से ठीकरिया ग्राम से आलूदा, पापड़दा होकर खवा रावजी तक जाने वाली सड़क है वह भी टूटी हुई है। उस पर चिकनी मिट्टी है और चिकनी मिट्टी होने के कारण जो भी गाड़ी उस पर चलती है वह उसी मिट्टी में गड़ जाती है। यह दस मील का टुकड़ा टूटा हुआ है, गर्मियों के दिनों में तो गाड़ियां चलती हैं बाद में नहीं चलती है। इसकी जानकारी मैं आपके द्वारा सरकार को देना चाहता हूं और मेरी अर्ज है कि इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, शिकायतें करते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है।

एक छोटी सी अर्ज और है कि पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में एक ऐसी गड़बड़ी चल रही है कि लालसोट-दौसा सड़क पर पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से लकड़ियों का ठेका ग्यारह सौ रुपयों का दिया गया है। इसको कम से कम चार साल हो गए। सरपंच ग्राम हींगोटिया के नाम से बोली छुटी थी। इस नीलामी बोली में भूतपूर्व मिनिस्टर रामकरणजी जोशी का भी साझा था। इसमें दो सौ रुपया तो जमा हुआ, लेकिन नौ सौ रुपया अभी तक उनसे वसूल

(श्री मूलचन्द चौधरी)

नहीं किया गया है इसका क्या कारण है ? आज तक कोई इन्क्वायरी नहीं हुई है, इसका केस थाने में चल रहा है. लेकिन पी०डब्ल्यु०डी० में आज तक वह रकम जमा नहीं हुई है। उसके नौ सौ रुपए बाकी हैं।

एक छोटीसी अर्ज और है कि वहां पर एक रमेशदत्त ओवरसियर हैं, जो ठेका देता है, और वह ठेका देने के समय चार आने फी रुपया का कमीशन ठेकेदारों से मांगता है। अगर उसको कमीशन देते हैं तो वह ठेका देता है। इसके बारे में इन्क्वायरी भी पी० डब्ल्यु०डी० की तरफ से कई दफा हो चुकी है, लेकिन तहकीकात पूरी तरह से अभी तक नहीं हो पाई है। पी०डब्ल्यु०डी० में जो इस तरह के ओवरसियर हैं उनके बारे में पूरी तरह से इन्क्वायरी होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के आदमियों के होने की वजह से विभाग में बहुत गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपने जो फरमाया है उसको समझ नहीं सका हूं कि आप क्या कह रहे हैं, आप को जो कुछ कहना हो मुझे लिखकर दे दें मैं उसको देख लूंगा।

श्री मूलचन्द चौधरी : मैं आपको पहले भी कई दफा चिट्ठियां दे चुका हूं। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको मालूम नहीं हो। इसलिए मैं फिर मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि इसकी ओर गौर करके जल्दी से जल्दी तहकीकात करें और जो ओवरसियर हैं उसका ट्रांसफर होने के बाद ही इसमें घोटाला मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा।

(विपक्ष की ओर से कई माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री दयाचन्द सोन : वे तो खड़े ही नहीं हुए। हम खड़े हुए हैं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उनका कारण यही है कि हमारा निर्माण कार्यों पर खर्चा तो बहुत होता है पर हमारा टार्जेट जो सड़कें बनाने का है वह पूरा नहीं होता है। रकम पूरी खर्च हो जाती है पर सड़कें जितनी बनानी थीं, नहीं बन पाती है। इसका मैं एक ही कारण समझता हूं कि जिस वक्त आप अपने एस्टीमेट्स बनाते हैं तो उस समय हो सकता है कि आप अपने पुराने जो शिड्यूल हैं उनके आधार पर ही बनाते हो और उसकी वजह से जब टेंडर इन्वाइट होते हैं तब टेन्डर के कोटेशन मौजूदा हालात देखते हुए पचास प्रतिशत तक बढ़ जाते है। आप ओरिजिनल प्लान में जितना रुपया रखते हैं सड़कों के निर्माण या भवनों के लिए पर जब टेंडर में वही रकम चालीस पचास प्रतिशत बढ जाती है तो फिर वह सड़क या भवन भी कम बन पाती हैं उस रकम में। उसका काम भी कम होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके एस्टीमेट्स तैयार करने के शिड्यूल हैं उनको आप रिवाइज करें और आज के समय में जितना और जिस तरह से खर्चा होता है उसके अनुसार प्लान करें तो आपको मालूम रहेगा कि कितनी रकम की लागत से कितना काम हो सकेगा। इससे जो भी टार्गेट रखेंगे पूरा कर सकेंगे

(श्री गोविन्दसिंह)

और हर साल अधूरा काम शेष नहीं रहेगा राज्य सरकार आलोचना से भी बचेगी।

इसके बाद मैं एक बात के लिए पी० डब्ल्यू. मिनिस्टर साहब और उनके इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं कि अभी एक महीने पहले ही इस बारे में बात हुई थी तो मुझे बताया गया कि डेजर्ट सेक्टर में जिस तरह से सड़कें बना रहे हैं उस टेक्निक को काम में लेने से बीस प्रतिशत तक की बचत होगी। चीफ इंजिनियर साहब ने भी इस टेक्निक को अप्रूव किया है और हम अपने यहां पर इस टेक्निक को लागू कर रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपने यह तो महसूस किया कि राजस्थान की हालत को देखते हुए यहां पर अधिक से अधिक सड़कें बननी चाहिएं और इसके लिए जो कम खर्च करने की दृष्टि से जो आप नई टेक्निक लागू कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको यह वार्निंग भी देना चाहता हूं कि जैसा कि हमने नहरों के मामलों में देखा इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जब नई नहरें बनाईं तो वे कुछ समय बाद ही टूट गईं। इंजिनियरों से पूछते हैं कि यह कैसे हो गया तो वे कहते हैं कि इसको हमारे से ऊंचे अफसरों ने एप्रूव किया था, यहां तो जगह भी अच्छी थी, सब कुछ एग्जामिन कर लिया था, लेकिन आगे जाकर साल दो साल में ही नहरें टूट गईं। इसी तरह आपके यहां भी ऐसा नहीं हो कि अभी जो सड़क बनें साल दो साल बाद ही वे सड़कें खराब हो जायं। इसमें जो बीस पच्चीस प्रतिशत की बचत होगी वह भी ठीक नहीं रहेगी, इसलिए इसको एग्जामिन करा लें, जो कुछ काम किया वह सराहनीय है। जहां तक मेरे खुद के क्षेत्र का प्रश्न है मैं निवेदन करूंगा कि सोयत से सुनेल की सड़क काफी इम्पोर्टेन्स रखती है। वहां पर पुलिया बनना बाकी है। आपने पीपलाद नदी, अहू नदी पर सुनेल के पास पुल बनाकर वहां के क्षेत्र के लोगों पर बड़ा भारी अहसान किया है और वह उसके उपकार को नहीं भूलेंगे। लेकिन सोयत सुनेल सड़क जो कि भवानी मण्डी को उज्जैन और इन्दौर से मिलाती है इसकी इम्पोर्टेन्स को देखते हुए कम से कम जहां तक हो यह सड़क अगली साल में पूरी करा दी जाये।

इसके अलावा एक और निवेदन करूंगा कि गांगरोन रोड जो झालावाड़ से आती है उस पर दो पुलियां हैं और यह दो मील का ही टुकड़ा है अगर इस २ मील के टुकड़े पर काम हो जाता है तो जो गरीब आदमी भारा मोलो या घास वगैरह लेकर आते हैं उनको आसानी हो जायेगी और रोजाना उनके पेट भरने में उनको चलने में आराम मिलेगा इसलिए मेरा निवेदन है कि यह २,२ मील का टुकड़ा पड़ता है इसकी बरसात के पहले पहले हो सके तो पूरा पक्का करवा दें तो अच्छी बात है।

एक निवेदन यह है कि जिला झालावाड़ में जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं वहां पर क्राकरी और कटलरी और फर्नीचर की बहुत कमी है पिड़ावा, रायपुर, डग वगैरह में कम से कम वहां पर क्राकरी, कटलरी और फर्नीचर की व्यवस्था करायें और जहां बिजली पहुंच गई है वहां पर बिजली का भी इन्तजाम करायें। उपाध्यक्ष महोदय, यही मुझे निवेदन करना था।

श्री उपाध्यक्ष:— श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछले वर्षो में पी० डब्लू० डी० द्वारा जितनी भी हमारे राज्य में सड़कें बनाई हैं उनके लिए तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं लेकिन राज्य की सड़कों की आवश्यकताओं को देखते हुए पी० डब्लू० डी० को जो धनराशि मिली हुई है वह बहुत कम है। अगर हम ज्यादा धनराशि कर सकें तो यातायात की समस्या हमारे राजस्थान की हल हो सकती है और यह बहुत जरूरी हैं। इसके साथ ही अभी पी० डब्लू० डी० ने पिछले दिनों में जो कार्य किया उसके लिए मैं जरूर उसकी ताईद करूंगी। वह यह हैं कि बॉर्डर के ऊपर सड़कें बनाने की नई पद्यति का उन्होंने आविष्कार किया है। पहले जो हमारी सड़कें बनती थी उसमें सबसे बड़ी समस्या पानी और ईंटों की आवश्यकता पड़ती थी और पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था और ईंटों को बनाना पड़ता था जो बहुत मुश्किल था। इसलिए एक एक मील सड़क बनाने में कई लाखों रुपया खर्च आ जाता था। लेकिन अब जो नई विधि निकाली है उसमें न तो सीमेंट की जरूरत पड़ती है, न पानी की आवश्यकता पड़ती है और न ईंटों की। यह जो डिसकवरी की या इस बारे में जो हमारे इन्जीनियर्स ने दिमाग लगाया मैं मिनिस्टर साहब को कहूंगी कि जिन इन्जीनियर्स ने इस काम को हाथ में लिया हैं उनको किसी प्रकार से एनकरेज करने के लिए उनको सम्मान या किसी न किसी तरह की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि कोई आदमी कार्य पूरा नहीं करता हैं तो उसके लिए यह होता है कि उसकी आलोचना या निन्दा की जाये। तो उसके साथ ही साथ यह रूल भी हमें अपने पास में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करे या नया खोज करे जिससे हमारे मुल्क को फायदा मिलता हैं, कोई नया आविष्कार करता हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार को हमारे एम० एल० ए० गण को उतना ही जागरूक होना चाहिए क्योंकि आज सर्विस में जो काम करते है उनके दिमाग में यह भावना बैठ गई है कि खर और घोड़ा एक दाम है। काम करेंगे तो गालियां मिलेगी और नहीं करेंगे तो मिलेंगी और अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो भी तरक्की नहीं होगी। यह जो भावना उनके दिमाग में बैठ गई है उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। यह जो परम्परा चल रही हैं उसको निकाल दिया जाना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि जो अच्छा काम करते हैं या ऐसा कोई आविष्कार करते हैं जिससे राष्ट्रीय धन की बचत होती है, तो उनको हायर स्केल देने के लिए कोई कार्य करना चाहिये।

इसके अलावा जब अकाल में पी०डब्लू० डी० द्वारा काम होता है तो उस समय बहुत बड़ी मात्रा में जो अपव्यय होता है उसकी तरफ में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं राजस्थान में हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है, उस समय सड़कों को बनाया जाता है जो फेमिन कोड के अनुसार कच्ची बनती हैं। मेरा मतलब यह है कि आज सड़क बने, लाखो रुपये खर्च हों, पर अगले साल पानी बरसे तो खड्डे पड़ जायें और सड़क बरबाद हो जाये, इससे बढ़ कर राष्ट्रीय धन का कोई अपव्यय नहीं हो सकता। होना यह चाहिये कि सड़कें जो लें वे पक्की बननी चाहिये। अगर पैसा कम है तो उतना काम करके छोड़ दें। कच्ची मिट्टी लाने के बजाय कुछ मेटीरियल इकट्ठा करलें

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

कन्कर या ग्रौर मेटीरियल । तो ग्रकाल के समय यह मेटीरियल इकट्ठा किया जाये। दुर्भाग्य से राजस्थान में दूसरे तीसरे साल ग्रकाल पड़ता है, तो ग्रधूरे काम को दूसरे ग्रकाल के समय पूरा कर लें। सरकार इस तरफ ध्यान दे। पिछले साल ग्रकाल में मेरी कान्सटीटयुएंसी में सड़कों पर १५ लाख रुपये खर्च किये गये, लेकिन सड़कें ग्रधूरी रह गई, उन पर काम नहीं हो पाया ग्रौर खड्डे पड़ कर खराब हो रही हैं। इसके बदले ग्रगर कुछ मटीरियल इकट्ठा करके ही रख देते तो सड़कों के अगर काम नहीं आया तो पंचायत समिति के किसी दूसरे काम, हास्पीटल या स्कूल के काम में आ सकता था। हमारे यहां ग्रकाल का काम शुरु होता है तो तालाबों से पानी लिया जाता है। तो ग्रगर कच्ची नहरों को पक्का किया जावे तो ग्राज जो पानी सीमकर वेस्ट जाता है वह भी बच सकता है। इसके साथ साथ मैं ग्रपनी कान्सटीट्युएंसी की एक समस्या ग्रापके सामने रखती हूं।

स साल देवगढ़ रोड़ बन रहा है तो उसको चक्कर देकर दिवेर से ले जाते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि नेशनल हाईवे तक ५० मील का फर्क पड़ जाता है। ग्रौर ग्रगर बरार ताल से देवगढ़ लेकर ग्रामेट ले जाते हैं तो ५० मील का फर्क पड़ता है ग्रौर ३००, ४०० गांवों को भी फायदा हो सकता है।

तो ग्राप ऐसा एक ग्रार्डर निकाल दें कि ग्रकाल के समय मेटिरियल इकट्ठा किया जाये ग्रौर रख दें, ख्वाहमख्वाह कच्ची सड़क बनाने में कोई फायदा नहीं। फिर दूसरे ग्रकाल के समय उस सड़क को पूरा कर सकते हैं। यहां हर दूसरे-तीसरे साल ग्रकाल पड़ता ही है।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : पहले ही कह रही है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : वह तो पड़ेगा ही। ग्राप कुएं बनाते नहीं, पानी होगा नहीं तो ग्रकाल तो पड़ेगा ही।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में चर्चा हो रही है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार करोड़ों रुपये का बजट इसके लिए रखती है ग्रौर तीन पंचवर्षीय योजनाग्रों से यह कार्य करती ग्राई है लेकिन यह कार्य जो भी होते हैं वह क्षेत्रीय भावनाग्रों से किये जाते हैं। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि पिछड़े हुए जितने भी क्षेत्र है उनके लिए हम सभी साधन जल्दी से जल्दी उपलब्ध करायेंगे ताकि वे साधन पिछड़े हुए क्षेत्रों को या पिछड़े तबके के लोगों को मिले····

उसी तरह दूसरी तरफ उनको किसी प्रकार की सहूलियत न देकर ग्रौर सरकार उनको उपेक्षापूर्ण तरीके से रखती है। तो एक उदाहरण दूं। विरोधी दल के नेता यह कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है ग्रौर भीखाभाई के क्षेत्र में ज्यादा विकास ग्रौर निर्माण कार्य हो रहे हैं तो ट्रेजरी बैंक से कहा गया कि भीखाभाई का क्षेत्र पिछड़ा हुग्रा ग्रौर जितने पिछड़े क्षेत्र है उसमें ज्यादा राहत देते हैं उसी तरह से मैं ग्रपने क्षेत्र के लिए कहूं कि क्या वह पिछड़ा हुग्रा क्षेत्र

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

नहीं है कि जिसके लिए इस तरह की राहत मिल जाय। मेरा क्षेत्र भी एक शिड्यूल्ड कास्ट का क्षेत्र है उसमें आज तक कोई भी काम १५ सालों में डेड मील के टुकड़े को छोड़कर नहीं किया गया है। दंड से भानपुर तक कोई डेढ़ मील का टुकड़ा बना है। बाकी उस तहसील में कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि १८६५४ मील सडक राजस्थान सरकार ने बनाई है वह किस एरिया में बनाई है? मैं तो यह कहूंगा कि मेरे उस क्षेत्र में नहीं बनने की यह वजह है कि एक ऐसी भावना रखी गई कि किसी को कुछ नहीं तो किसी का बहुत जबकि राजस्थान में हर क्षेत्र को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। यह जो इस तरह से पक्ष पात की नीति है वह खराब है। बजट बनाने वाले या योजना बनाने वाले को ऐसा नहीं करना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि पिछड़ेहुए क्षेत्र के लिए कोई भी ऐसी नीति नहीं है कि किसी भी प्रकार की सहायता वहां पर उपलब्ध करा सकें, किसी भी क्षेत्र में चाहे वह चिकित्सा का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे सड़क का हो। तो सरकार को सोचना चाहिए कि पिछड़े क्षेत्रों को राहत मिले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ मेरे क्षेत्र पर मंत्री महोदय या इस विभाग की महरबानी हो जाय तो सड़कों का निर्माण हो सकता हैं। अकाल राहत कार्यों के जरिये से भी निर्माण कार्य हो सकता हैं। क्योंकि अकाल राहत कार्य भी खुलवाये जायेंगे। यदि ऐसा करवा दें तो जनता आपकी आभारी होगी। मैं कहूंगा कुछ सड़कें बनाई जाय जैसे एक टुकड़ा अचरोल से ताल होता हुआ प्रतापगढ़ से मिला दिया जाय इसके बीच में ऐसा है कि ताल का पीर है वहां पर हजारों आदमी हरसाल मेले में आते हैं, अगर उसको जोड़ दिया जाय तो कम से कम मेले में आने वाले लोगों की जो परेशानी होती है वह दूर हो जाय। और यह टुकड़ा प्रतापगढ़ तक जोड़ दिया जाय तो उस क्षेत्र को काफी फायदा होगा।

दूसरी आंधी से डागरवाड़ा होता हुआ सैंथल से मिला दिया जाय तो उसमें ज्यादा खर्चे की बात नहीं है तीसरा नायला से धूला रानी जी का खवा होता हुआ नकटी घाटी और यही से रायसर मिला दिया जाय। चौथा बाण्डी नदी यानी चोमू रोड से बगवाडा मानपुरा होता हुआ चांदवाजी को जोड़ दिया जाय। एक ढांई मील का टुकड़ा हैं दिल्ली रोड से और खौरा मीना तक ले जाय जो कि एक अच्छा गाँव है।

दूसरी बात यह कहूं कि अगर आप इस तरह से इस क्षेत्र को सड़को की उपेक्षा सहुलियत देगे तो वहां के किसानों को शहर में खाद्यान लाने में सहुलियत मिलेगी और वे शहर में अच्छी कीमत वसूल करने की कोशिश करेगे। तो जब तक आप सड़क का साधन नहीं देंगे तब तक अनाज की कीमत जो उनको मिलना चाहिए उस कीमत से वह वंचित रह जायेगा।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि चिकित्सा का वहां कोई खास प्रबन्ध नहीं किया गया है अगर सड़कों का निर्माण होता तो मरीज जयपुर या किसी अच्छे कस्बे में इलाज के लिए पंहुच सकते हैं। कम से कम सड़कों का निर्माण वहां हो जाना चाहिए।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि श्रम सहकारी समितियां जो आपने गरीबों के लिए बनाई हैं तो उन श्रम सोसाइटियों को विभाग की तरफ से वह प्रोत्साहन नहीं मिलता है जो कि ठेकेदार लोगों को मिलता है। सबसे पहली बात तो यह है कि उनको ठेके बहुत छोटे दिये जाते। दूसरी बात सरकार से भी उन लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उनको कुछ रुपया दे दिया जाये ताकि वे उस रुपये से कुछ काम करें। उनको ठेका दे दिया जाता है छोटा सा जो कि उसके लिए नाम मात्र का है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि उन को ठेके ज्यादा और बड़े दिये जांय और कुछ सहायता उनको लोन वगैरह की उपलब्ध कराई जाये ताकि वे लोग ठेके को पूरा कर सकें। वे पूंजी के अभाव में बड़े तो क्या मगर छोटे से काम को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको रकम की सहूलियत मिलनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि···

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

···सड़क में जितना मेटेरियल काम में लिया जाता है वह इस तरह का लिया जाता है कि कहीं सीमेंट की पुलिया बनती है तो उसमें कमी रख दी जाती है और उसमें सीमेंट की कमी होने की वजह से वह पुलिया जल्दी ही टूट जाती है। जो सड़कें बनती हैं उनमें जो चीजें डाली जानी चाहिए वह पूरी नहीं डाली जाती हैं इसलिए वे जल्दी ही खराब हो जाती हैं। तो विभाग को इस ओर सतर्क हो जाना चाहिए या तो विभाग की कमी है या ठेकेदार की कमी है इसके बारे में सोचना चाहिए। जबकि अच्छी कीमत में ठेका देते हैं तो कार्य कैसे जल्दी खराब हो जाते हैं वह किसकी जिम्मेदारी होती है। या तो विभाग की गड़बड़ी का मामला है या ठेकेदारों का तो इस बारे जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी तो कार्य सफल रूप में नहीं होगा। अगर आप इस बारे में ज्यादा ध्यान दें तो सड़कें ज्यादा बन सकती हैं और जो नाजायज रुपया बेकार जाता है वह दूसरी सड़कों में काम आ सकता है। इससे जहाँ १०० मील सड़कें बनी है वहाँ १५० मील बन सकती है। यह जो रुपया बरबाद होता है उसके लिए विभाग को सतर्कता बरतनी चाहिए। सरकार का निर्माण कार्यों पर रुपया बहुत ही होशियारी से खर्च किया जाना चाहिये। विभाग में जो हर अधिकारी का पर्सेन्टेज बन्धा हुआ है उस पर्सेन्टेज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो अच्छा कार्य नहीं होगा। इसमें काफी रुपया गबन होता है। इस रुपये में जिन लोगों की डिमाण्ड होती है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसमें इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला है। अगर मंत्री महोदय सतर्कता बरतें तो घोटाले कम हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी सड़कें मैंने बताई है उन सड़कों के लिए मंत्री महोदय महरबानी करेंगे क्योंकि वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, शिड्यूल्डकास्ट का क्षेत्र है, वहां पर ये सड़कें बन जानी चाहिए ताकि वहां की जनता आपको बहुत ज्यादा आशीष दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सौन !

श्री दयाचन्द सोन (बारा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पी० डब्ल्यू० डी०

(श्री दयानन्द सौन)

विभाग की डिमाण्ड पर बहस हो रही है। विभाग द्वारा बहुत से जो काम ठेकों के अलावा होते हैं उनमें काफी गड़बड़ घोटाले होते हैं कई जगह तो हमारे देखने में आता है कि जो वहाँ पर लेबर लगाई जाती है, उनकी जो हाजरी होती है उसमें भी गड़बड़ होती है। जितने भी एस्टीमेट बनाये जाते हैं तो मान लें कि उसमें लाख रुपये का एस्टीमेट बना तो जो लाख का काम होना चाहिये वह आगे जाकर डेढ़ तक पहुंच जाता है। इसका मुख्य कारण है कि जितना अमानी या लेबर द्वारा डिपार्टमेंट के द्वारा काम होता है उसमें काफी इस तरह की गड़बड़ होती हैं। जहां जहां भी आपके राजस्थान में आप देख लें कि जो भी काम जिसके अगर ठेके में देना होता हैं तो उसका एस्टीमेट जो बनाया जाय तो उसमें हर जगह जहां विभाग द्वारा काम हुआ हैं वहां गड़बड़ घोटाले हुए हैं, और जिस तरह का माल लगना चाहिए था चाहे वह सीमेंट लगे, चाहे चूना लगे वह उस मात्रा में नहीं लगाया जाता है। ऐसी गड़बड़ होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं बारां अस्पताल का उदाहरण देना चाहता हूं। बारां का जो नया अस्पताल बना है उसका जितना एस्टीमेट था वह करीब ढाई-तीन लाख के करीब था। लेकिन अभी तक बहुत सा काम अधूरा है, और जो कुछ भी बना है वह जितना एस्टीमेट था उससे डेढे पर पहुंच गया है, और वहां काफी गड़बड़ हुई है। वहां का बहुत सा सामान अब भी लोगों के हाथों लोहा, सीमेंट चोरी से बेचा जा रहा है। लेकिन विभाग ने इसकी कभी परवाह नहीं की। बारां के अलावा चार पांच साल पहले शाहबाद में जो स्कूल का भवन बना. वह बिल्डिग तैयार हुई, उस पर पट्टियां चढ़ गई, हमारा सौभाग्य था कि विद्यार्थी उस समय वहां पर नहीं बैठे हुए थे वरना बहुत मुश्किल हो जाता, बिल्डिंग तैयार हुई, उसका पेमेंट भी काफी हो गया और बाकी होने वाला था कि सारी की सारी बिल्डिग तहस नहस हो गई।

(शेम शेम)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): छोटी छोटी बात पर शेम शेम।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): बिल्डिग बनने से पहले ही टूट जाय तो क्या कहें।

श्री दयाचन्द सोन : हो सकता है आपके पास कमीशन नहीं आता होगा लेकिन आपके डिपार्टमेंट की जो मशीनरी है उसका बिना कमीशन लिये कोई काम नहीं चलता। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र में बहुत से ठेकेदार जो गरीब थे और दो चार हजार रुपयों से ठेके का काम करते थे वे आज बिल्कुल बेकार बैठे हैं। दो चार हजार से आज वे काम नहीं कर सकते। अगर कोई काम उनको मिल गया तो समय पर उनको बिल का पेमेंट नहीं मिलता और किसी तरह से मिल गया तो कमीशन के मारे वे परेशान हैं, और अगर कमीशन देने से इन्कार किया तो पेनल्टी के मारे परेशान हैं। कोटा जिले के ठेकेदारों के गले पर एक तरह से छुरी फेर दी है.........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): जब आप कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है तो ठेका कैसे लेंगे ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा: आप बैठ जाइये। इतने पिछ लग्गू मत बनें।

श्री दयाचन्द सोन : छोटे छोटे मुलाजिम हैं पी० डब्ल्यू० डी० के वे कहते हैं कि मिनिस्टर और अधिकारी लोग आते हैं तो उनको टी पार्टी में काफी खर्च करना पड़ता हैं और नहीं करें तो काम कैसे चले। छोटे आदमी १००, २०० रुपये खर्च कर दें तो उनके सामने बड़ी समस्या आयेगी जितने पैसे मिले उतने खर्च कर दें तो कैसे काम चलेगा आज सड़कों पर सैंकड़ों पेड़ ठेकेदारों ने काट दिये और जला देते हैं। वे लकड़ी का बिल देते हैं और आप उनको पेमेंट करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मांगरोल मे सूरसाल का ५/७ मील का टुकड़ा है, मांगरोल से कालापटा तक का ८.१० मील का टुकड़ा है। तीन चार वर्षों से आपका ध्यान दिलाया जाता है लेकिन सड़कें बनने का मौका ही नहीं आता है। खास तौर से पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब कोटा जिले से इतने नाराज क्यों हैं पता नहीं। उधर जो कुछ होता हैं

(३.४२ म. प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

वह झालावाड़ की ओर होता हैं। कोटा के नाम से उनको पसीना आ जाता हैं। मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप भी उस इलाके में आते जाते रहते हैं उसी सड़क पर से गुजरते हैं और चुनावों के टाइम पर तो काफी घूमते हैं उस समय आपको कितने झूंने खाने पड़ते हैं और सड़क खराब होने के कारण आपकी गाड़ी डिगमिगाने लगती है, हमको तो आपकी हालत पर रहम आता हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि हमारी तरफ की सड़कों का भी ध्यान रखा करें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके विभाग के द्वारा काम कराया जाता है उस समय लेबर वगैरह से काम कराया जाता है, मेरे ध्यान में आया है कि तीन तीन चार चार महीनों तक उनको पैसा नहीं मिलता है। मजदूरी करने वालों को तीन चार महीनों तक पैसा नहीं मिले तो वे कहां से नाज लायेंगे और कहां से अपने परिवार के लोगों को खिलायेंगे। उनके पास इन्कम का इतना साधन नहीं होता कि कुछ दिन पैसे मिले नहीं तो भी काम चल जाय। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि या तो आप इस तरह की व्यवस्था करें कि उनको रोजाना मजदूरी मिल जाया करे या जितना काम हुआ उसका पैसा फौरन मिल जाना चाहिये। आपकी भी दो चार महीना तनख्वाह रुक जाय तो आपके पास इतने साधन होते हुए भी परेशान हो जाते हैं तो मजदूरों का क्या हाल होता होगा जबकि आप उनको तीन चार महीनों तक पैसे नहीं देते। मैं आपके जरिये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गरीब मजदूरों को समय पर मजदूरी दिलवाने की कृपा करें।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री देवीलाल।

श्री दयाचन्द सोन : अभी तक तो मैं बोल रहा हूं, खत्म नहीं किया है। एक सेठानी ने जच्चाखाना बनाने के लिये ५०/६० हजार रुपये दिये क्योंकि वहां पर लेडी डॉक्टर नहीं थी और महिलाओं को बहुत तकलीफ होती थी.......

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): वह फेमिली प्लानिंग में कट गया...

श्री दयाचन्द सोन: आप बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं।

सभानेत्री महोदया, औरतों को औरतों के साथ हमदर्दी होती हैं इसलिये उन्होंने दिल खोल कर खर्च करने के लिये ५०,६० हजार रुपये दिये। कितनी ही औरतें डिलीवरी के समय मर जाती थीं लेकिन वहां पर जच्चाखाना अब तक नहीं बना।

(शेम शेम)

५०,६० हजार रुपये जो भी उनके जमा हैं वे वापिस ट्रान्सफर करिये ताकि इस रकम को और कामों में लगावें। आप क्यों बीच में जमादार बन बैठे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु०): सभानेत्रीजी, मेरे कटौती प्रस्ताव सड़कों पर तीन हैं। पहला तो है कालीहड़ा से सराड़ा की सड़क के बारे में। यह सड़क सलूंबर जाने वाली सड़क से तहसील सराड़ा हैड क्वार्टर से मिलती है। यह केवल १४ मील का टुकड़ा है लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना से तीसरी योजना तक चली आ रही है आज तक नहीं बन पाई है। तीसरी पंच वर्षीय योजना प्लानिंग चला आ रहा है लेकिन इसका बाकी काम तहसील हैड क्वाटंर पर आज तक पूरा नहीं हो पाया है। दो जगह पुलियों का काम था वह भी तहसील हैड क्वार्टर के पास इस वर्ष चालू किया है। दूसरा केजड़ा के पास पुलिया का काम नहीं हो पाया है। ५-७ वर्ष पहले सर्वे किया गया। पत्थर इकट्ठे किये गये, लेकिन, आज तक पुलिया का काम नहीं हो पाया। इस लिये आपके द्वारा मंत्रीजी से निवेदन है कि सड़क के पुलिया का काम इस वर्ष भी पूरा नहीं होगा तो कब होगा। तीन योजनाएं निकल गई और १४ मील का टुकड़ा पूरा नहीं हो सका। यह १४ मील का टुकड़ा तहसील हैड क्वार्टर तक डामर की सड़क से मिलाया जाय ताकि जिला हैड क्वार्टर तक आने जाने की सुविधा हो जाय।

तीसरी सड़क सिमारी से सराड़ा तक १० मील का टुकड़ा है। इसके आगे कल्याणपुर होकर रिषभदेवजी तक बसेज चलती हैं। पैसेन्जर काफी ज्यादा आते जाते हैं। बरसात के दिनों में यह सड़क काफी खराब हो जाती है। कई जगह नाले हैं उनके पानी की वजह से बरसात के दिनों में खास तौर से पैसेन्जरों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिये इस रोड़ को प्लान में लेकर पक्की बनाया जाय।

तीसरी सड़क है बरसाल से चावड़ जो डीगरी रेलवे स्टेशन होकर सलूंबर चली जाती है और जयसमुद्र साइड में रेलवे स्टेशन है उससे मिलती है। इसको भी प्लॉन में लेकर बनाया जाया। पक्की नहीं बनावें तो कम से कम ग्रेवल रोड़ बनादें तो भी सुविधा हो जाय। इसलिये मैं मंत्रीजी का ध्यान इस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। सड़कों के निर्माण के बिना इस क्षेत्र का विकास हो नहीं सकता। न उनमें देखने जा सकते हैं और उन पिछड़े हुए क्षेत्रों के अन्दर जन-कल्याण का काम कम से कम आवागमन के साधन सड़कों के बिना नहीं हो सकते। मेरा निवेदन है कि इन सड़कों की ओर पूर्ण रूप से ध्यान देकर इनका निर्माण कराये जाने का माननीय मन्त्री महोदय प्रबन्ध करें।

(श्री देवीलाल मीणा)

चौथी सड़क हैं, जो ऋषभदेव से कल्याणपुर, घोड़ासर होकर सलूम्बर तक जाती है। यह रोड़ प्लानिंग में है और यह दस साल से प्लानिंग में चलती आ रही है। इसमें बीच बीच में कंकरीट का काम हुआ है लेकिन फिर भी सड़क ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। यह टोकर तक कुछ कम्पलीट है और ऋषभदेव और घोड़ासर और सलूम्बर के बीच में ज्यों की त्यों पड़ी है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी इस सड़क की ओर ध्यान दें। यह सड़क प्लान में है और सलूम्बर से रेलवे स्टेशन कल्याणपुर और ऋषभदेव और कल्याणजी को मिलाती है। वहां जाने वाले काफी यात्री इस सड़क पर होकर आते हैं। जब रेल से निकलते हैं तो इस सड़क से काफी यात्री जाते हैं ऋषभदेवजी। हर साल यात्री बस से उधर जाते हैं। इसलिए यह जो सात मील के टुकड़े पर मिट्टी पड़ी है इसको कंकरीट की बनानी चाहिए। यदि इसे पक्का करा दिया जाय तो भगवान के दर्शन करने वाले लोगों, ऋषभदेवजी के दर्शन करने वाले लोगों को सुविधा होगी। मेरा निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जाकर विकास के दृष्टिकोण से कार्य करने का ध्यान रखा जाय जब तक इन गांवों में सड़क नहीं होंगी तब तक उनके विकास का काम कोई हो नहीं पायेगा क्योंकि सड़कें नहीं होने की वजह से पंचायत क्षेत्रों में आपके ऑफिसर जा नहीं सकते हैं, वहां की स्थिति को वह देखने के लिए नहीं जा नहीं सकते हैं। जहां पर अच्छी सड़क होती है वहां तो वह मोटर में, जीप में चले जाते हैं लेकिन जहां जहां सड़क नहीं हैं वहां वह पैदल जाने वाले नहीं हैं। इसलिए सड़कों की ओर ध्यान दिया जाकर इनका जल्दी से जल्दी निर्माण कराया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री विजयपाल कटारा।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु०) : सभापति महोदया, हमारे सामने अभी सड़क निर्माण के बारे में बहस चल रही है। मैं भी आपके सामने जो छोटी मोटी सड़कें आदिवासी क्षेत्रों को विकास की दृष्टि से मिलाने के लिए रखी गई हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा।

सबसे पहला जो मेरा कट मोशन है वह डूंगरपुर से आसपुर जो रोड़ है उसके बारे में है। आज बीस साल होने को आ गये लेकिन बीस साल के अन्दर दो मील या तीन मील का टुकड़ा आज तक नहीं बन पाया हैं। सरकार और बड़े बड़े नेताओं में न मालूम क्या लड़ाई झगड़ा है कि उसकी वजह से और बड़े बड़ें नेताओं की कान्स्टीट्यूएन्सी होने की वजह से आज तक पूरी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। मेरा निवेदन हैं कि जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होगा तब तक देश के अन्दर, या किसी जिले के अन्दर, या किसी पंचायत के अन्दर, या किसी पंचायत समिति के अन्दर विकास होना सर्वथा असंभव होगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो बीस या तीस मील का टुकड़ा डूंगरपुर से आसपुर और आसपुर से सावरा और सावरा से जाता है बांसवाड़ा यह रोड़ एक महत्वपूर्ण रोड़ है और इस रोड़ को जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक धनराशि लगा कर गवर्नमेंट कम्प्लीट कराये। मुझे दुःख के साथ इस रोड़ के विषय में कहना पड़ता है कि इस कान्स्टीट्यूएन्सी

(श्री विजयपाल कटारा)

से विरोधी दल के नेता आये हुए हैं, वह तो बहुत सीधे सादे हैं और बड़े भोले हैं और उनको तो आप ऐसे वैसे शब्द कह कर बैठा देते हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिये वह नहीं हो पाया है...

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): ठीक है, बोलो, बोलो, बोलो।

श्री विजयपाल कटारा : मैं निवेदन करूंगा कि जो इस रोड पर चलने वाली बसें हैं वह आये दिन टूटती हैं। क्योंकि ठीक ढंग से सड़क कम्प्लीट नहीं बनी हैं इसलिये बसों को चलाने में मुसीबत आती है। मेरा निवेदन है कि ठीक ढंग से बस नहीं चलेंगे तो आवागमन के रास्ते से पैसंजर्स को जिला हैड क्वार्टर पर आने में काफी मुश्किल होती रहेगी।

दुसरी रोड़ है, डूंगरपुर से संथुआ। यह रोड़ पीठ तक पूरी हो चुकी है और पीठ से संथुआ के बीच में कोई कार्य शुरू नहीं किया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस रोड़ को भी जल्दी से जल्दी बनाया जाय, और इस रोड़ को कम से कम डामर रोड बनाना चाहिये। जहां तक मुझे संकेत मिला है इस रोड के ऊपर कुछ डामर बिछाने के लिये कुछ पैसा मंजूर हो गया है। इसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा।

लेकिन जो दुसरी रोड है बिरजापुर से बड़गांवा, इस रोड पर कंकरीट बिछाने की योजना सिर्फ कागजों में है। जो यह बिरजापुर से बड़गांवा सड़क जाती है यह गुजरात से राजस्थान को मिलाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है। और इसी क्षेत्र से भीखाभाई भी चुन कर आये हैं जो आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं। वह रोड़ से होकर ही गुजरते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बोलो, बोलो; जोर से।

श्री विजयपाल कटारा : लेकिन यह सड़क नहीं बनी तो यह सम्भव है कि इस रोड़ के कारण ही भीखाभाई आगे हार भी सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रख कर इस रोड़ को तैयार करवायें ताकि वह जीत कर आ सकें। मेरा निवेदन है कि यह रोड़ जो आपने बनाई है और बीच बीच में जहां अधूरी पड़ी है इसको अकाल के समय में पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा काम कराया जाकर पूरा कराया जाय। जो गांव के मजदूर हैं वह इस सड़क को बना सकेंगे। आप उनको मजदूरी देना चाहते हैं और उनके लिए साधन उपलब्ध करना चाहते हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस रोड़ की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दें।

दूसरी रोड़ है जिस पर डामर बिछाने के लिए मैंने कट मोशन दिया है वह है डूंगरपुर से सागवाड़ा और सागवाड़ा से बांसवाड़ा। इसे डामर रोड़ आप इस रूप में बना रहे हैं कि एक तरफ आप डामर बिछाते हैं तो दूसरी तरफ उखड़ जाती है। यह आपकी काम करने की रीति है तो इससे सरकार की जो धन राशि जिस प्रकार से खर्च होनी चाहिए उससे ज्यादा सरकार की धनराशि खर्च होती है। इसलिए सरकार अच्छा मेटिरियल पहले से लगा कर उसके साथ डामर बिछाने की कोशिश करेगी तो उसे डामर रोड़ के आधार पर अच्छी तरह बना सकेंगे।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज बीस साल से डूंगरपुर के अन्दर जो माही नदी है

(श्री विजयपाल कटारा)

जो बीच में पड़ती है उसके ऊपर आप पुल नहीं बना सके हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपने जो योजनायें बनाई हैं, उसमें आपने इस प्रकार की योजना तैयार की है कि आप आदिवासी एरिया के अन्दर गांवों का विकास करने के लिए सड़कों को बनायेंगे और कोई भी तहसील हैड क्वार्टर्स सड़क के बिना नहीं रहेगा और कोई भी पंचायत हैड क्वार्टर सड़क के बिना नहीं रहेगा लेकिन आप जो योजना बनाते हैं वह कागजों में ही रह जाती है। आपको उसे कार्यान्वित करना चाहिए। इसके अन्दर जो सबसे पहली बाधा आती है वह इस रूप में आती है कि आपके और ठेकेदार के बीच में गठबन्धन चला आ रहा है बहुत बड़ा और जब ठेकेदार से आपको कोई हिस्सा या पर्सेन्टेज के रूप में पैसा नहीं मिलता है तब उस ठेकेदार को बहुत बुरी तरह से आप परेशान करते हैं और ठेकेदार को परेशानी होने के कारण गांवों के अन्दर, राजस्थान के जिलों के अन्दर काफी काम अधूरे पड़े हुए हैं। परेशानी के कारण ठेकेदार काम समय पर नहीं कर पाता है और इस वजह से काम अधूरे पड़े हुए हैं।

दूसरी सड़क पीपली से कुआं – यह महत्वपूर्ण सड़क है और यह जिला और तहसील हैडक्वार्टर को मिलाती है। चेअरमैन महोदया मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर में इस जिले के अन्दर कई छोटी छोटी सड़कें बनती हैं: वह सड़क एक तरफ बनती हैं तो दूसरी तरफ टूट जाती हैं इसका यह कारण है कि आपके और ठेकेदार के बीच में गठबन्धन होने की वजह से कच्चा माल लगाया जाता है और जो सड़क पुख्ता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। मैं आपको निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर से साथून कुछ मेडल डाल कर पपडी उपाड़ी जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी रोड है इस पर ध्यान दें और देखें तभी जाकर हमारे देश का कुछ सुधार होगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

चकिवी से कुआ और कुआ से पीढ़ यह सड़क भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस रोड को पी. डब्ल्यू. डी. को लेना चाहिये और दूसरी सड़क है सलूम्बर से दरियावास और दरियावास से सत्यपगढ़ जो प्रतापगढ़ को मिलती है। और विकास की दृष्टि से बड़ी खतरनाक रोड है। सरकार को निवेदन करूंगा कि इसको हाथ में लेना चाहिए।

डूंगरपुर से मेवाड़ा रोड। जब से मैं आया हूं सरकार से निवेदन करता आया हूं। आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरफ सरकार की रोड वेज चलती है और उधर गुजरात की एस. टी. ए.। राजस्थान में २० मील का एरिया गुजरात का मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस रोड को आप लेकर गुजरात में मिला दें और यह तो डूंगरपुर के बॉर्डर की हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

दूसरी सड़क मैं बताना चाहता हूं। खेरवाड़ा से रानीवाड़ा जाती है यह बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है। इसको चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में ली जावे और देश का विकास किया जावे वरना बड़ा खतरनाक मामला आने वाला है। जब तक सड़कों का

(श्री विजयपाल कटारा)

विकास नहीं होगा, आवागमन के रास्ते मजबूत नहीं होंगे, किसी भी माल को ले जाने में आपको सुविधा नहीं होगी तो देश की उन्नति नहीं होगी।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

इतना ही मैं आपके मारफत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं सरकार इस बारे में होशियारी और सतर्कता से कार्य करे और होशियार हो जावे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को करे तो मैं आपका आभारी हूंगा।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

वरना अविश्वास लोगों का आवेगा और आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी।

(शोर गुल)

श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : सभापति महोदया

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): सभापति महोदया, हमको आप क्यों नहीं समय दे रहीं हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आपको अपनी टर्न के अनुसार समय मिलता है।

श्री अमरसिंह (दूदू) : सभानेत्री महोदया मैं, अपना नाम पी.ए.सी. से वापिस लेता हूं।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सभापति महोदया, प्रतापगढ़ सब डिविजन में मुख्य सड़कें हैं, जो अन्य जिला तहसील, मंडियों से मिली हुई हैं। प्रतापगढ़ से मन्दसौर, प्रतापगढ़ से रतलाम, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से धरीयावद, उदयपुर, प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी चितौड़, प्रतापगढ़ से जिदन नीमच ये ऐसी सड़कें हैं जिनका बनाया जाना बहुत जरूरी है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई थीं मगर इनमें से सिर्फ एक डामर रोड़ बनी है और बाकी दूसरी सड़कों पर अभी काम नहीं हुआ है। बांसवाड़ा आदि सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है। यहां पर प्राईवेट लोग बसें चलाते हैं वे अपना रास्ता ठीक करके बसें चलाते हैं। लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। यहां पर दो तीन महीने निकल चुके तब जाकर फिर बसें चालू हुई हैं। प्रतापगढ़ से नीमच इसको भी डामर रोड़ नहीं कह सकते। इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। वे अभी तक ठीक हुए नहीं। इसलिए इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वे ठीक हो सकें। यह तो वही कहावत है :

(अश्रव्य)*

यही हालत सरकार की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जयलाल (डग) : सभानेत्री महोदया प्रजातन्त्र में दो तीन काम होते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं और वे सस्ती चिकित्सा, लोगों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था और तीसरा है आवागमन के साधन। ये आज प्रजातन्त्र की तीन मुख्य चीजें हैं। अगर ये तीनों चीजें लोगों को उपलब्ध नहीं हुई तो यह प्रजातन्त्र सही माने में प्रजातन्त्र नहीं कह सकते। अगर लोगों को आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हुए तो यह प्रजातन्त्र सही माने में लागू नहीं हो सकता। सभापति महोदया मैं यह निवेदन करूंगा कि जो डग चोमेला

---

* टिप्पणी :– भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ।

(श्री जयलाल)

भवानी मंडी जाने वाली सड़क का हिस्सा है उस पर कई महिनों से कार्य चल रहा है लेकिन मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूं कि अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ। मैंने लोगों से पूछा कि इसका कारण क्या है यह काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है ? इस पर वहां के लोग इस बात को कहते हैं कि यहां से विरोधी दल जीतकर गये हैं। विरोधी दल के सदस्य जीतने से जो कार्य होते हैं सरकार के उन कार्यों का असर विरोधी दल पर पड़ता है। सभापति महोदया, अगर सरकार की इस प्रकार की नीति रही, इसी प्रकार का पक्षपात रहा और सरकार ने काम किया तो प्रजातन्त्र सफल होने वाला नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि चाहे विरोधी दल का सदस्य हो या सत्तारूढ दल का सदस्य हो। चुनावों में कामयाब होने के बाद समान रूप से काम होने चाहिएं तभी सही माने में प्रजातन्त्र लागू हो सकता है। उनकी सड़क नहीं बनती। पिछले वर्ष भी मैं ने इस बारे में प्रश्न रखा था। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि शीघ्र ही कार्य पूरा होने वाला है। इसमें कई पुलियें अधूरे पड़े हैं और काश्तकारों को और सामान ले कर आने वाले लोगों को भवानी मंडी आना पड़ता है। उनको बहुत परेशानियें होती हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सड़क के कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाना चाहिए।

दूसरी बात कोटा जिले में सड़क है, अंता से मांगरोल जाने वाली सड़क बिल्कुल कच्ची पड़ी है इसलिए बीच में जितने भी गांव के लोग हैं वे अपना अनाज लेकर मंडी तक नहीं पहुंच सकते। वैसे अंता से मांगरोल की सड़क पक्की होनी चाहिए इसमें सरकार का भी भला है और किसानों का भी भला है और जनता का भी भला है।

सभापति महोदया, जिस प्रकार आज हम मांग कर रहे हैं तो सरकार का काम है कि इन मांगों को पूरा करे। जनता की इस प्रकार की आवाज को नहीं सुनना यह कोई सरकार का काम नहीं है। सरकार सर्वोपरि होती है, सरकार एक ईश्वर के समान होती है, जनता के दुख दर्द की बात सुनना उसका कर्त्तव्य है, जनता के दुखों को दूर करना और उसकी मांगों के अनुसार कार्य करना सरकार का कर्त्तव्य है। सभापति महोदया, जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है :

जाकी प्रजा होई दुखारी,
वह नृपति नरक अधिकारी।

जिनके राज्य में जनता को तकलीफें होती हैं वे नर्क के अधिकारी होते हैं। तो माननीय सभापति महोदया, जब संकट का समय आता है, दूसरे देश का आक्रमण का समय आता है तो गरीब लोगों के पास जाते हैं और उनसे मांग करते हैं, पर मांग का सवाल नहीं, देश की गरीब जनता देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को न्योछावर करने के लिए तैयार है और आप कांग्रेसियों से हम ज्यादा तैयार हैं, इस तरह हम आपसे ज्यादा तैयार हैं कि आप लोग देश की जमीन को जमीन का एक टुकड़ा मान कर चलते हो, कभी चीन को कुछ जमीन का टुकड़ा दे देते हो तो कभी पाकिस्तान को कोई टुकड़ा दे देते हो। हम इसे टुकड़ा नहीं मानते, हम इसको जन्मभूमि, कर्म भूमि, मोक्ष भूमि और युद्ध भूमि मान कर चलते हैं, यह है हमारी मान्यता।

(श्री जयलाल)

जिस प्रकार की जनता की आवाज होती है, मांगें होती हैं, सरकार के लिए उनको ध्यान में रखना आवश्यक हैं। सभापति महोदया, आज कल निर्माण कार्य होते हैं, इस प्रकार होते हैं कि आगे सड़कें बनती जाती हैं और पीछे बिगड़ती जाती हैं, टूटती जाती हैं। जहां चूने की आवश्यकता है वहां रेत लगाई जाती है, जहां रेत की आवश्यकता है वहां मिट्टी लगाई जाती है, लाखों रुपया लगा कर पुलियाएं बनाते हैं और वे टूट जाती हैं। इस प्रकार गैर जिम्मेदारी से काम करने से सरकार का और जनता का नुकसान होता है। गैर जिम्मेदारी से पुल बनाते हैं और वे टूट जाते हैं तो जनता और सरकार दोनों को नुकसान होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी काम कराये जायं मजबूती से कराये जायं, मजबूत होंगे तो जनता का पैसा व्यर्थ में बर्बाद नहीं होगा और सरकार को भी नुकसान नहीं होगा।

सांगोद से अन्ता आना पड़ता है वहां प्राइवेट बसें चलती हैं वहां रास्ता बड़ा विकट, ऊबड़ खाबड़ और खराब है, मन्त्री महोदय ने भी देखा होगा अन्ता. से सांगोद गये होंगे तो देखा होगा कि रास्ते में ऊबड़-खाबड़ और नाले आते हैं, रास्ता बड़ा खराब है। अन्ता से सांगोद जाने का रास्ता नहीं, यह क्या है ? उसको पूरा करना चाहिये। सांगोद से अन्ता आना जाना होता है तो कोटा जाना पड़ता है और कोटा से अन्ता आना पड़ता है, जनता को इससे बहुत तकलीफ होती है, सरकार इसकी जिम्मेदार है। जनता को तकलीफ देती है उसका सरकार को पाप लगता है मंत्री महोदय झालावाड़ पर छाया करते आये हैं, झालावाड़ की जनता पर छाया करते आये है, पर अब न मालूम क्या हो गया कि कांग्रेस में जाने पर कांग्रेस की गलत छाया मन्त्री महोदय पर भी पड़ गई, पक्षपात करने लग गये। जनता के कार्यों को पूरा करने के लिए, जनता की सुख सुविधा के लिए व्यवस्था करना, जनता को शिक्षा सस्ती मिले, न्याय सस्ता मिले, इलाज सस्ता मिले, यह सब सरकार की जिम्मेदारी है, जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक सरकार का टिकना भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद ही चुनाव आने वाला है, इसका परिणाम आपको चुनावों के वक्त में भुगतना पड़ेगा।

आज निर्माण के कार्य होते हैं तो बिलकुल गलत ढंग से होते हैं, जिस प्रकार होने चाहिये, उस प्रकार नहीं होते, गलत जिम्मेदारी से, गैर जिम्मेदारी से काम होता है तो सरकार को नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी निर्माण कार्य कराये जायें सतर्कता से अच्छे ढंग से कराये जायं, मजबूत कराये जायं तो निर्माण कार्यों से सरकार को और जनता को दोनों को लाभ मिल सकता है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : अभी वे बोल रहे हैं।

श्री जयलाल : जो डग से जुमेला सड़क जाती है, वह बड़ी ऊबड़ खाबड़ और खराब है, मन्त्री महोदय भी निकलते हैं तो देखते होंगे कि उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, इस तरह से कार्य करवाना किसकी जिम्मेदारी मान कर चलते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है, इन पर जो पैसा लगता है वह

(श्रीजयलाल)

सरकार का पैसा नहीं जनता का पैसा है। जनता के पैसे को इस तरह गलत ढंग से उपयोग में लाते रहेंगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमति सभानेत्री : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़) : सभापति महोदया, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिये जो मांग प्रस्तुत की गई है उस पर मेरे भी कटमोशन हैं, मैं आपके द्वारा सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यों तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कहीं हैं पर मैं सदन से निवेदन करूं कि भारत जब से स्वतन्त्र हुआ तब ही से हमें आवागमन की काफी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। मैं भूतपूर्व मेवाड़ स्टेट का गांव का रहने वाला हूं, वहां सड़कें नहीं थीं और आज हमारे गांव में १० बसें रोज आती हैं और जाती हैं, इसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद अर्ज करूं पर कुछ बातें नम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हैं। बूंदी से चित्तौड़गढ़ सड़क काफी समय पूर्व बनी और उसकी मरम्मत के लिये मैंने सरकार से बार बार निवेदन किया पर अभी तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई है; इस सड़क की हालत दिनोंदिन खस्ता होती जा रही है। साथ ही इस सड़क पर दो तीन ऐसे मोड़ आये हैं कि आये दिन एक्सीडेन्ट्स का खतरा रहता है। बलदर गांव में से सड़क निकलती है, उसके बारे में सरकार ने कहा था कि गांव के अंदर से सड़क निकलती है, उसको गांव के बाहर से सड़क निकालेंगे पर अभी तक सड़क गांव से बाहर नहीं निकाली गई है, बस्सी के पास मोड़ है, उसके लिये फौरन धन की स्वीकृति हुई पर काम सन्तोषपूर्वक नहीं चला। इसी तरह सेमलपुरा के पास में जो मोड है उससे आये दिन एक्सीडेन्ट होने का खतरा रहता है अतः मैं सभापति महोदया, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के आवागमन के इस साधन को शीघ्र ही ठीक करवाया जाय और इससे हर रोज जनता के जानमाल के नुकसान का खतरा रहता है। उस खतरे को दूर करके जनता की जान रक्षा की जाय।

इसी तरह से बस्सी से ग्वालियर की सड़क बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है, मध्यप्रदेश और राजस्थान की सड़क मिलती है पर उसकी पुल नहीं बन पाई है, बिजेपुर से आगे सड़क नहीं बन पाई, अगर वह सड़क अच्छी तरह से बन जायगी तो राजस्थान से मध्यप्रदेश का इलाका बहुत कम दूरी पर मिल सकेगा।

इसके साथ साथ राश्मी और गंगरार तहसील को मिलाने के लिए एक सड़क स्वीकृत हुई थी पर कुछ ही मील में काम बन पाया है, बाकी काम अधूरा पड़ा हुआ है। काफी समय पूर्व उसकी स्वीकृति हो चुकी थी, इसे अब जल्दी से जल्दी बनाना चाहिये।

इसी तरह से संग्रामपुर से पालका खेड़ा सड़क जो १० हजार की जनसंख्या को आवागमन से मिलाती है, गत वर्ष में पहले यह टुकड़ा स्वीकृत हुआ लेकिन वह

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

अभी तक नहीं बन पाया है। मुझे खुशी है कि इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में लिया गया है, मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी यह बन जायगा। यह बन जायगा तो १८ हजार की जनसंख्या को एक मील की जनसंख्या जो एक मील की उंचाई को लांघकर अपना सामान शहर लाती लेजाती है। और इसमें उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वह मुसीबत दूर हो जायगी। आशा है सरकार इसको शीघ्र ही पूरा करायेगी।

इसके साथ ही साथ यह भी अर्ज करूं कि हमारे यहां काफी इमारतें, स्कूलें डिस्पेन्सरीज सरकारी अनुदानों और पब्लिक के चन्दे से बनी हैं। बस्सी की डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग, ५० हजार की लागत की बिल्डिंग सन् १९५२ से सरकार को दे रखी है पर आज तक उस पर एक पैसा भी रिपेअर्स का सरकार की ओर से नहीं लगाया गया है, उस बिल्डिंग की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही है, दवाइयां बारिश के मौसम में भीग जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल्डिंग की मरम्मत जल्दी से जल्दी कराई जाय।

जनता के सहयोग से और सरकार के अनुदान से वहां हायर सैकन्डरी स्कूल के ८ कमरे बनाये और वहां पर हायर सेकेन्डरी स्कूल चल रहा है, काफी समय हो चुका किन्तु उसकी मेन्टेनेन्स के लिए सरकार की ओर से रकम स्वीकृत नहीं हुई। यह इमारत यूं की यूं पड़ी हुई है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको अपने हाथ में लेकर के मेंटेनेन्स की कृपा करेगी।

इमारतों और सड़कों के लिहाज से मैं अर्ज करूं कि शहर और देहात के इलाके में काफी अन्तर है। वहां हर बात में काफी श्रमदान भी लिया जाता है। शहरी इलाकों में तो उनकी मांग पर यूं ही बिल्डिंग्स बन जाती हैं। कोई श्रमदान नहीं लिया जाता है, सरकार को शहरी और देहाती क्षेत्रों को समानता से देखना चाहिये।

भीलवाड़ा से बस्सी तक या हमीरगढ़ से पारसोली तक, गंगारास से भीलवाड़ा तक इस थोड़े से डिसटेंस के अन्दर काफी जनता पिछड़ी हुई है, वहां पर कोई भी विकास का कार्य नहीं पहुंचा है। वहां हमीरगढ़ से पारसोली, गंगरास से बस्सी व भीलवाड़ा तक सड़क बनानी चाहिये ताकि बस्सी भीलवाड़ा जिला और चित्तोड़गढ़ आपस में मिल सके।

जो मौजूदा सार्वजनिक विभाग की ओर से कार्य हुए हैं उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु): सभापति महोदया, इस वर्ष हमारी सरकार की तरफ से सड़कों के बारे में जहां जहां काम हुए हैं और हो रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। कोटाला से कपासन तक जो टुकड़ा है, वह सरकार के नोटिस में है, सैंक्शन हुआ है, बराबर उस पर काम नहीं हुआ है। इसको पूरा किया जाय, गंगापुर से रायपुर, जिला भीलवाड़ा में एक नदी है वहां पर काम पूरा नहीं हुआ है, चौमासे में लोग परेशान रहते हैं, आवागमन में दिक्कत रहती है। इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय।

अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारी सरकार ने

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

अभी तक सड़कों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। वे और हम साथ पढ़े थे, हम जानते हैं कि डूंगरपुर-उदयपुर आने जाने के लिए क्या साधन था। मैं उनसे पूछता हूं कि आप जानते हैं या नहीं। आज एक एक घंटे में···

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर सु.): आपकी सरकार ने क्या किया ?

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : माननीय सदस्य संतोष से सुनलें क्योंकि आपके ध्यान में है और जो हमारी सरकार बनी, आजादी के बाद कितने काम हुए हैं, आप जरूर जानते हैं। मैं आपके डूंगरपुर की बात करता हूं। हमारी सरकार ने डूंगरपुर जिले में इतना पैसा खर्च किया जितना राजस्थान के किसी भी हिस्से में नहीं किया होगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन सु): यह तो पक्षपात है, रोना और किस बात का है।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज़।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : अहमदाबाद जाने वाली सड़क, डूंगरपुर से उदयपुर, बांसवाड़ा से डूंगरपुर, सरकार ने ये सड़कें मिलाई, नेशनल हाई वे रोड बनाया है लोगों को कितना फायदा हुआ है, आधे आधे घंटे के अन्दर गाड़ियां जाती हैं। केसरियाजी तीर्थ-स्थान है। अहमदाबाद से काफी लोग आते हैं, वहां पर सरकार ने मेहरबानी की। माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस नेता काम नहीं कर रहे है लेकिन सरकार तो कर रही है।

श्री परसराम मदेरणा : कांग्रेस की सरकार····

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : कांग्रेस नेता नहीं, कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप सरकार से एक तरफ तो खाना मांगते हैं और फिर कहते हैं कि खाना क्यों दिया ? यह नीति अच्छी नहीं है। गालियां देने से, धौंस देने से काम नहीं होगा।

श्री विजयपाल कटारा : सरकार आपकी अच्छी होती तो लोग भूख नहीं मरते ?

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : हमारी सरकार के मुकाबले पहले महारावल साहब की सरकार के समय बहुत मरते थे।

(शोरगुल)

श्री विजयपाल कटारा : कोई नहीं मरा। सब कुछ सस्ता मिलता था, अनाज सस्ता मिलता था। एक रुपए में पांच सेर घी मिलता था।

श्री श्रवणलाल : वह भी देशी घी मिलता था।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : माननीय सदस्य पुरानी बात कर रहे हैं।

आप और मैं एक ही जगह पढे थे। मैं भी उसी जगह से निकला हूं। आप छोटी मोटी बातों में नहीं उलझें। मादरी झालावाड़ से एक सड़क केसरियाजी जाती है, फोजारा, नैनपारा और सागवाड़ा से होकर, इस सड़क को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें ताकि लोगों को इस मार्ग पर आने जाने के साधन मिल जायं, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाते हैं और काम पूरा करके वापस उसी दिन अपने स्थान पर पहुंच

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

जाते हैं। आप कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार ने जो किया है वह किसी सरकार ने नहीं किया। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बननी चाहिए क्योंकि लोगों को दिक्कतें रहती हैं....

श्री विजयपाल कटारा : यह क्या कह रहे हो, अभी अभी तो कह रहे थे कि हमारी सरकार ने यह किया वह किया...

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : थोड़ी कमियां रही हैं, उनको पूरा करने की बात है। सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान दें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मावा।

श्री मावा (सलूम्बर) : रोड जो जयसमन्द होकर जाडेसर जाती है उस रोड का कोई काम नहीं हुआ है। बम्बोरी से सलूम्बर जो रोड जाती है उसका भी काम नहीं हुवा है, पुरानी रोड है। काफी एक्सीडेंट होते हैं। नदियां आती हैं। सलूम्बर से धरियावद रोड है उसके बीच में भी नदियां पड़ती हैं। सलूम्बर से धरियावद जो सड़क जाती है कच्चा रास्ता है, बसेस चलती है लेकिन गांव गांव खारिज होकर गाड़ियां पड़ी रहती हैं। पेसेन्जर दुख देखते हैं। पुलिया नहीं है।

जयसमन्द के ऊपर बड़े अच्छे हिज हाइनेस के महल बने हुए हैं। उनकी मरम्मत कराई जाय वरना उनको गिरवा दिया जाय ताकि पत्थर काम में तो ला सकें लोग महलों की किवाड़ जोड़ियों को ही तोड़ कर ले गये हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : आप उनको बोलने दीजिये, डिस्टर्ब न करें।

श्री मावा : लोग किवाड़ तोड़ कर ले गये। उनको ठीक कराए जांय।

सड़कों पर और भवनों पर बिलकुल कच्चा काम होता है। चेजा करने का काम मैं जानता हूं इसलिए कहता हूं कि पी० डब्ल्यू०डी०का काम बिल्कुल कच्चा होता है। सोने का काम मिट्टी होती है। मिट्टी का काम सोना होना चाहिये। काम का तखमीना नहीं होता है। तखमीना वापिस हो तो उनकी पोल ही खुल जावे। मेरे एरिया में आपको पधारना होवे तो मैं आपको साथ चल कर बताऊं तो उनकी सारी पोलें खुल सकती हैं। मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। बस इतना ही कहना है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हरिप्रसाद।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभानेत्री महोदया, आपने हमें जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिए सरकार का और आपका आभारी हूं। आज तो मुख्यतया सड़कों का प्रश्न है। इसमें कोई शंका नहीं है कि आज राजस्थान में पी० डब्लू० डी० विभाग ही ऐसा है जो भ्रष्टाचार के नाम से सबसे ज्यादा बदनाम है और अफसोस इस बात का है कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट इस विभाग के माननीय हरिश्चन्द्रजी जैसे हों, जिनके अन्दर न भ्रष्टाचार की कोई शंका हो सकती है और न दूसरी चीज की हो सकती है। अक्लमंद और होशियार हैं, उसके विपरीत भी कोई गुन्जाइश नहीं है। इसके बावजूद भी यह देखने को मिलता है कि जितने प्रावधान राज्य सरकार करती हैं उतना पैसा सड़कों पर नहीं लगता है और इमारतें नहीं बनती हैं। इमारतें

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

बनीं और सड़क बनीं कि टूट जाय और राष्ट्र की सम्पत्ति इस प्रकार से नष्ट हो जाय तो इसका कौन जिम्मेदार होगा ? अफसोस होता है कि इतने होशियार और योग्य मंत्री के हाथों में यह विभाग होते हुए भी, जिनमें न भ्रष्टाचार की शंका कर सकते हैं, न दूसरी बात की शंका कर सकते हैं, आज जितना डिपार्टमेंट आपका बदनाम है, चाहे भ्रष्टाचार के माने में हो, चाहे कार्यों के अनियमितताओं के माने में हो उस पर विचार करना पड़ेगा ।

बूंदी जिले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैंने बजट को पढा है । आप भी इसको जरा ध्यान से सुन लीजिये । केशवराव पाटन से लाखेरी, लाखेरी से कोटा, ६ लाख एक और १३ लाख एक का प्रावधान है । ६१ से लेकर ६३ तक १९ लाख रुपया खर्च करना था उसमें से १॥ लाख रु० कुल खर्च किया है। बजट में प्रावधान रखते हैं, लैप्स होता है, बजट की कमी बताकर टैक्स लगाते हैं, ठेका देते हैं तो काम काज नहीं हो पाता हैं । आप आज मान कर चलिये, मंत्री महोदय खुद मानकर चलेंगे कि लीकेज और सीपेज के कारण एक मोटर नहीं चल पाती हैं । बजट लैप्स होता है बूंदी जिले का जितना बजट है, लाखों उसके लिए रखे जाते हैं वह पूरा का पूरा लैप्स हो जाता है और सड़कों का निर्माण नहीं होता ।

जहाजपुर से नैनवा की सडक । मिट्टी डाल चुके हैं उसको बदल कर दूसरी जगह क्यों लगाया ? वहां पर फौजी लोग रहते हैं उसके बावजूद भी सड़क को दूसरी जगह लगाया गया ।

सभानेत्री महोदया, मेरी शिकायत है वह यह है कि भारत सेवक समाज के नाम पर लाखों रुपया चम्बल समिति को देते हैं, एडवान्स देते हैं और किसी प्रकार का काम नहीं कर पाते हैं, जिनको ठेके देते हैं वे ठेकेदार काम नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में आपने क्या किया है ! मंत्रि मंडल के डिसीजन की याद दिलाना चाहता हूं । मेज नदी की पुलिया और जयपुर से तलवार रोड के लिए कहा । उन्होंने यह आश्वासन दिलाया था कि एक साल में पूरा करेंगे ! मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छः वर्ष के बाद भी वह काम नहीं हुआ । कारण क्या है ? दो मिलेंगे । या तो ठेकेदारों के साथ में महरबानी है या डी.सी.सी. के कांग्रेसी ठेकेदार हैं । चम्बल समिति के अन्तर्गत भारत सेवक समाज ठेके लेता है । काम नहीं होता है । जनता दुख पाती है क्या कारण है ? पी.डब्ल्यू.डी. में भ्रष्टाचार है, आप क्यों नहीं रोक पाते हैं ? लोग कहते हैं उधर के आप इतने योग्य होते हुए भी इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पाते, इफिशियेन्सी नहीं ला पाते और जब तक आप के पास हैं, नहीं होगी, मुझे कांग्रेस के नेता ने कहा कि पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब खुद ठेकेदार हैं, उनकी रानी साहिबा और उनकी ओर से काम चलते हैं । वे अफसरों को दबा नहीं पाते और भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाते हैं । राज एण्ड कम्पनी घोटाला करती है,

(४·३८ म.प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति पदासीन)

भ्रष्टाचार करती है, अनियमिततायें करती हैं, उनको दबाते है तो उनका पर्दाफाश होता है ।

श्री गोविन्दसिंह (गिड़ावा) : गलत कह रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपकी श्रीमती जी के भी शेयर हैं। औरों के भी हैं। मेरे पास लिस्ट हैं। पी.डब्ल्यू.डी. भ्रष्टाचार का अड्डा है, धांधलीबाजी का घर है। उसका एक कारण हैं। उसका कारण यह है कि ये ठेकेदार आज भी ठेका लेते हैं। आज भी देख लीजिये। झालावाड़ में घोटाले हैं, धांधली है। यही कारण है कि आप चैक नहीं कर सकते। आप स्वयं चरित्रवान् हैं, भ्रष्टाचारी नहीं हैं। पर डिपार्टमेंट में अनियमितताओं का कारण क्या है? पी.डब्ल्यू.डी. के ऑफिसर्स जितनी मांग करते हैं, यह नहीं कि आपको मालूम नही है, आपको सब मालूम हैं। एक भाई ने कहा कि मजदूरों के मस्टर रोल गायब हो जाते हैं। बूंदी में गंगोली रोड पर मजदूरों ने काम किया लेकिन उनको आज तक पैमेंट नहीं मिला। बूंदी जिले के साथ खास तौर से पक्षपात है उसको समझना है। आपके ऑफिस में द्वन्द है और जनता को उसका शिकार नहीं होना चाहिये। नैनवा-पाटन रोड पर ६ गाड़ियां चलती थीं। माननीय मंत्रीजी से जाकर मिला, कई बार आपने ऑर्डर्स दिये लेकिन आज तक नही हुआ, आपने आश्वासन दिया था कि सड़कें बनेंगी। पंचायत समिति भवन का उद्‌घाटन किया तो उस समय भी आपने आश्वासन दिया था लेकिन वहां पर काम नहीं होते हैं उसका कारण है भारत सेवक समाज और आपके कांग्रेस के नेता। चम्बल समिति लाखों का एडवान्स ले लेती हैं, कम्पीटीशन में आवे और फायदा उठाए लेकिन काम नहीं करें, साधनों का उपयोग करते रहें, आप किसी प्रकार उनको चैक नहीं कर पाते हैं तो सभापति महोदय, किस प्रकार हालत सुधरेगी, यह जानना चाहता हूं।

बूंदी से नैनवा की रोड कितनी खराब हालत में है यह आपने भी महसूस किया हैं काम बन्द है। थोड़ा काम बूंदी में चल रहा है। मंत्री महोदय गये बूंदी में। डी.सी सी. ने सड़कों के बारे में किताबें दी, दो परसेन्ट भी काम नहीं कर पाये। राजनैतिक द्वन्द है इसका खमियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। लाखों का बजट में प्रावधान होता है। उसके बावजूद लेप्स होता है। गांवों का बजट बनाते हैं, टैक्स लगाते हैं। कई जगह काम नहीं कराना होता है तो बजट में प्रावधान कर देते हैं।

हमें सन्तोष हो जायगा, राजस्थान के लोगों को सन्तोष होगा कि सड़कें बनने वाली हैं, बजट में रुपया रख दिया जाता है लेकिन सड़कें दूसरी ही जगह बन जाती हैं। हमें यह सोचना पड़ेगा आखिर इसमें दोष किस का है? माननीय मंत्री महोदय, आप तो पुराने प्रशासक रहे हैं गरीब आदमी अगर कोई नेता बन कर आता है वह सोचता है कि चलो रुपया बना लो आपको तो इसकी भी कमी नहीं तो फिर आखिर यह हालत क्या है आपके इस विभाग में इतनी कमजोरियां, इतना करप्शन क्यों बढ़ता जा रहा है?

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लाखेरी में काफी बड़ी आबादी है और वह औद्योगिक सेन्टर भी है वहां पर विश्राम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों अधिकारी आते हैं, वे सीमेंट कम्पनी में बेशर्म होकर ठहरते हैं, वहां खाना खाते हैं। मैं कई अधिका-

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

रियों से मिला हूं वे खुद भी यह महसूस करते हैं कि लाबेरी में हम इनके खिलाफ कार्यवाही करने आते हैं लेकिन जब यहां कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं होने से उनके यहां ठहरना पड़ता है। अतः मेरा यह निवेदन है कि वहां डाक बंगले की व्यवस्था होना अत्यावश्यक है।

बूंदी के अन्दर कॉलेज बनाने का था वहां की बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है। छः लाख रुपया खर्च करना था, तीन लाख खर्च हो पाया है। अतः मेरा निवेदन है कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी पूरी करावें।

श्री सभापति : श्री प्रभुलाल सैन्टर।

श्री प्रभुलाल सैन्टर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जिन हालतों में हमारी सरकार गुजर रही हैं, जिस समय चीन और पाकिस्तान का हमारे देश पर आक्रमण हुआ उसके कारण हमारे बजट में काफी कटौती हुई है। फिर भी जब मैं राजस्थान के दूसरे हिस्सों में हुए काम को देखता हूं और उसका मुकाबला हमारे यहां हुए कामों से करता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। हर जगह काम हो रहा है लेकिन सन् ५२ से अब तक मेरे इलाके में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा जो काम हुआ है वह बिल्कुल ही कम हुआ है, इसके लिये यह कहना चाहिये कि बिल्कुल ही नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, १९५७ में हमारे क्षेत्र में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय पधारे थे; कनवास वाया खानपुर रोड होते हुए गुजरे थे। उस रोड की हालत को देखकर आपने फरमाया था कि इसको जल्दी ही बना दिया जायगा। पक्की बना दिया जायगा सड़क का सर्वे हुआ, प्लान बना, लेकिन अफसोस है कि उस सड़क को अधूरे कामों की उस लिस्ट में दर्ज नहीं किया, यही कारण है कि उस सड़क का नम्बर नहीं आ रहा हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धूलेट, कनवास, दनवाड़ व दहीखेड़ा कस्बों में जहां माध्यमिक शाला हैं, जिनके पक्के भवन नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर सड़क नहीं होने से काफी लोगों को कठिनाई अनुभव होती है। अभी जब झालावाड़ में गल्ले की कमी आयी थी वहां से गल्ला लाने में काफी दिक्कत हुई थी। यह निर्माण मंत्री बखूबी जानते हैं। इस इलाके में काली मिट्टी है बरसात में इन जगहों पर जाना दुस्वार हो जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि वहां से अगर हम कोटा पहुंचते हैं तो साठ मील पड़ता है दूसरे हिस्से से जांय तो ८०-८५ मील पड़ता हैं।

खानपुर कनवास वाया दहीखेड़ा रोड यह बनाना अत्यावश्यक है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि इस वर्ष कुछ न कुछ राशि मन्जूर की जावे ताकि मैं इस क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दे सकूं।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के लोगों ने ५४-५५ में ४५ हजार रुपया इकट्ठा करके हाई स्कूल बिल्डिंग बनवाई। आज तक हमारी सरकार द्वारा उसके लिये बहुत कम राशि दी गई। १५ हजार रुपये ६५ में रखे थे वह रकम भी खर्च करके भवन पूरा नहीं किया जा रहा है। इस स्कूल भवन में सन् ६० में चार कमरे मंजूर हो गये थे। लेकिन चीन के हमले की वजह

(श्री प्रभुदयाल सेन्टर)

से, पाकिस्तान के हमले की वजह से चारों कमरे नहीं बन सके, मैं आशा करता हूं कि अब वे कमरे शीघ्र बनवा दिये जावेंगे ताकि वहां के विद्यार्थियों की समस्या हल हो सके।

माध्यमिक शाला देहीखेड़ा एवं सारोलाकलां का किस्सा है यह शाला १६४६-५० में खोली गई थी वहां की ग्राम पंचायत से सरकार ने आश्वासन चाहा था कि वह दस साल का किराया दे सकती है। तो स्कूल खोल देंगे। वहां के पंचों ने दस साल का किराया देने का वादा किया था, वह सन् ६० में पूरा हो गया। आज भी उन बच्चों को खराब इमारत में बैठना पड़ता है बरसात में उसका कोई हिस्सा न गिर पड़ें यह डर हमेशा बना रहता है। उसकी हालत बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, माध्यमिक शाला, सारोलाकलां को हाई स्कूल बनाने के लिये भी आपके यहां से प्रावधान होना चाहिये। बच्चे वहां काफी मिल सकते हैं।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा, खानपुर, सारोला, सवतखेडी, कलबंडा आदि जगहों पर अच्छी पुलिया बनी हुई है जो जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। इस ओर मैंने मंत्री महोदय का भी ध्यान दिलाया था यह पुलिया आज तीन लाख में नहीं बन सकती। बीच में दरारें पड़ गई हैं कई बार ध्यान दिलाया गया उन पुलियाओं की शीघ्र मरम्मत होनी चाहिये। मैं यह भी आशा करता हूं कनवास खानपुर रोड की इस साल मंजूरी होगी, ताकि वहां के लोगों को विश्वास दिलाया जा सके।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो मांगें सदन में प्रस्तुत की गई हैं उसका मैं सांकेतिक विरोध करता हूं। वैसे राजस्थान निर्माण के बाद सड़कों का निर्माण काफी हुआ है लेकिन जिस द्रुत गति से होना चाहिये वह नहीं हो पाया है। साथ ही जिस अवस्था में सड़कें रहनी चाहियें उस अवस्था में सड़कों को रखी जाने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है।

सभापति महोदय, यह बात अवश्य है इस विभाग का मतलब प्लेडर-विदाउट डेन्जर लगाया जाता था यह बात अब सुनने को कम मिलती है। और जो रुपयों का इनकी असावधानी के कारण दुरुपयोग होता है उसको कम किया जाय, दुरुपयोग को रोका जावे ताकि कर दाताओं के रुपयों से ज्यादा अधिक काम हो सके।

सभापति महोदय, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कुछ संस्थाओं को इस विभाग द्वारा ठेके दिये गये हैं जिनके द्वारा काम बहुत खराब हुआ है और उनको रेट्स भी बहुत ज्यादा दी है। देवली में भारत सेवक समाज द्वारा काम करवाया गया जिसमें लाखों रुपयों का इधर उधर घोटाला हुआ। टोंक जिले में एक दो पुलियां बनाई कुछ दिनों बाद वे टूट गईं फिर कुछ दिनों बाद उन पुलियों का निर्माण करवाया गया। पहली, दूसरी और तीसरी योजना में जो कार्य स्वीकृत थे उन कामों को न किया जाकर राज्य सरकार दूसरे दूसरे कामों को अपने हाथ में ले लेती है। कलमडा तक रोड दूसरी योजना में समाप्त हो जानी चाहिये थी उसका रुपया माननीय मन्त्री महोदय ने दबाव में आकर मालपुरा की तरफ फेंक दिया। ऐसा नहीं करना चाहिये।

(श्री राधा कृष्ण गोयल)

टोंक में एक बहुत बड़ी बिल्डिग है जो रावजी की हवेली के नाम से मशहूर है। सार्वजनिक भवन है, रामलाल सक्सेना जब एडमिनिस्ट्रेटर थे टेम्पोरेरी किसी संस्था को काम चलाने के लिये दी थी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर साहब मेरे पास आये, आकर फरमाने लगे कि इस सारी बिल्डिग को आप सम्भाल लीजिये। सरकार ने हुक्म दिया है कि यह कांग्रेस को दे दी जाय। मैंने उनसे कहा मैं तो कांग्रेसी नहीं हूं। उस समय मेरे दिमाग में यह बात आयी कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है डेढ दो लाख रुपये की बिल्डिग है जो सार्वजनिक भवन है जिसको नाजायज तौर पर संस्था को दे दी गई और संस्था की बना दी गई। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें कि इस प्रकार से कैसे हुवा ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री वित्त): यह कब की बात है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल: लास्ट ईयर की। मुझे पूरी जानकारी इसलिये है कि मैं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रेजीडेन्ट रहा हूं उस समय डोक्यूमेन्ट्स मेरे कब्जे में रहे हैं यह बिल्डिग उस समय कब्जे में नहीं थी। प्रजा मण्डल कायम हुआ फिलहाल काम करने के लिये वह जगह बतायी गई थी। सरकार की तरफ से डिस्पेन्सरी चल रही है पहले इसमें एक पाठशाला भी थी। तख्ते के आगे जो भवन है उसी के सम्बन्ध में जिक्र कर रहा हूं।

टोंक में आये दिन पी० डबल्यू डी० कर्मचारियों का जुलूस और झगड़ा होता रहता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर वह गलती पर हैं तो सख्ती से उनकी आवाज को दबानी चाहिए और अगर उनकी मांगें वाजिब हैं तो उनको मन्जूर करने में ढ़िलाई नहीं करनी चाहिए यह वातावरण हम रोज की रोज सुनने और देखने को पसन्द नहीं करते कि रोज हजार मजदूर, पांच सौ मजदूर हर तीसरे रोज, हर सातवें रोज नारे लगाते हुए निकलते रहें और वहां के वातावरण को दूषित बनाते रहें इसके लिए उच्च अधिकारी ही जिम्मेदार हैं।

टोंक से सवाई माधोपुर जो सड़क बनी हुई है वैसे काफी पहले इसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए लेकिन उसे प्रायोरिटी नहीं दी जाकर दूसरी सड़कों को प्रायोरिटी दी गई है जबकि ट्रेफिक टोंक और सवाई माधोपुर सड़क पर काफी बढ रहा है। यह रेलवे स्टेशन तक ले जाने वाली सडक है। बस मैं संक्षिप्त में इतना ही निवेदन करके मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और मैं आशा करता हूं कि कि जो मांग हमसे स्वीकार कराई जा रही है उसका सदुपयोग करें और जितना रिजल्ट इससे निकलना चाहिए उतना रिजल्ट इस रुपये से राजस्थान की जनता को दें।

श्री सभापति : कुं० श्री महेन्द्रसिंह।

कुं० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद): सभापति महोदय, मैं मेरे कटौटी प्रस्ताव के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान सिर्फ एक पुलिया की तरफ आकर्षित करना चाहता हू जिसको कि चुनाव के समय में अपनी

(कु० श्री महेन्द्र सिंह)

कांग्रेस को जिताने के लिए आपने वहां पर काम शुरु किया था और वह मानस गांव की पुलिया है। इसका काम आपने महज इसलिए शुरु किया कि वहां से कांग्रेस जीतकर आये और इसी मकसद से आपने १५,०००) रुपये सन ६२ में खर्च किये। चुनावों के बाद आपने ऐसा आदेश निकाला कि जिससे वहां का काम बन्द हो गया और वह पुलिया आज तक बिना पैसा लगाये और बिना किसी रिपेयरिंग के पड़ी हुई है। इसके बारे में वहां की पंचायत समिति सुलतानपुर, लाडपुरा जिला परिषद कोटा, सारी संस्थाओं ने कई दफा माननीय मंत्री महोदय से और निर्माण विभाग से निवेदन किया कि इस पुलिया का काम शुरू होना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : आॅर्डस दे दिये हैं।

कु० श्री महेन्द्रसिंह : काम थोड़ा ही शुरू हुआ है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आॅर्डर कई दफा किये, गत वर्ष किया, अब भी किया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। इस वर्ष थोड़ा पानी को डाइवर्ट करने के लिए कच्चा बंध बनाया है। वहां काम बिल्कुल बन्द है। कल ही मेरे पास सूचना आई है कि वहां पर सिर्फ ७ आदमी ही काम करते हैं। उसकी प्रगति बिल्कुल ठप्प है और ऐसा लगता है कि बरसात तक काम पूरा नहीं होगा। उसकी फाउन्डेशन तक पूरी नहीं हो पाई है। पहले यह करते कि मेन कैनाल का सीपेज का काम उस नदी में थोड़ा जाता और उनकी मेन कैनाल को बन्द नहीं करते हैं तब तक काम नहीं हो सकता है। आपने पानी के डाइवर्शन के लिए कच्चा बंध बनाया है। लेकिन आपका काम बहुत ही सुस्ती से चल रहा है और ऐसा लगता है कि वह काम बरसात के पहले पूरा नहीं हो सकेगा। फिर पुलिया अधूरी रह गई तो लोगों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां काफी तादाद में लेबर लगाकर कम से कम इतना कर दें कि पीलर्स की फाउन्डेशन बरसात तक भरकर के इतना ऊपर आ जाये कि जिससे बरसात के बाद भी पुलिया पर काम चल सके और वह पूरा हो सके।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चम्बल क्षेत्र में सड़कों का अभाव है। सभापति महोदय, चम्बल क्षेत्र के पूरे इलाके में अगर हम जायें तो मुश्किल से दो तीन मेन सडकें हैं जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है। कई सड़कें तो ऐसी हैं कि जिनकी लम्बाई ३०-३० और ४०-४० मील लम्बी हैं जैसे कोटा से बड़ोद वाया मानस गांव, इसी तरह से इटावा से मांगरोल, इटावा से खातोली को ले लें। आज तक फैयर वैदर रोड्स हैं और इनका पक्का होना आवश्यक है और जो प्रगति आज गांवों की कमान्ड एरिया में होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खासतौर से पुलिया के लिए कहूंगा जिसका काम अभी पूरी तरह से नहीं चल रहा है वह बड़ी तेजी से चलना चाहिए और जो यह सड़कें मुख्य हैं जिनका ठीक होना अत्यन्त आवश्यक है उनको जल्दी से जल्दी कराया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस पर पूर्णतया विचार करें।

Page No.108

श्री राम प्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : सभापति महोदय, एक तो टाइम के एक्सटेन्शन के लिए मैं कहूंगा और फिर ५ बजे जवाब दिया जा सके इसके लिये मैं निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जब तक मांग पारित न हो जाये सदन का समय बढ़ाया जाये ?

[स्वीकृत]

जब तक मांग स्वीकार न हो तब तक के लिए समय बढ़ाया गया।

[विराम]

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर): सभापति महोदय, सदन के समक्ष आज बहुत ही अहम मसला है। यह विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें कि हमारे सरकार की एक, बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है, होनी भी चाहिए। जो विकासशील राज्य होते हैं उनके अन्दर सड़कों का बनना बहुत जरूरी है। मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि सड़कों को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाये। यह महकमा वह महकमा है जिसके अन्दर अस्पताल, विकास की जितनी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल, कालेज आदि जो भी भव्य इमारतें हैं वह इसी विभाग द्वारा निर्माण की हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है सभापति महोदय कि यह विभाग एक ऐसा विभाग है कि पहले पहल जब मैं जयपुर की लेजिस्लेटिव कौंसिल का मेम्बर बनकर आया था तो कांग्रेस बेन्चेज पर बैठने वाले कांग्रेसी मेरे जितने साथी थे वह कहते थे ये कि यह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट है—

श्री मथुरादासजी माथुर (योजना मंत्री) यह तो पुरानी बात है। कोई नई परिभाषा निकालिये।

श्री मानसिंह महार : राजाओं का युग है, राजाओं का युग आ रहा है तो पहले की बात ही कहनी चाहिए। वह कहते थे 'ब्लेण्डर विदाउट डेंजर'। मैं नहीं कहता कि ऐसी कोई बात हो। लेकिन मैं सभापति महोदय, जब इन सड़कों पर जाता हूं और देखता हूं तो कोई सड़क का जरा सा मोड़ निकालना और उसस ५० हजार का खर्चा किया जाता है किसी सड़क की पुलिया को तोड़ कर थोड़ी दूर पर दूसरी पुलिया बनाई जाती है तो मेरा हृदय गद्गद् हो जाता है। राजस्थान में अकाल पड़ रहा है, राजस्थान पर ३३३ करोड़ का कर्जा है, राजस्थान दीवाले में डूबा जा रहा है और यह अंधी सरकार इस प्रकार के छोटे छोटे लीक लकोटे करती है तो दुख होना स्वाभाविक है। इन लीक लकोटों में भी सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि पी० डब्ल्यू० डी० की जो रेट्स है वह ऐसी है कि जिनमें ओपिनली ४० परसेन्ट का ठेकेदार को फायदा होता है। १०० रुपये का कोई ठेका लेता है तो वह खुले आम ६० रुपये का काम करता है और ४० रुपये की उसको बचत होती है ठेकेदारों को तो यह बचत सीमित है तो भी मैं कहूंगा लेकिन उस ४० में से २० परसेन्ट खुले आम पी०डब्ल्यू०डी० का स्टाफ लेता है। ओपिनली याने २० परसेन्ट तक तो कहने की गुंजाइश नहीं है, अगर इससे वेशी पी० डब्ल्यू० डी० का

(श्री मानसिंह महार)

स्टाफ लेता हैं तो कुछ कहने की बात है। It is an open secret कोई डिनाई नहीं कर सकता••

श्री मथुरादास माथुर : Then why mention it ?

श्री मानसिंह महार : Because I think that those who are doing horrible things are living in fools paradise. Therefore, I have to mention it. ....

(५ म० प०)

तो सभापति महोदय, इस लिए मुझे कहना पड़ता है कि इस पी० डब्ल्यू० डी० में २० प्रतिशत....

श्री मथुरादास माथुर : अंग्रेजी जानते हैं, यह मालूम हो गया।

श्री मानसिंह महार : उस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का बीस प्रतिशत तो निश्चित है। ठेकेदारों में से कई से बातें हुई कि भाई यह क्या है। तो बोले साहब कि इस प्रकार से चूने को मिट्टी का रूप न दें तो पी० डब्ल्यू० डी० का बीस प्रतिशत कहां से लावें।

सभापति महोदय, अभी एक मंत्रीजी जिनका कि, इससे ताल्लुक ही नहीं है, प्रेम से एक मजाक कर दिया। लेकिन मैं जिन मंत्रीजी का इससे ताल्लुक है उनसे कहूंगा कि आप पुराने अनुभवी राजा हैं, आप आजकल या इनकी तरह के डालडा घी वाले मंत्री थोड़े ही हैं, आप तो शुद्ध घी खाए हुए मंत्री बने हैं। आपसे मैं पूछता हूं कि आपने इस विभाग को क्या सुधारा। आप में हम बहुत आस्था रखते हैं। हम समझते थे कि ठेकेदारों से जो इंजीनियर लोग पर्सेन्टेज लेते हैं इसको आप कम करेंगे। लेकिन आपके राज्य में वही पर्सेन्टेज २० परसेंट से ३० और ३५ परसेंट तक पहुंच गया है। यह आपकी काबलियत का नमूना है, यह मैं मानता हूं। तो यह जो बीस प्रतिशत थी वह तीस और पैंतीस परसेंट तक पहुंच गई, अब फिर ठेकेदार क्या कमाई करते होंगे. वे भी तो बीस परसेंट से कम तो कमाई नहीं करते होंगे। हमने उन लोगों से पूछा कि अब यह पैंतीस परसेंट कैसे देने लगे तो उन्होंने कहा कि साहब क्या करें, पहले रिश्वत कुछ नीचे के तबके तक थी अब रिश्वत ऊपर तक पहुंच गई है, एड़ी से लेकर चोटी तक। अब यह पैंतीस परसेंट हो गई है तो हम क्या करें। आप ऊपर कम करा दीजिए हम देने में कमी कर देंगे। लेकिन यह नहीं हो सकता है।

कल परसों कहा गया कि ठेकेदारी प्रथा खत्म कर रहे हैं वन विभाग में। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि मैंने पहले भी कहा था लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार जहां पकड़ में आ जाती है वहां जवाब नहीं देती। आज जो विधान सभाओं में उग्र वातावरण बनता है उसका मुख्य कारण यह है कि कोई वाजिब बात कही जाय, उसके लिए पूछा जाए तो मंत्री लोग जवाब नहीं देंगे। मैंने कहा था कि जयपुर से चोमूं जो सड़क जाती है उस सड़क के ऊपर हरमाड़ा घाटी है उसको चौड़ा कराने के लिए, उस सड़क को चौड़ा कराने के लिये भारत सेवक समाज को ठेका दिया गया। यह भारत सेवक समाज तो सभापति महोदय, ठेकेदारों का भी दादा

(श्री मानसिंह महार)

पड़ शादा निकला। इससे ठेकेदार तो चालीस परसेंट पचास परसेंट लोगों को दे दिवाकर और बेचारे काम तो कर देते थे। लेकिन इस भारत सेवक समाज ने दो तीन साल में भी न तो इस सड़क को चौड़ा किया और न इस घाटी का काम किया। सरकार से लाखों रुपये प्राप्त कर लिए इस भारत सेवक समाज ने और लाखों रुपये प्राप्त करके भी अपना काम पूरा नहीं किया और आज सब चुप हैं। इसकी कोई इन्क्वायरी नहीं कोई और बात नहीं। भारत सेवक समाज को जो रुपया दिया गया है उस रुपये के लिए सरकार प्रयत्नशील नहीं है कि वह रुपया वापस वसूल किया जाय। भारत सेवक समाज के एक कार्यकर्ता जो कि उस संस्था से बहुत कनेक्टेड हैं उनसे एक बार मेरी बात हुई तो कहने लगे कि हमने तो खा पीकर साफ कर लिया, अब क्या धरा है। पी० डब्ल्यू० डी० मंत्री रोते फिरें, हम तो एक छदाम नहीं देंगे। मैं मंत्रीजी से बहुत गम्भीरता से निवेदन करूंगा कि मैं समझता हूं कि यह एक बहुत गम्भीर विषय है। आपने भारत सेवक समाज को ठेका दिया। ठेकेदारों को आप काम होने पर पैसा देते हैं। जो ठेकेदार अमुक काम को इतने समय में पूरा कर देता है जब आप पैसा देते हैं। लेकिन हम भारत सेवक समाज तो नन्दाजी का लाड़ला बेटा होने के नाते उसको काम करने से पहले ही पैसा पी० डब्ल्यू० डी० दे देती है। इसका परिणाम क्या होता है कि काम तो वे बाद में शुरू करेंगे। लेकिन भारत सेवक समाज को पैसा दिया जाता है पहले। पहले का काम तो किया ही नहीं और फिर ऊपर का दबाव आया और पैसा दे दिया जाएगा।

इसी प्रकार से एक नमूना आप जोधपुर का देख लीजिए जहां आपने भारत सेवक समाज को काम दिया और आपका लाखों रुपया यह भारत सेवक समाज वाले खा गए। मजदूर जो हैं सभापति महोदय, हरमाड़ा के, जिन्होंने उस सड़क पर काम किया था वे मेरे पास आए, चूंकि यह इलाका मेरी कांस्टीट्यूएंसी में पड़ता है और मेरे नजदीक है इसलिए पचासों मजदूर मेरे पास आए और बोले कि भारत सेवक समाज से हमारी मजदूरी के पैसे दिलाओ। मैंने कहा भोले जीवों, उनको तो ठेकेदार बनाकर बिठाया था वे तो खा पी गए अब मैं कहां से पैसे दिलाऊं।

श्री माथा : उदयपुर में भी दस पन्द्रह हजार मांग रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : ऐसे बहुत से मसले हैं सभापति महोदय। मैं आदरणीय मंत्रीजी से बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करके हमको बताय और उनको भी मालूम हो। क्योंकि मैंने तीन-चार रोज पहले एक मसला रखा था लेकिन जवाब के वक्त जवाब गायब, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसमें नन्दाजी का हाथ है, भारत सेवक समाज के जन्मदाता हैं उस रूप में। आप में दम नहीं है और अगर दम है तो आज जवाब के समय बतायें कि किन किन सड़कों पर कितना २ घोटाला हुआ है। मैं पी० डब्ल्यू० डी० की कितनी ही बार बुराई करता हूं और करूंगा लेकिन यह तारीफ भी करूंगा कि उसने उस घाटी का, उस सड़क का काम जो है पी० डब्ल्यू० डी० ने अपने हाथ में लिया और बहुत एफिशियेंसी से अपने हाथ में लिया और सरकार को लाखों रुपयों का घाटा मिलने के बाद उस काम को बहुत जल्दी खत्म कर दिया।

(श्री मानसिंह महार)

शायद मैंने पी० डब्ल्यू० डी० की तारीफ कर दी तो मंत्रीजी खुश हो रहे हैं। मगर मैं तो उन आदमियों में से हूं कि जहां अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ भी करता हूं और मैं बुराई इसलिए करता हूं कि आप हमारे तबके के आदमी हैं और आप उस विभाग को लिए बैठे हैं और उसमें कोई घोटाले हो जांय या कोई अनियमितता हो जाय और इस तरह का रद्दी काम होता रहे तो हमको शर्म आती है। हमारा सिर शर्म से झुकता है, क्योंकि हम तो यह कहते हैं और खीस कर स्वतंत्र पार्टी यह कहती है कि राजा लोग बहुत योग्य है, वे लोग जब शासन में होंगे तभी काम ठीक होगा, हम जागीरदार बहुत वर्षों से शासन किए हुए हैं तो हमको तजुर्बा है लेकिन जब वे वहां बैठे रहें और हमारे जैसे आदमी इसी विभाग में बैठें और वे भी इस विभाग में बैठ कर इन सफेद टोपी वालों की तरह हो जांय और इन सफेद टोपी वालों की तरह से काम करने लगें तो यह मैं बरदाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यह कह देता हूं। वरना आप देख लीजिए सभापति महोदय, सदन में और सदस्य बैठे हैं लेकिन जैसी तड़क भड़क का कोट माननीय पी० डब्ल्यू० डी० मंत्रीजी पहने हैं वैसा और कोई नहीं पहने बैठा है। आप देख लीजिए, वह अपनी वेश भूषा में, उनके तौर तरीकों में और कांग्रेस वालों से ऊंचे हैं यह मैं मानता हूं। इसीलिए मैं उनसे ऊंचा काम भी चाहता हूं। शासन में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए भी आप ऊंचा काम ही करें ..

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर): मंत्रीजी के कोट पर डिबेट हो रही है या पी० डब्ल्यू० डी० की डिमान्ड पर।

श्री मानसिंह महार: तो मैं निवेदन कर रहा था और अपने पोइन्ट को स्ट्रेस कर रहा था····

श्री सभापति: कोट से तो बुशशर्ट भी काफी रोनक देता है।

श्री मानसिंह महार: आप तो जैसी भी वेष भूषा पहिनते हैं, मैं उसको बहुत एप्रिशियेट करता हूं।

तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्रीजी साफा भी पहनते हैं उनको मैंने कई बार साफा पहिने भी देखा है तो जब वे साफा पहिनते हैं तो वह भी इतना महीन कि मालूम पड़े जैसे रेशम है। अभी निकासी के मौके पर भी साफा पहने देखा था। मैं मानता हूं कि मंत्रीजी खादी पहिनते हैं लेकिन वह खादी भी ऊंची क्लास की पहनते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप सड़क पर डम्भर कुटवायें तो वह भी ऊंची क्लास का ही कुटवायें तो अच्छा रहे। लेकिन वह नहीं होता सभापति महोदय। आप बिल्डिंगों को ही देख लीजिए। मैंने एक बार पहले भी एक केस रेफर किया था लेकिन आज उसको छोड़ता हूं। आज तो यही निवेदन करता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० से जितनी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं वे बेचारी पूरी नहीं होती, उससे पहले ही उनमें पानी टपकना शुरू हो जाता है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी इनकी बिल्डिंग को लेलें। एक मंत्री इस राजस्थान में पैदा हुआ था जिसने कि गंगापुर के स्कूल को लेकर चार इन्जीनियरों को मोअत्तिल किया था, श्री बद्रीप्रशादजी गुप्ता ने किया था। लेकिन तहलका मचा पी० डब्ल्यू० डी० में और मंत्री मंडल में, और सबको बिना इन्क्वायरी के रिइन्स्टेट कर

(श्री मानसिंह महार)

दिया। लेकिन आप तो शासन किये हुए हैं। आपने आज तक किसी को इस प्रकार की गलती के लिए मोअत्तिल किया है? नहीं कर सकते। डरते हैं। आपको डर लगता है। आपके बंगलों को देख लीजिये कि क्या है? उनमें भी पानी के धब्बे मिलेंगे। नये बंगले हैं। आप खुद रहते हैं वह नया बंगला है। विरोधी पक्ष के नेता रहते हैं, वह नया बंगला है, पुराना नहीं। एम० एल० एज० के फ्लेट्स को देखिये। आप कहीं भी पधार जायें, गावों में चलें तो पी० डब्ल्यू० डी० की जितनी बिल्डिगें हैं उनको देखिये। आप अगर कहें कि नहीं है यह बात तो मैं आपको दिखाने की बात कहता हूं। अगर आप कहें कि यह कमी है जैसा कि आप कहेंगे यह मैं जानता हूं तो मैं कहूंगा कि इस कमी के लिए आपने आंखें क्यों मूंद रखी हैं? आज तक क्यों न कार्यवाही की? लेकिन यह नहीं, सभापति महोदय, इतनी हालत खराब होते हुए भी मंत्रीजी यह कहते हैं कि यह विभाग तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सुधार हुआ है? क्यों न? जहां चीफ इन्जीनियर, उनके नीचे के सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर, एडिशनल चीफ इन्जीनियर, जो भी हैं सब दूध के धोये हैं। बद्रीप्रसादजी थे तब तो वह जो बन्धी लाइन थी वह इन्जीनियर तक पहुंच कर रुक जाती थी वह अब टाप तक पहुंच गई है इसलिए एफिशियेन्सी तो बढ़ गई है, इसमें दो राय नहीं हैं। मगर पहले तो ऊपर से नीचे तक नहीं थी तो बहुत कुछ हो सकता था लेकिन अब तो ऊपर से नीचे तक सब एक नाव में हैं।

ओवरसियर्स को ले लीजिये। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मैंने जिक्र किया था कि जो आज पंचायती राज्य के लिए लोग कहते हैं कि हम पंचायती राज्य के पुजारी है, मैं पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आप जो ओवरसियर्स देते हैं पंचायती राज्य की पंचायत समिति को उनकी क्या हालत है? आपने एक समिति को भी योग्य ओवरसियर दिया है? आप नहीं देंगे। मैं जानता हूं क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वहां पर पँचायत समिति जो है वह है प्रधान और सरपंच के नीचे आ जाती है, तो ओवरसियर को वहां प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप वहां रद्दी आदमी देंगे, और योग्य आदमी जो होते हैं······

एक माननीय सदस्य : वह जाना नहीं चाहते।

श्री मानसिंह महार : कैसे जायें? वे ओपनली कहते हैं जो ओवरसियर पंचायत समितियों में जाते हैं कि साहब हम पी० डब्ल्यू० डी० में रहते हैं तो तीन-तीन हजार महिने का कमाते हैं और यहां पंचायत समितियों में आते हैं तो तनख्वाह के अलावा अच्छा टी० ए०, डी० ए० भी नहीं मिलता है। यह इस विभाग के लिए शर्म की बात है। आप कहीं भी चले जाइये हर पंचायत समिति की शिकायत है, लेकिन मंत्रीजी देखने को तैयार नहीं हैं कि हम ठीक ढंग के ओवरसियर्स पंचायत समितियों को भेजे। पंचायती राज्य को अगर किसी आदमी ने राजस्थान में असफल किया है तो वह एक आदमी पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर राजस्थान का है। मैं उनके ऊपर यह आरोप लगाता हूं कि आज पंचायत संस्थाओं की पवित्रता को खत्म करने के लिए जो कुछ काम हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। आप ही वह व्यक्ति हैं जो ओवरसियर्स ऐसे

(श्री मानसिंह महार)

आप समितियों को भेजते हैं कि ६-६ वर्ष से, सभापति महोदय, समितियों के काम का नाप करते नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा था। अब उसको दोहराता हूं। सुनाई नहीं होती है। जवाब देंगे तो एचीवमेंट बतायेंगे कि सड़क इतने मील बना दी, हमने फलानी बिल्डिंग बना दी, और हमने क्या क्या बिल्डिंगें बना दी। तुमने क्या बिल्डिंगें बना दी हमारा टैक्स का जो पैसा था उसको लेकर कुए में डाल दिया। कोई एचीवमेंट नहीं है। आप जो लम्बे-चौड़े खड्डे इस सदन में सुनाते हैं तो इन खड्डों की आवश्यकता नहीं है। आप आजकल छोटी छोटी पुस्तिकाएं हमारे पास इतनी भेज देते हैं कि हम उन पुस्तिकाओं को देखकर आपके उन खड्डों को देख लेते हैं। हम जवाब में एचीवमेंट की बात नहीं सुनना चाहते हैं। हम जो खामियां बताते हैं तो उनका हमें मुंह-तोड़ जवाब दें। लेकिन वह नहीं होगा। हड़मारा के खड्डे वाली नहीं कही जायगी। यह कहा जायगा कि २०० मील सड़क बना दी। यह नहीं कहा जायेगा कि सड़क आगे बन गई और पीछे टूट गई। बनी तो इनके कागजों में बन गई। सभापति महोदय, चोमूं से खेजरोली तक इस सरकार ने एक सड़क बनाई। आज उस सड़क की इतनी दयनीय हालत है कि जिसकी कोई हद नहीं। चार पांच वर्ष हो गये सड़क बने लेकिन आज तक उस पर डामर नहीं पड़ा। बिना डामर के आज के हैवी ट्रेफिक के युग में किसी सड़क को तोड़ने-फोड़ने के लिए छोड़ दिया जाना सरकार के धन का क्रिमिनल वेस्ट है और यह महाराजा साहब आपने किया है। आप जब से मंत्री बनकर आये हैं तब से इस प्रकार की क्रिया चली है। आप जब नहीं थे तब सड़क बनती थी और डामर भी साथ के साथ होता था।

एक माननीय सदस्य : दूसरे कौन थे ?

श्री मानसिंह महार : जो भी हों। किसी की बुराई करने की मेरी आदत नहीं है। यह कोई व्यक्तिगत आपके लिए नहीं है, लेकिन आप कुछ ढीले हैं।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : उमर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : माननीय सभापति महोदय, कब तक बैठेंगे ?

श्री मानसिंह महार : क्या हुआ ? सात बजे तक चलेगा हाउस। डेढ़ घंटा तो वैसे ही हो गया। सभापति महोदय, यह फैसला हो गया है कि जब तक जवाब नहीं हो तब तक बैठेंगे। हम १२ बजे तक रात के प्रेम से सुनेंगे। आप घबराइये मत लड्ढा जी।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट में कितना करप्शन है ? वह और किसी महकमे में नहीं है। इस महकमे में जितनी इनएफिशियेन्सी है उतनी इनएफिशियेन्सी कहीं नहीं है। सड़कों की, सभापति महोदय, यह हालत है कि कहा गया था कि सड़कों का जाल बिछायेंगे तो कुछ पर्टीक्यूलर एरिया में बिछाई गई हैं। झालावाड़ के चारों तरफ सड़कें सड़कें हो जायेंगी, उदयपुर के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ जायेगा जब हमारे जयपुर के नजदीक ही आप जायेंगे सभापति महोदय तो······

श्री उदयलाल बर्दिया (लसाड़िया) : जब से सुखाड़ियाजी आये हैं उदयपुर में सड़कों का जाल बिछ रहा है।

श्री मानसिंह महार : मैं जयपुर की सड़कों की बात जानता हूं। हमारी आमेर तहसील है जिसमें दो कान्स्टीट्यूएन्सीज़ हैं उसमें राजस्थान के बनने के बाद चौमू से कलवाड़ा मिलाने वाली सड़क की योजना थी एक योजना थी चन्दवाजी से सामोद को मिलने की। इस प्रकार की जितनी सड़कों की योजनाएं थीं वह राजा साहब के पधारने के बाद सारी खाड़े में पड़ गई। एक योजना भी तो क्रियान्वित नहीं हुई।

सभापति महोदय यह तो सर्वविदित है कि इन्जीनियरों के तबादलों में, प्रमोशन्स में, इनमें कितना पक्षपात हो रहा है! इन्जीनियर्स हाई कोर्ट में जाते हैं, रिटें करते हैं, स्टे आर्डर लाते हैं। मैं कहता हूं कि जिस विभाग के इन्जीनियर्स पक्षपात से इतने दुखी हों वह विभाग कभी भी सही ढंग से नहीं चल सकता है।

इसलिए मेरा नम्र निवेदन है माननीय मंत्रीजी से कि कुछ मुद्दे जो मैंने उठाये हैं उनका जब वे जवाब दें तब इस राजस्थान वाइड प्रोब्लम को जो मैंने सदन के समक्ष रखा है और भारत सेवक समाज की बात जो मैंने रखी हैं उनका सही जवाब दें। आप यह बताएं कि भारत सेवक समाज के जरिये जो काम कराया है, जो काम था उसमें कितना रुपया आपने घाटा खाया है। यह वर्कवाइज आप बता देंगे मेरी तो यही एक प्रार्थना है।

श्री गणपतलाल वर्मा (मांडलगढ़) : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री गणपतलाल वर्मा : सभापति महोदय, आज भवन और पथ निर्माण विभाग की मांग के ऊपर बहस चल रही है। वैसे राजस्थान बनने के बाद सड़कों के निर्माण में जो पार्ट इस सरकार ने अदा किया है वह भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान के ग्राम वासियों को आवागमन के साधन ही सुलभ नहीं हुए हैं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी उनको काफी लाभ मिला है। लेकिन सड़कों का हम जाल बिछादें, मिट्टी डाल दें और अधूरा काम रखें, पुलिया नहीं बनावें और उसके बाद भी कहें कि सड़कों का काम बहुत कर लिया है। तो यह प्रगति नहीं कही जा सकती। मिसाल के तौर पर मैं भीलवाड़ा की एक दो सड़कों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं : चित्तौड़ बून्दी रोड सन ४८-४६ से चल रहा है लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। इसी तरह भीलवाड़ा बिजोलिया रोड सन् ५४ से चल रही है पर पूरी नहीं हो पाई। आज बिजोलिया क्षेत्र में कई पत्थर की खानें है जहां पर करीब ८ हजार और १० हजार के बीच में मजदूर काम करते हैं। बरसात के दिन आते ही रोटी रोजी का सवाल उनके सामने आता है क्योंकि सड़क का काम पूर्ण नहीं होने के कारण उनका आना जाना रुक जाता है। जो काम अधूरा रह गया हैं उसको पूरा क्यों नहीं कराया जाता। यह एक महत्वपूर्ण सड़क है जहां पर हजारों मजदूरों के रोटी रोजी का सवाल है इसलिये यह पूरा किया जाना चाहिये। मंत्रीजी का ध्यान हमने कई बार इस ओर आकर्षित किया, उन्होंने हमारी बात सुनी भी है लेकिन फिर भी न मालूम क्या कारण है कि यह काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आज इस सड़क की यह हालत हैं कि आगे बनती है पीछे पीछे टूटती जाती है इसका कारण

Page No.115

(श्री गणपत लाल शर्मा)

यह है कि इस सड़क पर रोजाना करीब एक हजार टन ट्रक से पत्थर बाहर जाता है इतने हेवी ट्रेफिक के कारण जो सड़क अधूरी बनती है वह टूट जाती है। इस प्रकार के निर्माण से बार बार खर्चा लगता है इसलिये मैं समझता हूं इस पर डामर करना चाहिये ताकि ५ साल तक इसकी तरफ देखना ही न पड़े।

दूसरी भीलवाड़ा जाहजपुर रोड है उस रोड को बने काफी समय हो गया लेकिन पुल का निर्माण बनास नदी पर नहीं हो पाया। इस बजट में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस महत्वपूर्ण सड़क के लिये जो भीलवाड़ा से देवली वाया शाहपुरा कोटा और जयपुर को मिलाती है। इस बनास की पुलिया का निर्माण होना बहुत आवश्यक है इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : अब काफी समय हो चुका है। सरकारी पक्ष को जबाब देना है।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : काफी समय हो गया है...

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मुझे इतना ही बता दें...

श्री सभापति : काफी समय लगेगा। आपके काफी लोग बोल चुके हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : मुझे बहुत थोड़े में अर्ज करना है।

श्री सभापति : ५ मिनिट श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण के संबंध में कटौती प्रस्तावों पर बहस चल रही है। इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह मानकर चलना कि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है इसको मानने को मैं तैयार नहीं हूं। राजस्थान बनने के बाद सड़कों का निर्माण काफी हुआ है, यह प्रयत्न किया गया है कि हर गांव में सड़क पहुंचाई जाय। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि तीन योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और इन तीन योजनाओं में जो प्लान में रोडस थीं उनमें से फर्स्ट प्लान से तीसरे प्लान के बीच में कितनी ही रोडस कंपलीट कर चुके हैं और कितनी ही रोडस ऐसी चल रही हैं जो फर्स्ट प्लान में शुरू होकर थर्ड में कंपलीट हुई हैं और कई रोडस ऐसी है जो फर्स्ट प्लान में एप्रूव होने पर भी थर्ड में कंपलीट नहीं हुई। आप प्लानिंग की बात करते हैं और उसके आधार पर कार्य पूरा नहीं करते हैं इस तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। फर्स्ट प्लान में कितनी कंपलीट हुई कितनी नहीं, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा। उनियारा से इन्द्रगढ़ तक की रोड सैकन्ड फाइव ईयर प्लान में थी और थर्ड खतम हो चुका है लेकिन वह पूरी नहीं हुई। ५०-६० हजार की स्वीकृति दी गई। इस तरह से प्लान में रोडस के लिये भेदभाव बरता जा रहा है। माननीय मंत्रीजी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह हैं कि जिन लोगों की जमीन सड़क बनाने के लिये एक्वायर की जाती है उनको मुआवजा बहुत देर से मिलता है। इस बारे में मैंने प्रश्न भी दिये हैं। मुआवजे के संबंध में कई प्रश्न पूछे गये।

(श्री दिग्विजयसिंह)

मंत्रीजी से कहते हैं तो कहते हैं कि क्यों नहीं मिला सड़क निकलने से पूर्व मुआवजा मिलने का आदेश था। मुआवजा पहले मिल जाय और बाद में सड़क का काम प्रारम्भ हो तो आपको भी इसमें सुविधा हो क्योंकि जिसकी जमीन आपने ली उसको समय पर मुआवजा नहीं चुकाते हैं तो आपके विभाग को व्याज या इन्टेरेस्ट देना पड़ता है। आपको एक मामले में ४६,०००) इन्टेरेस्ट के देने पड़े है। इसके बारे में जो फैसला हुआ है वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

'Avoidable payment of interest charges in a land acquisition case—Pending complaints of land acquisition proceedings, the department took possession of a private land for the construction of Polytechnic building at Ajmer in April, 1949, the construction of building was sanctioned eight months thereafter, in December, 1959 and construction commenced only in September, 1966. The award for compensation was declared in January, 1964 but the sanction for payment of the compensation (Rs. 3·71 lacs) was accorded by Government more than a year later in March, 1962 and the payment was tendered by the Executive Engineer, the buildings and Roads division Ajmer in August, 1962.

As a result of taking possession of land in advance of requirement and delay in payment of compensation Government had to pay Interest amounting to Rs. 0·48.'

इस तरह की जो आपके विभाग से अनियमितताएं हो जाती हैं उनसे आपके विभाग पर इन्टेरेस्ट का भार पड़ता है। इसलिये व्यवस्था इस प्रकार की करें कि जमीन का एक्विजिशन करते हैं। तो पहले मुआवजे का चुकारा करदें ताकि आपके विभाग पर हल्कापन आ जाय और काश्तकारों को भी जल्दी पैसा मिल जाय क्योंकि जिनकी भूमि जाती है उनको दर्द होता है यह बात सही है। यह महत्वपूर्ण बात है इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

रोड के टेन्डर दिये जाते हैं उस संबंध में दो किस्म के टेन्डर मांगते हैं रोड का अलग और ब्रिजेज कल्वर्ट्स वगैरह के लिये अलग। इससे क्या होता है कि रोड कंपलीट हो जाती है तो पुलिया इन्कंपलीट रहते है और पुलिया बन जाते हैं तो रोड इनकंपलीट रहती हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है और जो रुपया लग चुका होता है उसकी युटिलिटी कुछ नहीं रहती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दोनों काम साथ साथ करें तो दोनों की युटिलिटी रहेगी। टोंक से सवाई माधोपुर रोड जाती है उस पर एक पुलिया अधूरा पड़ी है। रोड बन चुकी है पहले इस रोड पर एक जीप की दुर्घटना हुई थी और एक आदमी मर चुका है मैं चीफ इंजीनियर साहब से भी निवेदन कर चुका हूं जल्दी ही पुलिया बनायी जाय।

इसके अलावा मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप कम से कम यह लक्ष्य तो रखें कि राजस्थान के हर जिले को दूसरे जिले से टार रोड से मिलाया जायगा। मैं यह भी जानता हूं कि मंत्री महोदय यह काम करना चाहते हैं लेकिन धन का अभाव है इसलिये नहीं कर सकते लेकिन फिर भी लक्ष्य यह रखें कि एक जिले को दूसरे जिले से टार रोड से मिलाना है। यह

(श्री दिग्विजयसिंह)

लक्ष्य रखेंगे तो मैं समझता हूं राजस्थान का काफी उपकार करेंगे।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान मेरे इलाके की ओर दिलाऊंगा। मांगरोल से १५ मील का कच्ची सड़क का टुकड़ा है, जो स्टेट के जमाने से कच्चा है। इसके लिये ६ लाख २० हजार रुपयों की मंजूरी भी हो गई लेकिन सालाना यह रकम लेप्स हो जाती है और सड़क बन नहीं रही है। तीन चार बरस से यही क्रम चला आ रहा है। बरसात के दिनों में यह रास्ता बंद हो जाता है और काश्तकार इस रास्ते से निकाल कर अपने घर नहीं पहुंच सकते क्योंकि सड़क कच्ची है, रास्ता खराब हो जाता है। गर्मी के दिनों में भी एक एक फुट के गड्ढे हो जाते हैं। मंत्रीजी से भी इस बारे में कई बार मिला हूं। मंत्रीजी उधर की तरफ जाते हैं घूमते भी हैं लेकिन न मालूम किस वजह से उनकी निगाह इस पर नहीं पड़ती। यह जनसंघ के लिये सुरक्षित इलाका है इसलिये शायद नहीं करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि टेन्डर हो जाते हैं, पत्थर पड़े हुए हैं फिर भी क्यों नहीं काम प्रारम्भ किया गया?

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पन्द्रह मील का टुकड़ा जल्दी पक्का बनायें।

इटावा से खातौली तक सड़क का दस मील का टुकड़ा है वहां काम हो रहा है और दस मील तक पत्थर डले हुए हैं। तब क्यों नहीं इसको बनाया जाता। आज स्थिति यह है कि टेण्डर हो जाते हैं और वह फिर समाप्त हो जाते हैं। उसकी वजह से मैं निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी बनाया जाय।

मांगरौल से गंगौर तक का तीन मील का टुकड़ा है, इसका टेण्डर हो गया है लेकिन उसके बाद वह टेण्डर कैंसिल हो जाता है। इसको पक्का क्यों नहीं बनवाते हैं, क्या वजह है? वहां के आदमी आपसे इस सम्बन्ध में मिले थे जब मन्त्री महोदय उद्घाटन करने गये पब्लिक हैल्थ सेन्टर का, और उन्होंने कहा था कि यह चार मील का, तीन मील का टुकड़ा है इसको पक्का बनाया जाय। आप उन लोगों को आश्वासन देकर चले आये। आप वहां पर फूल माला पहिन कर और उद्घाटन-भाषण करके चले आते हैं और उनको आश्वासन दे आते हैं। वह बन जायगी यह कह देते हैं। फिर भी नहीं बनती है। आप तो वहां घूम घाम कर चले आते हैं। फिर क्या वजह है कि जो तीन मील का टुकड़ा है वह पक्का नहीं बना है।

बंगरोली कलां के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां बनास नदी बहती है और जो आवागमन के साधन हैं उनको उसमें से होकर निकलना पड़ता है। जब उसमें पानी बहुत आ जाता है तो आये दिन बैल मर जाते हैं और मनुष्य मर जाते हैं। इस तरह की दुर्घटनायें आये दिन होती हैं लेकिन उस पर पुलिया नहीं बनाई गई है। इसका क्या कारण है? आप वहां गये तो आपने कहा था कि इसको जल्दी बना दिया जायगा। फिर भी नहीं बनी। क्या वजह है इसकी? आप आश्वासन क्यों देते हैं? अगर आप नहीं बना सकते तो क्यों नहीं कह देते हैं कि नहीं बनेगी। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि या तो

(श्री लक्ष्मी चन्द)

बमबोरी कलां की पुलियां है इसको बनाया जाय। अगर आप नहीं बना सकते है तो आप सचेत हो जायं और वहां पर जायं नहीं। क्योंकि लोगों ने कह दिया है कि अगर मंत्री जी आयेंगे तो उनको काले झण्डे दिखायेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप वहां पधारें तो पहले इस समस्या को हल कर के पधारें। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप पुलिया नहीं बनवाते हैं तो झूठे आश्वासन नहीं दीजिये। मैंने प्रश्न पूछा था तो उस पर आपने कह दिया कि मैं चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड से बात करूंगा। लेकिन आप कब तक बात करते रहेंगे। आपको बात करते करते पांच वर्ष तो हो गये हैं। कब तक यह पुलियां बन जायगी? इससे लोगों को आये दिन परेशानी हो जाती है और मृत्यु हो जाती है क्योंकि आवागमन का साधन है नदी पर। होकर इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पुलिया को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाया जाय और इसको जल्दी बनवाया जाय। अगर आपका यह विचार है कि क्योंकि यहां से जनसंघ से विरोधी दल के सदस्य जीत कर आये हैं इसलिए यहां पर कोई काम नहीं हो तो आपकी इच्छा है। आप करोड़ रुपया खर्च करते हैं वह कहां करते हैं, वह झालावाड़ में करते है, सुखाड़िया साहब का जो क्षेत्र है वहां करते हैं। लेकिन जहां से विरोधी दल के सदस्य जीत कर आयें हैं उसमें आप क्यों खर्च करेंगे? आप कहते हैं कि हम गरीब जनता के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं और सड़क बना कर उनकी उन्नति कर समाजवाद लाना चाहते हैं। लेकिन आवागमन के साधन जुटाने के सम्बन्ध में क्या हुआ हैं? जनता आप से क्या आशा कर सकती है? आप चुनावों में बड़े बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम सड़क बनायेंगे, हम अस्पताल बनायेंगे और स्कूल खोलेंगे। लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं? आप गरीब जनता को क्यों मारते हैं झूठे आश्वासन देकर? मेरी समझ में नहीं आता है कि आप आश्वासन क्यों देते हैं? आप यह दीजिये कि हम नहीं करेंगे। और अगर आश्वासन देते हैं तो उनको बनाया जाय। आप झूठे आश्वासन क्यों देते हैं? मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करें और पक्की सड़क बनाई जाय। मेरा निवेदन है कि जो छोटे छोटे नाले हैं उनके ऊपर पुलिया बना दीजिये क्योंकि इनके कारण आवागमन के साधन खत्म हो जाते हैं, और छः छः महीने तक बस नहीं चलती हैं और पैसेन्जर्स को परेशानी होती है। इन आवागमन के साधनों को बनाया जाय, मैं निवेदन करूंगा, और इस समस्या को हल किया जाय।

श्री जीवराजसिंह (गुढ़ा): सभापति महोदय....

श्री सभापति: बोलिये। सिर्फ २ मिनिट।

श्री जीवराजसिंह (गुढ़ा): सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान पी० डब्ल्यू० डी० विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। वैसे तो राजस्थान सड़कों के मामले में पिछड़ा हुआ है लेकिन उनमें भी झुंझुनू और सीकर बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो काम ठेके पर दिया जाता है; जो ठेकेदार लोग होते हैं वह ठेकेदार रॉ मैटिरियल काम में लेते हैं वह कितना क्या लगाते हैं। यहां यह स्थिति है कि आधा मेटिरियल भी नहीं लगाया जाता है। अगर आप यह सत्य नहीं समझते हैं तो आप किसी भी आदमी को भेज दीजिये, वह मौके पर जाकर देख सकता है। मैं इस सम्बन्ध में नाग साहब से मिला था। लेकिन

(श्री जीवराज सिंह)

नाग साहब तो बिल्कुल नाग की तरह बैठा दिये गये हैं। वहां उनके पास कोई भी मिलने जाय उससे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और न उसकी वाजिब बात मानने के लिए तैयार हैं। मैं चीफ इन्जीनियर साहब से भी मिला था उनसे बात की और उन्होंने लिखा भी लेकिन वे उसका कोई सही उत्तर नहीं देते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो सीकर से उदयपुर रोड बनी है वह इतनी कमजोर बनी है कि थोड़े से दिनों में ही टूट गई। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था। सड़क की उसके बाद मरम्मत हो गई है। लेकिन जिस किसी की भी कमी सड़क बनाने के इस मामले में रही उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। मेरा निवेदन है कि जो गवर्नमेंट का इस सम्बन्ध में कमजोर काम करने वालों के प्रति व्यवहार बना हुआ है वह अच्छा नहीं है। इसके अलावा उदयपुर से खंडेला रोड बनी हुई है वह टूट गई है। ऐसी हालत में उस सड़क को ठीक कराया जाय। इसी तरह से एक रोड उदयपूर से चली जाती है यही हालत है उसके रास्ते में एक भाना माली का व गफूर, फकीर का मकान छापोली ग्राम के पास है। उस जमीन व मकान पर अधिकार माली व फकीर का है। उनने कई अर्जियां पेश कीं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं भी इस सम्बन्ध में नाग साहब से मिला था लेकिन उनने फरमाया कि जो लाइन सर्वे के नक्शे में है वह तो विधाता की रेख जैसे बन गई है। थोड़े दिन वह लोग खामोश बैठे रहे लेकिन जब सर्वे लाइन चेंज करी तो वह विधाता की रेख भी खत्म हो गई है। तो जब एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने सुनवाई नहीं की तो हम ऊपर गये और चीफ इन्जीनियर से मिले उनने इस मामले को एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर से लिख कर पूछा। मगर उत्तर नहीं। तो मैंने कहा वहां तो आपने नाग को बैठा दिया है। मेरा निवेदन है आप किसी को भी मौके पर ले जाकर दिखा सकते हैं, जो कोई चाहे वह अच्छी तरह से देख ले। मकान को गलत सड़क के बीच में लिया गया है। वह सड़क जहां सौ दो सौ गज दूर रखी गई थी, जब हम चीफ इन्जीनियर से मिले तो उसके बाद में बिल्कुल मकान से लगा कर रख दी है।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि नवलगढ़ से गुढ़ा और नवलगढ़ से उदयपुर सड़क है यह तहसील हैड क्वार्टर को मिलाती है और गुढ़ा से नीम का थाना सड़क बनायी जाये। क्योंकि नीम का थाना मण्डी है वहां किसान अपनी पैदावार लेकर नीम के थाने जा सकें। इसलिए किसानों की सहूलियत के लिए जल्दी से जल्दी इसको बनवाने की कृपा करें।

(श्री हरिश्चन्द्र, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के बोलने को खड़े होने पर)

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं दो मिनिट की इजाजत चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप जो कहना चाहते हैं उसके लिए मेरे से मिल लेना।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : आप मिलें तो कह दें।

श्री अब्दुलजब्बार : सभापति महोदय…

श्री सभापति : नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० के बजट के सिलसिले में कई सुझाव यहां रखें..........

श्री सभापति : माननीय मंत्री, एक सैकण्ड !

श्री हरिश्चन्द्र : हम इस बात का प्रयत्न करते हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! बोलने न देने का असन्तोष न रखें। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि कांग्रेस दल की ओर से २६ कटौती के प्रस्ताव पेश किये गये उसमें से ११ सदस्य बोले, स्वतंत्र पार्टी की ओर से १६ कटौती के प्रस्ताव सदस्यों ने रखे, उसमें से दस सदस्य बोले और जनसंघ के दस सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे उस में से आठ लोग बोले हैं। इसलिए किसी प्रकार का अफ़सोस नहीं होना चाहिए इस सम्बन्ध में।

श्री अब्दुलजब्बार : यह कोई सिद्धान्त नहीं है। आपकी आज्ञा जो है, मैं समझता हूं, यह ठीक है। मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को मान लिया है कि जो मैं कहने जा रहा हूं, उसके सम्बन्ध में स्वयं बात हो जायगी।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं जानता हूं, आप क्या कहने जा रहे हैं।

श्री सभापति : बिना बोले आपकी बात का जवाब दे देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिना बोले यह समझ लेते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अर्ज करता हूं, जहाँ तक राजस्थान की आर्थिक और माली हालत सुधारने का सवाल है उसमें कम्युनिकेशन भी एक महत्वपूर्ण अंग है और उस लिहाज़ से राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर और आज के दिन तक काफी प्रगति हुई है। उस प्रगति का ब्यौरा कुछ मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा।

पहली पंचवर्षीय योजना में टोटल एक्सपेंडीचर जो हुआ वह ४६.०७ लाख हुआ और अचीवमेंट हुआ उसमें २,३६६ मील सड़क बनी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल खर्चा हुआ १००७.६१ लाख और ५१५४ मील सड़कें बनी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम उम्मीद करते हैं और जो पैसा हमें मिला है वह ६ करोड़ ५६ लाख रुपया हमको मिलेगा। इसके बदले में २८४८ मील सड़कें बनेगी।

जहां तक कॉम्युनिकेशन्स का सवाल है यह निस्सन्देह सही है कि राजस्थान के अन्दर अगर हमें काश्तकारों की माली हालत को और दूसरे लोगों की माली हालत को ठीक करना है तो यह ठीक है कि कॉम्युनिकेशन्स का विस्तार हो लेकिन कॉम्युनिकेशन्स का विस्तार ही होना एक ही विस्तार होकर रह जावे इससे कोई सुधार नज़र नहीं आवेगा। जब एक रोड का मेन्टीनेन्स प्रोपरली नहीं होता रहे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं कहूंगा कि जब से प्लानिंग हुआ है तब से परसेन्ट के आंकड़े निकालें तो आप को मालूम होगा कि फर्स्ट प्लान में टोटल १०.२ परसेन्ट प्राप्त हुआ। दूसरी योजना में ६.७ परसेन्ट मिला और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम अनुमान लगा रहे हैं कि वह ३.६६ परसेन्ट मिलेगा तो प्रथम

(श्री हरिश्चन्द्र)

पंचवर्षीय योजना में १०.२० परसेन्ट था तीसरी प्लान में ३.६६ परसेन्ट के आस पास पहुंचेंगे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : वह भी नहीं मिलना है।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर आप माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि राजस्थान में रास्तों का विस्तार बढ़े, रास्ते अच्छे हों तो इसके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में धन राशि पी० डब्ल्यू० डी० को मिले तो सड़कें बनेंगी। इसके अलावा जैसा माननीय सदस्य जानते है कि जो १० वर्ष या १५ वर्ष पुराना ट्रेफिक था वह अब नहीं रहा उसमें भी बहुत कुछ अन्तर हुआ है। ट्रेफिक की फ्रिक्वेन्सी और वेहमेंट बढ़ गया है। जो ट्रक पहले ५ या ६ टन का होता था वही ट्रक आज १३ टन १४ टन का होता है, और हमारे यहाँ पर पहले जो ट्रक चलते थे वे उस वेट को लेकर चलते थे मगर आज हमारे यहां पर जो ट्रक चलते हैं वे इस वेट को लेकर चलते हैं जो अमरीका आदि देशों में चलते हैं। इसलिये फ्रिक्वेन्सी बढ़ जाने और वेट ज्यादा होने के कारण सड़कें आपकी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकतीं, इस बात को भी माननीय सदस्यों को सोचना है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना बनती है। प्लानिंग कमीशन के सामने गया तो हमने लक्ष्य रखा था कि १८ करोड़ मिलेंगे। मगर उसको काट कर १३ करोड़ कर दिया। मगर वे १३ करोड़ भी नहीं मिले। जो एक्चुअल फिगर है वह मैंने आपके सामने रखा है वह ६ करोड़ मिले हैं। तो जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम हम कर सकते हैं। हमने कोशिश इस बात की की थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम सड़कें बनादें और ५ हजार की आबादी के गांवों तक पहुंचा दें। लेकिन हम इस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सके क्योंकि.........

श्री मानसिंह महार : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह जवाब कौनसी-कौनसी मांगों पर दिया जा रहा है?

श्री हरिश्चन्द्र : जिस तरह से आपने भाषण दिया उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री मानसिंह महार : एक मांग पास हो चुकी है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप भी वहीं बैठे थे जब एग्रीमेंट हुआ था।

श्री मानसिंह महार : कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। जो डिमान्ड पहले पास हो गई, हम भागे नहीं मैदान छोड़ कर, आप ही भाग गये। आप दोनों डिमान्डों पर बोल कर अपना केस कमजोर कर रहे हैं।

श्री सभापति : आपका केस तो मजबूत हो रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं यह कह रहा हूं कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५००० की आबादी वाले गांवों तक सड़कें बनवा दें। मगर ऐसी राजस्थान में तहसीलें हैं जो नहीं जुड़ी हैं। ऐसी १८ तहसीलें हैं। इसलिये सबसे पहले चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमें यह करना होगा कि इन तहसीलों को जोड़ना होगा। क्योंकि तहसील सब डिविजन हैड क्वार्टर और केपिटल जब सारी चीजें जुड़

(श्री हरिश्चन्द्र)

जाती हैं तब हमारा फैलाव आगे बढ़ता है और हम नीचे के लेवल पर ले जा सकते हैं। जहां तक ...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): आपका बीस वर्ष का प्लान विकास के कार्यों का था उसमें आपने तीसरी पंच वर्षीय योजना में कितना एचीव किया है।

श्री हरिश्चन्द्र: २० वर्ष का प्लान है उसके टारजेट रखे गये थे उनको हम पूरा नहीं कर पाये हैं।

जहां तक नेशनल हाई वे का प्रश्न है। नेशनल हाई वे में इस बात को देखकर हमें अफसोस है और सदन को भी अफसोस है कि राजस्थान का माइलेज है जम्मू और काश्मीर से ऊपर है मगर दूसरी रियासतों के मुकाबले में कम है हमने चार पांच मोटी मोटी सड़कों के नाम भारत सरकार को भेजे हैं। हमारी इस कमी को देखते हुए भारत सरकार राजस्थान को नेशनल हाई वे और प्रदान करेगी।

यहां पर बोर्डर रोड्स के बारे में प्रश्न उठा और पहले भी इस प्रकार का प्रश्न सदन में उठा था। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूं कि बोर्डर रोड की सेंक्शन आई है उसमें भी काम हमने लिये हैं वे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

* (अश्रव्य)

बीकानेर .... रोड	२६.४.६४
बीकानेर से *	१६.१०.६५
ब्यावर .... *	१२.१०.६५ को आई
बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर	१७.६.६५ को आई
बाड़मेर	३०.६.६५ को आई है।
बाड़मेर मुनावा	२६.६.६५ को आई।
गडरारोड, ब्राह्मणों की ढाणी	१४.१०.६५ को आई।
ब्रिजेज ऑन लूनी रिवर एन्ड बालोतरा	१४.६.६५ को

* टिप्पणी-भाषण अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): ब्राह्मणों की ढाणी बन चुकी है।

श्री हरिश्चन्द्र: सांचोर रोड की इजाजत आई है।

इसके अलावा और रोड्स भी हैं जिसको सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अ. देअर ऑरगेनाइजेशन एग्जिक्युशन कराने की सोची थी। अब वे इस बात को सोच रहे हैं कि वे सारे के सारे काम हमको पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा एग्जिक्युट करावेंगे। जब हमारे पास उनकी सेंक्शन आ जायेगी हम उन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे।

फेमिन रोड्स के कामों के बारे में मैं कहूंगा कि जो ६३:६४ और ६४:६५ में काम हुए हैं उसकी टोटल १०२२ मील १५ अगस्त ६४ तक हमने बनाई है।

मैं यह समझता हूं कि यह काम एक बहुत अच्छा काम राजस्थान में हुआ है लेकिन इन रोड्स के अन्दर माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया कि ये रोड्स कहीं अधूरी पड़ी हैं, कहीं क्वेरीज में मेटिरियल पड़ा है। हमने अनुमान लगाया कि अकोर्डिंग टु स्पेसिफिकेशन्स १,३७,४०,००० रु० और चाहिये तब जाकर यह सड़कें उस कदर हो जाय कि जो सारी खामियां नजर आती हैं, उनकी पूर्ति हो जाय। यहां पर इस बात के लिये भी कहा गया कि सड़कें एक तरफ बनती हैं और दूसरी तरफ टूट जाती है। जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया अगर पर्याप्त मात्रा

(श्री हरिश्चन्द्र)

में पी०डब्ल्यू०डी० को धनराशि नहीं मिली तो सड़कें टूटेंगी, इस वास्ते टूटेंगी कि....

श्री मानसिंह महार : मुबारिक हो।

श्री हरिश्चन्द्र : इस वास्ते टूटेंगी कि आपका टनेज बढ़ गया है, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्रेफिक बढ़ गई है। मेन्टेनेन्स की ग्रान्ट जिस हिसाब से मिलनी चाहिये उस हिसाब से नहीं मिलती हैं....

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): मैं तो यह कहता हूं कि आपकी रोड्स ठीक बनती ही नहीं है, इधर बनती जाती है और उधर टूटती जाती है। तो इस तरह से बनाने से क्या फायदा है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन सर, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा कि सड़कें बनाई जाती हैं तो बेसिकली मोडर्न ट्रक्स ट्रेफिक के परिवहन को सहन नहीं कर सकती इस तरह की बनाई जाती हैं क्या। मंत्रीजी ने कहा कि ग्रान्ट नहीं मिली तो सड़कें टूटेंगी, जहां तक ग्रान्ट का मामला है, मेरी उनके साथ सहानुभूति है पर मेरे खयाल में जो आधुनिक वाहन हैं, जो परिवहन है उनकी रिक्वायरमेंट्स को निगाह में रखते हुए रोड्स का निर्माण किया है या नहीं ? यदि नहीं, तो इस डिफेक्ट को दूर करें नहीं तो रिपेअर्स के चार्जेज, ओवरहैड कोस्ट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली और बढ़ जायेगी। मेरा खयाल है, इस सम्बन्ध में टेक्निकल राय ली होगी और इस सम्बन्ध में पूर्ति ही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री हरिश्चन्द्र : विरोधी दल के माननीय नेता ने जो कुछ कहा है। मेरे जो वर्क्स इस वक्त चल रहे हैं वे १८० लाख के इस समय चल रहे हैं, उसके अगेन्स्ट में इस साल के बजट के अन्दर ८०-६० लाख रुपया मिला है। आप खुद माननीय सदस्य जान सकते हैं कि जब मेरी पी०डब्ल्यू०डी० का कमिटेड एक्स्पेन्डीचर १८० लाख का है और ८०-६० लाख ही मिलता है तो राजस्थान की सड़कों की गति जो इस वक्त है उसको कम करना पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ...

श्री मानसिंह महार : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर,

श्री हरिश्चन्द्र : पहले मुझे जो पॉइन्ट उठाया गया है उसका जवाब देने दीजिये। मैंने आपको सुना है, मैंने आपको इन्टरप्ट नहीं किया If you could just hear me I am replying to him. Courtesy demands that when I am replying to your own leader, you should not get up. उसके बाद खड़े हों। I am replying to his question.

श्री मानसिंह महार : Thank you.

श्री हरिश्चन्द्र : उनका रिप्लाई दे रहा हूं, आप बीच में खड़े हो गये।

श्री मानसिंह महार : गलती हुई माफी चाहता हुं, इतने नाराज न होइये।

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं नाराज नहीं।

दूसरा प्रश्न अपोजिशन के नेता ने रखा है कि क्या जो सड़कें बनती हैं उस हिसाब से बनती हैं कि हैवी विहिकल्स के ट्रेफिक को बीअर कर सकें। मैं अर्ज करना चाहता हूं

(श्री हरिश्चन्द्र)

कि हम उस सेटिस्फेक्शन के पास ही नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिये जो धनराशि दी गई है उससे कई गुना धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, मोडर्न टेक्निकेलिटी से सड़कें बनानी पड़ेगी, जिस हिसाब से कि मोडर्न ट्रेफिक है। खास तौर से कोटा के लिये अर्ज करना चाहता हूं, कोटा में एक प्रोब्लेम और है, उधर तो नहरें बन रही हैं, इनिशियल स्टेजेज में पानी शीप होकर, पस्युलेट होकर पास आता है और उसके पास सड़कें बनी हैं, वहां ट्रेफिक चलता है तो निस्संदेह बात है कि सड़कें बैठेंगी, पुरानी सड़कों में सोलिंग नहीं है, बोर्डर्स नहीं हैं, तो वे सड़कें बैठेंगी, इस पर माननीय सदस्यों को चिन्तन करने की जरूरत है और जो प्रावधान पी० डब्ल्यू० डी० को दिया है मोस्ट इनएप्रोप्रियेट है ...।

श्री मानसिंह महार : अब पूछूं ?

पहले तो मैंने अनटाइमली इन्टरप्ट किया उसके लिये क्षमा चाहता हूं क्योंकि वे बहुत बड़े आदमी हैं, नाराज होते हैं। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं सन्तुलन की बात चाहता हूं।

आप कहते हैं कि सड़कें ज्यादा टूटेंगी, यह तो इनएफिशियेन्सी है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि सड़कों की मरम्मत कराने के लिये पैसा नहीं है, मैं कहता हूं इससे बढ़ कर क्या नमूना इनएफिशियेन्सी का आयेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह विवेचन नहीं है....

श्री मानसिंह महार : अगर आप महसूस करते हैं कि कम फण्ड्स दिये हैं, अगर आपकी डिमाण्ड को ठुकरा दिया तो हम इधर बैठे हुए सदस्य कुछ नहीं कर सकते, आपको रिजाइन कर देना चाहिये। आप राजस्थान की बहबूदी के लिये मन्त्री बने बैठे हैं वह काम नहीं कर सकते तो फिर कुर्सी के क्यों चिपके बैठे हैं ? बैड प्लानिंग है, सड़कें ज्यादा बन गई, सड़कें सुधारने को पैसा नहीं है, इतनी जबरदस्त अव्यवस्था होने के बाद भी मन्त्री मण्डल में क्यों कायम रहना चाहते हैं, इससे बढ़ कर शर्म की बात और क्या हो सकती है।

श्री जोधसिंह चौहान : इधर सड़क बनती है एक दिन में पीछे टूट जाती है, पैसा नहीं है तो सड़कें नहीं बनानी चाहियें, इस तरह सड़कें बनाने से तो नहीं बनाना अच्छा।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जो एक्चुअल पोजिशन, पी० डब्ल्यू० डी० की स्थिति है उसको सदन के सामने रखा है, रखना ही चाहिये क्योंकि सदन से छुपा कर चलें तो ठीक नहीं। पर परिस्थिति यह है कि नॉर्मल मिनिमम ग्रान्ट दी जाय रिपेअर्स की तो भी १ करोड़ ८२ लाख ३५ हजार रुपया मिलना चाहिये, बेअर मिनिमम मेन्टेनेन्स के लिये। क्योंकि केटेगरी ए० रोड्स के लिये २ हजार रुपया पर माइल, केटेगरी बी० रोड्स के लिये ६०० रुपया पर माइल और केटेगरी सी० रोड्स के लिये २०० रुपया पर मील यह जो आंकड़े हैं, इस हिसाब से भी जोड़ें तो हिसाब लगाइये कितना मिलना चाहिये, वही आता है।

इसके एवज में मुझे मिला है १७३ लाख रुपया, यह बेअर मिनिमम के भी नीचे है। जब तक पर्याप्त मात्रा में रिपेअर्स के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं हो, जिस दायरे में

(श्री हरिश्चन्द्र)

आप सोचते हैं कि ठीक चले वह नहीं चल सकता। जब तक राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तब तक इस बात को लेकर चलें कि हमारी सारी सड़कें अमेरिकन स्टाइल पर बनें, या दूसरे फौरेन कन्ट्रीज हैं उनके स्टाइल पर हो जायं तो वह नहीं हो सकेंगी।

श्री मानसिंह महार : तो टूटती जायंगी और बनाते जाओगे, इससे तो अच्छा है कि जितनी हैं, उनको मेन्टेन तो करें और अधिक बनाने से क्या फायदा ? इस तरह से·····

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसींद) आमेर में मत बनाओ।

श्री जोधसिंह चौहान : (गिरवा) : अरे परवरिश को तो रोको। भागूंदा रोड़ बनी, बड़गांव की एक दिन नहीं चली और टूट गई। इससे तो नहीं बनायें तो अच्छा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मन्त्री महोदय ने कहा कोटा के बारे में कि इरिगेशन के कारण रोड्स की दिक्कत आ रही है। कांडला पोर्ट से राणा प्रतापसागर पर जो एटोमिक पावर के लिये हेवी मशीन्स आयेंगी, उसके लिये जो ५॥ लाख और ८। लाख रुपया लोन का मिला है, इस १३॥। लाख रुपये का तो यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया है या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब तक प्लान्ट आ जायगा, उससे पहले सड़क बन जायगी। पर अजमेर से बूंदी होते हुए राणा प्रताप-सागर पर जायेंगी। पैसा लगाने के लिये स्टाफ बढ़ाने के लिये हमने कहा है।

(६ म.प.)

मैं जो जो कटौती के प्रस्ताव आए हैं, उन पर थोड़ी सी झलक डालना चाहता हूं। जैसे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बारां और भंगरोल सड़क के बारे में कहा। यह एक समय होता है जबकि बजट सेशन होता है तो उस समय इस तरह की चीजें आती हैं लेकिन अगर माननीय सदस्य के सामने कभी भी इसी विषय को लेकर कोई भी चीज नोटिस में आए तो कम से कम अगर आप मुझसे मिलें और कहें कि यह चीज हो रही है...,

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : बारां से डिप्यूटेशन्स भेजे गए हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : दुख इस बात का है कि माननीय सदस्य बोलते हैं मिलना कभी होता नहीं है, जब सेशन होता है तब चीज सामने आती है।

श्री दयाचन्द सोन (बारां–सु०): बारां में आए तो शायद आप एम, एल. ए. को पहिचानते भी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र : अगर मिलने की कोशिश करें तो पहिचानूंगा। जिस प्रकार से यह बात कही गई, अगर एक भी माननीय सदस्य आया हो और कहे कि सुनवाई नहीं करता हूं तो मेरा दोष है। यहां आप कह जाते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं, जब सेशन होता है तब मिलते हैं······

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपके पास कितनी बार आए, लेकिन आपकी चलती नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने कौन से भ्रष्टा-चार के लिए कहा ?

Page No.126

श्री विजयसिंह झाला : आपके नीचे के जो अधिकारी हैं, वे आपकी चलने नहीं देते। ढांचा ही ऐसा है कि एक-दो मंत्रियों के सिवाय किसी की चलती नहीं है।

श्री मानसिंह महार : Shame! Shame!! resign please. इसका जवाब दिया जाय, यह बहुत सीरियस एलीगेशन है।

श्री विजयसिंह झाला: आपकी चलती है या नहीं, इसका जवाब दें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं जैसा हूं वैसा हूं, ४२ साल की उम्र है बदल नहीं सकता। जैसे आप हो वैसे मैं हूं।

श्री विजयसिंह झाला: हम तो आपको, ६० वर्ष का समझते थे।

श्री हरिश्चन्द्र : कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नई सड़कें बना रहे हैं और पुरानी सड़कों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वे कैसे बनेंगी ? अगर नई सड़कें बनवाते हैं तो भी नाराज, अगर नहीं बनवाएं तो भी नाराज।

जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ। मैं उनको गिनाने के लिए तैयार हूं कि उनके क्षेत्र में बिजली गई, दो दो बड़ी सड़कें बनीं। उनके क्षेत्र के अन्दर सड़क कभी नहीं थी, वह बनी।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय सु.): यह मैंने कहा था। मैंने कहा था कि मेरे इलाके में काम नहीं होता है।

ठाकुर श्री जीवराजसिंह (गुढा) : ठेकेदारों की एग्रीमेंट के बारे में बताइए ?

श्री सभापति: No, no interruption please. मंत्री महोदय के जवाब होने के बाद में जो कोई माननीय सदस्य पूछना चाहें तो मैं इजाजत दूंगा। जब तक मंत्री महोदय का जवाब खत्म न हो तब तक कोई न इन्टरप्ट करे।

श्री हरिश्चन्द्र : जोधपुर, नागौर, जालौर और बांसवाड़ा के लिए कहा गया कि माइलेज का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैं इस पर थोड़ी सी झलक डालना चाहता हूं। जोधपुर में इंटीग्रेशन के समय ८७५ मील सड़कें थी तीसरी योजना के बाद १,१११ मील सड़कें बनीं इसमें फेमिन की सड़कें शामिल नहीं है। नागौर में ४५८ मील थी, अब १०४२ मील, जालौर में १६५ मील थी जब १०४२ मील, बांसवाड़ा में...

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : डामर के लिए मैंने..

श्री हरिश्चन्द्र : डामर के लिए सांचोर से रानीवाड़ा....

श्री सभापति : कोई भी इन्टरप्शन नहीं करें। (मंत्री महोदय से) अगर आप इन्टरप्शन्स का जवाब देंगे तो मैं सदस्यों को कैसे रोक सकूंगा ? Why do you take cognizance of it. You go on making your speech.

श्री हरिश्चन्द्र : तो बांसवाड़ा में तीसरी योजना के अन्त तक ४६४ मील सड़कें बनीं। अगर आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि हर जिले की माइलेज क्या है।

इसके सिवाय यहां पर कुछ दिनों से भूख हड़तालें चल रही हैं और इस बात क

(श्री हरिश्चन्द्र)

प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान को किसी न किसी रूप से बंद किया जाय। यह बड़े दुख का विषय है कि जब राजस्थान प्रगति के मार्ग पर चल रहा हो और राजस्थान में औद्योगीकरण हुआ हो और मजदूरों को रोजगार दिलाने की कोशिश की हो और मैं यह भी कह सकता हूं कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार ने शासन किया है उस समय से निरन्तर प्रयास किया है कि मजदूरों की जितनी भी दिक्कतें हों चाहे पी०डब्ल्यू०डी०, चाहे पावर हाउस, चाहे वाटर वर्क्स हो, हमने जितना भी अधिक से अधिक फायदा हो, लिमिटेशन्स और रिसोर्सेज को देखते हुए करने की कोशिश की है लेकिन क्योंकि ऐसा वातावरण हिन्दुस्तान में चल रहा है इसलिए जो कम्यूनिस्ट लेड एटक की यूनियन हैं, उनके द्वारा इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान को बंद किया जाय राजस्थान में कई यूनियन्स हैं लेकिन इंटक और एटक इन दो यूनियन्स के आंकड़े यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं :

इंटक	१९६४ तक टोटल	—	२५,२०२
एटक	,,	,,	५,०२५

अब ५०२५ लोग इस ख्याल को लेकर चलें कि राजस्थान की आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति को हम बंद करना चाहें तो मैं सदन को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, राजस्थान चलेगा, बन्द नहीं होगा।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें तालियां बजाने की क्या बात थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्योंकि समय काफी हो गया है जिन भी माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं मैं चीफ इंजीनियर से कहूंगा कि जिन कटौती प्रस्तावों में जनरल टर्म्स की बात नहीं है और स्पेसीफिक बात कही गई है, तो हरेक सदस्य को कोशिश करके दो तीन महीने के अन्दर, उसकी क्या पोजीशन है, वह आपको जानकारी देंगे पत्रों के जरिए। इसी आश्वासन के साथ मैं आशा करता हूं इस कि मांग को स्वीकार किया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप जो बजट प्रोवीजन रखते हैं, जैसे बूंदी जिले में, वह लैप्स हो जाता है, आपके विभाग वाले समय के अन्दर खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने चीफ इंजीनियर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और इसके लिए वह आपको कन्विन्स करेगा। हमने पैसा भी दिया है अगर वहां के इंजीनियर्स के पास पैसा होते हुए भी नहीं खर्च किया है तो जरूर एक्शन लिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : झालावाड़ से मांडोर की सड़क को चौड़ी करने की कोशिश करें....

श्री सभापति : No more Questions.

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : एक जिला हैडक्वार्टर से दूसरे जिला हैडक्वार्टर तक कोलतार की सड़कें कब तक कम्पलीट करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई भी जिला हैडक्वार्टर केपीटल से अनकनेक्टेड नहीं है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

लेकिन अगर आप उसको यह कहें कि आल वेदर किया हैं. बारिश में भी निकल जायेंगे ? वह पोजिशन आज नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : सवाई माधोपुर जाने के लिए टोंक होकर रास्ता खराब है।

कु० श्री महेन्द्र सिंह (दिगोद): बारां तक हो जावेगी ?

श्री दयाचन्द सोन (बारां मु०) : बारां में बिल्डिंग आपको दी थी।

श्री हरिश्चन्द्र : डिपार्टमेंट के हैंड ओवर की होगी।

श्री दयाचन्द सोन : आपके पास है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्डिंग दी थी वह पी० डब्लू० डी० ने टेक ओवर की।

श्री हरिश्चन्द्र : तो किया करते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ५० हजार की लागत की बिल्डिंग बना कर दी तो कब्जे में ली थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्या करना चाहते हैं, आप मुझे समझा दीजिये।

बिल्डिंग जो है उस पर पी० डब्लू० डी० का कब्जा नहीं हुआ तो कब्जा कर रहे हैं, कब्जा हो गया तो क्या चाहते हैं ?

श्री दयाचन्द सोन : जिस काम के लिए दी उसको उस काम में उपयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : किस उपयोग में आ रही है ?

श्री दयाचन्द सोन : आपके ही दफ्तर खोल रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : किस आदमी ने डोनेट की ?

(६.१० म० प०)

राज्य कर्मचारियों द्वारा विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शन विषयक वाद विवाद

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन यह करना है कि विधान सभा के सामने लगभग १५ हजार राज्य कर्मचारी महंगाई भत्ते की वृद्धि के लिए एक प्रदर्शन के रूप में यहां पर आये हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान का मंत्रिमंडल यहां पर है। राजस्थान विधान सभा के प्रतिनिधि के राजस्थान की सर्वोच्च सत्ता यहां पर विद्यमान है और इस सर्वोच्च सत्ता के समक्ष, वेतन भत्ते के प्रश्न को लेकर इतनी बड़ी तादाद में यहां उपस्थित हुए हैं। विधान सभा के नेता और माननीय मुख्य मन्त्रीजी हैड आॅफ दी स्टेट हैं इस नाते आवश्यकता इस बात की है कि वे इन कर्मचारियों के सामने जाकर उनकी सारी स्थिति क्या है उस सम्बन्ध में आश्वस्त करने की चेष्टा करें और उनको किसी प्रकार विश्वास में लें, महंगाई भत्ते में शीघ्र से शीघ्र विचार करें जो उनकी मांगे हैं उन पर सहानुभूति पूर्ण विचार करेंगे और उनको तत्परता से निपटायेंगे। राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के सदस्य और सरकारी कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर उपाध्यक्ष जी मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के साथ जाकर उनको आश्वस्त करेंगे तो इस सदन की और मन्त्रिमण्डल की शोभा बढ़ेगी।

श्री मानसिंह महार (ग्रामेर): माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्यमन्त्रीजी को इस बात की खुशी होनी चाहिये कि इतना ग्रभूतपूर्व संयम रख कर इस प्रकार का प्रदर्शन कि दफ्तर बन्द कर यहां पर एक जलूस लेकर ग्राये । जो उन्होंने संयम रखा ग्रौर जो नारे लगा रहे हैं उनसे यह साफ लगता है कि वे किसी प्रकार की घटना के लिये तैयार नहीं हैं । वे प्रार्थना करने के लिए ग्राये हैं ग्रौर ग्राप भी जानते हैं सभापति महोदय इस मंहगाई के युग में उनके साथ सरासर ग्रन्याय हुग्रा है। यह हम लोग भी महसूस करते हैं ग्रौर मैं तो समझता हूं कि सदन को एक बहुत बड़ी बह होगी कि मुख्य मन्त्रीजी उनसे मिलें, उनसे मिलते समय सदन में कुछ न कुछ करने की घोषणा करें । मैंने पहले भी चेतावनी दी थी कि सर्विसेज को कम्युनिस्टों ग्रौर उनके हाथों में लाने बचाने के लिए कुछ कीजिये, ग्रापने भंडारों का एलान किया, जिनसे कतई उनको सन्तोष नहीं हुग्रा। उनको तो क्या हमको भी ग्रापके इस एलान से सन्तोष नहीं है । जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए उन कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं वे न्यायोचित हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी को उनके यहां पीसफुली ग्राने पर बहुत खुश होकर कुछ न कुछ एलान जरूर करना चाहिये ! कोरे मिलने से ही काम नहीं चलेगा । माननीय मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि पार्टीबाजी या और ऐसे नहीं, लेकिन ग्रापके कर्मचारी हैं जिनके बल पर ग्राप राजस्थान का राज्य करते हैं, उनका यह प्रश्न है । इनको सन्तुष्ट रखेंगे तो ग्राप और भी कायम रह सकते हैं ग्रौर यदि ग्राप उनको ग्रौर ग्रसन्तुष्ट कर देंगे तो यह बहुत गलत चीज होगी । इसलिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि सदन की सब कार्यवाही रोक दी जाय, उनके डेपुटेशन से चलकर मिलें मुख्य मन्त्रीजी उनकी भावना की कद्र करते हुए इस प्रकार का ऐलान करें कि जिस प्रकार से दुखी हैं उस दुख से उनको दूर करें। यह नहीं कि भण्डार खोल दिये ग्रौर दुख दूर हो गया । यह ग्राशा तो कौल साहब से की जा सकती थी लेकिन मोहनलालजी सुखाड़िया से कोई ठोस कदम की ग्राशा करते हैं । इस लिए सभापति महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की महानता होगी कि सब सदन के सदस्य उन लोगों से जाकर मिलें, दस पन्द्रह मिनट के लिए सदन की कार्यवाही रोक दी जाय नीचे जाकर उनके प्रतिनिधि मण्डल से मिलें ग्रौर उनको ग्राश्वस्त करें । यदि नहीं करते हैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी तो वे एक गलत चीज कर रहे हैं । कोई पार्टी विशेष का जुलूस ग्राये तो वे कह सकते हैं कि नहीं मिलेंगे । लेकिन ये तो किसी पार्टी विशेष का नहीं । यह तो खुद मोहनलाल जी सुखाड़िया का जुलूस है । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर): सभापति महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है ग्रौर मैं एक हद तक यह भी समझता हूं कि मेरे दल का सम्बन्ध है हम उस चीज को मानकर चलते हैं कि कर्मचारियों ग्रौर मन्त्रियों बीच की समस्या है वह उनकी ग्रापसी ग्रन्दरुनी समस्या है । मैं नहीं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री को इस समस्या को लेकरके हम दबाव डाल कर कोई उलझन के ग्रन्दर पटकें । किन्तु उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह ग्राम जनता का सवाल है ग्रौर हमको ग्रधिकार है कि ग्रगर सरकार की नीति ऐसी है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि जिसके सम्बन्ध में हम सहमत नहीं हो तो हम अपने विचार व्यक्त करें। मैंने पहले भी कहा कि यह दूषित नीति है, प्लानिंग की नीति ठीक है। एक्स्पेंडिंग इकोनोमी की नीति एक हद तक ठीक है लेकिन एक्सपेंडिंग इकोनामी एक्स्प्लोइटिंग इकोनोमी की हद तक पहुंचेगी तो सरकार को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं यहां पर नहीं कह सकता कि सरकारी कर्मचारियों के साथ मेरी सहानुभूति है क्योंकि मैं इस सिद्धान्त को मान कर चलने वाला हूं कि यह सरकार का इन्टरनल मामला है लेकिन उसके साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवश्य ही कहूंगा कि यह आम जनता का सवाल है।

उपभोक्ता भण्डारों को खोलेंगे तो प्राईसेज बढ़ती चली जायेंगी, तो डी०ए० वगैरह पर करोड़ों रुपया खर्च करके एक चीज के पीछे चेन्ज करते जायेंगे और प्राइसेज बढ़ती जायेगी मुश्किल हल मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं निकल सकता, समस्या पर जैसा विचार करना हैं करेंगे लेकिन गम्भीर विषय है। मन्त्रीमंडल और कर्मचारियों में एक तालमेल है। कर्मचारी सन्तुष्ट रहें। असन्तुष्ट हैं तो मेरे ख्याल में सरकार आपकी नहीं चल सकती और यह सरकार के लिए अशोभनीय और बुरी बात है।

आपके द्वारा मन्त्रिमण्डल को और मुख्य मन्त्री को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सब ही जाकर बाहर उनसे मिलें। लेकिन मैं निवेदन करूंगा शिष्टाचार के नाते और आपके कर्मचारियों को सन्तुष्ट करने के नाते माननीय मुख्य मन्त्री को चाहिये कि डेपुटेशन के नेता, जैसी आपकी व्यवस्था हो, उनसे मिले और सहानुभूति का प्रदर्शन करें। यह तो सब ठीक है लेकिन उसके साथ साथ कोई ठोस कदम उठायें जिससे ये शिकायतें बार बार न आयें। बार बार आती है तो किस हद तक चुप रहेंगे। आखिर वे भी जनता तो हैं। कर्मचारी तो हैं लेकिन जनता का प्रश्न है। जनता के आम प्रश्न को लेकर मैं आशा करता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। यह आपका अन्दरुनी मामला है इसलिये मैं विशेष तो आज इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है उसके मैं हक में नहीं हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि इनकी दिक्कतें और दूसरी जो कुछ बाते हैं उस सम्बन्ध में इस सदन में भी और सदन से बाहर भी सरकार की तरफ से सदैव सहानुभूति का रुख रखा गया है अपने सीमित साधनों को सामने रखते हुए। इस सदन में मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां तक मंहगाई का प्रश्न है, हम इसको हल करने के बारे में अब तक मंहगाई भत्ते में वृद्धि करके और उनको रिलीफ देने का प्रयत्न करते रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े अर्थ शास्त्रियों ने इस बात को माना है और माननीय सदस्य भी इस बात को मानते हैं कि मंहगाई भत्ते के बढ़ाने से जिस क्रम की तरफ विरोधी दल के माननीय नेता ने ध्यान आकर्षित किया मंहगाई बढ़ती जाती है, उसको रोकने के बारे में कदम उठाना पड़ेगा। जो कदम हम उठाने जा रहे हैं उससे मंहगाई के रुकने में कुछ मदद मिलेगी। एसेन्शियल कौमोडिटीज हैं उन चीजों को एक निश्चित कीमत पर देने से जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

धन देकर के जो मनी मारकेट के अन्दर पम्प होता है उसकी वजह से मंहगाई बढ़ने के कारण पैदा होते हैं उसकी तरफ एक कदम होगा । इस लिहाज से राज्य सरकार ने निर्णय किया है और मैं समझता हूं जैसे पहले एडहाक इन्क्रीज देते रहे उसके मुकाबले इस व्यवस्था से आखिर जाकर राज्य कर्मचारियों को ज्यादा लाभ पहुंचेगा । इस सम्बन्ध में कल मैंने विषद् रूप से इस सदन में अपनी बात रखी थी । मैं आशा करके चलता था कि मैंने जो कल बातें कहीं थी उन चीजों की कीमत जो निर्धारित की जायगी जिस पर उनको दिया जायगा, वे कीमतें कब की हो, किस आधार पर हों उनको निश्चित किया जाय । इस बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है उसके बाद इस प्रकार के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । फिर भी जो यह प्रदर्शन हुआ उसके लिये मैं जैसा कि शुरु में कह चुका हूं मुझे इस बात का दुख है । राज्य कर्मचारी डेपुटेशन के तौर पर मिलें और तरह से मिलें वह परम्परा ज्यादा स्वस्थ परम्परा हो सकती है बमुकाबले प्रदर्शन की बात हो और और तरह के सवाल खड़े हों ।

सभापति महोदय, जहां तक उनसे मिलने का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से दूसरे प्रदर्शन आये उन प्रदर्शन करने वालों की तरफ से डेपुटेशन मिलने को आये उनसे हम मिले हैं, अगर राज्य कर्मचारियों का डेपुटेशन हम से मिलना चाहता है हमें उनसे मिलने के अन्दर कतई एतराज नहीं है । जहां तक सारा मंत्री मंडल और विधान सभा के सदस्य मिलने के लिये जाय मैं समझता हूं । इसकी सारी पेचीदगियों को और सारी बातों को ज्यादा व्यापक रूप में गम्भीर रूप में समझेंगे और जो अब तक दूसरे प्रदर्शन करने वाले आये उनसे डेपूटेशन से हम मिलते रहे हैं । उनका डेपूटेशन मिलना चाहता होगा तो इन सब बातों के होते हुए भी हम मिलने के लिये तैयार है । इतना ही मैं सदन में निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : सभापति महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है मुख्य मंत्री ने बताया कि वे इस प्रकार के प्रदर्शन के हक में नहीं हैं और उन्होंने यह भी बताया कि वे क्या करने वाले हैं, कल उन्होंने विधान सभा में जानकारी दी थी उसके बाद डेपूटेशन की तौर पर वे मिलते यह उनकी इच्छा थी उनको इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना था मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डेपुटेशन के रूप में मिलना चाहिये था....

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा कि प्रदर्शन करने से पूर्व उनको चाहिये था कि वे डेपूटेशन के रूप में मिलते । सभापति महोदय, आपने विधान सभा में भाषण दिया आपकी इच्छा थी और आप के बोलने के ऊपर उनको विश्वास करके चलना चाहिये था और कर्मचारियों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिये था । आप में इस प्रकार कर्मचारियों को विश्वास व्यक्त करना चाहिये था । आज जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है यहां के कर्मचारी यहां विधान सभा के सामने आकर प्रदर्शन कर रहे हैं जो कुछ उनको आपसे उम्मीद थी वह आकांक्षा पूरी नहीं हुई । और जब उनकी आकांक्षा आप पूरी नहीं कर सके या आपके कहने के बाद भी उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया आखिर यह किस कारण किया? अगर

(श्री भैरोंसिंह)

आपमें उनको विश्वास होता, आपने कल भाषण दिया और उसमें कहा कोई प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। आप यह मानकर चलिये आज तो राजधानी जयपुर में राज्य कर्मचारियों ने जो प्रदर्शन किया वह आपके प्रति अविश्वास प्रगट करता है इसका परिणाम क्या निकलेगा आपने कभी सोचा है ? केवल मात्र आपने इतना सा कह दिया कि अर्थशास्त्रियों का यह मत है। हम तो शुरु से यह मानकर चलते थे कि आप यदि अर्थशास्त्रियों का कथन शुरु से ही मानकर चलते तो आज यह प्रोब्लेम क्रिएट नहीं होती। आपने अर्थशास्त्रियों की बात नहीं मानी मंहगाई भते बढ़ाते गये पहले तो गलती कर दी अब आप उसको सुधारना चाहते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या केन्द्रीय सरकार ने जो अपने कर्मचारियों का मंहगाई भता बढाया क्या वहां अर्थशास्त्रियों की बात मानने वाले नहीं थे या वे अर्थशास्त्र के जानने वाले नहीं है। वहां कोनसा प्रश्न पैदा हो गया कि जिसके कारण अर्थशास्त्र के आपके इस सिद्धांत को हिन्दुस्तान की किसी स्टेट ने नहीं केवल आप ही उस पर चलना चाहते हैं। इनकी मांगे केवल यही हैं कि उनका मंहगाई भता केन्द्रीय कर्मचारियों के भत्ते के बराबर हो। जब केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिलता हैं तो आप उसे देने के लिये तैयार क्यों नहीं हैं। दूसरा उनकी यह मांग है कि जब तक आप उपभोक्ता भंडार नहीं खोल देते तब तक आप एडहाक तौर पर केन्द्रीय कर्मचारियों का भता उनको दे दो। आपने यह भी नहीं बताया कि किस तारीख तक आप यह भंडार आदि खोल देंगे कि किस तारीख से उनको सामान मिलना शुरु हो जायगा। जब तक आप यह शुरु नहीं कर देते हैं तब तक आपको एडहाक तौर पर मंहगाई भत्ता केन्द्र के समान देने में क्यों एतराज होना चाहिये ? इतनी वाजिब मांगों को नहीं मानते हुए आप उल्टा दोषी सरकारी कर्मचारियों को ठहराते हैं और उन पर रोब गांठने की कौशिश करते हैं कि वे प्रदर्शन नहीं करें।

मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि राज्य कर्मचारियों का यह पहला प्रदर्शन है। उन्होंने पहली बार प्रदर्शन किया है इसमें केवल अराजपत्रित कर्मचारी हो सम्मिलित हुए हैं। यह जो आपके सोचने का यही ढंग रहा तो आज तो ये कर्मचारी आये है कल डाक्टर्स सामने आयेंगे, इन्जीनियर्स सामने आयेंगे, टेकनिकल सरविसेज के लोग सामने आयेंगे। बुनियाद तो इसकी आप कायम कर रहे है। आपको चाहिए कि किसी भी कीमत पर आप राज्य कर्मचारियों की कोनफीडेन्स सीक करें। आपकी सरकार है आप बहुमत के आधार पर राज्य कर रहे हैं, आपको बहुमत का अभिमान है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें राजनैतिक दांव पेच का सवाल नहीं है आज १५ हजार कर्मचारी विधान सभा भवन के सामने आये हैं।

आज एक परिवार में पांच व्यक्ति मान कर चलें तो ७५ हजार व्यक्तियों का जुलूस है जिससे आप मिलने के लिये संकोच करते हैं उनको विश्वास में लेने का संकोच करते हैं। यदि उन लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि मुख्य मंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्य उनकी फरियाद सुनने के लिये तैयार नहीं हैं तो उनमें और असन्तोष बढ़ेगा। इस समय असन्तोष बढ़ाने का नहीं, असन्तोष मिटाने का सवाल है। जहां तक बाकी के प्रदर्शनों का सवाल है ये प्रदर्शन किसी न किसी

(भैरोंसिह)

पोलिटिकल पार्टी द्वारा आयोजित होकर आते हैं, किसी पार्टी का उनके साथ झंडा होता है। ये जो लोग आये हैं न किसी प्रकार का इनके पास झंडा है न किसी पार्टी द्वारा यह प्रदर्शन लाया गया है, ये लोग तो आपके सबोर्डिनेट्स हैं, इनको आप रखते हैं प्रोमोशन देते है, महंगाई, भत्ता देते हैं, आपको और इनके बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। यह बात तो मुझे विधान सभा में कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये मुख्य मंत्री महोदय स्वयं अपने साथियों को लेकर दरवाजे पर खड़े होते। वे जिस अनुशासन में आये हैं उन्होंने जो अनुशासन रखा है उसके लिये आपको अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिये और उनको आप ऐड्रेस करते तो ज्यादा अच्छा होता उनमें आपके प्रति विश्वास बढ़ता लेकिन आप यह न कर उनके विश्वास को खोते हैं, इससे विधान सभा के सम्मान में भी कमी आई हैं और ज्यादा इनमें असन्तोष बढ़ेगा इसमें दो राय नहीं है।

मांग संख्या ४२, सार्वजनिक निर्माण कार्य इत्यादि

(पूर्व क्रम से)

श्री सभापति : मांग संख्या जिसके ऊपर अभी वाद विवाद हुआ है और जिसको पारित करना है उसको मैं सदन के वोट के लिए रखता हूं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५३,१०.००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३ पारित की गई सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक २८ मार्च...... ......

(६.३१ म० प०)

शासकीय वक्तव्य देने विषयक अध्यक्षपीठ द्वारा व्यवस्था

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : मुझे एक स्टेटमेंट जैसा मैंने सुबह निवेदन किया था देना है।

श्री भैरोंसिह : सदन स्थगित हो चुका है, मांग पारित हो चुकी है। अब हम इस स्टेटमेंट को सुनना नहीं चाहते।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही मांग पारित होने तक बढ़ाई गई थी और उसके बाद में सदन नहीं बैठ सकता। अगर आपको वक्तव्य देना था तो आपको मांग पारित होने से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। वह अब नहीं दी जा सकती।

सदन की कार्यवाही सोमवार प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ६ बज कर ३२ मिनट पर सोमवार दिनांक २८ मार्च, १९६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ का उत्तर देखिये)

डिमान्ड चार्जेज

प्रथम ६००-के० वी० ए० र० ६.५० प्रति माह प्रति के० वी० ए० बिलिंग डिमांड अतिरिक्त १२०० के० वी० ए० र० ६.०० प्रति माह प्रति के० वी० ए० बिलिंग डिमान्ड अतिरिक्त १८०० के० वी० ए० से ऊपर ५.५० पैसे प्रति माह प्रति के० वी० ए० बिलिंग डिमान्ड और एनर्जी चार्जेज :—

प्रथम ५०,००० यूनिट प्रति माह ५.६८ पैसे प्रति यूनिट ।

अतिरिक्त १,५०,००० प्रति माह ५.८२ पैसे प्रति यूनिट ।

अतिरिक्त ३,००,००० प्रति माह ५.५१ पैसे प्रति यूनिट ।

५,००,०००) रु० प्रति माह से ऊपर ५.३० पैसे प्रति यूनिट उपरोक्त टैरिफ फैक्ट्री लाइटिंग क्लाज, फ्यूल एडजेस्टमेंट क्लाज व मासिक न्यूनतम राशि के अनुसार संशोधित होता है ।

राजस्थान विनायल व केमिकल्स इन्डस्ट्रीज, कोटा को हाई वोल्टेज पर विद्युत एक विशेष टैरिफ (रु० २०१.०४ प्रति के० वी० ए० प्रति वर्ष या रुपया १६.५५ प्रति के० वी० ए० मैक्सीमम डिमान्ड प्रति माह) के अन्तर्गत दी जाती है ।

कृषि के लिये कम वोल्टेज पर दी जाने वाली विद्युत् की दर १२ पैसे प्रति यूनिट है व वार्षिक न्यूनतम राशि रुपये ४२.०० प्रति वी० एच० पी० है ।

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

तहसील प्रतापगढ़ में शुगर फैक्ट्री एवं पावर लूम को बिजली

४०८. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में शुगर फैक्ट्री और पावर लूम गत साल लग चुका है ?

(२) क्या इन दोनों कारखानों को बिजली नहीं मिलने से दोनों कारखाने गत साल से बन्द पड़े हुए हैं ? यदि हां तो बिजली नहीं देने का क्या कारण है व अब भविष्य में कब तक दी जायेगी ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि ये दोनों कारखाने सहकारी आधार पर लगाये गये हैं और बिजली लेने के विषय में गत साल से मांग की जा रही है और सोसाइटी को नुकसान हो रहा है ?

उत्तर

(१) इस प्रकार की जानकारी नहीं है। कनेक्शन के लिये दरख्वास्त पावर लूम से २-२-६५ व शुगर फैक्ट्री से ४-६५ में अवश्य आई थी।

(२) अभी तक इन कारखानों में पूर्ण रूप से मोटर नहीं लगी हैं।

(३) किस आधार पर ये कारखाने बने हैं इसकी जानकारी नहीं है। यह अवश्य है कि इन कारखानों में अभी मोटर पूर्णरूप से नहीं लगी है।

ग्राम पंचायत चोरू को जल बोर्ड द्वारा सहायतार्थ दी गई धनराशि का गबन

४०९. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चोरू, तहसील उनियारा, जिला टोंक में जल बोर्ड की ओर से १५,००० रु० की धनराशि सहायतार्थ दी गई थी ? यदि हां तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि इस धनराशि को वहां के साबिका सरपंच श्री कल्याणमल ने खर्च नहीं किया और अपने निजी कार्य में उसका उपयोग किया ? यदि नहीं तो कहां कहां खर्च की गई ?

(३) क्या यह सत्य है कि हाल ही में उक्त साबिका सरपंच श्री कल्याणमल से १७४० रु० वसूल किये गये हैं ? यदि हां तो कब ? अब और कितनी रकम वसूल होना बाकी है ?

(४) क्या यह सत्य है कि श्री सूरजभानसिंह साबिका पंचायत इन्स्पेक्टर महोदय ने मौके पर इस खर्च की जांच की थी ? यदि हां तो कब और क्या उस रिपोर्ट में गबन होना लिखा था ?

Page No.136

उत्तर

(१) जी हां। सन् १९५४-५५ में।

(२) जी नहीं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां। २६-८-६३ को वसूल की गई व अब कोई रकम वसूल करना शेष नहीं है।

(४) जी हां। सन् १९५६ में। रिपोर्ट गबन होना लिखा था।

श्री कल्याणमल भूतपूर्व सरपंच द्वारा जिन स्थानों पर धनराशि खर्च की गई उनकी सूची

क्रमांक	नाम गांव जहां पंचायत ने काम किया	नाम काम
(१)	चौरू	(१) २ कुओं की मरम्मत कराई
		(२) ३ तलाइयों की मरम्मत
(२)	बिशनपुरा	(१) नया कुआ
(३)	पचाला	(२) बावडी की मरम्मत
(४)	बेगमपुरा	(१) नया कुआ
(५)	अमीनपुरा	(१) तलाई की मरम्मत
		(२) मरम्मत कुआ
(६)	रहमान नगर	(१) तलाई की मरम्मत
		(२) कुवे की मरम्मत
(७)	पालड़ी	(१) तलाई की मरम्मत

कालख सागर बन्ध से सिंचाई

५१०. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बंध कालख सागर से सिंचाई बढाने के लिये सम्बन्धित विभाग ने क्या कोई प्रस्ताव सरकार के सामने रक्खे हैं ?

(२) अगर हां, तो वे क्या क्या हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील इन्द्रगढ में अकालग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

५११. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ चम्बल अन-कमान्ड एरिया में हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पानी न बरसने से इस तहसील के सारे गांव अकालग्रस्त हैं ? और इनमें दोनों ही फसलें नहीं हो सकी हैं ?

(३) क्या यह सही है कि तहसीलदार के निरीक्षण से यह तहसील अकालग्रस्त पाई गई है लेकिन इसे अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या सरकार इन गांवों को चारा व अनाज सहायता के रूप में देने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी हां ।

२. यह सही है कि इस सब तहसील में वर्षा की कमी से कई गांवों में फसल खरीफ में क्षति हुई है ।

३. सब तहसील इन्द्रगढ़ के ३० गांवों में अभाव स्थिति है जिन को राज्य सरकार ने राजस्थान राजपत्र के विशेषांक एफ १ (२८) आर० सी।दि० २१-१-६६ को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है ।

४. जी हां ।

उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान कार्य ।

५१२. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(१) क्या यह सही है कि कृषि विभाग के तहत कृषि अनुसन्धान कार्य को उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत देने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

(२) क्या यह सही कि एक उच्चस्तरीय कमीशन ने अनुसन्धान के कार्य कृषि विश्वविद्यालय को देने की सिफारिश की है तथा अमेरिकी आर्थिक सहायता भी यह कार्य कृषि विश्वविद्यालय को सौंपने पर मिलने का प्रस्ताव आया है ?

(३) यदि हां तो सरकार का निर्णय क्या रहा ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. ऐसे किसी कमीशन के बारे में जानकारी नहीं है। यह ठीक है कि अमरीकी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में ऐसा सुझाव आया हैं कि अनुसंधान कार्य कृषि विश्वविद्यालय को दिया जावे।

(३) सरकार ने इस पर विचार कर आदेश दे दिये हैं कि fundamental research तो विश्वविद्यालय करेगी तथा applied research कृषि विभाग द्वारा की जावेगी।

सी. टी. एस. बसें जयपुर

५१३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सी० टी० एस० की बसें जो जयपुर में चलती हैं अधिकतर खराब हैं और उनमें बैठने की सीटें भी अच्छी नहीं है ? यदि हां तो कितनी बसें खराब हैं और उनको क्यों नहीं हटाया जाता है ?

(२) क्या यह भी सच है कि बसों की संख्या कम होने से काफी भीड़ रहती है और हर बस ओवर लोड चलती है ? यदि हां, तो बसों की संख्या बढ़ाने में क्या कठिनाई है ?

उत्तर

(१) सी० टी० एस० की बसों के खराब होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(२) सेन्ट्रल ट्रांसपोर्ट सर्विस की जयपुर नगर में पहले के परमिट पर इस समय १५ बसें चल रही हैं। इसके अलावा इनको ३० नई बसें और लगाने का परमिट दिया गया है जिसमें से उन्होंने ६ बसे लगा दी ओवर लोडिंग के लिये परिवहन विभाग के इन्सपेक्टर्स बसों की जांच करते हैं और ऐसा होने पर इनका चालान किया जाता है।

ग्राम भावरी में गबन

५१४. श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५९-६० में जिला सिरोही, पंचायत समिति, पिंडवाड़ा के ग्राम भावरी में एक चबूतरा बनाने का झूठा हिसाब बना कर उस समय के ग्राम पंचायत सरूपगंज (हाल ग्राम पंचायत भावरी) के सरपंच मगनमल ने ३६१) रुपयों का गबन किया था ?

(२) क्या यह सही है कि दिनांक ११-९-६१ को ग्राम पंचायत भावरी ने अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास करके दिनांक २५-९-६१ को पंचायत के सदस्यों ने एक दरख्वास्त कलेक्टर सिरोही को वास्ते जांच करने को दी थी ?

(३) क्या क्या यह सही है कि श्री जगनारायणसिंह, तत्कालीन सहायक कलेक्टर

पंचायत एवं सचिव जिला परिषद् सिरोही ने दिनांक १-११-६१ को भावरी मुकाम ग्राम चोरे पर मुकम्मिल जांच कर उस पर उपस्थित पंचों एवं मौतबिरों के हस्ताक्षर लिये थे और वह कार्यवाही एस० पी० सिरोही को श्री मगनमल के विरुद्ध जेर दफा ४०८-४०६ आई० पी० सी० में केस रजिस्टर के करने लिए व कोर्ट में मुकदमा चालान करने के लिये दी थी ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि शासन सहायक सचिव (जांच) पंचायत, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ. ३ (एजे.) (१०१) सिरोही।६५)२४४५६-५०, दिनांक २६-६-५६ के जरिये कलेक्टर सिरोही एवं एस० पी० सिरोही को जांच जल्द कर केस चालान करने को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(५) क्या सरकार ने हाल ही में जारी किये गये अध्यादेश द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री मगनलाल को पंचायत समिति पिंडवाड़ा के प्रधान पद से निलम्बित किया है ? यदि, नहीं तो क्यों ?

(६) सरकार कब उसे निलम्बित करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां ३५१) रु० का

(२) जी हां।

(३) जी हां, अभियोग चलाने के सम्बन्धित कार्यवाही जारी है।

(४) जी नहीं। केवल जांच शीघ्र पूर्ण कराने हेतु लिखा गया था।

(५) जी नहीं, पुलिस जांच के दौरान निलम्बित करने का प्रावधान नहीं है।

(६) पुलिस द्वारा केस अदालत में प्रस्तुत कर देने के बाद ही विचार किये जा सकता हैं।

साहबा-भालेरी सड़क में आई भूमि का मुआवजा

५१५. **श्री मोहर सिंह (चूरू) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या साहबा से भालेरी सड़क के लिए ली गई भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों को दिया गया है ? यदि हां तो कब और कितना ? यदि नहीं दिया गया तो अब कब तक सरकार मुआवजा देगी ?

उत्तर

१. जो नही। रावस्व विभाग से अबार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा दिया जा सकेगा।

पंचायत समिति सांगोद व छीपाबड़ोद में हेल्थ सेन्टर्स

५१६. **श्री जुझारसिंह (चेचट) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जिला कोटा की पंचायत समिति सांगोद व छीपाबड़ोद में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर कब से मन्जूर किये गये हैं और समितियों में हेल्थ सेन्टर व सब-सेन्टर के लिए कौन २ से स्थान चुने गये हैं ?

(श्री जुझारसिंह)

(२) क्या यह सही है कि जनता द्वारा योगदान आज से करीब दो साल पूर्व जमा करवाया जा चुका है परन्तु अभी तक सेंटर या सब-सेन्टर के भवन को चालू करने के लिये विभागीय मदद व मंजूरी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(३) इन समितियों के सेन्टर्स व सब-सेन्टर्स पर अब तक कितना कितना स्टाफ किस किस स्थान पर नियुक्त किया जा चुका है और कितना कितना और नियुक्त करना बाकी है ? क्या आवश्यक मात्रा में दवाईयां अलग अलग स्थानों पर पहुंचाई जा चुकी है? उन्हें रखने का क्या प्रबंध है ?

(४) इन समितियों के सेन्टर्स व सब-सेन्टर्स को कब तक पूरा करवा दिये जाने की योजना है ?

उत्तर

(१) जिला कोटा पंचायत समिति सांगोद क्षेत्र में आंबा में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने की स्वीकृति सरकार से पत्र संख्या एफ १.(४८) एम० पी० एच०/ ६३ दिनांक २६-११-६४ द्वारा दी गई। यह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर दिनांक १०-४-६५ को खोला जा चुका है इससे सब-सेन्टरों के लिये क्रमशः कुन्दनपुरा पुलेट मोइकलां के स्थान चुने गये हैं।

पंचायत समिति छीपाबड़ौद क्षेत्र में सारथल में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोलने की स्वीकृति सरकार के पत्र संख्या एफ० ६ ६) एम० पी० एच०/६५ दिनांक १२-११-६५ द्वारा दी गई जिसको चालू कराने की कार्यवाही जारी है (सब-सैन्टरों के खोलने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति छीपाबड़ौद से रेजोल्यूशन प्राप्त होने पर राज सरकार से मन्जूरी दी जावेगी।

(२) आंबा की जनता द्वारा एक भवन राज सरकार को प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिए दिया गया है, जो अपूर्ण है इसे पूर्ण कराने की कार्यवाही जारी है।

(३) आंबा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में निम्नलिखित स्टाफ की नियुक्ति की जा चुकी है :—

क्र.सं.	पद	स्वीकृत संख्या	मौजूदा स्थिति
१.	डाक्टर	१	--
२.	कम्पाउंडर ग्रेड I	१	--
३.	कम्पाउंडर ग्रेड II	१	२ (जिसमें १ कम्पा० ग्रेड II का ग्रेड के स्थान पर कार्य कर रहा है)
४.	कम्पाउंडर ग्रेड III	१	१
५.	स्वा० निरीक्षक	१	१
६.	लेडी हैल्थ विजीटर	१	१
७.	एक्जक्लेरी हैल्थ वर्कर	३	३ (तीनों उप-केन्द्र पर कार्य कर रही हैं)
८.	मिडवाईफ	४	१
९.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	७	२
१०.	ड्राईवर	१	-

Page No.141

(चिकित्सा मंत्री)

उपरोक्त प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में दवाईयों का स्वीकृत बजट १५००) रु० का है परन्तु इसे ३०००) रु० लगभग की दवाईयाँ सप्लाई की गई है स्टोर में दवाइयां को रखने के स्थान को भी उचित व्यवस्था कर दी गई है।

चूंकि सारथल में प्राथमिक हैल्थ सेन्टर अभी खोला नहीं गया है अत: वहां कोई भी स्टाफ कार्य नहीं कर रहा है ।

(४) इन पंचायत समितियों के प्राइमरी हैल्थ केन्द्रों का निर्माण कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही पूरा किया जावेगा।

आबूरोड रोडवेज डिपो की आमदनी

५१७. श्री दलपत सिंह (आबू): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि आबूरोड रोडवेज डिपो की आमदनी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है ?

(२) रोडवेज डिपो आबूरोड की १९६५-६६ में क्या आमदनी हुई और १९६४-६५ के मुकाबले कितनी बढ़ी या घटी ?

(३) अगर यह बढ़ी है तो उसके मुख्य मुख्य क्या कारण हैं ? और घटी है तो क्या ?

उत्तर

(१) सिरोही जिले में निगम के दो डिपो हैं, सिरोही व आबूरोड जिसमें आबू डिपो की आमदनी अधिक है।

(२) सन् १९६४-६५ में जनवरी ६५ तक कुल आय ८,३२,३४५ रु० की तथा सन् १९६५-६६ में जनवरी १९६६ तक ८,९५,७१६) रु० की आय हुई। इस तरह सन् १९६५-६६ में ६३,३७१ रु० की आमदनी अधिक हुई।

(३) सन् १९६५-६६ में १९६४-६५ से आमदनी अधिक होने का एक मात्र कारण निगम की गाड़ियों का अधिक मील चलना है।

गीजगढ़-गंगापुरा सड़क का कार्य

५१८. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या गीजगढ से गंगापुर सड़क वाया गुढाचन्द्रजी का कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा कर दिया गया है ? यदि हां तो कब और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) क्रोस ड्रिनेज कार्य को छोड़कर सड़क जून १९६५ में पूर्ण हो चुकी है।

राज्य में अकाल

५१९. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): श्री हीराभाई (कुशलगढ) : क्या राजस्व व अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में इस वर्ष किन किन जिलों में अकाल घोषित किया गया है ? उक्त जिलों में कितने कितने गांव में अकाल घोषित किया गया है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(२) जिलेवार अकाल सहायता के लिये कितनी कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ? कृपया आंकड़ों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जो धनराशि दी गई है उसका उपयोग किस एजेन्सी द्वारा किया जावेगा और यह राशि कब तक खर्च होनी चाहिए ?

(४) क्या यह सत्य है कि अकाल राहत कार्यों के लिये मजदूरी की जो दरें रखी गई हैं वह कम हैं और इस कारण लेबर नहीं मिलती है और इस रकम का ठीक उपयोग नहीं होता है ?

(५) क्या सरकार दरों में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में इस वर्ष २४ जिलों में अकाल घोषित किया गया जिसकी सूची मय जितने गांवों में अकाल घोषित किया गया सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जिलेवार जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसका मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(३) जो धनराशि दी गई है उसका उपयोग रेवेन्यू ऐजेंसी, पी० डब्ल्यू० डी० और इर्रीगेशन एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। यह धनराशि वित्त वर्ष ६५-६६ के अन्त तक खर्च हो जानी चाहिये।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आबू रोड-भटाना बस

५२०. श्री दलपतसिंह (आबू): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि आबूरोड से भटाना तक रोडवेज की बस दो वर्ष से चल रही थी ? यदि हां, तो अब बन्द क्यों कर दी गई हैं ?

(२) क्या ये बसें अब पुनः चलेंगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां। सन् १९६५ की वर्षा ऋतु में इसे बंद कर दिया गया था। यह मार्ग कच्चा होने के कारण बरसात में इस पर गाड़ियां नहीं चल सकतीं। बरसात के बाद से अभी तक यह मार्ग ठीक नहीं हो पाया है, इसलिए गाड़ी वापस चालू करने में देर हो रही है।

(२) मार्ग की मरम्मत हो जाने पर गाड़ियां शीघ्र ही चला दी जायेंगी।

अकालग्रस्त क्षेत्रों को सहायता, तहसील पीपल्दा

५२१. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष तहसील पीपल्दा के कौन कौन से गांव पानी न बरसने से अकालग्रस्त हैं और सरकार ने उन्हें क्या सहायता प्रदान की है ?

(२) क्या यह सही है कि इन गांवों में दोनों फसलें नहीं हुई हैं ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(३) क्या यह सही है कि इस तहसील में चम्बल का अन-कमाण्ड एरिया भी है ? यदि हां, तो उनमें कौन कौन से गांव आते हैं ?

उत्तर

१. पिपल्दा तहसील की सब-तहसील इन्द्रगढ़ के ३० गांव जिनकी सूची संलग्न है अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं। पीपल्दा तहसील के २० गांवों को अकालग्रस्त घोषित किये जाने की सिफारिश अकाल सहायता विभाग को और प्राप्त हुई हैं। जिनकी सूची भी संलग्न है।

अकाल सहायता विभाग द्वारा ३०,००० रुपये व योजना विभाग द्वारा १,६५,००० रुपये नये कुओं के लिए स्वीकृत किये गये हैं। तथा ४८,००० रुपये की एक और राशि योजना विभाग द्वारा पम्पिंग सेट के लिए स्वीकृत की गई है। जिन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया जा चुका है उनकी लगान व अन्य मतालबों की वसूली स्थगित कर दी गई है।

२. अभी तक खरीफ के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है रबी की नहीं क्योंकि गिरदावरी अभी चालू है।

३. जी हां। सब तहसील इन्द्रगढ़ में कुल ८४ गावों में से ६३ गांव अनकमान्ड के हैं तथा तहसील पीपल्दा में केवल १ गांव। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू रतनगढ सड़क में आई भूमि का मुआवजा

५२२. श्री मोहर सिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या चूरू से रतनगढ़ तक की सड़क के लिए ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया ? यदि हां तो कब और कितना दिया गया ? यदि नहीं दिया गया तो कब तक दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं। अवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा दिया जायगा।

स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री, कोटा

५२३. श्री कृष्णकुमार गोयल(कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री, कोटा में सरकार का कितना रुपया शेयर ऋण व सिक्यूरिटी के रूप में लगा हुआ है ?

(२) इसके अतिरिक्त अन्य किन किन विभागों का कितना कितना रुपया उक्त फैक्ट्री में रायल्टी, लीज आदि का बकाया है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री वन्द पड़ी है ? अगर हाँ, तो कब से व क्यों ?

(४) सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

१. राज्य सरकार द्वारा कोई रकम स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री कोटा में नही लगाई है।

Page No.144

(उद्योग मंत्री)

२. (१) वन विभाग का ३०,००० रु० रोयल्टी का (२) उद्योग विभाग का ८१४ रु० ४ पैसा ११-६-६४ से १०-६-६५ तक का।

३. जी हां। १६-१-६६ से।

४. सरकार ने फैक्ट्री मालिक को बुला कर बातचीत शुरू की है और उनके सामने जो दिक्कतें हैं उसे मिटाने की कोशिश कर रही है।

स्थगित प्रश्न

१४-३-६६

डाक्टरों की कमी

२४४. **श्रीमती गोरी पूनियां (डेगाना)**; क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस समय राजस्थान में कुल कितने डाक्टरों की कमी है ?

(२) पिछले दो वर्षों में राज्य के विभिन्न मेडीकल कालेजों से कुल कितने डाक्टर एम. बी. बी. एस. की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तथा उनमें से कितने डाक्टर सरकारी नौकरी में गए तथा कितने डाक्टरों ने सरकारी नौकरी में जाने से इन्कार कर दिया ?

उत्तर

(१) इस समय कुल ३५६ डाक्टरों की कमी है।

(२) जयपुर एवं बीकानेर चिकित्सा महा विद्यालय से पिछले दो वर्षों में निम्न-लिखित विद्यार्थियों ने एम. बी. बी. एस. की परीक्षा पास की है:-

१. सवाई मानसिंह चिकित्सा महा-विद्यालय जयपुर से जून १९६४ में १३० एवं १९६५ में १२४ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

२- सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर से सन् १९६४ में ४५ व सन् १९६५ में ७१ कुल ११६ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

इन दो वर्षों में ११० डाक्टर सरकारी नौकरी में आये तथा शेष डाक्टर २६० नौकरी में नहीं आये।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण—शनिवार, दिनांक, २६ मार्च, १६६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१०	१६	निर्णाय	निर्णय
१०	अंतिम से २	की	कि
११	६	दुर्भान्यपूर्ण	दुर्भाग्यपूर्ण
१२	६	मे	है
१३	अंतिम से ८	फर्म्म	फर्म
२२	७	कौटा	कोटा
२२	१३	शिकायतें	शिकायत
२५	१०	एन्वेस्टीगेशन	इन्वेस्टीगेशन
२६	२	कार्यवाह	कार्यवाही
३०	६	करने	करके
३२	१	उसकी	उसका
३६	अंतिम से ३	तयार	तैयार
४०	२३	किया	दिया
४२	१३	चम्बस	चम्बल
४७	१०	उपाध्य	उपाध्यक्ष
४७	१६	में	मैं
४७	अंतिम से ३	चिथौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
४८	,, २	शीघ्रे	शीघ्र
४६	शीर्षक	माच	मार्च
४६	४	खण्डोर	खण्डार
४६	४	हुइ	हुई
५०	३	कर	घर
५०	१३	विशाना	विशना
५०	२१	कटना	घटना
५४	अंतिम	करने स्थिति	करने की स्थिति
५५	३	समझ	समझे
५७	अंतिम से १०	अपयाप्त	अपर्याप्त
६०	८	वर्कस	वर्क्स

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६५	अंतिम से ८	जानी	जाती
६५	,, ,, १	मेटिरियल	मेटिरियल
६६	२०	कौ	को
६६	अंतिम	अधार	आधार
७१	,, ,, १	ईस	इस
७८	,, ,, ४	not recorded	not be recorded
८१	,, ,, ६	सकण	सकता
८२	३	(आसपुरा)	(आसपुर)
८२	अंतिम	गगा	गया
८४	अंतिम से ११	जायगी	जायगा
८४	,, ,, ६	जाय े	जायगी
८६	१६	गाली	गोली
८६	अंतिम से ८	उसकी	उसको
८७	अंतिम,	५०सार्वजनिक निर्माण कार्य	Delete
६४	अंतिम से २	वेंग	बेंगू
१०१	१३	की	को
१०२	१६	भंवरलाल	भैरवलाल
१०५	अंतिम	के लिये २।	के लिये)।
११४	६	शीषेक	शीर्षक
११५	अंतिम से ६	सावेंजनिक	सार्वजनिक
११८	,, ,, ३	बेठ	वैठ
११६	१६	ध्यैय	ध्येय
११६	अंतिम	की	का
१२२	१६	भौर	ओर
१२२	२२	१ ५	१४५
१२२	२२	आबादी	संख्या
१२५	१४	पे	वे
१२७	१६	निर्माणे	निर्माण
१२८	अंतिम से ४	इसक	इसके
१३०	१७	पसा	पैसा
१३१	शीर्ष	(श्री कुभार गोयल)	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
१३२	अंतिम	बढ़	वड़े

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३६	१६	बढ़ाया	बचाया
१३६	अंतिम से १६	तीस के	तीस मील के
१३८	६	सभापति महोदया,	उपाध्यक्ष महोदय,
१३८	अंतिम से ६	सो	हो
१३८	५	इसलिले	इसलिये
१३६	४	सावेंजनिक	सार्वजनिक
१४०	११	मदा	मंदा
१४०	अंतिम से ११	ग्रोवल	ग्रेवल
१४५	५	बढ़ाती	बढ़ी
१४५	अंतिम से ४	गेजिटेढ	गजेटेड
१४७	४	जौ	जो
१५१	११	वसय	व्यास
१५५	२०	पच्यीस	पच्चीस
१५८	अंतिम से ७	डिस्टिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
१५६	,, ,, १३	लड़क	सड़क
१६२	शीर्षक	पूं ला.	पू. की ला.
१६६	१०	बहत	बहुत
१६६	१६	वानिग	वार्निंग
१७१	७	मे ी	मेरी
१८७	११	कार्याबिन्त	कार्यान्वित
१६४	२०	सर्तकता	सतर्कता
२००	शीर्षक	पूर्व का	पू. की
२०५	१६	नर्हीं	नहीं
२०७	अंतिम से ३	भंत्री	मंत्री
२०८	१७	अलाता	अलावा
२१२	१५	जी	की
२१३	१	कांग्रैस	कांग्रेस
२१३	अंतिम से १	थोड़ा जाता	थोड़ा हो जाता
२१५	,, ,, ८	बिल्ड़ि स	बिल्डिग्स
२१६	१५	तोढ़	तोड़
२१६	अंतिम से ३	ओयिनली	ओपिनली
२१८	११	कप	कम
२१६	शीर्षक	एंव २७	एंव ४२

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२१६	१३	रुपथा	रुपया
२१६	अंतिम से १०	हम	यह
२२०	१२	खा	सा
२२१	६	औइ	और
२२२	२१	अच्चा	अच्छा
२२५	१६	वात	बात
२२५	१६	हड़मारा	हरमाड़ा
२२७	अंतिम से १२	पोठरवम	प्रोब्लम
२२६	शीर्षक	शर्मा	वर्मा
२३५	१७	पर। होकर	पर होकर।
२५२	अंतिम	क	का
२५४	शीर्षक	पूर्व	पूं.
२५५	३	।	तो
२५७	१८	लाने बचाने	लाने से बचाने
२५७	अंतिम से २	मान ीय	माननीय
२५८	१६	का	के
२५८	अंतिम से ८	मन्त्रियों बीच	मन्त्रियों के बीच
२६१	,, ,, २	जाव	जावें
२६३	७	अथ -	अर्थ–
२६८	५	४०८	५०८
२६६	४	रिपोर्ट गबन	रिपोर्ट में गबन
२७२	६	किये	किया
२७२	७	हैं	है